Seventh Series, Vol. XV; No. 37

Tuesday, April 7, 1981
Chaitra 17, 1903 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

Fifth Session

(Seventh Lok Sabha)

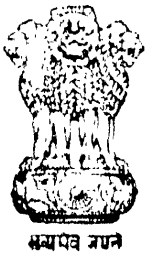

(Vol. XV contains Nos. 31 to 40)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price : Rs. 6.00

CONTENTS

No. 37, *Tuesday, April* 7, 1981/*Chaitra* 17, 1903 (*Saka*)

COLUMNS

Oral Answers to Question :

*Starred Questions Nos. 702, 704 *and* 706 to 708 . . . . 1—29

Written Answers to Questions :

Starred Questions Nos. 705, 709 to 721 and 597 . . . . 29—45

Unstarred Questions Nos. 6606 to 6619, 6621 to 6670, 6672 to 6683, 6685 to 6733 and 6735 to 6670 . . 45—244

A statement correcting reply to U.S.Q. No. 7369 dt. 17-4-79 . 244

Re. Motions for Adjournment—

Firing on Farmers of Nippani, Karnataka agitating for higher tobacco prices . . . . . 245—56

Papers Laid on the Table . . . . . 256—59

Committee on Papers Laid on the Table . . . . .

(i) Minutes 260

(ii) Seventh Report 260

Committee on Public Undertakings—

(i) Minutes 260

(ii) Sixteenth Report 260

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

Reported stranding of 400 Indian Seamen at Basrah Port since outbreak of Iran-Iraq War . . . . . 261—82

Shri Rasheed Masood . . . . . 261,264—74

Shri P.V. Narsimha Rao . . . . . 262—64

Kumari Pushpa Devi Singh . . . . . 274—76

Shri Ram Vilas Paswan . . . . . 276—81

Shri Parasram Bharadwaj . . . . . 281—82

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

COLUMNS

Statement Re. outcome of Inter-Governmental Meeting for Review of Indo Bangladesh Agreement on Ganga Water—

Rao Birendra Singh . . . . . 283—84

Matters Under Rule 377—

(i) Need for a super-fast train between Lucknow and Allahabad:

Shri B.D. Singh . . . . . 285—86

(ii) Essential facilities for the employees of National Institute of Sheep Development in Rajasthan :

Shri P. Rajagopal Naidu . . . . . 286—87

(iii) Need for a separate Archaeological circle in Orissa :

Shri Chintamani Panigrahi 287

(iv) Need for conversion of Dabhol Port into a major Port :

Shri Bapusaheb Paruleker . . . . . 288—89

(v) Alleged mis-recording of information re. religious and linguistic minorities in the recent Census :

Shri G.M. Banatwalla . . . . . 289—90

(vi) Reported rise in prices of vanaspati :

Shri Arjun Sethi 290

(vii) Relief to farmers for damage to crops caused by hailstorms in Rajasthan and Uttar Pradesh :

Shri Rajesh Pilot 291

Demands for Grants, 1981-82 . . . . . 291—396

Ministry of Labour—

Shri Mool Chand Daga . . . . . 291—305

Shri M. Kandaswamy . . . . . 305—309

Shrimati Usha Verma . . . . . 309—12

Shrimati Pramila Dandavate . . . . . 312—18

Shri B. K. Nair . . . . . 319—25

Shri Daya Ram Shakya . . . . . 325—303

COLUMNS

Shri Chanderpal Singh . . . . . 336—39

Shri Girdhari Lal Vyas . . . . . 339—49

Shri Narayan Choubey . . . . . 349—55

Shri Sunder Singh . . . . . 355—58

Shri R. P. Yadav . . . . . 358—62

Shri Harikesh Bahadur . . . . . 362—66

Shri A. K. Roy . . . . . 367—69

Shri Chitta Basu . . . . . 369—73

Shri Jaipal Singh Kashyap . . . . . 374—77

Shri Narayan Datt Tiwari . . . . . 377—95

Arrest of Member

(Shri Ashoke Sen) . . . . . 395—96

LOK SABHA

Tuesday, April 7, 1981/Chaitra 17, 1903 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, अभी तो 388 नियम, को निलम्बित कीजिये ।

MR. SPEAKER: I informed everybody.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब सलाह करके आये हैं कि क्वेचन आवर करना हो नहीं है तो वैसे ही छोड़ देते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं । नो प्वाइंट आफ आर्डर ।

(व्यवधान) **

MR. SPEAKER: Nothing is going on record without my permission.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये । बैठेंगे नहीं आप ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तो स्पीकर रह चुके हैं । आप से तो मुझे सीखना है । आप को बिठाऊं तो फिर करेंगे यही ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात नियम के अनुसार सुनी जा सकती है । कल

और परसों दो दिन से यह होता आ रहा है । उसके पश्चात मैं दूसरे ट्रैक पर नहीं चल सकता । एक ही ट्रैक पर चलूंगा । नियम सब के लिए एक लागू होते हैं । स्टेट सबजैक्ट सब के लिए एक समान स्टेट सबजैक्ट है, मैं दूसरा नहीं बना सकता हूं ।

(व्यवधान)

MR. SPEAKER: During question hour, there can be no point of order. I cannot have two yardsticks.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता आप लोगों में आत्मसंयम क्यों नहीं है । आप सुनते क्यों नहीं हैं ? मेरी समझ में नहीं आता कि आप ही नहीं सुनते तो दुनिया क्यों सुनेगी । लोग तो आप से भी ज्यादा उतावले रहते हैं । आप तो बिल्कुल संयम नहीं बरतते । मैं तो अकेला हूं आप ढेर सारे हो । मेरी फिर भी नहीं सुनते । आप का साथी हूं, आपका बनाया हुआ हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सबजैक्ट जो टुबैको का था इस पर मेरे पास काल अटैन्सन आये हुए कई दिन हो गये थे और बिल्कुल मेरे विचाराधीन था । क्योंकि मिनिस्टर अवेलेबल नहीं थे इस लिए रुका हुआ था । और कोई वजह नहीं थी । That was the only thing.

मैम्बर्स को भी पता है । कोई एक जरूरी चीज होती है जिसका मैं पूरा समाधान करना चाहता था । तो

**Not recorded.

मैंने यह पक्का इरादा किया हुआ था, यह एक ऐसा मसला है जिस पर हमें करना चाहिए । तो मैं कर रहा था । अब भी मेरे पास वही चीज है, जो कहने की बात होती है उसका समाधान करने के लिये इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करवाना चाहता हूं, क्योंकि यह आपका सही स्थान है और आपको करना चाहिए मैं इस पर काल अटेन्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं ।

जहां तक ला एंड आर्डर की प्रोब्लम है...

(व्यवधान)**

MR. SPEAKER: Nothing is going on record without my permission.

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं तो बात कह रहा था, आप बीच में फिर बोल पड़े । वह अपनी बात कहते हैं आप क्यों उनकी बात सुनते हैं

(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : मैं तो आप की बात भी नहीं कहता, उन की बात भी नहीं कहता । न आपकी परवाह करता हूं और न मंत्री की परवाह करता हूं । मेरे लिये यहां मंत्री भी मेम्बर हैं और मेम्बर भी मंत्री हैं । अपने लिये कोई फर्क नहीं है । आपको क्यों वहम पैदा हो गया ? आप मंत्री को क्यों इतना बड़ा समझते हैं ? क्यों फर्क समझते हैं आप ?

तो मैं यह कह रहा था कि संयम से बात करें । कानून आपके बनाये हैं । यह इस मसले को जो आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप चर्चा करना चाहते हो, इसके लिए मेरे पास समाधान है । अगर हाउस चाहेगा तो मैं वह भी करवा दूंगा ।

जहां तक नियम 388 का ताल्लुक है, आप के बनाये हुए हैं । लेकिन आप उस को पूरा पढ़िये । मैं तो रोज पढ़ता हूं । मेरी जबानी याद है । 14, 15 महीने इनको आपने पढ़ाया मुझे । आपके बिहार गया था तो मुझे पता लगा कि मंडल जी वहां स्पीकर रह चुके हैं इसलिए उन से शिक्षा ले लिया करूंगा ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका जो समाधान है इसके लिए है । बहस करवा सकते हैं । लेकिन कल बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में रखवा देता हूं जिसमें सारा इनका भी मसला और आपका भी मसला तय हो जायेगा आ जायेगा । आप निश्चित रहिए । आज मैं फैसला करके करवा दूंगा ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : हमारी सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : सुनने की बात तब रहे जब मैं समाधान करने के लिए न तैयार हूं । अगर फिर भी यह हाउस नहीं चलने देना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है । जैसे मर्जी हो आप चलायें । मैं तो सदन को आपके काम के लिये चला रहा हूं, आपके लिए चला रहा हूं ।

(व्यवधान)**

MR. SPEAKER: No, No. I cannot. I have withheld my consent.

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख रखे हैं । मुझे मंडल जी के लिए खतरा पैदा हो रहा है । मुझे आप के लिए बहुत चिन्ता है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है, मैडम । रीजन की बात किस से करें ?

**Not recorded.

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है आपको ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: Nothing is going on record.... (*Interruptions*)*

कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा। (*Interruptions*)*

This has not gone on record.

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब बैठिय आप। यह अच्छा नहीं लगता है । मैंने आपकी बात सुन ली है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : No, not at all. I am not going to budge an inch. जो मेरा फैसला है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये । यहां पर जो कुछ मेरी परमिशन के बगैर कहा जाता है, वह रिकार्ड नहीं होता है — न उनका न आपका । मैंने कह दिया है । सो क्लियर इट इज । हमने कल मीटिंग की थी । मैंने हाथ जोड़कर विनती की थी और आज भी कर रहा हूं, कि कोई ऐसा मसला नहीं है , जिसका समाधान यहां मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह करना चाहें तो मैं चुप बैठा रहूंगा, आप चाहे जैसे हाउस को चलाते रहें ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप आपस में क्यों बोलते हैं ? आपस में न बोलिये । मैंने आप को कहा है कि इसका समाधान है । आप बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं । इसका सारे का सारा समाधान मेरे पास है । मैं करवा दूंगा। लेकिन आप अपनी मर्जी से करना चाहें , यह नहीं हो सकता है । मर्जी तो मेरी चलेगी, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से मुझे यहां बिठाया है । मैं जरूर कराऊंगा। मैंने यकीन दिलाया है । मैं कभी भी अपने दिलाये हुए यकीन से पीछे नहीं गया हूं ।

(व्यवधान)**

MR. SPEAKER: That is what I have told you, the whole House.

इन को भी बता रहा हूं और आप को भी बता रहा हूं । अब आप एक काम कीजिये, आज बात कर लीजिए ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब मैं बिलकुल नहीं सुनूंगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : तो आप डिस्कस क्यों नहीं करना चाहते इस सवाल को ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : तो फिर आप तो नहीं करने देना चाहते ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप को यही तो कहा कि डिस्कशन होगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : तो आप बैठिये न, मैं डिस्कशन करवा रहा हूं । मैं बता रहा हूं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता । अपनी मर्जी से नहीं चलेगा । मेरी मर्जी से चलेगा हाउस ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चलेगा ।

(व्यवधान)**

**Not recorded.

MR. SPEAKER: Nothing is going on record without my permission. I have not allowed him.

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो एक बात कह दी । अगर आप को उस पर यकीन नहीं आता तो आप जो मर्जी आवे करें । मैंने यकीन दिलाया हाउस को कि डिस्कशन होगा लेकिन आप की मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से ।

(व्यवधान)**

MR. SPEAKER: I mean what I said; they are according to rules. It is not my personal opinion.

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास चारों तरफ से प्रस्ताव है ।

*(Interruptions)***

MR. SPEAKER: Dr. Vasant Kumar Pandit.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Question No. 702.

*(Interruptions)***

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए । मैंने तो नहीं कहा । आप तो मुझसे बात कर रहे हैं । मैंने नाटक कहा ?

*(Interruptions)***

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Import of domestic gas cylinder

*702. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to lay a statement showing:

(a) whether India imports cent-per cent requirements of domestic gas cylinders;

(b) if so, figures of import for the last three years and the reasons thereof;

(c) if not, what is the production of domestic gas cylinders in India during the last three years;

(d) what plans have been drawn up to encourage indigenous production of cylinders;

(e) what is the estimated requirement of domestic gas cylinders in the next three years, (year-wise); and

(f) how much quantity and value of domestic gas is now being wasted or burnt for want of cylinders; (figures of the estimated loss in rupees for the last three years)?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). No import of domestic gas cylinders has been made by the oil companies.

(c) The production of domestic gas cylinders in the organised sector in the country during the last three years is reported to be approximately as follows:—

1978	—	1,20,000	
1979	—	8,70,000	
1980	—	9,40,000	(Estimated)

(d) The current production capacity of 18 lakh cylinders a year is expected to increase to about 25 lakhs by 1982. The oil companies have been directed to step up the procurement of cylinders and to assure the prospective manufacturers a guaranteed off-take of 50 per cent of the capacity proposed to be established by them. The State Governments have been requested to exempt such manufacturing units from power cuts. Steps have also been taken to ensure the availability of steel to meet the

**Not recorded.

requirements of gas cylinder manufactures to the extent possible.

(e) The annual requirement of cylinders in the next three years will be between 14 and 20 lakh cylinders a year depending upon the actual enrolment of new customers.

(f) There is no wastage of cooking gas in the country for want of domestic gas cylinders.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Sir, in these days of acute shortage of fuel like coal, firewood, oil, kerosene etc. gas has become an essential item of necessity in every household. There are certain discrepancies in the reply of the hon. Minister. I would like him to correct the seeming discrepancies. Sir, I asked whether any gas cylinders are being imported in India. The Minister in his reply has said that no oil company has imported. Now, it gives a suspicion that somebody else might be importing.

Secondly, the production in 1980 was 9,40,000 cylinders while the Minister himself says the current production capacity is 18 lakh cylinders. When will this capacity be reached? Already you expect to increase the capacity to 25 lakh cylinders by 1982. I would like to know what is the established capacity of manufacture of domestic gas cylinders? How much gas is available including the gas which will be available after Bombay High comes in operation? How much gas is being wasted on account of dearth of gas cylinders?

SHRI P. C. SETHI: Sir, I have clearly stated that as far as import of cylinders is concerned they are not being imported. Further, excepting the oil companies there is no other user. Therefore, the question of import of gas cylinders by any other person does not arise.

Sir, it is true the established capacity in the country is 18 lakh cylinders and we are utilisng only 60 per cent of the capacity and that is because sometimes there are power cuts or labour trouble. However, there has been no wastage of gas on account of this. The current production is estimated to be 9,40,000 cylinders. The capacity has been further raised to 25 lakh cylinders. It will be our endeavour to produce 18 to 20 lakh cylinders next year and, therefore, there will be no short-fall of gas cylinders at all. As far as LPG is concerned we are having about 4 lakh tonnes of LPG at present. The Uran plant has gone on stream and we are likely to get an increased production of 10,000 tonnes per month from there and after it stabilises the total production from Mathura, Koyali, and Uran in Bombay and also Assam is likely to be augmented by 5 lakh tonens. The total established capacity would be 9 lakh tonnes.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Sir, the prospective manufacturers have been given a guaranted off-take of 50 per cent of their production. What will they do with the remaining 50 per cent? I would also like to know what is the durability of the gas cylinder? When does it become useless? How long does it last? Has Government taken all these factors into consideration while establishing productin capacity?

SHRI P. C. SETHI: Sir, we have taken a replacement figure of 2 lakh cylinders per year on the basis of wear and tear. Sir, I would not be able to say as to how long particular cylinder would last. It will depend on the handling. Sir, it is true that 50 per cent off-take of production is assured to the company but that does not mean that we will not take more.

श्रीमती प्रमिला दंडवते : अध्यक्ष महोदय, हम गृहणियों का अनुभव है कि सिलैंडर में गैस कम रहती है । यह सारा इन्डिजीनस प्रोडक्शन है । मैं सरकार से यह विनती करती हूं कि क्या उस पर

एक इन्डीकेटर लगाने की व्यवस्था हो सकती है, क्या कोई रैगुलेटर लगाने की व्यवस्था हो सकती है, ताकि यह पता चल सके कि सिलैंडर में कितनी गैस भरी हुई है ? मैं यह कहना चाहती हूं कि इस में संशोधन होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, क्या इस बारे में भी सरकार सोच रही है ?

SHRI P. C. SETHI: I fully agree and I appreciate the suggestion given by the Hon. Member. We are trying our best and we have asked the R&D Department to look into this matter.

प्रो० मधु दंडवते : हिन्दी का जवाब हिन्दी में दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप जो सिफारिश कर रहे हैं, वे अच्छे खाने के लिए कर रहे हैं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : आपका सुझाव स्वागत योग्य है कि सिलैण्डर में इस प्रकार की कोई युक्ति लगाने की व्यवस्था हो सकती है, तो वह की जाए । लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने हर जगह जहां डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइन्ट्स हैं, वहां पर एक कम्प्लैंड सैल खोलने का फैसला किया है और आफिसर्स की नियुक्तियां की जा रही हैं । जहां कहीं भी गैस की सप्लाई में शार्ट-फाल होगा उसके वजन में उसको दुरूस्त करने की कोशिश करेंगे । वैसे सप्लायर के यहां से सिलैण्डर सील-बन्द चलता है, लेकिन बीच में कहीं अफरा-तफरी होती है उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : गैस सिलैण्डर में इन्डीकेटर के बारे में आपने कुछ नहीं कहा ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : आपके सुझाव का मैंने स्वागत किया है और आपको धन्यवाद दिया है । उसके लिए मैं रिसर्च डिपार्टमेंट से कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार की कोई युक्ति निकल सके, जिससे गैस मेजर की जांच की जा सके, तो बहुत अच्छा है ।

SHRI XAVIER ARAKAL: Sir, the estimated production of gas cylinders is 9,40,000. In his answer to part (a) of the question, the hon. Minister has stated that the annual requirements of cylinders in the next 3 years will be between 14 and 20 lakh cylinders a year. In answer to part (f) of the question the Minister stated that there is no wastage of cooking gas in the country. How can these two things be correlated ? There is disparity between the quantum of requirements and the answer of 'No wastage'. My second point is this. so far as Cochin area is concerned there is acute shortage of gas cylinders. And, due to lack of gas cylinders, the consumers are facing serious difficulties. The position of the housewives is rather difficult because they use gas cylinders for cooking purposes. (*Interruptions*) men also, there is a real problem in this regard. So, I would like to know what are the specific steps which the Government is taking in order to ensure regular supply of gas cylinders.

SHRI P. C. SETHI: If the hon. Member would kindly look at my reply in answer to part (e), he would see that I have stated as follows:

> '(e) The annual requirements of cylinders in the next 3 years will be between 14 and 20 lakhs cylinders.'

We are organising a production of 25 lakh tonnes by 1982 this 18 lakhs of cylinder requirement would be fully met. So far as the shortfall in production is concerned, I have already stated the steps which we are taking. As far as delay in the supply of cooking gas is concerned, we have already

issued certain instructions in this regard. The Uran plant has already gone into production. The requirements of the present consumers will be met and we will see that the supply is regularised. And the complaints which have been made to the effect that there have been delays of 2½ months in Jaipur and 15 to 20 days in Ghaziabad, and so on,—will not arise and these requirements will be fully met.

कुकिंग गैस का आयात और लागत मूल्य

*704. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुकिंग गैस का आयात किया जाता है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में और इसका आयात मूल्य क्या है;

(ख) देश में कुकिंग गैस की कितनी मात्रा उपलब्ध है और कुकिंग गैस के भण्डारण तथा परिवहन की लागत प्रति इकाई कितनी है और उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस की सप्लाई कितनी कीमत पर होती है; और

(ग) कुकिंग गैस के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितना अन्तर है और विक्री एजेंट के लाभ का अंश क्या है ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir. About 50930 MTs of Liquid Petroleum Gas has been imported during 1980-81. The c.i.f. price of imported LPG during January, 1981 was Rs. 2767.78 per tonne.

(b) About 400,000 tonnes of LPG per annum is available in the country at present but this is expected to increase to about 900,000 tonnes by the next financial year. The retail selling price per cylinder of 15 Kgs. in Delhi is Rs. 45.53 of which the cost of gas is Rs. 26.58 and the freight charge is Rs. 5.43.

(c) The difference between the cost price and the sale price, in Delhi for example, is Rs 18.95 per cylinder which comparises excise duty, sales tax, marketing costs and return, and dealers' commission. The dealers' commission is Rs. 3.62 per cylinder.

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि हम ने वर्ष 1980–81 के दौरान लगभग 50930 मी० टन तरल पेट्रोलियम गैस का आयात किया है एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि हमारे देश में स्टोरेज के अभाव के कारण पूरी कैपिसिटी का इस्तेमाल नहीं हो पाता है और यह बताया गया है कि हम 60 परसेन्ट, कैपिसिटी ही यूटीलाइज कर पाते हैं हड़ताल के कारण और पावर शार्टेज के कारण । तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है, जिस के कारण हमारी जो उत्पादित गैस है, जितना भंडार हमारे पास उपलब्ध है, वह व्यर्थ न जा सके ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अध्यक्ष महोदय कुछ जगहों पर हड़तालों की वजह से, लोक आऊट की वजह से जो गैस की कमी हो गई थी, उस को पूर्ति करने के लिए यह गैस आयात की गई थी । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि अप्रैल के महीने में उरान में लगभग 5 हजार मी० टन गैस का प्रोडक्शन शुरू हो जायगा । इसलिए हमारा यह ख्याल है कि इस वर्ष हमें तरल गैस का आयात नहीं करना पड़ेगा ।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी

वर्तमान में जितने कनेक्शन उपभोक्ताओं को दिये जा चुके हैं, उन कनेक्शनों के आधार पर गैस की जो डिमान्ड है, उस के मुकाबले में सप्लाई की शार्टेज कितनी है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां मध्य प्रदेश में कुकिंग गैस की शार्टेज विशेषतया होती है । वहां के जो डीलर्स होते हैं, वे कहते हैं कि हमारे पास गैस नहीं है । इसलिए वहां पर इस में काला बाजारी होती है और गैस की कमी की बजह से काला बाजारियों को प्रोत्साहन मिलता है । इस काला बाजारी को रोकने के लिए मंत्री जी क्या उपाय करने वाले हैं । गैस जो सिलेंडरों में कम होती है, उस के लिए तो आप ने कहा है कि हम चैक करेंगे लेकिन इस के लिए कौन सी प्रणाली या व्यवस्था आप करेंगे ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक गैस कनेक्शनों का सवाल है, इस समय 30 लाख कन्ज्यूमर हमारे कस्टमर हैं, जिन को गैस के कनेक्शन मिले हुए हैं और अभी तक इन कन्ज्यूमरों की बेसिस पर 1 58 सिलेंडर का रेशो है, जो हम रखे हुए हैं । यह बात सही है कि अभी हाल में कोयाली रिफाइनरी में अक्तूबर से गो-स्लो स्ट्राइक और स्ट्राइक की बजह से एल० पी० जी० के भरने में और लोडिंग में, दोनों में काफी गड़बड़ हुई । 2 अप्रैल को वह स्ट्राइक खत्म हुई है । उस की बजह से खास तौर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गैस की कमी थी । अब उस कमी के दूर होने का पूरा हम को ख्याल है ।

श्री सत्यनारायण जटिया : ब्लैक मार्केटिंग जो होती है, उस के लिए नहीं बताया ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हम ने उस के लिए एक कम्पलेंट सेल खोल रखा है और अगर किसी डीलर के यहां काला बजारी होती हुई पाई गई, तो उस को सख्त सजा दी जाएगी ।

PROF. N. G. RANGA: Is it not a fact that the dealers have sent repeated representations in which they have stated that during the last 5 or 6 years the commission that has been allowed to them is very inadequate? In view of the fact that they have invested quite a lot of money and also a high security involved in this, may I know whether the Government have considered their demands for an increase in the commission that has to be given to them?

SHRI P. C. SETHI: The representations from the dealers had been pending in the Minstry for quite some time. Recently in the month of March, we have taken a decision to increase the commission by 25 paise per cylinder. That has been done and the House would be glad to know that we have not passed on this burden to the consumers. The Oil companies will bear this burden.

But this is an interim increase that we have made. We are awaiting the report of a Committee on the basis of which we will take the final decision.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Bangladesh has got a substantial quantity of surplus gas which is suitable for cooking. Since it is very adjacent to certain areas of India and there was a proposal for buying such surplus gas from Bangladesh, I would like to know what steps have been taken by the Government and what progress has been made in this regard.

SHRI P. C. SETHI: There is unfortunately no progress.

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या उनको

इस बात की जानकारी है कि आजकल न तो कोयला मिलता है और न ही जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, पहले कम से कम कोयला और लकड़ी तो मिल जाया करता था, मिट्टी के तेल की प्राप्ति में भी कठिनाई है, लेकिन मध्य प्रदेश में अनेक जिले ऐसे हैं जहाँ अभी तक गैस सप्लाई के लिए लाइसेंस नहीं दिए गए हैं । भोपाल में तो यह हालत है कि गैस खत्म हो जाती है तो 3—3 महीने तक क्यू लगती है । क्या इसकी जानकारी मंत्री महोदय को है और इसके समाधान के क्या उपाय किए जा रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अध्यक्ष महोदय, ये तीनों प्लांट, मथुरा, ऊरान और आसाम, शुरू हो जाने के बाद 1981—82 में प्रत्येक जिले में, जिसकी पापूलेशन 50 हजार है, वहां पर गैस की एजेंसियां खोलने का इरादा है । इस साल और अगले साल यह कार्य किया जाएगा । भोपाल के बारे में जो शिकायत माननीय सदस्या ने की है वह शिकायत सही हो सकती है, क्योंकि भोपाल कोयली रिफाइनरी से सम्बन्धित है । भोपाल की इस शिकायत को दूर करने की कोशश की जाएगी, क्योंकि कोयली रिफाइनरी की स्थिति अब सुधर गई है ।

Memorandum regarding Activities of Eastern Coalfields Limited.

+

***706. SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER:**

SHRI E. BALANANDAN:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have received a memorandum dated 8th January, 1981 regarding activities of Eastern Coalfields Limited;

(b) if so, what were the problems and suggestions contained in the memorandum; and

(c) what action has been taken by Government on the said memorandum?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). A statement is being laid on the Table of the House.

Statement

(a) Government have received a memorandum dated 18th January, 1981 on the subject.

(b) The memorandum suggests that Eastern Coalfields Limited should stop the alleged unplanned slaughter mining and unscientific mining, carry out sand stowing in all mines prevent surface, subsidence etc. refill all old and abandoned quarries, plan for rehabilitation of the persons affected by surface subsidence, paying them adequate compensation for both land and crop and offering employment. It also suggests that all construction by the coal company should be done with prior permission of Director General of Mines Safety and District and other authorities. It suggests procurement of foreign collaboration to find out ways and means to save the areas declared unsafe.

(c) All planning and operation are carried out under the guidance and supervision of experienced mining engineers. There has been no case of eviction or evacuation due to unsafe mining practice after nationalisation. Sand stowing is practised in all mines to protect important surface features as desired by DGMS. All new opencast projects have provision for reclamation of quarried land. Refilling of subsided areas is also done for reclamation of land. The coal company have full expertise to decide the site of construction and it is not

considered necessary to seek prior permission of DGMS or other authorities. Government has sought expertise form Poland to study the problems in the areas declared unsafe by the State Government authorities.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Sir, I have read the statement and it is quite evasive. Even after nationalisation, unplanned and unscientific mining is still continuing. I would like to know whether it is a fact that in a memorandum submitted to the hon. Minister, it has been stated that the General Manager, Coordination, ECL had bluntly declared in the meeting presided over by the District Magistrate, Burdwan and attended by the MLAs, D.G.M.S., Mining Advisory, West Bengal that stowing operation would not be taken up due to high cost for its execution.

Is it not a fact that a major part of Raniganj city has been declared unsafe for habitation because of the subsidence that occured near Raniganj station, Kumar bazar, Sishubagan, Mahavir Colliery etc.? Is it also not a fact that Barakar and Kulti towns have been declared unsafe and construction of more than two storeyed buildings has been prohibited? I would also like to know whether it is not a fact that ECL is constructing quarters, more than two storeys, in the unsafe area? If so, what steps does the Government propose to take to tackle the problem of lakhs of people of the Asansol-Raniganj area etc? What is the recommendation of the Polish experts in this regard?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURY): Attempts have been made to do the mining operations in these areas on a planned and scientific basis.

In the pre-nationalisation days, there was unscientific mining. That we agree. But after nationalisation, attempts have been made to do justice and plan on a scientific basis. Now there are two types of areas, Mr. Speaker, Sir. One is the lease-hold area and the other one is the non-lease-hold area. In the leasehold area, it is the direct responsibility of the coal companies to look after the safety of the people as a whole. In the non-lease hold area that question does not arise. But, even then the present Government has taken the view that they have to evolve a harm policy for the lease-hold area as well as non-lease-hold area. In regard to this various suggestions have come to us, but we do not want to take any chance. So, we have sought the assistance and advice of the Polish. They have a lot of experience on this. They have accepted our invitation and we are expecting a team. Whatever suggestions the team makes after going round the area, we will try to implement the suggestions.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Sir, the first part of my question has not been answered. I asked the General Manager (Coordination) E.C.L. He said that the stowing operation will not be taken up due to high cost of its execution.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: That question does not arise, as I have said that we will have a firm policy on safety measures.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Sir, it is estimated that in the next ten years about 50,000 acres of land will be affected in one way or other for mining operations in E.C.L. and about 50,000 people will be affected. I would like to know the policy of the Government in regard to giving compensation, rehabilitation and employment to the evicted persons, whether the Government will give employment to 70 per cent persons from the adjacent villages within the radius of five kilometres from the project or mines area? I would like a clear answer from the Minister on this.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Mr. Speaker, Sir, our aim is to make the area safe. We are against shifting. For this we require expert opinion. Now, only for Raniganj town, if the shifting occurs, as per West Benngal Government's assessment, this will cost Rs. 750 crores. This is a colossal amount. So, we are against any shifting. So, we are thinking of experts opinion. This is the position at the present moment.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: He has not understood my question. About 50,000 acres of land will be acquired and about 50,000 people will be evicted. For future, what is the policy for the evicted people in regard to giving them employment, compensation and rehabilitation?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Our policy is to give them jobs and employment in stages and also to give them compensation as suggested by the State Government.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Mr. Speaker, Sir, there is really a dangerous position because thousands of people are going to be affected. Now, in his answer the Minister has said that they are awaiting expert opinion. But that is a matter for the future. I would like to know what are you going to do at present? when the whole area is facing imminent danger, you just cannot wait for expert opinion. Something has to be done at present.

I want to know what you are contemplating as an immediate step, especially when you have already received so many representations, including the representation from the local MLA?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Mr. Speaker, Sir, I have said that this is the experts' job and we are expecting the experts any day and immediately we will take steps.

DR. KRUPASINDHU BHOI: Mr Speaker, Sir, in the answer the Minister has said that Coal India Ltd. and the Government will take action against the culprit in the lease-hold area if somebody is doing illegal mining. But after nationalization of coal is it not the obligatory duty of Coal India to catch hold of the illegal miners in different coal fields?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: We don't have any power so far; but we tell the State Government to take necessary action. The difficulty which arises is this: somehow or the other, they get a stay order from the High Courts; and that makes things more difficult. But after the Supreme Court's judgement, things have become much better, and we are trying to stop illegal mining.

Recommendation of Fazal Committee

*707. SHRI CHITTA MAHATA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have rejected the most important recommendation of the Fazal Committee that the Coal India Limited as the holding company should be wound up and its four subsidiaries be converted into independent companies; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). The report of the Fazal Committee is still under the consideration of Government.

SHRI CHITTA MAHATA: I would like to know from the Minister when the report of the Fazal Committee was received by the Government. What are the specific reasons why Government has not so far taken any final decision on the findings of the Fazal Committee? In view of this, I would also like to know the terms and condi-

tions under which the Fazal Committee was constituted; and when it was constituted.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: The Fazal Committee was constituted last year. By the fag end of the year the report was given. It was passed on to us by the Finance Ministry. The Finance Ministry has to deal with it, and the question should be referred to the Finance Ministry. (*Interruption*) I said: fag end of last year. About the date, I will give you later.

SHRI CHITTA MAHATA: I would like to know from the Minister whether the Company Law Board was consulted before constituting the Fazal Committee, and whether the Government would again send the findings of the Fazal Committee, for approval, to the Company Law Board.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: I have said that the Fazal Committee was constituted by the Finance Ministry, and that the question should be referred to the Finance Ministry. It does not relate to our Ministry. We are considering the report which has been sent by the Finance Ministry.

SHRI CHITTA BASU: Is it the Finance Ministry, or the Ministry of Energy? Sir, you had admitted it in the name of the Ministry of Energy. It is your responsibility to see that the papers are allotted to different Ministries. And this question relates to the Finance Ministry.

Royalty on Coal

*708. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of ENERGY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2905 on 10th March, 1981 regarding 'Royalty on Coal' and state:

(a) what is the basis of fixation of royalty on coal for each State concerned;

(b) whether Government of West Bengal proposed a different formula in this regard; and

(c) if so, what are the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The rates of royalty on minerals including coal are governed by Section 9 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act 1957. The Act, inter alia, also provides that the rate of royalty shall not be enhanced in respect of any mineral more than once during any period of four years. The rate of royalty on coal has been fixed on a tonnage basis.

(b) and (c). The Government of West Bengal had suggested fixation of royalty rate on ad-valorem basis for all grades of coal. This matter was carefully considered by a Study Group appointed by the Department of Coal and subsequently by Government; and it was finally decided to continue the practice of adhering to fixation of rates of royalty on a tonnage basis.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Firstly, he has mentioned the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act 1957—when my friend Mr. Vikram Mahajan was perhaps in his shorts. (*Interruption*) It is relevant because it has become totally out-dated. At that time, the price per tonne of coal was only a fraction of what the price is today. (*Interruptions*) He does not mind a small joke; but his *chamchas* here are shouting all the time.

Section 9(3) says: "The Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Second Schedule"; and what they have read out as the proviso, is correct, viz. that they cannot enhance it more than once in four years. But the Second Schedule unfortunately is so much out of date and irrelevant today. The Government should have taken steps to amend it. The Second Schedule says with regard to Section 9 as follows:

"Group I coals:

Bengal-Bihar coalfields:

(a) Coking coal: Grades A, B and C.

(b) Non-coking coal: Selected Grade A".

All the eggs have been put in the same basket. Would the hon. Minister kindly tell us about it? I would prefer the Senior Minister to say something about it, if he chooses to do so. I cannot compel him nor you can compel him, Sir. What is the real F.O.R. price of coals of the grades that have been put in the same basket—Coking coal: grades A, B and C and Non-coking coal: Selected Grade A? What are the F.O.R. prices prevailing as on date? Of course, my second supplementary would be different and I will ask that later on.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: It is not possible to give them, because it depends on different mines; because in a few cases F.O.R. also depends on the transport and so on. It depends on the transport cost for each mine, in such cases. (*Interruptions*) Let me answer it. Substantially, we have revised the royalty rate and Bengal would be able to get an additional amount. (*Interruptions*) Under old royalty rate, they would have got about Rs. 8 crores. Now they will get about Rs. 12 crores. This is the difference. Secondly, they have raised the cesses on the coal which they were entitled to raise, but we have told them not to raise them, because they were frozen at the old rates. But still they have raised the cesses and they will get an additional amount from that particular money. The question today is whether the consumer should be fleeced or he should be given coal at a reasonable rate. We have taken a decision that coal should be given to consumers at a reasonable rate. Thirdly, the question is whether the Act is outmoded or not. It is a matter of opinion. We do not agree.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: My question has not been replied to because I have not asked the F.O.R. price on colliery basis; I have asked the F.O.R. price on grade basis? What is the F.O.R. price of coking coal grade A? What is the F.O.R. price of coking coal Grade B? What is the F.O.R. price of coking coal grade C; and what is the F.O.R. price of non-coking coal Selected Grade A? Let the Minister answer them and then I will put my second supplementary.

MR. SPEAKER: This can be sent to him.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Why?

MR. SPEAKER: You give him a notice.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: (*Interruptions*) No, this is relevant to this question. May I point out for your kind information that Mr. Vikram Mahajan, about whom I have a better impression compared to what his senior colleague, said that the West Bengal Government is going to get about Rs. 12 crores. If you see the reply to Unstarred Q. No. 2905 of 10th March, 1981, you will find that according to your statement, it is Rs. 10.85 crores; it is not Rs. 12 crores. This is how the House has been treated. You kindly see that they do not do any home work. They totally depend on the bureaucrats. If you scratch them a little deep they cannot say anything. Now, this is an Annexure. Four different grades have been put in the same basket—four different grades altogether substantially varying one from another. They do not say, whether it is a pithead price or the F.O.R. price. F.O.R. means free on rail for their education. That includes pithead, carrying, loading, sealing and other expenses. I would like to ask from the hon. Minister to whom I have to put a second supplementary—as to what is the F.O.R. price grade-wise as stated in the Second Schedule Group I coals?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI): The question does not come with-ing the purview. (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I will leave it to you. (*Interruptions*) They are not fit to be Lower Division Clerks. (*Interruptions*) I will show you this. I have got a copy of the Act. The Act refers to this. On page 4, it says as follows:

"The Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Second Schedule so as to enhance...."

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: The royalty is according to the tonnage.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It has put four grades together. I am asking it because the price of the grades vary substantially. The difference in price between grade A coal and grade C coal could be double.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am asking, for the information of the House, as to what is the f.o.r. price of Grade A coal. There are four grades in that. I am asking for the f.o.r. price as fixed by the Government, as required by law.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: The question is quite clear. For the question asked the answer is there. There are two opinions. One is the royalty which is fixed on tonnage basis. There is another opinion....(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: That has nothing to do with the grades. (*Interruptions*)

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: There is another opinion....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Is there any difference between one grade and the other?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: There is. (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: It is bound to be there (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: What according to the Schedule, are they required to pay? (*Interruptions*)

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Ask him to table a question.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You have not got it. (*Interruptions*) He does not know. He has not got it (*Interruptions*) My second question is th's. The country is reeling under two most important things: Power and coal. And this Minister does not know even the f.o.r. prices of coal (*Interruptions*) My second question is....(*Interruptions*)

My second question is the price of coal....(*Interruptions*)

PROF. K. K. TIWARY: Sir, Shri Jyotirmoy Bosu has compared the Minister with a clerk. (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I did not. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: No, no, please.

(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Why should I insult a clerk? (*Interruptions*) Why should I insult a clerk? (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I do not know how it could be degrading.

(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: My second question is, that the price of coal at the present moment fixed, is far below what the market can afford to pay, in the sense that, you know, Sir, in Punjab it is Rs. 1,200 per tonne. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Do you want it to be reduced?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: No, no. I want to say that coal should get an equivalent value because of the middleman and the present problems for getting hard coke even at Rs. 400 or Rs. 500 per tonne,....(*Interruptions*) That is being sold in the market. Will the hon. Minister kindly tell us the price, taking into consideration the qualities, outside the provisions of the Act? The actual price should be reviewed by a committee of knowledgeable people who know coal mining and who are not interested and involved in the business. (*Interruptions*)

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: The question does not arise. (*Interruptions*) Prior to 1968 Royalty under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 was payable on the basis of fixed pound value. (*Interruptions*) The Study Group on Royalties, Rates and Development for Mining Areas had pointed out various difficulties.... (*Interruptions*) He should not have.... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Question hour in over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

T.V. Centre at Aurangabad and Nasik

*705. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether in view of the fact that there is a demand from the Aurangabad and Nasik area (Maharashtra) a T.V. Centre is to be opened there; and

(b) if so, upto what time the T.V. Centre is expected to be opened in Nasik and Aurangabad (Maharashtra)?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b). Due to constraints on resources, it is not proposed to set up a T.V. centre in Aurangabad and Nasik areas in Maharashtra during the Sixth Plan period (1980—85). The requirement of these places would be kept in view while formulating future plans for expansion of television in the country.

High Speed Diesel Oil for various States

*709. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Central Government have made any assessment regarding the utilisation of high speed diesel oil of the various States (State-wise) since January, 1980;

(b) if so, whether the quantity supplied to the State of Karnataka is sufficient according to the demand made by the State;

(c) whether there has been any gap between the demand and supply of the high speed diesel oil to the State of Karnataka; and

(d) if so, the steps Government have taken or propose to take to improve the position in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) This Ministry makes a monthly allocation of High Speed Diesel Oil (HSD) to the States and Union Territories. Further break-up of the allocation as between the different diesel consuming sectors like agriculture, transport, industry, etc. is to be done by the State Governments themselves. The States have been advised to fix inter-sectoral priorities for different uses of HSD and to regulate its distribution accordingly.

(b) and (c). The Government of Karnataka has, in recent months, indicated a quantity of 47,000 tonnes of HSD as the minimum monthly requirements of the State. The sales of HSD in the State in the period January, 1980 and February, 1981 ranged between 33,700 and 48,000 tonnes per month. The supply position of HSD in Karnataka is generally satisfactory now.

(d) The demand for HSD in Karnataka was generally met in the above period. In fact, in certain months, the HSD offtake was lower than the allo-

cations due to low demand even though adequate supplies were available in the depots of the oil companies.

Sambalpur Doordarshan

*710. DR. KRUPASINDHU BHOI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation regarding poor functioning of Sambalpur Doordarshan;

(b) if so, the details of such representation; and

(c) the action taken thereon by Government?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b). Doordarshan Kendra, Sambalpur receives suggestions/complaints from the viewers from time to time. The complaints received during the last year relate mainly to repetition of Oriya films, increase in the transmission time and screening of more Hindi feature films, etc.

(c) Efforts are made to avoid repetition of Oriya films. It is not proposed to increase the frequency of Hindi feature films since the programmes telecast from Sambalpur transmitter are specially designed to meet the needs of the rural areas. Due to limited programme facilities available at the Base Production Centre, Cuttack, which produces the programmes for the Sambalpur transmitter, it has not been found possible to increase the transmission hours.

Need to Amend Indian Companies Act

*711. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Indian Companies Act has become outdated and needs to be drastically amended;

(b) whether Government are also aware that thousands of bogus companies have been set up and they cheat the public as well as the Government; and

(c) if so, whether Government propose to take any steps to amend the law?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) to (c). In keeping with the fact that law of the land must keep pace with the changing character of the time and needs of the society and in conformity with the accepted socio-economic philosophy of the country, the Central Government is seized of the examination of the report of the High Powered Expert Committee appointed to suggest *inter-alia* the amendments to the Companies Act, 1956, suggestions made by experts, Chambers of Commerce and other institutions.

It is not to the information of the Government that there is any large-scale formation of bogus companies. The various procedures and the scrutiny prescribed for the registration of the companies under the provisions of the Companies Act, 1956 are fairly stringent and comprehensive. There is a proper identification of the promoters/subscribers under section 15 ibid. It is, however, to be conceded that no law can ensure a completely fool-proof arrangement but such stray cases, when detected, can be dealt with effectively under the extent provisions of the Companies Act and in certain cases under provisions of penal laws.

भारत में न्यायिक प्रणाली

*712. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या कार्य मंत्री विधि, न्याय और कम्पनी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान न्यायिक प्रणाली दोषपूर्ण है जिसके अन्तर्गत हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसमें परिवर्तन किये जायेंगे और किस तरीके से ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) संविधान में हरिजनों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कतिपय रक्षोपायों का उपबंध है। सभी व्यक्तियों को उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप शीघ्र, निष्पक्ष और कम खर्चीला न्याय सुलभ कराने के लिए न्याय प्रशासन की विद्यमान प्रणाली के पुनर्विलोकन की आवश्यकता पर सावधानी पूर्वक विचार किया जा रहा है। न्यायिक सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है।

Transportation of Coal by Road by Coal India

*713. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) is it a fact that Government have allowed Coal India to transport coal by road;

(b) if so, what is the procedure and how many persons or parties have taken advantage of it; and

(c) the total amount of coal meant for transportation by road?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHOUDHURY): (a) to (c). Since coal is transported by the consumers, the question of Government allowing Coal India to transport coal by road does not arise. However, a large number of consumers all over the country who are located either close to the coalfields or who are not able to obtain adequate number of railway wagons for transporting coal, obtain their coal requirements by road. In 1980-81, about 25 million tonnes of raw coal was transported from the mines of Coal India and Singareni Collieries Co., Ltd., by road. Coal companies do not maintain any consolidated data regarding the number of consumers to whom coal has been released by road.

Building of Low Cost Cinema Houses in Semi-Urban and rural Areas.

*714. SHRI JAGDISH TYTLER:
SHRI HIRALAL R. PARMAR:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the National Film Development Corporation is launching a project for promoting the building of low-cost cinema houses in semi urban and rural areas;

(b) if so, the details of this scheme;

(c) the number of cases which have already been approved by it; and

(d) the financial implication thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b). The scheme for financing the construction of low-cost cinema houses in rural, semi-urban and urban areas was launched by the erstwhile Film Finance Corporation during 1979. The Corporation was amalgamated with the National Film Development Corporation in April, 1980 and the scheme is now being operated by the latter company. A statement giving broad details of the Scheme is laid on the Table of the House

(c) and (d): The Corporation has so far sanctioned loans in 17 cases for a total amount of Rs. 85.76 lakhs.

Statement

Broad Details of the Scheme for Financing construction of theatres by National Film Development Corporation.

I. The theatres will be functional and economical.

II. The Corporation finances construction of theatres on the following scales:—

(a) For theatres in rural areas, loan upto a maximum of Rs. 1 lakh;

(b) For theatres in semi-urban areas, loan upto a maximum of Rs. 3 lakhs.

(c) For theatres in urban areas, loan of 50 per cent of the total cost upto a maximum of Rs. 7.5 lakhs.

III. Repayment will be in 60 equal instalments commencing from 30 days after the opening of the theatre or within the following time limits, whichever is earlier:—

(a) For theatres in rural areas, 8 months from the date of release of first instalment;

(b) For theatres in urban areas, 11 months from the date of release of first instalment;

(c) For theatres in urban areas, 14 months from the date of release of first instalment.

IV. Interest on these loans is 12½ p.a. with rebate of 1 per cent for payment on due dates, and a further rebate of 1 per cent payment within half of the stipulated period.

V. Theatres financed under these schemes shall be available on 50:50 percentages sharing basis for screening NFDC financed/sponsored films.

हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) में लगे मेले के लिए प्रचार

*795. **श्री राम विलास पासवान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) में लगे एशिया में प्रसिद्ध मेले का प्रचार करने वाले उनके मंत्रालय के यूनिटों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक के द्वारा क्या-क्या कार्य किया गया ;

(ख) इस सम्बन्ध में अगले वर्ष सम्भावित योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या फिल्म डिविजन का विदेशों में प्रदर्शन हेतु हाथियों के मेले के आधार पर एक रंगीन विशेष फिल्म बनाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों का अपने कवरेज / प्रचार कार्यक्रमों में देश के विभिन्न मेलों और त्यौहारों का उपयुक्त रूप से उपयोग करने का सतत प्रयास रहता है। पिछले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व सन्ध्या पर हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) में लगे इस मेले को उपयुक्त कार्यक्रम के रूपों के माध्यम उपयुक्त प्रचार से कवरेज दिया गया था। इस अवसर पर विभिन्न माध्यम एककों द्वारा दिए गए कवरेज आयोजित किए गए कार्यक्रमों को दर्शाने वाला विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) इस अवस्था पर माध्यम एककों द्वारा कोई विशिष्ट योजना सोची नहीं गई है। तथापि माध्यम एकक अपनी सामान्य गतिविधियों के अंग के रुप में इस मेले को उपयुक्त प्रचार/कवरेज देते रहेंगे ।

(ग) फिल्म प्रभाग सोनपुर मेले की झलकियों को 1949 से अपनी न्यूज-रीलों में कवर कर रहा है और उन्हें रिलीज कर रहा है। तथापि यह समझा जाता है कि संभवतया विशेष डाकुमेन्ट्री फिल्म, सादी या रंगीन, का निर्माण रोचक न हो, क्योंकि मेले में भाग लेने वालों की संख्या कम होती जा रही बताई गई है।

विवरण

पिछले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व सन्ध्या पर हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) में लगे एशिया के प्रसिद्ध मेले को प्रचार देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों द्वारा दिया गया कवरेज आयोजित किए गए कार्यक्रम ।

2. **फिल्म प्रभाग** :– फिल्म प्रभाग ने पिछले वर्ष लगे सोनपुर कार्तिक मेले को 25 मीटर की लम्बाई में कवर किया और उसको भारतीय समाचार समीक्षा 1677 (प्रादेशिक) में शामिल किया जो 5–12–1980 को रिलीज की गई थी ।

2 **आकाशवाणी** : आकाशवाणी द्वारा सोनपुर मेले को दिए गए कवरेज का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) 20 नवम्बर, और 24 नवम्बर, 1980 को कृषि समाचार में प्रत्येक दिन 2–2 मिनट की अवधि के लिए मेले के समाचार ।

(2) 28 मिनट के लिए 22 नवम्बर 1980 को "कर्टेन रेजर" के रूप में "सोनपुर मेला की झांकी" ।

(3) 5 मिनट के लिए 26 नवम्बर, 1980 को समाचार ध्वनि चित्र में डिस्पैच ।

(4) 25 मिनट के लिए 28 नवम्बर, 1980 को सोनपुर कृषि प्रदर्शनी की झांकी ।

(5) 28 मिनट के लिए 2 दिसम्बर, 1980 को सोनपुर मेला पशु प्रदर्शनी की झांकी ।

3 **दूरदर्शन** : उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा सोनपुर मेले को विशेष रूप से कवर किया गया था और उसको जयपुर, मजफ्फरपुर तथा रायपुर से निम्नलिखित तिथियों को टेलीकास्ट किया गया था :—

1980 22–1–1981 दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर

29–1–1981 दूरदर्शन केन्द्र, मजफ्फरपुर

5–2–1981 दूर दर्शन केन्द्र, रायपुर

4 **क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय** : क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की मजफ्फरपुर और मोतीहार यूनिटों ने 20 नवम्बर, से 29 नवम्बर, 1980 तक कार्यक्रम आयोजित किए । ब्यौरा इस प्रकार है :–

यूनिट का नाम	फिल्म शो	गीत और नाटक कार्यक्रम	मौखिक संचार कार्यक्रम	फोटो प्रदर्शनी
1 मजफ्फरपुर	23	10	11	10
2 मोतीहारी	21	11	5	शून्य

5. **विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय:** विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की पटना स्थित क्षेत्रीय प्रदर्शनी यूनिट ने 21–11–80 से 5–12–80 तक सोनपुर मेले में समाजिक और साम्प्रदायिक मेल मिलाप के विषय पर "हम एक हैं" नामक प्रदर्शनी लगाई । जीवन के सभी क्षेत्रों के लगभग 3 लाख लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा बताया गया है ।

6. **पत्र सूचना निदेशालय:** पत्र सूचना कार्यालय ने विज्ञापन और दृश्य प्रचार

निदेशालय तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का प्रचार किया।

7. **गीत और नाटक प्रभाग** : गीत और नाटक प्रभाग द्वारा अपनी सोनपुर विभागीय मंडलियों के माध्यम से या पंजीकृत गैर-सरकारी दलों के माध्यम से सोनपुर में प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	
1	मिश्रित सांस्कृति कार्य क्रम	
	नवम्बर, 1980	7
2	—तथैव—	
	नवम्बर, 1980	10
3	कव्वाली	
	नवम्बर, 1980	6
4	कठपुतली कार्य क्रम	
	नवम्बर, 1980	15

Alleged violation of Company Law by M/s. Engineering and Industrial Equipment (India) Private Limited

*716. SHRI DHARAM DASS SHASTRI:
SHR K. LAKKAPPA:

Will the Minister of LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is true that M/s. Engineering and Industrial Equipment (India) Private Limited, Madras is violating companies laws under Section 217(3) of the Companies Law Act;

(b) if so, the action contemplated by Government against this company; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) M/s. Engineering and Industrial Equipment (India) Private Ltd. violated Section 217(3) of the Companies Act, 1956, by not furnishing an explanation in the Board of Directors' Report on the qualified remarks made by its auditors in their reports on the Balance Sheets of the Company as at 31-3-1978 and 31-3-1979 regarding non-maintenance of proper records relating to fixed assets.

(b) The matter is being pursued with the company for necessary action.

(c) Does not arise.

Agitation by employees of Gujarat Refinery

*717. SHRI B. V. DESAI:
SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Indian Oil Corporation held consultations with the Union and Gujarat Governments on the grave crisis precipitated by the nine day work-to-rule agitation launched by the Gujarat Refinery employees;

(b) if so, what was the outcome of the talks held;

(c) whether the Refinery stir had greately affected the oil supplies;

(d) whether the agitation had brought down the loading of petroleum products to less than 25 per cent, adversely affecting despatches, power generation, industrial production, transport sectors and the agriculture sector; and

(e) if so, what steps were taken by the Centre in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) It was decided that the agitation was unreasonable and that the IOC should induct Home Guards to assist in the operation of the refinery and take appropriate action against agitators.

(c) and (d). Yes, Sir. for a few days the operation of the Refinery decreased to 25 per cent of its normal.

(e) The induction of the Home Guards and other special measures taken helped to improve the operation of the Refinery. The agitation ceased on April 2, 1981.

Withdrawal of Films from circulation

*718. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) are Government aware of any films—whether documentary or newsreel—withdrawn from theatrical circulation during 1977 to 1979;

(b) if so, how many and why; and

(c) what is the loss incurred?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): (a) to (c). In March, 1977 the Govrnment asked the Films Division to carry out scrutiny of documentaries and newsreels being screened in the country and to withdraw from circulation all such documentaries and newsreels which are considered inappropriate. As a result of these instructions, the Films Division withdrew 40 documentary films from its theatrical circuit and 5 documentary films from its non-theatrical circuit apart from 22 Indian News Reviews. The Films Division was also asked not to release 4 films and abandon production of 2 films. One film entitled 'Freedom From Fear' was completed but the Films Division was instructed not to release it. The total cost involved in production and distribution of the documentaries and newsreels withdrawn from circulation is approximately Rs. 1,66,00,000/-.

दूरदर्शन पर बच्चों की फिल्में दिखाना

*719. **श्रीमती कृष्ण साही :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल फिल्म समिति द्वारा बनाई गई फिल्में दूरदर्शन पर नहीं दिखाई जाती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बच्चों के लिए सिनेमा हाल जाने की अपेक्षा दूरदर्शन पर फिल्में देना सुविधाजनक है ; और

(ग) क्या सरकार दूरदर्शन पर बच्चों की फिल्में दिखाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे): ( ) से (ग). बाल फिल्म समिति द्वारा बनाई गई फिल्मों को, टेलीकास्ट करने के लिए दूरदर्शन द्वारा प्रस्तावित भुगतान की दरों की अस्वीकार्यता के कारण टेलीकास्ट करने के लिए दूरदर्शन द्वारा हासिल नहीं किया जा सका । तथापि, बाल फिल्म समिति अब टेलीकास्ट के लिए सहमत हुई दरों पर बाल फिल्में सप्लाई करने के लिए सहमत हो गई है । दूरदर्शन का विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट करने के लिए इन फिल्मों का उपयोग करने का प्रस्ताव हैं ।

News Agencies running in Loss

*720. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) names of the Hindi and other news agencies which are running in loss;

(b) amount of loss suffered by each of them in the current year and also in each of the past two years;

(c) steps taken and proposals under consideration to help them;

(d) whether there is any suggestion that some of them may be integrated with such English news agencies which are in sound economic position; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): (a) to (c): There are four news agencies in the country, namely, Press Trust of India, United News of India, Hindustan Samachar and Samachar Bharati. The news agencies are in the private sector. Their financial affairs are managed by the news agencies themselves and do not come under the jurisdiction or responsibility of the Government.

(d) and (e): The news agencies are independent entities and it is for them to consider and decide their organisational structures or set-ups. There is no proposal for reorganisation of news agencies under the consideration of the Government.

Patratu Thermal Power Station Facing shortage of spares

*721. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Patratu Thermal Power Station is facing shortages of spares;

(b) whether the required spares are indigenously available;

(c) if not, whether those spares are to be imported; and

(d) if so, what steps have so far been taken to import them in order to facilitate the Commissioning of the Project as per schedule?

THE MINISTER OF ENTRGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHOUDHURY): (a) to (d): Patratu Thermal Power Station in Bihar has four units of 50 MW each and two units of 100 MW each imported from Soviet Union and two units of 110 MW each supplied by BHEL. While the spares for the main plant and equipment for units 1 to 6 supplied by Soviet Union have to be imported from there, the spares of auxiliaries for these units and for the indigenous units 7 and 8 are available from indigenous manufacturers. There have been some difficulties with respect to imported spares and as such the question of expediting the supply of spares from Soviet Union has been taken up with the Soviet authorities who have agreed to give the matter priority.

A scheme of Central Stocking of insurance spares like rotor, stator coils etc., for imported units is also being financed by the Department of Power. Such insurance spares are not required for normal operation and maintenance of the units but are needed in case of major breakdown like damage to rotor, stator etc. Patratu Thermal Power Station has already drawn spares under the scheme including a generator rotor for a 50 MW set and a D.C. excitor for a 100 MW set.

Shortage of Coal affected Construction work of Rajasthan Canal

*597. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to paucity of coal, construction work of Rajasthan canal has come to a grinding halt thus delaying an estimated revenue of about Rs. 300 crores a year

(b) the reasons due to which adequate quantity of coal was not supplied in the past; and

(c) the outcome of the efforts made by Central Government in arranging higher priority for the movement of coal to the project site?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHOUDHURY): (a) and (b). Accordnig to the information available one of the reasons

why work on Rajasthan Canal project has been delayed is due to the shortage in the availability of coal. Adequate stocks of coal are available at the pitheads to meet the demand of consumers in full including that of the Rajasthan Canal Project. Coal shortage has, however, been experienced by the project on account of transportation constraints.

(c) The question of increasing movement of coal to Rajasthan Canal Project was taken up with the Ministry of Railways who have indicated that in view of high priority of the Project, instructions have been issued to step up the supply of coal to the Project and additional rakes are expected to move to the project.

Visit by Retired officers to Ministry

6606. SHRI SANAT KUMAR MANDAL: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2002 dated the 3rd March, 1981 regarding employment of Officers after retirement and state:

(a) whether in view of the very close contacts which these two officers referred to in the above reply and the influence they wield with their vast resources, any check is being exercised over their free movement in the various Branches/Sections in his Ministry and their ready access to the staff dealing with the cases of their principals and through that staff to the official records;

(b) if so, what and if not, reasons therefor; and

(c) the number of times they visit his Ministry in Shastri Bhawan during a month on an average during the last one year?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b): All representatives of Private Firms and their Association are allowed to meet officers of the rank of Under Secretary and above by appointment with the officer concerned. The representatives of Private Firms and their Associations are not permitted to meet officers below the rank of Under Secretary and other staff and they cannot therefore be said to have free access to the Sections and the staff.

(c) No record of the number of visits of outsiders is maintained by this Ministry.

Films engaged in Production of Polyster Metalised Film

6607. SHRI CHATURBHUJ: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the names of the firms engaged in the production of polyster metalised film;

(b) the total production capacity of above firms and their total production during the vast two years;

(c) whether this production was sufficient to meet the domestic consumption;

(d) if not, the total import of Polyester Metalised Films made during the past two years; and

(e) the steps being taken to meet the requirement of Polyester Metalised Films in future?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) The following companies are engaged in the manufacture of polyester metalised films:—

(i) M|s. Rexor India Ltd., New Delhi,

(ii) M/s. Chemicoat Limited, Vadodara and

(iii) M/s. Garware Plastics & Polyester Private Limited, Bombay.

(b) The total installed capacity of the above Companies is 1025 tonnes. Production in the years 1979 and 1980 was 461 tonnes and 696 tonnes respectively.

(c) No, Sir.

(d) Separate statistics about the quantum of import of metalised polyester film are not readily available.

(e) M/s. Garware Plastics and Polyster Private Limited have been allowed Expansion in their capacity for the manufacture of polyster film, Expansion in the capacity of metalising in the case of M/s. Garware Plastics and M/s. Rexor India Limited has also been approved. Three other units have been approved for manufacture of metalised polyster film along with other metalised products.

ट्रस्ट के लिये आचरण संहिता

6608. श्री राम सिंह शास्त्री : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-2 में गणदेवी पुलिस स्टेशन के सामने स्थित दामोदर जीवराज, हेमराज ट्रस्ट पर कम्पनी अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं यदि हां, तो इस न्यास पर कौन कौन से कानून और से नियम लागू होते हैं और क्या केन्द्रीय सरकार ने न्यासों के लिए कोई आचरण-संहिता बना रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या न्यासों पर कम्पनी अधिनियम भी लागू होता है और यदि हां, तो बम्बई में ऐसे कितने न्यास हैं, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है ; और

(ग) क्या इन न्यासों में, जिनका लाभ न्यासी उठा रहे हैं, अरबों रुपये की पूंजी लगी हुई है और यदि हां, तो न्यासियों द्वारा इन नियमों का उचित रूप से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1. दामोदर जीवराज, हेमराज ट्रस्ट ने लोक न्यासी के पास कोई घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, अतः यह कहना संभव नहीं है कि क्या यह न्यास कम्पनी-अधिनियम के उपबंधों को आकर्षित करता है, अथवा नहीं। प्रश्न में दिये गये पते पर की गई जांचों से पता चला कि उक्त पते पर ऐसा कोई न्यास विद्यमान नहीं है। न्यासों के लिये कोई आचरण-संहिता नहीं है ।

2. कम्पनी अधिनियम की धारा 153-ख के अन्तर्गत, जहां किसी व्यक्ति (न्यासी) द्वारा किसी कम्पनी के कोई हिस्से अथवा ऋण-पत्र, उसमें विहित सीमाओं से अधिक की मात्रा में न्यास में धृत किये जाते हैं, तथा जहां न्यास लिखित संलेख द्वारा सृजित हो, वहां न्यासियों को "लोक न्यासी" को इस आशय की घोषणा करनी चाहिये । कम्पनी अधिनियम की धारा 187 ख में भी प्रावधान है कि इस प्रकार के मामलों में, कम्पनी की किसी बैठक में, कम्पनी के सदस्य के रूप में न्यासी द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकार एवं शक्तियां (जिनके अन्तर्गत परोक्षी द्वारा मत देने का अधिकार भी आता है) न्यासी द्वारा प्रयोक्तव्य न रह कर, लोक न्यासी द्वारा प्रयोक्तव्य हो जायेंगे ।

(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित उपबंधों के अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम के कोई अन्य उपबंध न्यासों पर लागू नहीं हैं । कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले बम्बई स्थित न्यासों की संख्या 57 है ।

(ग) इस विभाग के पास, न्यासों में नियोजन की बाबत कोई सूचना नहीं है, क्योंकि यदि न्यास, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत विहित सीमा से अधिक के हिस्सों/ऋण-पत्रों में नियोजन करते हैं, तो उनके लिए केवल घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

Supply of Bitumen to West Bengal

6609. SHRI M. ISMAIL: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) how much bitumen was supplied to West Bengal during the last year; and

(b) what was the quota of allotment and what was the demand of West Bengal during the above-mentioned period?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) A total quantity of about 70,000 tonnes of bitumen was supplied to the State of West Bengal during the year 1980-81.

(b) The revised allocation of bitumen to West Bengal for 1980-81 was 86,000 tonnes. In January, 1980, a request for allotment of 68,000 tonnes of bitumen to the State, during the period from January to June 1980 was received in this Ministry.

Lifting of Diesel Curbs

6610. SHRI DAULAT SINGH JADJA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Centre has sent any direction to State Governments in regard to lift diesel curbs in their State;

(b) if so, the names of the States which have lifted curbs on diesel and on what date; and

(c) when all the restrictions on the distribution of diesel will be lifted throughout the country?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise in view of the reply to (a) above.

(c) Diesel allocations have been substantially increased for March and April, and it should be possible for the States who distribute the product to lift all restrctions in view of adequate availability of the product.

Public Deposits raised by companies

6611. SHRI R. PRABHU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the amount of deposits taken from the public by companies as on 31st March, 1979 and 31st March, 1980 as per the Returns furnished by these companies;

(b) the number of companies which have accepted these deposits;

(c) the names and the number of companies defaulted in repayment of these deposits. and

(d) the names of companies which have been prosecuted for their failure to refund the public deposits?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b) The Reserve Bank of India periodically compiles and publishes data about the deposits held by various categories of companies. On the basis of a 'quick' survey of the returns of deposits received by it, the Bank has furnished the following figures in respect of non-banking non-financial companies, deposit acceptance of which is regulated by this Department:—

Date	No. of companies	Amounts of deposit held
31.3.1979	3102	Rs. 688.5 crores
31.3.1980	3050	Rs. 986.9 crores

(c) According to the information furnished by the Registrars of Companies, based on the returns of deposits as on 31.3.1979 received by them, 242 non-banking non-financial companies had defaulted in payment of matured deposits though claimed; their names are indicated in Annexure I, laid on the Table of the House. Placed in Library. (*See* No. LT 2326/81).

(d) There is no provision in the Companies Act, 1956, for the prosecution of a company for its failure to repay the natured deposits, except a

transitory provision [section 58A(3)(a)] in regard to deposits accepted by a company before the commencement of the Companies (Amendment) Act, 1974, which, unless renewed in accordance with the Deposit Rules were required to be repaid as per the terms of such deposit. The failure to repay the deposits on maturity gives rise to a civil claim and the depositor can seek redress in an appropriate court of law.

गुजरात तेल शोधन कारखाने में आन्दोलन

6612. श्री रामावतार शास्त्री : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तेल शोधन कारखाने के कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों के ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या एक सौ से अधिक कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी किये गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गुजरात शोधन कारखाने के कामगार संघ ने दिनांक 28-2-81 से "नियमानुसार कार्य करने" का आन्दोलन आरंभ किया था, परन्तु दिनांक 2-4-81 से उसे उन्होंने समाप्त कर दिया है ।

(ख) बोनस अधिनियम के अन्तर्गत 20% के अनुमेय बोनस के अतिरिक्त उनकी मुख्य मांग अनुग्रहपूर्वक अदायगी से संबंधित थी ।

(ग) आन्दोलन अनुचित था ।

(घ) और (ङ). कार्य करने से इन्कार करना, "नियमानुसार कार्य करने" के रूप में धीरे कार्य करना, प्रबंधकों के कानूनी आदेशों की अवहेलना करना, उत्पाती व्यवहार करना, कार्य में अवरोध पैदा करने आदि के कारण, 130 कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी किये गये थे ।

Deposits of gas in Bengal Basin

6613. SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether his attention had been drawn towards a news-item in the "Hindustan Times" dated the 15th March, 1981 wherein an international authority on 'deltas' Dr. Ram Saxena, had expressed the opinion that the Bengal basin had large deposits of gas; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (d). Dr. Ram S. Saxena is the President of a U.S. Consultancy firm M/s. Geoconsultants International (GCI) with which ONGC has entered into a contract on August 4, 1980, for delta model study of the Bengal basin. The duration of the contract is 18 months from the date of signing after which the report of the study would be made available. Meanwhile, the data from seismic surveys already carried out from the wells drilled in Bengal basin is being reprocessed and reanalysed in U.S.A. by M/s. GCI in association with ONGC geoscientists. Pending availability of the results of this study, it is not possible to comment on the reported press statement of Dr. Ram S. Saxena.

Documentary on the lives of Late Shri Jyotiro Phule and his wife

6614. PROF. MADHU DANDAVATE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to bring out a documentary on the lives of great social revolutionaries late Shri Jyotiro Phule and his wife Smt. Savitribai Phule; and

(b) if so, when the proposal likely to be implemented?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) In so far as the Films Division is concerned, there is no proposal for production of a documentary film on the lives of great social revolutionaries late Shri Jyotiro Phule and his wife Smt. Savitribai Phule.

(b) Does not arise.

Villages not yet electified in Gujarat

6615. SHRI R. P. GAEKWAD: Will the Minister of ENERGY be pleased to state the number of villages that have yet not been provided electricity in the Gujarat State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): According to the latest progress report received from the Gujarat State Electricity Board, 6,396 villages in Gujarat have not been provided with electricity as on 31-12-1980.

As compared to 819 new villages electrified in Gujarat during the year 1979-80 (up to 31-12-1979), the achievement during 1980-81 is electrification of 1,012 new villages.

विदेशों के सहयोग से आरंभ की गई परियोजनाएं

6616. श्री निहाल सिंह : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके सहयोग से (एक) डी. एम. टी. एक्सटेंशन प्रोजेक्ट (दो) एक्रीलतास (तीन) 25 मेगावाट विद्युत संयंत्र और (चार) वी. सी. तथा पी. वी. सी. परियोजनाएं, जिनकी स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई थी, आरम्भ की जा रही है और उन देशों के साथ किये गये करारों की शर्तें क्या हैं ; और

(ख) उपरोक्त परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) ने विभिन्न परियोजनाओं के लिये जिन विदेशी सहयोगियों के साथ सहयोग समझौते किये हैं उनके नाम तथा समझौते की संक्षेप में शर्तें संलग्न विवरण-पत्र में दी गयी हैं ।

(ख) परियोजनाओं के पूरा होने की अनुमानित तिथियां नीचे दी गयी हैं:—

(i) डी. एम. टी. विस्तार—मार्च, 1982

(ii) एक्रीलेट्स—फरवरी, 1982

(iii) 25 मैगावाट पावर संयंत्र—1981 का उत्तरार्ध

(iv) वी. सी./ पी. वी. सी.—जुलाई, 1983.

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सहयोगी का नाम	शर्तें	समझौते की अवधि
1	2	3	4	5
1	डी. एम. टी. विस्तार	कोई विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं किया गया है ।	—	—
2	एक्रीलेट्स	मैसर्स असाही केमिकल्स इंडस्ट्रीज कंपनी लि., जापान	चार विभिन्न एक्रीलेटों के उत्पादन के लिये भारत में आई. पी. सी. एल. ने एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला द्वारा किये गये अनुसंधान एवं विकास के द्वारा प्रौद्योगिकी विकसित की है तथा एक भारतीय इंजीनियरी कम्पनी के साथ इंजीनियरी—विकसित की है। चार एक्रीलेटों में से एक एक्रीलेट अर्थात मिथाइल एक्रीलेट के मामले में जापान की एक कम्पनी मैसर्स असाही केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि. के साथ समझौता किया गया है जिसके द्वारा असाही मिथाइल एक्रीलेट संयंत्र के लिये आई. पी. सी. एल. द्वारा तैयार किये जाने वाले कुछ आधारभूत एवं विस्तृत इंजीनियरी दस्तावेजों की प्रक्रिया अवलोकन की दृष्टि से जांच करेगा एवं मौखिक टिप्पणी देगा। असाही आई. पी. सी. एल. के कर्मचारियों को असाही के जापान में मिथाइल एक्रीलेट संयंत्र के परिचालन एवं रख-रखाव का प्रशिक्षण भी देगा ।	—
3	25 मैगावाट पावर संयंत्र	कोई विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं किया गया है ।	—	—

1	2	3	4	5
4.	बी. सी. और पी. बी. सी. परियोजना	(i) मैसर्स बी. एफ. गुडरिच कंपनी लि., यू. एस. ए. (ii) मैसर्स स्टाफर कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड, यू. एस. ए.	लाइसेंस शुल्क, प्रक्रिया जानकारी शुल्क, आई. पी. सी. एल. के कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा प्रवासी सहायता के लिये एक मुश्त भुगतान	जिस तिथि से समझौता लागू होगा उससे 7 वर्ष की अवधि तक।
		(iii) मैसर्स वाडगग बी. बी. लिमिटेड	आधारभूत इंजीनियरी सलाह तथा प्रापण सेवाओं के लिए एक मुश्त भुगतान	
		(iv) मैसर्स टैक्नीप, फ्रांस		

Exhibition of documentaries by Cinemas

6617. SHRI CHINTAMANI JENA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Films Division is supplying documentaries to 10,000 cinemas in India and they have to exhibit one film compulsorily in a show but most cinemas are not releasing the films received from Bombay; and

(b) if so, whether Government keep a watch on cinemas in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) The Films Division is supplying documentaries and newsreels to all the Cinemas in the country for exhibition along with feature films. The Cinema houses are required to exhibit documentary or a newsreel at each show compulsorily under the condition of the licence issued by the State Government concerned. Whenever instances of default come to notice, they are reported to the Licencing Authorities concerned for taking suitable action.

(b) The Films Division do not have the requisite machinery for keeping watch on cinemas in this regard. However, surprise visits to the Cinema Houses are made to see whether the Films Division's documentary or newsreel is being shown.

Criteria for selection for selection Grade Posts

6618. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state what are the criteria followed to select employees in Dandakaranya Project for Selection Grade posts which are now said to carry no additional responsibility?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): Seniority subject to rejection due to unfitnes.

Time allotted to Educational Broadcast

6619. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) total time allotted to 'educational' broadcasts from (i) Delhi (ii) Simla (iii) Jullundur Radio Stations per week;

(b) the language/languages in which this programme offered alongwith the subjects of the programme; and

(c) whether the duration is proposed to be increased in view of the radio listening services to the rural areas?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) The details of the total time allotted to 'Educational Broadcasts' per week from (i) Delhi (ii) Simla and (iii) Jullundur Radio Stations are furnished below:—

Delhi—8 hours

Simla—4 hours and 25 minutes

Jullundur—4 hours and 40 minutes

(b) The languages in which Educational broadcasts are put out are as follows:—

Delhi—Hindi and English.

Simla—Hindi, Urdu and English.

Jullundur—Hindi, Punjabi and English.

Subjects covered are indicated in the enclosed Statement.

(c) The following proposals for increase in duration are under consideration:—

Delhi—Broadcasts for teachers are proposed to be put out during summer vacation from 15th May, 1981.

Simla—Broadcasts for Primary schools will be considered when radio sets in Primary schools are installed.

Jullundur—No increase is proposed.

Statement

Subjects of the programme covered are indicated below:—

(1) *Delhi:*	
(i) For Secondary classes:	Social studies, Hindi and English.
(ii) For Primary classes:	Enrichment programmes.
(iii) For the University classes:	Economics, History, Political Science, Commerce Mathematics, English, Urdu, Hindi, Punjabi and Sanskrit.
(2) *Simla*	
(i) For Secondary classes:	Social Studies, General Science, Hindi and English and also Enrichment subjects for schools.
(ii) For teachers:	Latest Techniques and Innovations in Methodology for teachers.
(iii) For Non-formal Education (Rural) Audience:	Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Forestry, Fishery, Environment, Family Welfare, Cultural Heritage, Everday Science, Self-Employment and Developmental activities—in Non-formal Education for rural audience.
(iv) For Post-school learners:	Hindi, English, Political Science, Economics, Population education, Sports, Science and Social Topics for Post-school audience. These programmes are part of Youth Programmes.
(3) *Jullundur:*	
(i) For Schools:	Textbook based programmes.
(ii) For Universities :	Radio support to Correspondence degree course of Punjabi and Punjab Universities.

Electrification of villages in Mizoram, Meghalaya, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Nagaland

6621. DR. R. ROTHUAMA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the total number of villages and towns so far electrified upto date in the States of Mizoram, Meghalaya, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Nagaland;

(b) the number of Hydro Electric/ thermal|diesel run power houses so far commissioned, State-wise, in these States;

(c) the number of hydel projects currently taken up by the Centre in these States;

(d) the current financial allocations for 1981-82 sanctioned by the Centre under Rural Electrification Programmes to these States; and

(e) current year's proposed targets for electrification of villages in these Sates?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The total number of villages and towns electrified up to 31st December, 1980, in the States of Mizoram, Meghalaya, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Nagaland are given in Statement I.

(b) The number of Hydro Electric/ Thermal/Diesel run power houses so far commissioned, in the States|Union Territories referred to in reply to part (a) of the Question is indicated in Statement II.

(c) National Hydro Electric Power Corporation is executing Loktak Hydro Electric Project (3x35 MW) in the State of Manipur in Central Sector. In addition, North Eastern Electric Power Corporation is constructing Kopili H.E. Project (2x50 MW÷2x25 MW) for the benefit of North Eastern Region. The Administration of Union Territory of Arunachal Pradesh is engaged with the construction of three Nos. micro hydel stations with an aggregate installed capacity of 2.3 M.W.

(d) and (e). The State/Union Territory-wise details of the financial allocations approved by the Planning Commission and targets of village electrification for 1981-82 are given in Statement III.

Statement I

Villages and Towns Electrified up to the end of December, 1980

Sl. No.	Name of the State/UT	No. of villages electrified	No. of towns electrified
1	2	3	4
1	Mizoram	28	2
2	Meghalaya	624	6
3	Manipur	322(*)	8
4	Tripura	851	6
5	Arunachal Pradesh	297	4
6	Nagaland	360	3

(*) Progress received up to 30-6-1980.

Statement II

Number of Hydro-Electric/Thermal, Diesel Power Units so far Commissioned

Sl. No.	State/U.T.	Hydro including micro hydel		Thermal		Diesel	
		No.	Cap(MW)	No.	Cap(MW)	No.	Cap(MW)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mizoram . . .	..	..	..	..	9	3·5
2	Meghalaya . .	4	126.71	1	2.50	Not available	1.95
3	Manipur . . .	1	0.60	..	..	,,	14.40
4	Tripura . . .	1	10.00	..	..	,,	5.98
5	Arunachal Pradesh .	14	8.62	..	..	32	2.4
6	Nagaland . . .	1	1.50	..	..	Not available.	2.16

Statement III

Financial allocations and targets of village Electrification for 1981-82

Sl. No.	Name of the State/UT	Financial allocation (Rs. lakhs)	Targets of village electrification
1	2	3	4
1	Mizoram	85.00	22
2	Meghalaya	222.00	200
3	Manipur	98.00	100
4	Arunachal Pradesh	100.00	120
5	Tripura	153.00	190
6	Nagaland	110.00	50

Organisational Gaps in Fertiliser

6622. SHRI S. M. KRISHNA: Will the Minister of PETROLEM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the high level action Committee of experts on public sector undertakings has pointed out "organisational gaps" in fertiliser units and suggested immediate introduction of scientific measures for inventory control to enable them to pick up production;

(b) if so, the broad outlines of the recommendations made in the Report; and

(c) the action taken or proposed to be taken thereon by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c). The Experts Committee on public undertakings in its Report on the fertilizer sector has made some recommendations covering different aspects of materials management. These include centralization of materials management function, creation of a cadre for materials management, proper application of ABC analyses etc. Government proposes to take suitable action after fully studying the Report.

Leakage of official secrets to outsiders

6623. SHRI A. U. AZMI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether his Ministry has drawn any lesson from the recent arrest of an Official working as a P.A. to a Director for the alleged leakage of official secrets to outsiders;

(b) if so, what and the measures he has ordered to be taken to prevent such cases arising in future by fixing the level of Officers who can take official files homes; checking of the brief cases of staff at lower levels dealing with public firms such as drug, chemicals, man-made fibre and other vulnerable subjects;

(c) what action he has taken to prevent the entry of Resident Representatives/Liaison Officers of various Houses to the Branches|Sections| Rooms of P.A.S. to Officers particularly of those who had at one time been working in his Ministry; and

(d) whether he would consider the desirability of exercising a surprise check over the brief cases of such private firms' personnel and those of his Ministry upto the level of Section Officer and if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) This will have to wait till full details of the manner of leakage become available.

(b) Adequate instructions already exist for safeguarding the security of Government documents. These instructions have been and are being brought to the notice of the officers of this Department from time to time.

No one except a gazetted officer can take Government records out of the security zone without a proper permit. The Security Staff of the Ministry of Home Affairs who are on gate duty at the Department can, in case of suspicion, search the belongings of any person at the time of his exit from a security zone.

(c) The Resident Representiatives/ Liaison Officers are not allowed to visit the Sections and the rooms of P.As. They can, by appointment, visit officers of the level of Under Secretary and above.

(d) According to the existing instructions, in case of suspicion, the security staff can search the belongings of any person at the time of his exit from the security zone.

Development of tirbal population in Dandakaranya Project area

6624. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government of Orissa and the Dandakaranaya Development Authority discussed about the development of the tribal population in the project areas;

(b) if so, the details of discussion therefor; and

(c) the amount spent by the State Government and the D.D.A., Koraput for the upliftment of the tribals in Fifth Plan and the proposing Sixth Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) Yes, Sir; discussions are periodically held between the representatives of the Dandakaranya Development Authority and the Government of Orissa about tribal settlement in Dandakaranya Project.

(b) These discussions cover the identification and release of land by the Government of Orissa for tribal settlement in Dandakaranya area, its reclamation by the D.D.A. and identification and actual settlement of tribal families by the State Government on the land so reclaimed.

(c) The Dandakaranya Development Authority spent an amount of Rs. 20.57 lakhs on tribal settlement in its area during the Fifth Five Year Plan and a provision of Rs. 403.21 lakhs has been made in the Sixth Five Year Plan for this purpose. We have no information as to the amounts spent by the State Government for the upliftment of tribals in the Project area in the Fifth Five Year Plan and the provisions made by them in the Sixth Five Year Plan.

Allotment of coal to Tamil Nadu

6625. SHRI C. CHINNASWAMY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the allotment of coal to Tamil Nadu is not sufficient to meet their demands;

(b) whether Government are also aware that total allotment of coal has not been delivered due to non-availability of wagons; and

(c) if so, the steps taken by Government to revise the allotment as it has already affected industrial production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). Coal demand of Tamil Nadu could not be met in full due to the production shortfalls in Singareni Collieries which meets the bulk of the demand; and partly due to the inadequate availability of railway wagons to transport coal.

(c) With a view to meet the demand of coal in Tamil Nadu and other Southern States steps are being taken to improve the coal production in Singareni Collieries. Besides a programmme to load 10920 wagons/day has been approved by the Cabinet Committee on Industrial Infrastructure. Coal India is also releasing coal by road against the shortfall in rail movement from the sponsored quantity. Coal is also being released from certain identified mines free of any restrictions.

Telecasting of folk songs and dances of areas not covered by T.V.

6626. SHRI JITENDRA PRASAD: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether folk centre dances and songs and other glimpses of social life of certain areas do not find

a place in the national television network due to the absence of T.V. Centres in those areas or States;

(b) whether some ways and means are being devised to give maximum coverage in the T.V. programmes to the social and cultural life of such remote and hilly areas of HP and UP as are not having any TV Centres at present; and

(c) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN. M. JOSHI): (a) No, Sir.

(b) and (c). The Film Camera Units of Doordarshan Kendras visit the rural|tribal areas as and when possible to film social and cultural life of these regions, within the limited resources available. Lucknow Doordarshan Kendra has been telecasting programmes of folk-lore and folk dances of Uttar Pradesh from time to time. In addition, folk music and dances of various States are being telecast in the National Programme of Music and Dances. So far, folk music and dances of West Bengal, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh have been put out in the National Programme. Folk music and dances of HP are telecast from Doordarshan Kendras, Delhi|Mussoorie and Amritsar|Jullundur, from time to time.

Linking of development of energy with education

6627. SHRI RAJESH PILOT: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government are considering to implement the long felt need of linking development with education in the field of energy production; and

(b) if so, have any Universities, I.I.Ts. or Engineering Colleges been or are being encouraged to undertake small power production units' construction as a part of their regular activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). The Government is encouraging efforts of linking education with development in the field of energy. The Indian Institutes of Technology and a number of Engineering Colleges, Technical Institutions, Engineering Departments of Universities and Autonomous Institutions are conducting post graduate courses and research in various branches of engineering and technology relevant to energy production. A number of sponsored research projects in the field of energy have also been undertaken by these institutions with necessary financial assistance from the sponsorers. A Centre for Energy Studies has been started in the Indian Institute of Technology, Delhi. This Centre is doing research in developing new sources of energy and in the area of increasing efficiencies of energy utilisation and production from conventional sources.

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

6628. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कितनी विद्युत उपलब्ध है ;

(ख) समूचे देश में, बिहार में, उत्तर बिहार में और बिहार में गंगा के दक्षिणी भाग में विद्युत की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक उपलब्धता क्या है और यह भारी असमानता किस प्रकार दूर की जा रही है ; और

(ग) बिहार में विभिन्न प्रशासनिक जिलों में विद्युत की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक उपलब्धता कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 1978–79 के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) देश में तथा बिहार राज्य में (केवल यूटिलिटीज में) 1978–79 के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता क्रमशः 150.73 यूनिट तथा 87.15 यूनिट थी । उत्तरी बिहार और बिहार के शेष भाग में (यूटिलिटीज में तथा गैर-यूटिलिटीज में) वर्ष 1978–79 के लिए बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमश 23.60 यूनिट तथा 188.80 यूनिट थी । बिजली की प्रति व्यक्ति कम उपलब्धता के कारण मुख्यत: निम्न-लिखित हैं ; संबंधित क्षेत्र में औद्योगिक वाणिज्यिक तथा कृषि संबंधी गतिविधियों का स्तर पिछड़ा हुआ होना तथा राज्य में आबादी अधिक घनी होना । बिहार में कई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और इससे विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना है ।

(ग) विद्युत की उपलब्धता के बारे में जिलेवार, आंकड़े, मंत्रालय और राज्य बिजली बोर्ड के पास उपलब्ध न होने के कारण यह सूचना दे सकना संभव नहीं है ।

विवरण

प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1878-79

राज्य/क्षेत्र का नाम	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (यूनिट)
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
1. हरियाणा	263.74
2. हिमाचल प्रदेश	157.78
3. जम्मू व कश्मीर	122.22
4. पंजाब	395.32
5. राजस्थान	116.28
6. उत्तर प्रदेश	96.82
7. चंडीगढ़	467.57
8. दिल्ली	402.32
उप-जोड़	148.91
पश्चिमी क्षेत्र	
1. गुजरात	264.87
2. मध्य प्रदेश	107.32
3. महाराष्ट्र	279.33
4. गोवा, दमन और दीव	221.74
5. दादरा और नागर हवेली	77.74
उप-जोड़	216.90
पूर्वी क्षेत्र	
1. बिहार	87.15
	131.28

1	2
3. पश्चिम बंगाल	127.22
4. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	51.82
5. सिक्किम	42.79
उप-जोड़	104.83
दक्षिणी क्षेत्र	
1. आंध्र प्रदेश	118.43
2. कर्नाटक	204.98
3. केरल	207.32
4. तमिलनाडु	228.69
5. पांडिचेरी	250.84
6. लक्ष द्वीप	24.86
उप-जोड़	165.90
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
1. असम	42.37
2. मणिपुर	13.94
3. मेघालय	172.39
4. नागालैंड	41.03
5. त्रिपुरा	16.76
6. अरुणाचल प्रदेश	21.05
7. मिजोरम	11.87
उप-जोड़	36.76
अखिल भारत	150.73

वाणिज्यिक विज्ञापन द्वारा सरकार को बदनाम करना

6629. **श्री आरिफ मोहम्मद खान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मार्च, 1981 को दैनिक 'हिन्दुस्तान" के मुख्य पृष्ठ पर "जरूर पढ़ें"—"अजीब परोपकार" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें अधिसंख्य लोगों द्वारा उपयोग को जाने वाली वस्तु को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से भारत सरकार के विरुद्ध कुछ निराधार बातें कही गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) उल्लिखित समाचार सरकार के ध्यान में आया है ।

(ख) निजी क्षेत्र के विज्ञापन सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं । तथापि, सरकार का यह विचार है कि निजी विज्ञापकों/विज्ञापन एजेंसियों को विज्ञापन देने के बारे में स्वयं एक आचार संहिता विकसित करनी चाहिए ।

Interruptions in Radio Broadcasts from AIR, Sangli

6630. SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that many times during its schedules the working of Sangli transmission is interrupted and the frequency of interruption is to such an extent that when transmission resumes the announcer consumes some more minutes in appologising to the listeners for interruptions;

(b) are Government also aware that complaints in this connection are not responded to by the Administrative Wing of Sangli Centre; and

(c) the reasons of transmission interruption of A.I.R., Sangli, and steps Government propose to take in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) Yes, Sir. Of late there has been an increase in the number of interruptions on AIR, Sangli.

(b) No complaint regarding the interruptions has been received by AIR, Sangli so far.

(c) The interruptions are mainly due to power failures. Power supply authorities are regularly approached to improve the supply position to the AIR Centre.

Increase in the price of leading National Dailies

6631. SHRI KRISHNA PRATAP SINGH:

SHRI SUBHASH YADAV:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that most leading national dailies are now priced at 50 paise and more and more space is being devoted to advertising and less and less to hard news and editorial matter; and

(b) the reaction of Government thereto and what steps are proposed to be taken to bring down the price of daily newspapers and also to ensure more news in comparison to advertisements?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b). The Supreme Court had declared the Newspaper (Price and Page) Act, 1956 and the Daily Newspapers (Price and Page) Order, 1960 as un-constitutional and void. Legally, the Government cannot force the newspapers to peg their prices at fixed level.

For the growth of a healthy press, it is necessary to have reasonable ratio between the space devoted to news and advertisements. The government is considering ways and means to achieve this objective within the framework of law.

Appointment of district Judge of Tamil Nadu as Legal Officer at Centre

6632. SHRI N. DENNIS: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any District Judge of the Tamil Nadu Cadre has been appointed Legal Officer for Central Government Offices; and

(b) the details of other officers in the Tamil Nadu Judicial Service serving in Central Government?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b). According to the Government of Tamil Nadu, Shri K. S. Gurumoorthy District Judge, is the only Judicial Officer from Tamil Nadu who has been appointed as Senior Government Advocate in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs; and no other officer from the Tamil Nadu Judicial Service is now serving in the Central Government.

Representation to Teachers in State Legislative Councils

6633. SHRI S. A. DORAI SEBASTIAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the demand of the primary school teachers voiced in their recent Conference held in New Delhi in the second week of March, 1981 that they should be given representation in the Legislative Councils of the States;

(b) if so, whether Government are formulating a Constitution (Amendment) Bill for this purpose, following the assurance of the Law Minister given in this Conference that Government would give priority to such a Constitution (Amendment) Bill?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) Yes, Sir.

(b) No such assurance was given.

"एक्सप्लायटिंग आइल"

6634. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1981 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित संपादकीय "एक्सप्लायटिंग आइल" की ओर दिलाया गया है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या संपादकीय टिप्पणियां तथ्यों से परिपूर्ण हैं, यदि हां, तो किस प्रकार से और यदि नहीं, तो क्यों ; और

(ग) क्या तेल की संभावना का पता लगाने के लिए विदेशी सहयोग के आगे चलकर भारत के लिए लाभप्रद होने के स्थान पर अलाभकर सिद्ध होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख): दिनांक 10-2-81 को इंडियन एक्सप्रैस में छपा संपादकीय सरकार के ध्यान में आया है । सम्पादकीय के मुख्य विषय एवं इन विषयों से सम्बन्धित वास्तविक स्थिति नीचे दी गयी है :—

पेट्रोलियम मंत्रालय से विदेशी कम्पनियों द्वारा प्राप्त की गयी शर्तें धोखा हैं एवं इसके हानिकारक परिणाम होंगे । यह सत्य नहीं है । अभी तक किसी भी कम्पनी ने कोई शर्तें निर्देशित नहीं की है और अगर ऐसा है तो भी विदेशी कम्पनियों द्वारा दर्शायी गयी शर्तों को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता । इसके बजाए, किसी विदेशी तेल कम्पनी के अन्वेषण के ठेके के लिए प्रस्ताव पर सरकार द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों के आधार पर ही विचार किया जायेगा । **जबकि यह सभी आंकड़े विदेशी कंपनियों को निःशुल्क दिये जाते हैं, उनके अपने सर्वेक्षणों के परिणाम केवल उनकी अपनी सम्पत्ति रहेंगे ।** यह भी सत्य नहीं है । यह एक आधारभूत शर्त होगी कि तेल कम्पनियों द्वारा व्युत्पन्न आंकड़ों सहित सभी आंकड़े तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को उपलब्ध कराये जायेंगे ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को प्रबंधों से अलग रखा गया है । यह भी सत्य नहीं है । इस के विपरीत यह अपेक्षा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग प्रबंध तथा परिचालन

समितियों में भाग लेगा तथा उसे ठेके में 50 प्रतिशत तक ले जाये जाने वाले ब्याज (कैरिड इन्ट्रस्ट) का अधिकार भी होगा ।

(ग) जी नहीं ।

मैसर्स गोल्डन टोबैको कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

6635. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स गोल्डन टोबैको कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, के कितने औद्योगिक एकक हैं और वे कहां कहां स्थित हैं ;

(ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 में इसने कुल कितना शुद्ध लाभ कमाया ; और

(ग) इसके कुल कितने वेतन-भोगी कर्मचारी हैं और इसमें सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी का क्या नाम है और वह कितना वेतन पाता है तथा सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी का क्या नाम है और उसे कितना वेतन मिलता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) बम्बई में पंजीकृत मैं० गोल्डन टोबैको कम्पनी लिमिटेड के, एक बम्बई तथा दूसरा बड़ौदा में स्थित दो एकक हैं ।

(ख) कम्पनी द्वारा करारोपण का प्रावधान करने के पश्चात कमाये गये लाभ की कुल राशि, 30 जून, 1979 के वर्ष समाप्ति की 63.52 लाख रु. तथा 30 जून, 1980 के वर्ष समाप्ति की 80.50 लाख रु० थी ।

(ग) कम्पनियों द्वारा उनके वेतन-भोगी कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतनों की बाबत सूचना, कम्पनी अधिनियम, 1956 के किसी भी उपबन्ध के अन्तर्गत देना अपेक्षित नहीं है । तथापि, उन कर्मचारियों, जो यदि पूर्ण वर्ष के लिये नियुक्त किये गये हों, व उन्होंने 36000 रु. प्रतिवर्ष से कम नहीं प्राप्त किये हों, अथवा यदि वर्ष के किसी भाग के लिये नियुक्त किये गये हों, व 3000 रु. प्रतिमास से कम नहीं प्राप्त किये हों, के बारे में कम्पनियों के लिये, अधिनियम की धारा 217 (2क) के अन्तर्गत, सूचना देना अपेक्षित है । मैं० गोल्डन टोबैको कम्पनी लिमिटेड की, 30 जून, 1980 के वर्ष समाप्ति की रिपोर्ट के अनुसार, इसका प्रबन्ध निदेशक श्री डी० के० पोद्दार, ने अधिकतम पारिश्रमिक (वेतन, परिलब्धियां आदि) प्राप्त किया था, जो 92024 रु० की राशि का था । तथापि, उन कर्मचारियों, जिन्होंने अधिकतम वेतन प्राप्त किया, के नाम तथा उसकी राशि, की बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Suggestion for taking over of Lignite Mines by Centre

6636. SHRI RAMJIBHAI MAVANI:

SHRI NAVIN RAVANI:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have received a copy of letter dated 12th February, 1981 under Ref. No. 758/81 from 'Morbi Roofing Tiles Manufacturers Association' of 'Morvi' (District Rajkot) of Gujarat State regarding taking over of Lignite Mines by the Central Government to save the industries of Gujarat;

(b) if so, the details of the said letter;

(c) what action has been taken by the Ministry in the matter;

(d) the outcome thereof; and

(e) when and how these mines are expected to be taken by the Centre?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The letter referred to in part (a) of the question has not been received in the Department of Coal.

(b) to (e). Does not arise.

Wiring of Electric Poles by DESU in Sagarpur

6637. SHRI KESHORAO PARDHI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in some areas in the middle of Sagarpur, an unapproved colony in Palam zone in outer Delhi, the work of wiring the electric poles has not been taken up by DESU;

(b) whether it is also a fact that a piece of land as required by the DESU has been provided by the residents of the said area for installation of transformer by the DESU; and

(c) if so, the reasons for which the said wiring work has not been started so far and the time by which it is likely to be taken up and completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). Out of 4 Kiosk sub-stations to be installed in Sagarpur colony, two in the East and two in the West of the Colony, 3 sub-stations have already been commissioned and the connected areas electrified. In the case of the 4th sub-station, there was some problem about the availability of land for the same. This has now been settled and the work of construction of kiosk sub-station is likely to be completed within a period of 2 months and the electrification of the connected areas would be completed in three months after completion of the sub-station.

Power connection for Tube-Wells

6638. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether some cases have come to the notice of Government that after getting sanction for tube-well sunk for agricultural purposes, at times the applicants desirous of getting timely tube-well connections are asked to bring electric poles from the various stores of the undertaking, at their own cost for installation; and

(b) if so, the details regarding the rules in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). No, Sir. Even where due to non-availability of transport, the consumers volunteer to bring the poles to the work site to expedite the tube-well connections, it is understood that such transportation charges are not included while working out the cost to be recovered from the applicants.

In some of the tube-well connections executed by the Rural Electric co-operative Societies, however, the members prospective members have been putting in voluntary labour (Shramdaan) and sometimes poles are carried to the work site by them of their own accord.

Production and distribution of Soda Ash

6639. SHRI BHIKU RAM JAIN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the total production of soda ash in the country during the last three years i.e. 1978-79, 1979-80 and 1980-81 and upto 31st January, 1981;

(b) what was the consumption of soda ash during these years;

(c) what is the total soda ash imported during these three years and the quantity expected to be imported within 1981-82;

(d) whether it is a fact that soda ash distribution in the country is not uniform and that whether in some States it is through Director of Industries, in some other States it is open, with the result that where there is no control the surplus quota holders sell their products in the black market; and

(e) if so, what steps Government propose to take against holders and for fair distribution of the soda ash in the country?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). The production and estimated demand of soda ash in the country during the last three years are as given below:—

(In lakhs tonnes)

Years	Production	Estimated Demand
1978-79	5.81	6.00
1979-80	5.55	6.20
1980-81	4.46 (upto the end of Jan. 1981)	6.30

(c) A statement showing import of soda ash during 1978-79 and 1979-80 (upto January, 1980) is given in the Statement.

It is not possible to quantify the imports likely to be made during the year 1981-82, as the item soda ash is under O.G.L. (Open General Licence).

(d) and (e). Soda ash is not subject to statutory price and distribution control. However, this Department issued guidelines in January, 1979 whereby the manufacturers are required to supply direct to industrial consumers at least the quantity received by such consumers during the calendar year 1977, a year of normal supply. Such direct supply by producers to industrial consumers accounts for nearly 86 per cent of production. The manufacturers have also undertaken to supply about 1,000 tonnes of soda ash per month to the National Consumers Cooperative Federation for distribution through their retail outlets to the small scale users viz. washermen and housewives. It is the balance quantity of production remaining after meeting the requirements of industrial consumers as per guidelines and the supplies to NCCF, that is disposed of through trade channels. As a result of the measures taken by Government the open market price of soda ash which was as high as Rs. 3,600|- per tonne in 1978 and was ruling at about Rs. 3,000|- per tonne for more than a year has decline to Rs. 2,100|- to Rs. 2,400|- per tonne. This Department is also obtaining from all the maunfecuturers regularly complete lists of industrial consumers and traders to whom supplies are made and is passing on the lists to the respective State Governments for verification and taking action, if any, to ensure proper utilisation. Any allocations made by any State Government are on the basis of ad hoc arrangements made by

Statement

Import of Neutral Sodium Carbonate (Soda Ash) during 1978-79 and 1979-80 (upto January, 1980)

Quantity in tonnes
Value in Rs. Lakhs.

S. No.	Description of item	ITC Rev. 2 Code No.	1978-79		1979-80 (upto Jan.,'80)	
			Quantity	Value	Quantity	Value
1	2	3	4	5	6	7
1	Neutral Sodium Carbonate—Dense.	523.2301	4918	71.56	33,299	510.37
2	Neutral Sodium Carbonate — Light.	523.2302	14352	98.97	34,426	454.68
3	Neutral Sodium Carbonate (Soda ash)—others.	523.2309	4110	29.81	2,578	54.19

NOTE : Figures are provisional and subject to revision.

SOURCE : (I) *For* 1978-79: Monthly statistics of Foreign Trade of India Vol. II (imports) published by Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta.

(II) *For* 1979-80 (*upto Jan.* 80). Advance data received in the Office of the Economic Adviser, Deptt. of Commerce from Directorate General Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta.

Crude requirement during Sixth Plan

6640. SHRI ARJUN SETHI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have made any assessment regarding the requirement of crude oil during the Sixth Five Year Plan period; and

(b) if so, the details in this regard and the ways through which Government would be in a position to meet the deficit in oil requirement?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). The estimated requirement of crude oil during the Sixth Five Year Plan period and the estimated indigenous production are given below year-wise:

(*In Million Tonnes*)

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
Crude requirement . . .	26·9	31.10	35 3	35.4	42.9
Indigenous production . . .	10·2	16.9	20.5	21.0	21.3

The deficit in the crude oil requirements will have to be met through imports. However, all efforts are being made to increase the crude oil production in the country as well as to moderate the demand for petroleum products.

Inquiry Committee of Press Council of India

6641. SHRI HARIKESH BAHADUR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to lay a statement showing:—

(a) whether there was a meeting of the Inquiry Committee of the Press Council of India on November 29 and 30, 1980;

(b) names of members who attended the meeting;

(c) daily sitting allowance and travelling allowances paid to each of them; and

(d) what are the rates of daily sitting allowance and travelling allowance for the Members of the Press Commission?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) Yes, Sir.

(b) S|Shri Sharad Dwivedi, Umashankar Joshi, Sunit Ghosh, Prem Chand Verma, S. Viswam and Dr. Rafiq Zakaria besides Shri Justice A. N. Grover, Chairman of the Press Council of India.

(c) Name	Reimbursement of conveyance expenses	Reimbursement of travelling expenses	Daily allowance	Total
1	2	3	4	5
1. Shri Sharad Dwivedi (Local)	Rs. 40/- (for 2 days)	Nil	Nil	Rs. 40/-
2. Shri Umashankar Joshi (Outstation)	Nil	Rs. 468/- one way fare)	Rs. 300/- (for four days @Rs. 75/- per day)	Rs. 768/
3. Shri Sunit Ghosh (Local)	Rs. 20/- (for one day)	Nil	Nil	Rs. 20/-
4. Shri Prem Chand Verma (Local)	Nll	Nil	Nil	Nil
5. Shri S. Viswam (Local)	Rs. 40/- (for two days)	Nil	Nil	Rs. 40/-
6. Dr. Rafiq Zakaria (Outstation)	Nil	Nil	Rs. 300/ (for 4 days)	Rs. 300/-

The Chairman is a whole-time officer of the council.

(d) The rates of Daily Allowance for Members of the Press Commission are as follows:—

(i) For Out-station Members

Rs. 200|- per day in 'A' Class cities.

Rs. 150|- per day in 'B' Class cities.

Rs. 100|- per day in other cities.

When accommodation is made available to a member at 'A' & 'B' Class cities at Government expense, he will be entitled to daily allowance at the rate of Rs. 90|- only.

(ii) **For local Members**

Rs. 50|- per day irrespective of the classification of cities in which meetings are held.

Members of the Commission are allowed to travel by air. In case they travel by rail, they are entitled to reimbursement of actual fare including First Class ACC fare.

Streamlining of Legal aid to Undertrials in Jails

6642. SHRI AMRIT PATEL: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is proposed to streamline and expedite the arrangement for rendering legal aid to the poor specially to the undertrials languishing in jails without a committal or a trial for more than two years;

(b) the present arrangement in this regard; and

(c) what more steps are proposed?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b). To provide legal aid to the needy, Government appointed on the 26th September, 1980 a Committee under the Chairmanship of Justice P. N. Bhagwati, a Judge of the Supreme Court which is required not only to formulate in detail but also to implement comprehensive legal aid schemes after taking into account the working of various legal aid schemes in different States and to take and recommed such other steps as are necessary to secure their proper working. The Bhagwati Committee has prepared a Model Scheme which will apply both to accused in criminal cases and litigants in civil proceedings.

(c) No other proposal is under consideration at present.

Coverage of Fairs, Festivals Functions of Tribal People

6643. SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the coverage of fairs, festivals and functions of tribal people in tribal districts of the country by A.I.R. during the last three years, year-wise and State-wise; and

(b) the functions like poetic symposia|folk song symposia| women seminars and children programme covered by A.I.R. during the last three years, year-wise and State-wise?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b).All India Radio broadcasts programmes in 146 dialects, tribal and non-tribal, from its various stations, out of which the tribal dialects are about 110. A large number of programmes are broadcast in these dialects from stations situated in areas having mixed population, predominantly in the tribal areas. These broadcasts include field-based programmes consisting of coverages of fairs, festivals and functions of the tribal people. Also almost all AIR stations broadcast programmes for Women and Children as well as poetic symposia and folk music concerts. The collection of the details of these programmes for the last three years, year-wise and State-wise will be very large, spread over throughout the year. The collection and compilation of this information will be a stupendous task

and will require enormous time as well as manpower which All India Radio is lacking. Further, the collection of this information will not be commensurate with the results likely to be achieved.

Production of Alcohol

6644. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the country is not producing enough alcohal required for Industrial use;

(b) if so, what steps Government have taken to utilise the sugar rich molasses produced by gur and Khandsari industry for producing the required alcohol;

(c) figures for such use during the last three years;

(d) whether Government are aware of the reports published in certain journal (Business India, November 10—23) about large scale smuggling out of molasses and alcohol also; and

(e) if so, details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) The Central Molasses Board has estimated that in the current alcohol year 1980-81 (December-November), the availability of alcohol is likely to be 4200 lakhs litres as against an estimated aggregate demand of 5716.79 lakh litres.

(b) Molasses is not a by-product in the production of gur. All the State Governments have been requested to augment the availability of alcohol by promoting the use of khandsari molasses for alcohol production.

(c) No figures for the use of khandsari molasses for alcohol production are available.

(d) and (e). The report referred to does not allege that there has been large scale smuggling of molasses and alcohol. It only states that prices of molasses and alcohol in India are much lower than the international prices and that this disparity in prices has provided a strong temptation to ship out molasses and alcohol. It also states that alcohol is being exported as crude rum. The export of molasses is canalised through the State Trading Corporation. In the molasses years 1979-80 and 1980-81, no molasses was released to STC for export. Following reports of export of alcohol as crude rum, the export of potable liquor and Indian made foreign liquor containing alcohol exceeding 50 per cent (P/Y) was banned with effect from 22nd September, 1980.

मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को सीमेंट की सप्लाई

6645. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को पिछले दो वर्षों से अपेक्षित मात्रा में सीमेंट नहीं मिल रहा है ;

(ख) क्या राज्य की विकास संबंधी गतिविधियों से संबंधित बहुत सी योजनाओं पर सीमेंट की कमी का बुरा प्रभाव पड़ रहा है और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है ; और

(ग) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के लिये सीमेंट की उपलब्धता की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमेंट की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय उद्योग मंत्रालय के साथ निकट और सतत सम्पर्क बनाए हुए है । तथापि, मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को सीमेंट की सप्लाई, समस्त विद्युत क्षेत्र के लिए सीमेंट की कुल उपलब्धता पर निर्भर करती है, जिसका आबंटन भारत के सीमेंट नियंत्रक, उद्योग मंत्रालय, द्वारा किया जाता है ।

Newsprint for Dailies published from West Bengal

6646. SHRI AMAR ROYPRADHAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the dailies published from West Bengal suffered for the required quantity of newsprint in 1980-81; and

(b) the total quantum of newsprint sanctioned to the each of the dailies published from West Bengal during the year 1980-81 and the claimed circulation each of those dailies for the said period?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) No, Sir.

(b) As in Statement.

Statement

The names of dailies published from West Bengal alongwith their circulation and newsprint entitlement for the year 1980-81.

Sl. No.	Name of the Newspaper	Language	circulation	Enttilement (in Mts.)
1	2	3	4	5
1	Amrit Bazar Patrika .	English Daily	1,30,100	3503.52
2	Statesman . .	Do.	2,13,964	8134.23
3	Business Stadnard .	Do.	19,043	412.04
4	Calcutta Observer .	Do.	13,809	118 54
5	Hindustan Standard .	Do.	3,051	13.70
6	Jugantar . . .	Bengal Daily	3,30,199	5721.55
7	Anand Bazar Patrika .	Do.	4,23,199	8072.38
8	Basumati . . .	Do.	28,287	493.50
9	Satyayug . . .	Do.	28,387	426 27
10	Kalantar . . .	Do.	23,210	270.90
11	Ganashakti . .	Do.	12,206	126.67
12	Paigam . . .	Do.	16,352	169.20
13	Dainik Damodar .	Do.	6,278	13.54
14	Janani . . .	Do.	7,408	62.78

1	2	3	4	5
15	Lok Sevyk . . .	Do.	6,901	66.67
16	Aaj Kaal . . .	Do.	30,000	210.37 (4 months)
17	Uttar Banga Sambad .	Do.	10,000	78.12 (4 months)
18	Sanmarg . . .	Hindi Daily	54,884	895.36
19	Bishwamitra . .	Do.	63,972	1201.97
20	Rooplekha . . .	Do.	28,969	315.56
21	Chhapte Chhapte .	Do.	20,566	200.96
22	Sutrakar . . .	Do.	13,441	180.05
23	Prakash . . .	Do.	15,175	132.35
24	Parikshit . . .	Do.	9,583	85.90
25	Akbar-E-Mushrig .	Urdu Daily	20,290	145.32
26	Ghazi . . .	Do.	13,628	97.79
27	Rozana Hind . .	Do.	5,785	59.79
28	Aakas . . .	Do.	11,752	119.05
29	Asre-Jadid . . .	Do.	8,505	89.56
30	Imroze . . .	Do.	4,392	37.38
31	Aabashar . . .	Do.	4,776	11.39
32	Shane-Millat . .	Do.	5,950	51.15
33	Aazd Hind . .	Do.	12,548	99.87
34	Navi Prabhat . .	Punjabi Daily	2,200	26.87
35	Desh Darpan . .	Do.	3,235	31.98
36	Chinese Journal of India	Chinese Daily	808	7.99

Note : Out of the above newspapers except the paper shown at S.No. 17 which is being published from Siliguri others are from Calcutta.

Perspective Planning main hinderance in the development of hydro-electric energy

6647. SHRI HARINATHA MISRA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that lack of perspective planning is the main hinderance in the development of hydro-electric energy in the country;

(b) whether any comprehensive, time-bound, plan indentifying specific schemes for power development has been prepared; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) No, Sir.

(b) and (c).With a view to exploiting the country's hydro-electric potential, the Central Electricity Authority is undertaking a re-assessment of the hydro-electric potential. Simultaneously, the Working Group on Power, set up by the Planning Commission has indicated the broad perspective upto 1990. During the period 1980—85, 4768 MWs of hydro power and for the period 1985—90 15082 MW hydro power are planned to be added. It has also been decided to take up the investigation of projects with the assistance of latest

technology with a view to keeping ready a shelf of projects that can be taken up for execution.

Radio Broadcast in Konkani

6648. SHRI EDUARDO FALEIRO: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be peased to state:

(a) which are the All India Radio Stations in the country broadcasting programmes in Konkani language;

(b) the nature of such programmes in each states specifically; and

(c) time allotted to them in each Station specifically?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) Panaji, Bombay, Calicut, Dharwar, Trichur and Mangalore Stations of All India Radio.

(b) and (c). The information is given in the enclosed Statement.

Statement

Name of Station	Time	Duration	Detials of Programme
1	2	3	4
Panaji (Goa, Daman & Diu)	8.20 AM	10 Mts.	Konkani Songs, BHIUM VDER
	9.00 AM	10 Mts.	News in Konkani from Bombay.
	9.30 AM (Weekly)	30 Mts.	Childrens Programme in Konkani (Kallar Ani Mallar's) (Sunday).
	10.30 AM (Weekly)	30 Mts.	Saunsar: Magazine Programme in Konkani. (Sunday).
	12.50 PM	10 mts. (Weekly)	SHABDULI : Konkani Songs. (Thursday)
	5.30 PM	20 Mts. (Weekly)	Do. (Sunday).
	5.30 PM	15 Mts. (Weekly)	Aboleanch O JHELO: Konkani Songs.
	6.05 PM	10 Mts.	Konkani News—RVU-B.
	6.15 PM	10 Mts. (Weekly)	Shabduli Konkani Songs. (Tuesday)
	6.15 PM	10 Mts. (Weekly)	Almorechea Vellar : Devotional Songs—Konkani (Sunday).
	6.15 PM	10 Mts. (Weekly)	Human Interest News Bulletin 5 mts. and Taluka—News letter in Konkani 5 mts. (Thursday).
	6.15 PM	10 Mts. (Weekly)	Aboleancho Jhelo Konkani Songs (Saturday).
	6.30 PM	25 Mts. (Daily)	CHAVDER : Rrural Programme in Children Progamme for Rural Women R.R.F in Konkani.
	7.00 P-M	10 Mts.	Regional News in Konkani Pradeshik Kholro.

1	2	3	4
	7.10 PM	50 Mts. (Weekly)	MANAJO GATIM GEETAM : Konkani Request Programme for songs (Sunday).
	7.10 PM	50 Mts. (Weekly)	Yuv Vani Konkani (Friday).
	7.10 PM	50 Mts. (once in a month)	Folk Play in Konkani (1st Saturday).
	7.30 PM	30 Mts. (Weekly)	Honibai Vasri (Womens Programme) in Konkani (Tuesday).
	8.15 PM	30 Mts.	ABOLEANDRE : Konkani Songs. (Monday). Assembly Review in (Daily) Konkani except Saturday.
			Today in Parliament from 8.30 P.M. from VUD.
	8.15 P.M	30 Mts.	Shabduli Konkani Songs/(Sat.) Today in Parliament (During Session of the Parliament).
	9.15 PM	15 Mts.	Fondi-Fev: Humourous (Sunday) Programme in Konkani.
	9.15 PM	15 Mts. (Weekly)	Samachar Darshan (Monday) (Konkani)
	9.15 PM	15 Mts. (Weekly)	Talk/Discussion—Konkani (Wednesday)
	9.15 PM	15 Mts. (Weekly)	Tumcheo Chittan : Staurday Amchil Zaap: Reply to Listeners Letter in Konkani.
	9.30 PM	60 Mts. (Fortnightly)	Musical Play in Konkani 1st & 3rd Sunday.
	9.30 PM	30 Mts. (Weekly)	Konkani Vasini of National Programme of Feature (2nd Thursday).
			Play : 3rd Thursday.
	10.00 PM	30 Mts. (Fortnightly)	SAHITYA-JHELO : Literary Magazine Programme in Konkani (2nd & 4th Tuesday).
	10.30 PM	30 Mts.	Play Konkani : (1st Tuesday.)
Bombay (Maharashtra)	8.40 AM	20 Mts. (Daily)	Konkani Programmes including Konkani Light Songs.
	8.15 PM	20 Mts. (Daily)	Konkani Programmes including talks/discussions, Plays, features, dialogues weekly womens and children Programmes Literary Programmes & Songs.
	9.00 AM	10 Mts.	Regional News
	6.05 PM	10 Mts.	Do.

1	2	3	4
Calicut (Kerala) . .	7.50 PM	10 Mts.	Konkani Ganangal (1st & 3rd Sunday).
Dharwad (Karnataka) .		30 Mts.	Konkani Composite Programme. Once a Week. Jayi Jayee Composite Progamme.
Trechur (Kera'a)	—	15 Mts. (Weekly)	Konkani Songs.
Mangalore (Karnataka) .	6.15 PM each on Sunday, Wednesday, and Friday (Thrice a week)	25 Mts.	Sunday—Play, feature and Story. Wednesday—Discussion, Interviews, Literary Boys. Friday—Women, Children Youth variety.
	9.15 PM	15 Mts. (Saturday)	Konkani Karyakrama Format Talks.

Increase of electricity generation

6649. SHRI RASA BEHARI BEHERA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that electricity generation increased at the rate of 12.7 per cent per annum during 1950s and the 1960s;

(b) this rate came down sharply to 7.3 per cent per annum during the 1970s; and

(c) details of the present electricity generation per annum during 1980s?

THE MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The annual average increase in electricity generation during the decade 1950 to 1960-61 and during the decade 1960-61 to 1970-71 was about 12.74 per cent and 12.67 per cent respectively.

(b) The average annual increase for the decade ending on 1979-80 was about 7.25 per cent.

(c) The actual energy generation in the country during the period from April 1980 to March 1981 was 111, 514 million units (approx.) in utilities.

Employment to families whose land has been acquired by ONGC

6650. SHRI B. K. GADHAVI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one person is employed in ONGC from those families whose land has been acquired by ONGC; and

(b) if so, how many such persons are employed in Gujarat for the last 10 years and how much land and from how many families has been acquired?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of he House.

Loans by Arab petroleum exporting countries

6651. SHRI MOHAMMED ASRAR AHMED: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the organisation of Arab Petroleum Exporting Countries has agreed to give soft loans to India to ease India's burden in respect of the heavy cost incured for petroleum exports; and

(b) if so, detail thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) No agreement providing for soft loans to India, was signed between the Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries and India.

(b) Does not arise.

बस्तर जिले के विकसित, विकासशील और दूर-दराज क्षेत्रों में फिल्में दिखाना

6652. **श्री बो० आर० नहाटा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजकीय प्रशासन और लोगों के लाभ के लिए बस्तर जिले के विकसित, विकासशील और दूर-दराज क्षेत्रों में फिल्में दिखाने की ग्रोर योजना बना रहा है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक कार्यान्वित होने की ग्राशा है ग्रौर यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना ग्रौर प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (बस्तर जिले के जगदलपुर ग्रौर कंकेर में स्थित ग्रपनी दो यूनिटों सहित) द्वारा देश के विकसित, कम विकसित ग्रौर दूरवर्ती क्षेत्रों में निर्धारित मानकों के ग्रनुसार फिल्में पहले ही दिखाई जा रही है । तथापि, सरकार की घोषित नीति के ग्रंग के रूप में समूचे देश के ग्रादिवासी, दूरवर्ती ग्रौर पिछड़े क्षेत्रों को कवर करने पर ग्रधिक बल दिया जाएगा ।

Production of Crude oil in Assam

6653. SHRI INDRAJIT GUPTA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether production of crude oil in Assam is fast returning to normal;

(b) whether anticipated production by March 1984 will be over 8 million tonnnes;

(c) the present refining capacity in Assam and extent of surplus crude; and

(d) whether Government are considering to put up a third refinery in Assam as per the unanimous resolution of 18th February, 1975 adopted by the State Asembly?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTLIZERS (SHR P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. The Sixth Five Year Plan (1980—85) envisages a production of 5.6 million tones per annum of crude oil from eastern region by March, 1984.

(c) 1.85 million tonnes per annum. The balance quantity of crude oil is required to feed the Barauni Refinery in Bihar. As such there is no surplus crude.

(d) There is no proposal to set up a new refinery in Asam at present.

Fertilizers Plants at Ramagundam and Talcher

6654. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) performance of coal based fertilizer plants at Ramagundam and

Talcher till their starting; facts in details with month-wise of production and capacity utilisation;

(b) whether it is a fact that there is no technological uncertainties left in this going into smooth production;

(c) whether Government propose to install such coal based fertilizer plant at Sindri;

(d) if so, when; and

(e) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) The coal based fertilizer plants at Ramagundam and Talcher went into commercial production with effect from 1st November, 1980. The month-wise details of production and capacity utilisation from November, 1980 to February, 1981 are as follows:—

Month	Ramagundam		Talcher	
	Production of urea (Tonnes)	percentage of capacity utilisation	Production of urea (Tonnes)	percentage capacity utilisation
November, 1980	15016	36·4	2753	6·7
December, 1980	2580	6·3	3319	8·0
January, 1981	1096	2·7	529	1·3
February, 1981	20039	48·6	2483	6·0

(b) The production during the first 4 months after the plants went into commercial production was well below the rated capacity on account of a number of teething problems faced by the plants. Remedial action to set right these problems has been taken. However, it is too early to say categorically that there are no technological uncertainties about these plants reaching their rated capacity.

(c) The question of setting up any more coal based fertilizer plants in the country can be taken up by Government only after the techno-economic viability of such plants is established by the experience of operating the Talcher and Ramagundam plants for some time.

Power projects of Punjab pending clearance

6655. SHRI R. L. BHATIA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the following new and expansion projects submited to the Centre by the Punjab Government have been pending clearance since long:—

(i) Anandpur Sahib Project;

(ii) Mukerian Hydel project;

(ii) Mukerian Hydel project; Plant, Bhatinda;

(b) if so, the stage at which these stand;

(c) whether the State which is the main foodgrains supplier to the deficit State is experiencing serious shortage of power not only to tube-wells but its further industrialisation

has also been very much affected; and

(d) if so, the action Government propose to take in the matter and how far it will help in bridging the gap between the demand and supply for power?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). The Anandpur Sahib and Mukerian Hydro-electric Projects, submitted by the Punjab Government are under various stages of examination and scrutiny, pending clarifications on queries raised by CWC/CEA and settlement of various inter-State aspects. There have been claims by Rajasthan and Haryana for a share in the benefits of these projects. It was proposed that these claims be referred to an Arbitrator provided the States agreed that his findings would be binding on all concerned. Such an agreement has not been secured and hence the inter-State aspects have not been resolved so far.

Regarding Gurunanak Dev Thermal Plant Extension, Stage-III, comprising of 2 units of 210 MW each, the Punjab State Electricity Board has submitted the Project Report which is under examination. However, the proposed coal linkage for this scheme has been diverted to Ropar Thermal Power Station Stage-I which has been accorded higher priority by the Punjab State. The question of availability of coal for the Stage-III of Gurunanak Dev Thermal Station is now being examined by the Department of Coal.

(c) and (d). Power from Bhakra and Beas complex is given by BBMB to the State of Punjab and other partner States in agreed ratios. The Board reviews the power supply position monthly at its technical meetings where all the partner States are represented and decides the pattern of releases and power generation. In the short term, the gap between demand and supply is sought to be met, by improving the performance of plants, through better operation and maintenance. In the long run, every effort is being made to take up new projects with a view to increasing the installed capacity.

मध्य प्रदेश में बिजली की कमी का फसलों पर प्रभाव

6656. **श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में बिजली की कमी का मध्य प्रदेश की भावी फसल पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए कोई तत्काल कार्रवाई करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं । यद्यपि मध्य प्रदेश में विद्युत की कुछ कमी है, फिर भी साप्ताहिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर, जब सप्ताह में एक बार ग्रामीण फीडरों को प्रातः 8.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक सप्लाई नहीं दी जाती है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण फीडरों को सामान्यतः लगभग 20 घंटे सप्लाई बनाए रखी जाती है ।

(ख) और (ग). राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई उपाए किए गए हैं और किये जा रहे हैं । इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) भार मांग का बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था ।

(2) मौजूदा प्रतिष्ठापित क्षमता से विद्युत का उत्पादन अधिकतम करना ।

(3) कुल लगभग 2400 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना । मध्य प्रदेश में इस समय निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

परियोजना का नाम	1980–85 के दौरान लाभ	1985–90 के दौरान लाभ
	(मेगावाट)	
सतपुड़ा 8 वीं और 9 वीं (ताप विद्युत)	420	—
कोरबा पूर्व (ताप विद्युत)	120	
कोरबा पश्चिम (ताप विद्युत)	420	
कोरबा पश्चिम विस्तार (ताप विद्युत)	420	
पेंच (राज्य का हिस्सा)	106.6	
बोरसिंह पुर (ताप विद्युत)	—	420
बोध घाट (जल विद्युत)	—	500
जोड़	1486.60	920

इसके अतिरिक्त, इस समय केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वयनाधीन कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र से भी मध्य प्रदेश को विद्युत की सप्लाई का कुछ लाभ मिलेगा।

असिस्टेन्ट प्रोड्यूसरों/प्रोड्यूसरों की पदोन्नति

6657. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1956 से 1965 तक की अवधि में आकाशवाणी में असिस्टेन्ट प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर के रुप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों में से अधिकांश अभी तक प्रोड्यूसर के पद पर हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1958 से 1965 तक की अवधि में जिन लोगों को आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव के रूप में नियुक्त किया गया था उनमें से अधिकांश व्यक्तियों को असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पदों पर पदोन्नत कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त दो वर्गों के पदों में पदोन्नति के मामले में इस विषमता के क्या कारण हैं और इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या सरकार इस विषमता को दूर करने की दृष्टि से प्रोड्यूसरों को अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंप कर उन्हें शीघ्र ही पदोन्नत करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन जोशी) : (क) जी, हां । 1956–65 की अवधि के दौरान आकाशवाणी के असिस्टंट प्रोडयूसर प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत केवल कुछ ही व्यक्तियों को मुख्य प्रोड्यूसर और उपमुख्य प्रोडयूसरों के रूप में नियुक्त

किया गया है । 1972 में स्टाफ आर्टिस्टों के शुल्क मानों को युक्तियुक्त बनाने के फलस्वरूप असिस्टेंट प्रोड्यूसर की श्रेणी को 1 अप्रैल, 1971 से प्रोड्यूसर के साथ मिला दिया गया है ।

(ख) 1958 और 1965 की अवधि के दौरान ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव के रुप में नियुक्त किए गए कुछ व्यक्तियों को सहायक केन्द्र निदेशक और केन्द्र निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है । तथापि, उनमें से किसी को भी उप महानिदेशक के ग्रेड में पदोन्नत नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) . प्रोडयूसर और ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव विभिन्न पदोन्नति अवसरों वाले विभिन्न संवर्गों से सम्बन्धित हैं । जबकि प्रोड्यूसरों को संविदा पर लगाया जाता है, ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव नियमित सिविल पदों पर कार्य करते हैं । सरकार ने आकाशवाणी की कार्यक्रम सेवाओं के संवर्ग ढांचे का अध्ययन करने के लिए 1977 में एक संवर्ग पुनरीक्षण समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने, अन्य बातों के साथ साथ, सीनियर प्रोड्यूसरों का एक नया संवर्ग बनाने सहित, प्रोड्यूसरों के पदोन्नति अवसरों को बढ़ाने की सिफारिश की है । इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट विचाराधीन है ।

Proposal to double the power generation capacity of projects in Uttar Pradesh

6658. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a proposal to double the power generating capacity of projects in Uttar Pradesh in the near future;

(b) if so, the major details thereof; and

(c) what are the financial implications of the Centre and State both in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). The total installed generating capacity in the State of Uttar Pradesh as on 31-3-1980 was 3340 MW. Presently power projects aggregating to a capacity of 3310 MW have been sanctioned and these are in various stages of construction. U.P. will also get its share of 350 MW out of 1000 MW additional capacity likely to be available during the period 1980—85 from Singrauli STPS under execution in the Central Sector.

(c) The State's Sixth Plan outlay for the power sector has been tentatively kept at Rs. 2125.90 crores. Central assistance is provided on the basis of a formula approved by the National Development Council for the overall Plan outlay of the respectively states. The outlay provided for the Sixth Plan for Singrauli STPS and Singrauli Extension being executed in the Central Sector is Rs. 474 crores.

Closure of Fertilizer Plant at Panipat

6659. SHRI B. D. SINGH:
SHRI RASHEED MASOOD:
SHRI GEORGE FERNANDES:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Panipat Fertilizer Plant has been closed, if so, since when the plant has been closed stating the reasons for its closure;

(b) the loss incurred by the plant due to its closure;

(c) whether it is also a fact that the Fertilizer Plant is based on continuous process and it is likely to suffer further damage due to its closure; and

(d) if so, the steps taken by Government to overcome the bottlenecks, if any and to ensure its uninterrupted functioning?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) The Panipat fertilizer plant of National Fertilizers Limited was closed on the 14th of February, 1981 due to a near total power cut imposed by the Haryana State Electricity Board. With the restoration of full supply of power in the last week of March, 1981, the plant has been restarted.

(b) The loss of production incurred by the plant due to this closure is expected to be about 48,000 tonnes of urea.

(c) and (d). Repeated closures of fertilizer plants which are all continuous process plants could, in addition to causing production losses, cause damage to the sensitive equipment of the plants. In view of this, the Government of Haryana and the Haryana State Electricity Board have been requested to provide continuous and uninterrupted power supply to the Panipat plant and exempt it totally from power cuts.

Production of 16 MM Film

6660. PROF. K. K. TEWARI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether National Film Development Corporation has decided to acquire infrastructure for producing 16 mm. film on a large scale; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) and (b). Production of films in 16 mm is both convenient and less expensive. To give a boost to the production of films in 16 mm format, the National Film Development Corporation has decided to set-up 16 mm infrastructure. Its capital cost would be Rs. 87 lakhs. Details of the equipment, both imported and indigenous, and their costs are given in the annexed statement. The Corporation will make available this equipment to film producers on reasonable hire charges. These facilities are expected to be ready by September-October, 1981.

Statement

Details of Equipment for the 16mm infrastructure of the National Film Development Corporation referred to in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 6660.

Sl. No.	Description of the equipment	Cost (in lakhs)
1	2	3
		Rs.
1.	Three 16 SR Arri Cameras with Zoom Lenses	12·00
2.	Two Steenbeck Editing Tables with accessories and spares	10·00
3.	Two Nagra Tape Recorders and spares	4·50
4.	"Magna-Tech" Recording & Dubbing Chain alongwith Optical Recording system with spares and accessories	39·00
5.	Four Synchronisers with picture facility	2·00
6.	Magnetic recording Tapes (500 Nos.)	2·5

1	2	3
7.	Various types of Microphones e.g. MKH 816 TU, D 900 C D 224 C C 24 etc.	1·2
8.	Lighting equipment, like colour tram sunguns and stands	0·4
9.	Splicers & Synchronisers	0·3
10.	Meltron ¼" Sync. Tape Recorder with spares and accessories	1·80
11.	Technical furniture like studio mixer table and twenty nos. of Theatre Chairs & Equipment rack	2·00
12.	Air-conditioning system with 2 X 7·5 Ton plants and ducting system	6 50
13.	Electrical fittings	0·80
14.	Accoustic Boards & Carpets for Recording Studio	2·00
15.	Wooden Partitions and Panel doors	0·80
16.	Delivery Van for transport of Cameras and Recorders within the city	1·20

T. V. Facility for Shriganga Nagar and Bikaner

6661. SHRI MANPHOOL SINGH CHAUDHARY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether microwave system is used for telecasting television programmes in the country;

(b) whether Shriganga Nagar and Bikaner, the border districts are proposed to be brought within the range of television through microwave system;

(c) if so, by what time,

(d) whether Shriganga Nagar District would be brought within the range of television after the Jullunder Television centre comes under full operation; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). There is no proposal to bring Shri Ganganagar and Bikaner under the TV. coverage during the Sixth Plan period (1980—85) due to constraints on resources.

(d) and (e). Programmes telecast from Jullundur Doordarshan Kendra are not likely to be received in Shri Ganganagar since it is outside the service range of Jullundur transmitter.

Offer by private parties to set up mini Power Plants

6662. SHRI S. M. KRISHNA. Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) which of the States and private parties have submitted plans for mini-power plant projects;

(b) whether his Ministry has since examined the feasibility and viability of such power plants planned by various States etc;

(c) if so, the outcome thereof and if not, the stage at which the matter stands;

(d) what would be the generating capacity of a mini power plant and the capital outlay involved; and

(e) whether these would be manufactured indigeneously or import of the entire plant or only a part thereof allowed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (d). Proposals for Mini hydro projects have been received from 9 States/Union Territories. The details regarding the installed capacity and the estimated cost of the schemes is given in Statement I. These schemes are under various stages of consideration. The feasibility and viability of such power plants are taken into consideration by the CEA at the time of clearing the proposals from the techno-economic angles. Proposals for small thermal schemes (unit size less than 25 MW) have been received from Assam, Sikkim and Andaman and Nicobar Islands. Statement II gives information regarding the capacity, estimated cost, and commissioning schedule of these thermal/diesel schemes. No proposal has been received from Private Sector, as utility, for setting up of Mini power plants.

(e) Import of generating equipment is resorted to only in cases where indigenous manufacturers are not in a position to supply the equipment.

Statement-I

MINI-HYDRO SCHEMES

Schemes	State/Union Territory	Installed Capacity	Estimated cost (Rs. in crores)
1	2	3	4
Kargil	J & K	3x500 KW	1·38
Dhumkhar . . .	J & K	4x500 KW	1·90
Holi	M.P.	3x1,500 KW	3·425
Mt. Abu . . .	Rajasthan	2x1,250 KW	5·16
Thirot	H.P.	3x1000, KW	4·16
Pykara Dam Power House	Tamil Nadu	1x2,000 KW	1·45
Bordikarai . . .	Assam	3x250 KW	1·93
Booning	Manipur	2x500 KW	0·897
Maharani . . .	Tripura	2x500 KW	1·67
Sessa Nallah . . .	Arunachal Pradesh	3x500 KW	0·91
Serului	Mizoram	1x500 L 2x250 KW	0·5079

Of the schemes mentioned above the scheme at Maharani has been techno-economically cleared by Central Electricity Authority. The other schemes are under various stages of examination by the CEA.

Statement-II

SMALL THERMAL SCHEMES

Sl.	Name of the Scheme	Name of the Stal/ Territory	Capacity	Estimated cost (Rs. in Crores)	Commissioning SCHEME
1.	Coal based thermal Power Station	A&N Island	2x5 MW	9·84	1985-86
2.	Lakwa Gas Turbine sets .	Assam	3x15 MW	15·64	1981-82
3.	Waste Heat Utilisation Plant at Namrup . . .	Assam	1x22 MW	9·02	1981-82
4.	Mobile Gas Turbine sets .	Assam	2x3 MW	4·28	1981-82
5.	Additional Mobile Gas Turbine sets . . .	Assam	4x3 MW	7·64	1981-82
6.	Diesel Generating Sets .	Sikkim	4x562·5 KVA	1·18	1981-82

All the above schemes has been cleared by CEA and sanctioned. These are under various stages of implementation.

Drillings for oil and Gas by O.N.G.C. in West Bengal

6663. SHRI R. P. DAS: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) how many wells are being drilled at present in West Bengal by O.N.G.C.; and

(b) the reasons as to why the O.N.G.C. and other companies have so far failed to find out gas or oil after a considerable period of exploration work in West Bengal?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) At present ONGC is drilling only one well namely Abhay-1 in Nadia district in West Bengal.

(b) The exploratory drilling operations carried out by Indo-Stanvac Petroleum Project and ONGC have not resulted in the location of commercial reserves of hydrocarbons in West Bengal, as the exploration had so far been carried out on the basis of the development of the basin in simple marine conditions which is the normal process of exploration in a virgin area. However, the data obtained has indicated that exploration targets are likely to be in the deltaic conditions of the basin development where hydrocarbons entrapment conditions are much more subtle and complicated. The search in such difficult hydrocarbon traps calls for much sophistication in geophysical data acquisition, processing and interpretation besides a thorough understanding of the development of the basin under deltaic conditions. ONGC has been progressively introducing such sophistication in the exploration of West Bengal basin and this has helped in narrowing down the range of exploration targets. The process is continuing.

Legal aid to the poor in Andhra Pradesh

6664. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Centre is increasing legal aid given to the poor; and

(b) whether Centre assured to give Rs. 25 lakhs to Andhra Pradesh Government if it provided an equal amount for legal aid to the poor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) The Central Government made a provision of Rs. 25 lakhs for legal aid in the budget for the year 1980-81. In the budget for the year 1981-82 the provision for legal aid has been raised from Rs. 25 lakhs to Rs. 50 lakhs.

(b) No, Sir.

Setting up of coal-based Fertilizer Plants during sixth Five Year Plan

6665. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether any more coal-based fertilizer plants on the pattern of the Korba Project or otherwise are proposed to be set up under the Sixth Five Year Plan; and

(b) if so, the details in this regard indicating the location or possible location thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b): There is a provision for start of work on a coal based fertilizer plant during the 6th Plan period. However, the question of setting up any coal based fertilizer plants in the country can be decided by Government only after the techno-economic viability of such plants is established by the experience of operating the recently commissioned Talcher and Ramagundam plants for some time.

Public Deposits Raised by M/s. Pure Drinks (New Delhi) Limited

6666. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether during late 1979 or early 1980 Pure Drinks (New Delhi) Limited has asked for public deposits;

(b) whether it is mandatory to give the last 3 years profit figures;

(c) if so, for which 3 years do they have to give the profit figures on the application forms for fixed deposits;

(d) whether it is a fact that they have omitted the figures for 1977-78; and

(e) if so, what action is proposed?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) Yes, Sir. The company published an advertisement on 9th February, 1980, inviting deposits from public.

(b) Yes, Sir.

(c) In terms of Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 the non-banking non-financial companies inviting deposits from public are required to indicate in the advertisement, the profits of the company, before and after making provisions for tax, for three financial years immediately preceding the date of advertisement. These particulars alongwith all changes in relation to such particulars upto the date on which the invitation for deposits is issued by the company are also required to be incorporated in a statement accompanying the said form.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में हत्या के अनिर्णीत मुकदमे

6667. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हत्या के मुकदमों की संख्या कितनी है और साथ ही गत दो वर्षों से इस तरह की विचाराधीन पड़ी अपीलों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उनके अनिर्णीत रहने के क्या कारण हैं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों से उस न्यायालय में हत्या के 12 ऐसे मामले लम्बित हैं जिनमें दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील की गई है और ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें दोषसिद्धी के विरुद्ध अपील की गई हो । दो वर्षों से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम समय से लम्बित अपीलों की संख्या 12 है । इनमें से 10 अपीलें दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपीलें हैं और दो दोषसिद्धि के विरुद्ध ।

(ख) उच्च न्यायालय कुल कार्यभार को देखते हुए वह क्रम निर्धारित करता है जिसके अनुसार अलग अलग मामले विचार हेतु लिए जाते हैं और उनका निपटारा किया जाता है ।

Persons belonging to SCs/STs Selected as programme Executives

6668. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) how many candidates belonging to Scheduled Castes have been selected to the post of Programme Executive in All India Radio for the last ten years;

(b) is it not a fact that all the posts Programme Executive as per advertisement are not being filled in the All India Radio; and

(c) if so, what is the reason for that?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) Sixty candidates belonging to Scheduled Castes community have been selected for the post of Programme Executives through Union Public Service Commission during the last ten years.

(b) It is true that sometimes all the posts reserved and advertised for Scheduled Castes are not filled up because sufficient number of suitable candidates are not available. However, in such cases, the vacancies so reserved are carried forward.

(c) This happens because adequate number of candidates belonging to these Castes are not selected and recommended by Union Public Service Commission.

Trade Agreement with Bulgaria

6669. SHRI N. K. SHEJWALKAR: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under a recent trade agreement with Bulgaria, two lakhs tonnes of diesel oil is going to be imported into India from that country;

(b) if so, what are consideration for getting petroleum products from Bulgaria which herself imports from USSR;

(c) the reasons why that quantity of petroleum products is not got direct from USSR when USSR herself is prepared to supply this quantity to Bulgaria; and

(d) are the prices that we are going to pay to Bulgaria for import of petroleum products at par with those prevailing among Eastern European Socialistic countries or at par with the International Price?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) An agreement has been signed by Indian Oil Corporation with Bulgaria for import of 2 lakhs tonnes of diesel oil.

(b) to (d): It would not be in public interest, as also contrary to international practices to disclose further details in this regard.

गाजियाबाद में खाना पकाने कि गैस के सिलैन्डरों की सप्लाई

6670. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद में खाना पकाने की गैस का सिलेण्डर प्राप्त करने में दो महीने का समय लगता है ;

(ख) क्या जांच में यह पता लगा है कि गैस सिलेंडरों को ऊंची कीमत पर अनधिकृत उपभोक्ताओं को बेच दिया जाता है ;

(ग) क्या एजेंसियों के लाइसेंसों में से एक लाइसेंस को लगभग एक वर्ष पूर्व रद्द कर दिया गया था और यदि हां, तो किसी अन्य फर्म को एजेंसी न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या गाजियाबाद में गैस के कनेक्शन की संख्या को देखते ए यह आवश्यक है कि नई फर्मों को लाइसेंस दिए जाएं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 15-3-1981 को गाजियाबाद शहर में खाना पकाने की गैस की सप्लाई में लगभग 18 से 20 दिन तक की सप्लाई बकाया होने की सूचना दी गई है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस क्षेत्र में इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा एक डीलरशिप निलम्बित की गई है । क्योंकि अभी तक डीलरशिप समाप्त नहीं की गई है अत: किसी अन्य फर्म को एजेंसी के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यह समझा गया है कि गाजियाबाद क्षेत्र में अतिरिक्त इण्डेन डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति के औचित्य के लिए खाना पकाने की गैस की पर्याप्त मांग है । तदनुसार इंडियन आयल कार्पोरेशन की 1981-82 के दौरान और तीन वितरकों की नियुक्ति करने की योजना है ।

पश्चिमी राजस्थान म 290 मैगावाट क तापीय बिजली घर का स्थापना करना

6672. **श्री अशोक गहलोत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी राजस्थान में 200 मेगावाट के तापीय बिजली घर की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) . पश्चिमी राजस्थान में 200 मेगावाट का एक ताप विद्युत केन्द्र

स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 6738 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर, पालना में 2×60 मेगावाट की क्षमता का, लिगनाइट पर आधारित एक विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुआ है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इसे तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी है और निवेश संबंधी निर्णय की प्रतीक्षा है।

कोयले की सप्लाई न दिए जाने के कारण मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों का बन्द होना

6673. श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को कोयले का इसका नवीनतम कोटा अभी तय नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में कपड़ा मिलें बन्द होने की स्थिति में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)

(क) और (ख) . कोयले के परिवहन के लिए रेल वैगन पर्याप्त संख्या में नहीं मिलने के कारण मध्य प्रदेश की कपड़ा मिलों को कोयले की सप्लाई में कुछ कमी रही है। कोल इंडिया लि० कोयला भेजने के लिए वैगनों की उपलब्धि बढ़ाने की दृष्टि से रेलवे के साथ लगातार सम्पर्क रखे हुए हैं। वैगनों की उपलब्धि में दिसम्बर 1980 से सुधार हुआ है। कोयला कंपनियां रेल द्वारा कोयले के परिवहन में होने वाली कमी को सड़क से ले जाने के लिये कोयला देकर भी पूरा कर देती हैं। इसके अलावा कुछ निर्धारित खानों से कोयला बिना किसी प्रतिबंध के भी दिया जा रहा है। कोयले की कुल मांग पूरी करने के लिए खान मुहानों पर पर्याप्त कोयला उपलब्ध है।

Setting up of a Soda Ash Plant in Bihar

6674. SHRI N. E. HORO: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to set up a soda ash plant in the State of Bihar; and

(b) if so, the details regarding its location and the time by when it is likely to be set up?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Survey in Arunachal Pradesh

6675. SHRI DAULAT SINHJI JADEJA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether a survey has been conducted at Dalbuing in Arunachal Pradesh for oil exploration;

(b) what are the findings;

(c) whether any other survey has been conducted in Arunachal Pradesh; and

(d) the result achieved?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). Oil India has conducted surveys in Ningru Petroleum Exploration Licence area in Arunachal Pradesh. The above surveys have helped in delineating a number of prospective structures where ten exploratory wells have so far been drilled in Kharsang, Shongking, Manabum and

Kumchai areas. Oil has been encountered in six of these wells in the Kharsang area.

Inspection/Investigations pending under Companies Act.

6676. SHRI R. PRABHU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many inspections/investigations under the Companies Act ordered for more than 5 years ago are still pending;

(b) if so, the names of these companies and the dates on which these inspections/investigations were ordered, and

(c) when these inspections/investigations are likely to be completed?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) Inspections in the case of 39 companies and investigations in the case of 4 companies ordered more than 5 years ago are pending.

(b) A statement showing the names of these companies and dates when ordered is attached.

(c) Keeping in view the limited number of staff and officers available for inspection and other official exigencies, it may take about 6 to 12 months to complete the pending 39 inspections.

As for pending investigations, (a) above these cases have been stayed under court orders and are still subjudice.

Statement

A INSPECTION CASES:

S. No.	Name of the Company	Inspection Ordered on
1.	Mohanvi Corporation Limited	21-9-66
2.	Shalimar Works Limited	26-5-72
3.	Universal Bank of India	27-5-72
4.	Kothari Trading & Investment Co. Pvt. Ltd.	8-8-73
5.	Arth Udyog Limited	20-9-74
6.	Pioneer Builders Limited	20-9-74
7.	Coal Shipments Limited	20-9-74
8.	Dangua Jhar Tea Company Limited	19-2-75
9.	Lebon Tea Company Limited	19-2-75
10.	Leesh River Tea Company Limited	19-2-75
11.	Marybong & Kyel Tea Company Limited	19-2-75
12.	Meenglass Tea Company Limited	19-2-75
13.	Isabheel Tea Company Limited	9-5-75
14.	Dolie Tea Company Limited	9-5-75
15.	Shree Rama Sugars & Industries Ltd.	20-4-74
16.	Giovanola Binny Limited	20-4-74
17.	Premier Instrument and Contractors Ltd.	8-8-74

S. No.	Name of the Company	Inspection ordered on
18.	Sri Visalam Chit Funds Ltd.	18-2-75
19.	Co' solidated Coffee Ltd.	14-5-75
20.	Deven Tea & Produce Company Ltd.	19-7-75
21.	Belanoor Tea and Rubber Co. Ltd.	19-7-75
22.	Baverly Estates Limited	19-7-75
23.	Varaja Laxmi Mills Ltd.	9-10-75
24.	Sri Rani Laxmi Ginning Spg. & Wvg. Mills Ltd.	9-10-75
25.	Arcot Mills Ltd.	9-10-75
26.	Ayyappan Textiles Ltd.	9-10-75
27.	Coimbatore Mahaluxmi Agencies Pvt. Ltd.	9-10-75
28.	Bundy Tubing of India Limited	30-10-75
29.	Vaiyithri Plantation Limited	30-10-75
30.	Mineral & Mining Co. Pvt. Ltd.	30-10-75
31.	Amalgamation Limited	6-2-76
32.	Bimetal Company Limited	6-2-76
33.	L.M. Van Mopps Diamond Tools (I) Ltd.	6-2-76
34.	Simpson & Company Limited	6-2-76
35.	T. Stanes & Company Limited	6-2-76
36.	Endeavour Investments Pvt. Ltd.	21-2-76
37.	Sound Zeward Union (India) Pvt. Ltd.	7-7-74
38.	N.S.H. Business Machines Limited	8-4-75
39.	Electronics & Computors (I) Ltd.	8-4-75
B.	INVESTIGATION CASES:	
1.	Hindustan Development Corporation Ltd.	4-9-75
2.	Ashoka Cement Limited	11-12-75
3.	Sudershan Trading Company Limited	31-12-73
4.	J.C. Mills Limited	7-12-67

Long term Programme for Oil Exploration

6677. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state details and main features of long-term programme for oil exploration in India with the assistance of U.S.S.R?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): The main features of the long-term programme on economic and technical cooperation of December 10, 1980 between the Government of India and the Soviet Union, are:—

(i) The Techno-economic Perspective plan, which is being currently prepared by Soviet and Indian specialists for exploration of onshore oil and natural gas reserves in India for 1981-1990 would be completed in the third quarter of 1981. Based on the results of the above plan, organisations of the two sides would study the possibilities of expansion of cooperation in the field of oil industry.

(ii) The Soviet side would render cooperation to the Indian side, in the execution, in one of the promising onshore areas in India, of integrated work for oil and gas including geophysical exploration and drilling work, elaboration of basic technical concepts of development of the deposits and installation of production facilities.

(iii) The Soviet side would render cooperation to the Indian side in execution of works connected with increase of oil production from shut down and low productivity wells.

To-day in Parliament

6678. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the names of the languages in which the programme 'TODAY IN PARLIAMENT' is broadcast, as also the names of the All India Radio Stations from which it is broadcast;

(b) whether the programme is proposed to be broadcast in more 'regional' languages and dialects so as to make it more accessible to the rural masses; and

(c) if so, the likely date by which this would be done and the languages/dialects selected for this purpose?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN JOSHI): (a) A daily review of Parliamentary Proceedings is being broadcast in English and Hindi from Delhi Station of AIR i.e. 'Today in Parliament' and 'Sansad Sameeksha' (Hindi counterpart of 'Today in Parliament'). Eighty one Programme Originating Stations of All India Radio are relaying this programme, a list of which is given in the enclosed statement.

(b) No, Sir. Broadcasting a daily review of Parliamentary Proceedings in Regional languages on the lines of 'Today in Parliament' is not feasible due to constraints of resources.

(c) Does not arise.

Statement

List of Programme Orginating Centres of A.I.R.

1. Agartala	5. Ambikapur	9. Bhadravati
2. Ahmedabad	6. Aurangabad	10. Bhagalpur
3. Aizawl	7. Bangalore	11. Bhopal
4. Allahabad	8. Baroda	12. Bhuj

List of Programme Orginating Centre of AIR

13. Bikaner
14. Bombay
15. Calcutta
16. Calicut
17. Chhatarpur
18. Coimbatore
19. Cuddapah
20. Cuttack
21. Darbhanga
22. Delhi
23. Dharwar
24. Dibrugarh
25. Gauhati
26. Gorakhpur
27. Gulbarga
28. Gwalior
29. Hyderabad
30. Imphal
31. Indore
32. Jabalpur
33. Jagdalpur
34. Jaipur.
35. Jalgaon
36. Jammu
37. Jeypore
38. Jodhpur
39. Jullundur
40. Kohima
41. Kurseong
42. Leh
43. Lucknow
44. Madras
45. Mangalore
46. Mathura
47. Mysore
48. Nagpur
49. Najibabad
50. Panaji
51. Parbhani
52. Passighat
53. Patna
54. Pondicherry
55. Pune
56. Port Blair
57. Raipur
58. Rajkot
59. Rampur
60. Ranchi
61. Rewa
62. Ratnagiri
63. Rohtak
64. Sambhalpur
65. Sangli
66. Silchar
67. Siliguri
68. Simla
69. Shillong
70. Srinagar
71. Twang
72. Tezu
73. Tiruchirapalli
74. Tirunelvelli
75. Trichur
76. Trivandrum
77. Udaipur
78. Varanasi
79. Vijayawada
80. Visakhapatnam
81. Suratgarh.

Units of Songs and Drama Division

6679. SHRI NARAIN CHAND PRASHAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the names of the places, Statewise where the units of the "Song and Drama Division" are located;

(b) whether any demand has been received by Government from the State Government/representatives of the people like M.P.s/M.L.As. for opening more units of this Division in their region; and

(c) if so, the decision of the Government in this regard and the likely dates by which the units would be opened?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) A statement is attached.

(b) and (c): Yes, Sir. It has not, however, become so far possible to accede to these demands in view of financial and other constraints.

Statement

The names of Places, State-wise where the offices/Units of song and Drama Division are located.

S. No.	Name of the State/Union Territory	Place where the office/unit is located
1.	Andhra Pradesh.	Hyderabad
2.	Assam	Gauhati and Imphal
3.	Bihar	Patna and Darbhanga
4.	Delhi	Delhi (Delhi Region and Headquarter Office)
5.	Himachal Pradesh	Simla
6.	Jammu and Kashmir	Srinagar
7.	Madhya Pradesh	Bhopal
8.	Karnataka	Bangalore
9.	Orissa	Bhubaneshwar
10.	Punjab, Haryana and Chandigarh	Chandigarh
11.	Rajasthan	Jodhpur
12.	Tamil Nadu	Madras
13.	Uttar Pradesh	Lucknow and Nainital
14.	West Bengal	Calcutta
15.	Maharashtra	Pune

Report of the Chairman, UP Electricity Board

6680. SHRI R. N. RAKESH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether any report by the Chairman of the Uttar Pradesh Electricity Board was submitted to the Central Government giving details of the impending bankruptcy of the Electricity Board; and

(b) if so, the details thereof and reaction of Central Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a): No, Sir.

(b) The question does not arise.

Ghataprabha and Kabini Hydro-Electric Projects in Karnataka

6681. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government of Karnataka have approached the Central Government regarding the clearance of the Ghataprabha and Kabini Hydro-electric Projects; and

(b) if so, reaction of Union Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). The Ghataprabha Hydel Scheme (2x16 MW) has been techno-economically approved by Central Electricity Authority and has been recommended to the Planning Commission for investment decision.

The Project report of Kabini Hydel Scheme (1x20 MW) received in September, 1979, has been examined in Central Electricity Authority/Central Water Commission and comments sent to Project authorities. Replies to these comments are awaited from Project authorities. This scheme will be cleared by Central Electricity authority after its technical and economic feasibility is estblished.

Television Adventure Serial

6682. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether an agreement has been signed with a French Company to make a television adventure serial the "New Indian trunk"; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) An agreement has been signed by NFDC, Bombay, with French Company, M/s. Technison or Paris, for co-production of a feature film "New Indian Trunk".

(b) The details of the agreement are as follows:—

(1) National Film Development Corporation will invest a sum of Rs. 8.00 lakhs for meeting part of the expenditure required to be incurred in connection with the shooting of this film in India. This amount will be utilised for the following items:—

(a) Tickets and freight vouchers or AIR India,

(b) Expenses of production in the country;

(c) Payment in rupees to Indian technicians hired for production of Indian part of the serial.

(2) Against this investment of Rs. 8.00 lakhs, NFDC will be entitled to 15 per cent share of net revenue, earned by screening of the film on one transmission channel, for a period of 2 years.

Retention of foreign equity by drug multinational companies

6683. SHRI B. V. DESAI: Will the Minister of PETROLEUMA CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Union Govt. have taken a final decision that barring two companies no other drug multinational may be allowed to retain 74 per cent foreign equity and if so, which are the two companies;

(b) whether Union Govt. have recived the equity dilution formula which was being worked out by the FERA Committee and if so, what are their recommendations;

(c) whether a final decision on Glaxo has been taken and if so, in how many cases the action has to be taken; and

(d) whether under this, most drug companies will have to dilute their foreign equity to a level between 50 to 60 per cent and if so, how many drug companies have done this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICAL AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d). Cases of 20 foreign drug companies, as per enclosed statement, for fixing level of equity under Foreign Exchange Regulation Act are yet to be decided. Reserve Bank of India have collected detailed data from these companies in respect of bulk drugs and formulations manufactured by them during the 3 year period ending 31-3-77. In view of the above, it is premature to say anything about the level of foreign equity that may be eventually allowed in individual cases.

Statement

1. M/s. Burroughs Wellcome & Company.
2. M/s. Mey & Baker (I) Limited.
3. M/s. Roche Products.
4. M/s. Parke Davis.
5. M/s. Glaxo Laboratories.
6. M/s. Johnson & Johnson Ltd.
7. M/s. Pfizer Limited.
8. M/s. Ciba Geigy of India Ltd.
9. M/s. E. Merck (I) Pvt. Ltd.
10. M/s. Merck Sharp & Dhome.
11. M/s. Sondoz (India) Limited.
12. M/s. Boots Co. (India) Ltd.
13. M/s. Hoechst Pharmaceuticals Ltd.
14. M/s. Warner Hindustan Ltd.
15. M/s. Organon India Limited.
16. M/s. Uni-Sankyo.
17. M/s. Hyeth Laboratories.
18. M/s. Bayer (India) Limited.
19. M/s. Cynamid India Limited.
20. M/s. Alakali Chemicals.

Purchase of shoe from organised sector

6685. DR. A. U. AZMI: Will the Minister of SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the value of leather shoes and other footwear purchased by the D.G.S.&D. from the organised sector like Bata and the small sector during 1980-81;

(b) the manner in which such purchases were made;

(c) whether it is a fact that the Bata only puts its stamp on the shoes which they purchase from small sector in Agra and other places; and

(d) if so, what is margin of profit kept by the Bata (India) Ltd. in such purchases and supply to Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) The value of orders placed on Bata (India)) Ltd., other large scale units, and small scale sector during the period 1980-81 is given below:—

Purchase from Bata	Purchase from SSI Unit	Purchase from othe large scal sector
Rs. 2,09,17,274	Rs. 6,69,72,456	Rs. 35,00,000

(b) Purchases from both the large-scale sector and the small scale sector are through the regular tender system followed by DGS&D.

(c) In respect of contracts entered into by DGS&D with Bata (India) Ltd., there is no information available that Bata purchases shoes from small scale sector and puts its stamp.

(d) Does not arise in view of answer at part (c) above.

Names of Power Projects in U.P. and H.P.

6686. SHRI JITENDRA PRASAD: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the names of power projects in Uttar Pradesh and Himachal Pradesh together with generation capacity of each of them;

(b) the installed capacity of each power station and the power actually generated during the last one year; and

(c) the reasons if any, for less generation of power against the installed capacity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). A statement showing the names of the power stations in UP and Himachal

Pradesh, their installed capacity, installed generating capacity and gross energy generation during 1980-81 is attached.

(c) The performance of hydro projects depends on the design potential of the project and the availability of water for generation. The generation from thermal power stations in U.P. during the year 1980-81 has been somewhat less due to higher forced outages of the generating units and lower generation during the stabilization period of the newly commissioned generating units. But it is now improving.

STATEMENT

Details about installed capacity installed generation capacity and gross energy generation during 1980-81 of power projects in Himachal Pradesh and Uttar Pradesh

S. No.	State/Station	Installed Capacity (MW)	Installed generating capacity (Derated) (MW)	Gross Energy generation during 1980-81 * (Million Units)	
1	2	3	4	5	
I. Himachal Pradesh					
	A. *Thermal*				
	Small diesel stations	2·51	2·51	0·03	(Gen. fig. for 79-80)
	B. *Hydro*				
1.	Giri Bata	60	60	73	
2.	Bassi	60	60	149	
3.	Baira Siul (Central Sector)	120	120	31	
4.	Small Hydro	6·02	6·02	18	(Gen. fig for 79-80)
		246·02	246·02	271	
II.	*Uttar Pradesh*				
	A. *Thermal*				
1.	Obra	1350	1350	4001	(1 unit of 200 MW commissioned on 28/3/81)
2.	H. Ganj	480	480	1142	
3.	Panki	284	281	1204	

1	2	3	4	7	
4.	R.P.H. (Kanpur)	75	65	134	
5.	Renusagar	125	125	1011	
6.	Small thermal**	146·6	131	230	
		2460·6	2432	7722	
B.	*Hydro*				
1.	Rihand	300	300	935	
2.	Yamuna	354·8	354·8	1259	
3.	Obra (H)	99	99	316	
4.	Ganga Canal	45·2	45·2	196	
5.	Matatila	30	30	129	
6.	Ram Ganga	198	198	327	
7.	Khatima	41·4	41·4	168	
8.	Chilla	108	108	244	
9.	Small Hydro	7·59	7·59	9·50	(Gen. Fig. for 79-80)
	Total hydro :	1183·99	1183·99	3493·50	
	Total Th.+Hydro (U.P.)	3644·59	3615·99	11205·50	

*Tentative

**Does not include small diesel generating units.

सस्कृत में रेडिटो कार्यक्रम

6687. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से संस्कृत में प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों के नाम क्या हैं और प्रत्येक की अवधि क्या है ;

(ख) संस्कृत के कौन-कौन से कार्यक्रम प्रसारित होते थे और उन्हें बन्द कर देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या संस्कृत कार्यक्रमों को बढ़ाये जाने तथा उनके समय में वृद्धि करने को कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बो० एम० जोशी) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

राज्य विद्युत बोर्डों की संख्या

6688. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य विद्युत बोर्डों की संख्या क्या है और उनमें से ऐसे बोर्डों की संख्या क्या है जिनके अध्यक्ष गैर-तकनीकी अथवा गैर-इंजीनियर लोग हैं ; और

(ख) विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन केन्द्रों की स्थापित क्षमता और वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है तथा इस क्षमता का कम उपयोग किये जाने के लिए मुख्य कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा 18 राज्य बिजली बोर्डों का गठन किया गया है। इनमें से, 7 राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्ष गैर-इंजीनियर है ।

(ख) जनवरी, 1981 की अवधि की प्रतिष्ठापित क्षमता, तथा महीनेवार सकल उत्पादन (ताप विद्युत् तथा न्यूक्लीय) तथा जल-विद्युत उत्पादन को दिखाने वाला विवरण (सभा पटल पर रखा गया। ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एलटी-2327/81) तापविद्युत् केन्द्रों का घटिया कार्य-निष्पादन मुख्यत: निम्न कारणों से रहा है:—

(1) स्वदेशी तौर पर निर्मित मुख्य संयंत्र और आनुषंगिकों से युक्त प्रतिष्ठापित क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि विशेष रूप से 200–200 मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता की 13 यूनिटें, जो सुस्थिर होने में पर्याप्त समय ले रही हैं और अधिकांश मामलों में वे कार्य-निष्पादन के अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची हैं ।

(2) बार-बार और लंबी अवधि की जबरन बन्दी की घटनाएं होना तथा कुछ यूनिटों द्वारा लंबी अवधि तक निर्धारित उत्पादन न कर पाना। स्टेशन ले आउट और डिजाइन संबंधी दोष तथा निर्माण, प्रतिष्ठापना और चालू करने में गुणवत्ता संबंधी आश्वासन की कमी के कारण होने वाली बन्दियां इनमें शामिल हैं ।

(3) बड़े यूनिटों के लिए अनुरक्षण प्रबन्ध का स्तर घटिया होना तथा इनके लिए देश में सुविज्ञता की कमी । यह मुख्य रूप से, आधुनिक प्रणाली पर आधारित, पर्याप्त और उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव के कारण हैं ।

(4) समय पर और अपेक्षित गुणवत्ता के फुटकर पुर्जे सप्लाई करने में स्वदेशी निर्माताओं द्वारा देरी की जाना ।

(5) अभिकल्प विशिष्टियों के चरणों में विभिन्न निवेशों के संबंध में अपनाए गए कोयले के पैरामीटरों में तथा वास्तव में सप्लाई किए गए कोयले के वास्तविक पैरामीटरों के बीच विभिन्नता ।

(6) ताप विद्युत् केन्द्रों पर कोयले का स्टाक न होने पर/अत्यन्त कम स्टाक होने के कारण उत्पादन कम किये जाने से उत्पादन में कमी ।

(7) आनुषंगिक उपस्कर की आंशिक अनुपलब्धता अधिक होना तथा ग्रिड की परिस्थितियों और भार स्वरूप आदि जैसी प्रचालन संबंधी अन्य आंतरिक और बाह्य बाधायें जिनके परिणाम-स्वरूप संयंत्र भार अनुपात कम रहा ।

(8) क्षमता में वृद्धि से प्रणाली में व्यस्ततम भार उठाने के लिए उपलब्धता में वृद्धि हुई परन्तु इसी के साथ अव्यस्ततमकाल के दौरान समुपयोजन न किए जाने में भी वृद्धि होना और इस प्रकार बेकार क्षमता में भी वृद्धि होना ।

(9) उपभोक्ताओं द्वारा घटिया समुपयोजन उपस्कर प्रतिष्ठापित करना । इसका एक ऐसा उदाहरण है कृषि पंप सैटों

की घटिया गुणवत्ता । उपभोक्ताओं द्वारा या राज्य बिजली बोर्डों द्वारा पावर फैक्टर करेक्शन उपस्कर न लगाये जाने से यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है । यह भी उल्लेखनीय है कि 1977–80 की तीन वर्षों की अवधि में तीन विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में कमी हुई थी लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर गहन प्रयास किए जाने के परिणाम स्वरूप क्षमता समुपयोजन में हाल ही के महीनों के दौरान, विशेषकर अक्तूबर, 1980 से पर्याप्त वृद्धि देखी गई है ।

Superior quality of Steel Grade Coal in Abandoned Mines of Giridih in Bihar

6689. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the abandoned mines of Giridih in Bihar have got superior quality of Steel grade coal of about ten millions of tonnes;

(b) whether this coal is better and cheaper than the imported steel grade coal;

(c) whether it is proposed to reactivate the abandoned Giridih Mines to bring out coal for steel Mills even by subsidising the mining;

(d) if so, details thereabout; and

(e) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) These mines were abandoned on the general exhaustion of reserves. There is no firm estimate of the reserves left behind. In any case all the coal left unworked in the abandoned mines is not coking coal.

(b) Imported coal has got much lower ash content. When the mines were abandoned production cost was far higher than the selling price.

(c) and (d). The coal company is studying plans of all the abandoned properties to consider the feasibility of mining the small reserves left unworked in patches before the abandonment of mines.

(e) Does not arise.

F.M. System

6690. SHRI RAJESH PILOT: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are considering to introduce F.M. system as an experimental measure;

(b) if so, details; and

(c) if not, reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) to (c). FM service has already been started in the country. The service at Madras was commissioned in July 1977 and at Bombay and Calcutta last year. FM service at Delhi is likely to start in the next year.

Intensification of T.V. programmes regarding family welfare

6691. SHRI RAJESH PILOT: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the Government are taking any steps to intensify the drive for family planning through interesting T.V. programmes; and

(b) if so, what initiative has been taken to invite such write ups and features from amongst students and amateur writers through some competitions?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) Yes, Sir.

(b) A proposal to invite scripts through competitions, is under consideration of the Government.

Expenditure incurred on National Hydro-electric Power Corporation

6692. SHRI RAJESH PILOT: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what has been total expenditure incurred on National Hydro-electric Power Corporation during last 3 years;

(b) what has been its contribution in terms of new projects prepared, processed and executed; and

(c) what steps have been taken to give priority to hydropower generation through crash programmes during the last 3 years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) A statement of expenditure during the last three years in respect of projects under execution is given below:

year	Expenditure Rs. Lakhs Anticipated	Actual
1978-79	4543·88	4990·68
1979-80	5085·12	5663·62
1980-81	7258·66	8251·57

(b) The position is indicated below:

ONGOING PROJECTS

1. *Loktak* (3x35 *MW*)—*Manipur.*

The project is expected to be completed by December, 1982. Due to the disturbed conditions in the region there has been a set-back in the transport and communication facilities disrupting supply of materials like cement, steel, fuel, etc. to the project.

2. *Baira-Siul* (3x60 *MW*)—*H.P.*

Efforts are being made to complete Stage II by end of December 1981. Six months ahead of schedule.

3. *Salal* (3x115 *MW*)— *J & K.*

After considerable lapse of time, the project has now picked up and has reached a stage of sustained construction activity. Between December, 1980 and March 1981, river diversion works were taken up and completed in record time, thus contributing to a saving of nearly six months in the overall schedule of the project. A detailed exercise to accelerate the execution of the project and advance its completion by one year is being undertaken.

4. *Devighat* (3x4.7 *MW*)—*Nepal.*

The project is being constructed under the Indo-Nepal Cooperation Programme on behalf of HMG Nepal. It is expected to be completed by December 1983.

NEW PROJECTS

1. *Koel-Karo* (710 *MW*)—*Bihar.*
2. *Dul-Hasti* (390 *MW*)—*J & K.*

Both these projects are awaiting formal approval of the Cabinet. In the meantime, all preparatory action has been taken

3. *Chamera Investigation (640 MW)—H.P.*

Work on investigation of this project has commenced, and is expected to be completed in 8-10 months.

(c) In pursuance of Government's policy, to give emphasis to the exploitation of the country's hydel potential, it has been decided to entrust large hydro projects, involving heavy investment and deployment of trained personnel, to the NHPC for execution. NHPC is being adequately strengthened and streamlined to meet its increasing responsibilities. The Ministry is also holding discussions with States, in which projects are held up on account of inter-state issues, with a view to resolving such issues. NHPC has also been instructed to take up the investigation of hydro projects on modern lines with a view to completing them in the shortest possible time, and keeping ready a shelf of projects with a view to having a sustained programme of construction.

Scheme to encourage Production of Petrochemicals and Fertilizers with help of University

6693. SHRI RAJESH PILOT: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have developed any plans to encourage production of petrochemical and fertilizers as a small scale with the help of University and college departments producing post graduates and Ph.D.'s;

(b) whether such production process will be linked to the syllabus will be encouraged as a part of vocationalisation and self employment orientation; and

(c) if so, details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) No, Sir. However industries based on petrochemicals such as plastic processed goods, plasticizers etc. are being encouraged in small scale sector. The entrepreneurs including university graduates and post graduates are getting help from Government agencies to take up these industries.

(b) and (c). Does not arise.

Projection of Country"s Picture by Press

6694. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Press is not giving a correct picture of the country; and

(b) if so, the steps taken by Government to suggest the press to give correct picture of our country through newspapers?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b). The Indian Press is completely free and the Government is committed to the freedom of the Press. The newspapers have full liberty in the matter of collection, presentation and comments on news etc. In doing so, the Press is expected to ensure objectivity, accuracy and fairness of reporting as part of their professional ethics. However, tendency towards un-informed reporting or sensationalisation of news are at times noticed in the Indian Press. Such tendencies are attempted to be corrected within the laws of the land by issue of contradictions, clarifications, Press briefings etc. as part of Press Information Bureau's normal day-to-day activities. Besides official handouts and feature articles, newsmen are provided opportunities to see for themselves the various projects in progress. On important occasions, press conferences are organised and the newsmen are invited to important functions so that they have the information direct from the source.

Recently, the Minister of Information and Broadcasting took the initiative of briefing the newsmen in groups

on various achievements of the Government of India as a whole. The arrangement has been working quite successfully.

Production of Molasses

6695. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is the total production of molasses in the country;

(b) at what price molasses are sold by Government;

(c) is it also a fact that purchasers of the molasses are making huge profits; and

(d) if so, why Government are not increasing the prices of molasses?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) As reported by the State Governments at the Meeting of the Central Molasses Board, the total production of molasses in the country, in the molasses year 1980-81 (Nov.-Oct.), is estimated to be 20.79 lakhs tonnes.

(b) Molasses is not sold by Government but by sugar factories. Molasses is subject to statutory price control. The maximum prices at which molasses can be sold is fixed under the Molasses Control Order, 1961, as amended from time to time.

The Maximum prices prevailing at present are as under:—

Grade of molasses	*Price*
Grade K-I	
Total reducing sugar by weight above 60 per cent.	Rs. 9 per 100 kilograms
Grade K-II	
Total reducing sugar by weight from 55 to 60 per cent	Rs. 7.50 per 100 kilograms
Grade K-III	
As per specification Grade I cane molasses	Rs. 6 per 100 kilograms
Grade K-IV	
As per specification of Grade II cane molasses	Rs. 4.80 per 100 kilograms
Grade K-V	
As per specification of Gr. III cane molasses	Rs. 3.60 per 100 kilograms
Below grade K-V	Rs. 3.60 for every 40 kilograms reducing sugar content therein
Grade I	Rs. 6 per 100 kilograms
Grade II	Rs. 4.80 per 100 kilograms
Grade III	Rs. 3.60 per 100 kilograms
Below Grade III	Rs. 3.60 for every 40 kilograms reducing sugar content therein

The above prices are exclusive of any excise duty or cess that may be levied under any law but include cost of loading the molasses in Tank wagons etc.

(c) Government are not aware of huge profits being made by purchasers of molasses.

(d) Does not arise.

Protection of Public Deposits raised by Indian Companies

6696. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total amount of money deposits taken from the public by Indian Companies as on 31st December, 1980 under the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 and by how many such companies;

(b) of the above how many companies are (i) under voluntary liquidation; (ii) under Court Liquidation; (iii) under Litigation proceedings; (iv) financially sick and insolvent; and (v) irregular in deposit refund or interest payments and how much of public deposits is involved in each of the above categories;

(c) how many of the above companies have been given a moratorium;

(d) the steps taken to protect public deposits in Indian Companies uptil now and hereafter; and

(e) whether the attention of Government has been drawn to the memoranda submitted by Small Investors' Association of New Delhi in 1980 and if so, the action taken thereupon?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) Since the Return of Deposits required to be filed under rule 10 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 by the non-banking non-financial companies having deposits are relatable to 31st March of an year only, the information about the total amount of deposits taken from the public by such companies as on 31st December, 1980 cannot possibly be furnished. In fact, such information for the financial year ended 31st March, 1981 will be available only after June 1981.

(b) and (c). In view of reply to part (a) above, the question does not arise.

(d) The Department has already taken the following steps to safeguard the interests of the depositors:—

(a) In accordance with the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 as amended on 30th March, 1978, non-banking non-financial companies have to indicate from 1st April, 1978 onwards in the advertisement seeking deposits, in addition to summarised financial position of the company, information on the following points:

(i) The amount which the company can raise by way of deposits;

(ii) The aggregate of deposits held;

(iii) Amount of deposits which are overdue for repayment;

(iv) The deposits are unsecured and rank *pari passu* with other unsecured liabilities.

From these particulars, the intending depositor would be able to judge for himself whether he should make a deposit in the company.

(b) Under the aforesaid rules, the non-banking non-financial companies are also required before 30th April of each year, to deposit or invest in the prescribed manner 10 per cent of its deposits maturing during the year ending 31st March next following, which can be utilised only for repayment of deposits maturing during the said year.

(e) No memorandum from Small Investor's Association, New Delhi was received in the year 1980. Certain

memoranda, inter alia, suggesting measures for safeguarding depositors interests were, however, received from the said Association in 1979, the contents whereof have been noted for such action as might be deemed appropriate at the time of next amendment to the Companies Act.

Committee on use of Plastics in Agriculture

6697. SHRI B. V. DESAI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to set up a 15-Member National Committee on the use of plastics in agriculture;

(b) whether Government have been considering for some time the promotion and development if uses of plastics in agriculture and irrigation as a major step in improving agriculture yields and efficiency;

(c) what are the terms and conditions of this committee; and

(d) when the committee is likely to submit its report?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The terms of reference of the Committee are as follows:

(i) To review the possibilities of use of plastics in agriculture with special reference to:—

(a) plant and crop protection;

(b) irrigation and optimum use of water;

(c) application of plant nutrients and pesticides;

(d) handling and storage of agriculture products;

(e) any other related area.

(ii) To review the overall economics of application of plastics in different areas under Indian conditions and to suggest measures for increased use of plastics Consistent with the established practices which are suitable in the Indian context;

(iii) Suggest in-depth studies on new products, new applications and on systems required for using plastics materials in agricultural sector;

(iv) Review the impact of the use of plastics in agriculture on environment;

(v) Review the existing facilities for the production of plastics products for use in agriculture including technological back-up for the conversion industry, availability of moulds and tools and to make recommendations on strengthening the existing system to promote the production of these products in the rural sector.

(d) The term of the Committee will be initially for a period of two years and the Committee will submit its Report at the end of its term, but the Committee may submit interim Reports as often as necessary.

D.V.C.'s Budget for 1981-82

6698. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the DVC (Damodar Valley Corporation) has finally adopted its budget for the year 1981-82;

(b) whether the said budget was sent to the Government of Bihar and West Bengal;

(c) if so, whether it is a fact that West Bengal Government did not accept that budget or place it before the West Bengal Legislative Assembly this year, as is usually done; and

(d) if so, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) and (d). Approval of the budget estimates for 1981-82 was an item on the agenda for the Damodar Valley Corporation meeting scheduled to be held on 27th February, 1981. This meeting, however, was deferred to 7th March, 1981 at the request of one of the Members. As Government of West Bengal asked for the printed budget for placement in West Bengal Assembly on 7th March, 1981, there was no alternative but to have the budget estimates approved by circulation. On receipt of approval from the Chairman and one of the Members, West Bengal Government was informed that the DVC's budget estimates for 1981-82 might be deemed as approved by the Corporation in terms of Rule 3 read with Rules 6 and 9 of the D.V.C. (Conduct of Business) Regulations, 1951. The Govt. of West Bengal, however, was of the view that the budget passed by circulation was not a properly approved budget. The approval of the budget by circulation was ratified later at a meeting of the Corporation held on 7th March, 1981.

मध्य प्रदेश में शीरे की उपलब्धता

6699. **श्री सत्य नारायण जाटिया :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मध्य प्रदेश में शीरा आधारित उद्योगों को दिये जाने के लिये मिलों एवं अन्य स्रोतों से शीरे की कितनी मात्रा मिलने की संभावना है ;

(ख) इन उद्योगों के लिये कुल कितने शीरे की आवश्यकता है और क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस मात्रा की सप्लाई के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इसकी सप्लाई के लिए क्या प्रबन्ध किये हैं ; और

(ग) केन्द्र सरकार को इस मात्रा की सप्लाई किन राज्यों से की जानी है और क्या शीरा महाराष्ट्र में उपलब्ध किया जा सकता है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) . केन्द्रीय शीरा बोर्ड की दिनांक 11-11-1980 की बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने यह रिपोर्ट दी थी कि शीरा वर्ष 1980-81 (नवम्बर-अक्तूबर) में शीरा का उत्पादन 14,000 टन तक होने की आशा है और उसकी मांग 33,000 टन तक होने की आशा है और इस प्रकार राज्य में लगभग 19,000 टन शीरे की कमी होगी। विभिन्न राज्यों में शीरे की मांग और उसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश को गुजरात से 10,000 टन शीरे का आवंटन किया गया। केन्द्रीय शीरा बोर्ड की उक्त बैठक में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिये गये अधिशेष शीरे के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को 32,500 टन शीरे का आवंटन किया गया।

Indian Films Banned in Dubai

6700. SHRI N. E. HORO:

SHRI K. MALLANNA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several Indian films have been banned in Dubai; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b). According to the information received from

the Consulate General of India, Dubai, the following Indian films have been banned in Dubai:

1. Abdullah
2. Anek Din Aagey
3. Apna Desh
4. Ali Baba Aur 40 Chor
5. Arab Ka Sitara
6. Avar Jeevikkunnu
7. Chhere Pe Cheere
8. Devta
9. Ganga Sagar
10. Geeta Mera Naam
11. Gupt Gyan
12. Gule Bakawali
13. Guru Manio Granth
14. Hoor-E-Erab
15. Humshakal
16. Heer Ranjhah
17. Har Har Ganga
18. Hare Rama Hare Krishna
19. Jahan Pyar Miley
20. Jhuk Gaya Aasman
21. Kam Shastra
22. Keemat
23. Kurukshetra
24. Kismat
25. Kalliyankattu Neeli
26. Liza
27. Puraskar
28. Maharani Padmini
29. Prem Pujari
30. Saki Hatim
31. Suhaag Raat
32. Cherazade
33. Shabnam
34. Shahinsha
35. Siddhartha
36. Sone Ka Haath
37. Teerandaz
38. Tumare Liye
39. Thilothama
40. Upkar
41. Yaar Mera.

मध्य प्रदेश में पैराफिन मोम पर आधारित लघु एकक

6701. **श्री सत्य नारायण जाटिया:** क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पैराफिन मोम पर आधारित लघु एककों की संख्या कितनी है उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और वर्ष 1980-81 में केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको पैराफिन मोम की कितनी मात्रा आवंटित की गई है ;

(ख) क्या उनको अपेक्षित मात्रा में पैराफिन मोम सप्लाई किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(घ) वर्ष 1980-81 में देश में पैराफिन मोम की मांग और सप्लाई की क्या स्थिति रही है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(घ) वर्ष 1980 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को किया गया कुल आवंटन 53,638 मी० टन था। तथा उनके द्वारा किया गया उठान 44,010 मी०

टन था। इसके अतिरिक्त 1980 के आबंटन की तुलना में 1443 मी० टन का विशेष आबंटन किया गया।

देश में इसकी मांग कहीं ज्यादा है।

Complaints from shareholders of Sugar Mills

6702. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many complaints have been received by the Company Affairs Minister from shareholders of various sugar mills;

(b) the action taken thereon; and

(c) how many sugar mills have became sick due to mismanagement and misutilisation of funds?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b). There is no system of compilation of statistics relating to complaints made to the Department of Company Affairs, industry-wise. It will also not be a feasible proposition to compile such information mill-wise, particularly as some companies may be engaged in a number of production activities relating to diverse industrial areas. Then again, the Department of Company Affairs is basically concerned with the administration of the Companies Act.

(c) The Department of Food, Ministry of Agriculture who are principally concerned with the Sugar Mills have stated that they have not prepared any list of sick sugar mills nor have they any precise criteria for determining such sickness. Proposals for taking over the management of sugar mills under the Industries (Development and Regulation) Act 1951, when received from the State Governments, are considered. At present the management of the following sugar mills has been taken over under the Industries (D&R) Act 1951 on the grounds of mismanagement/diversion of funds:—

(1) Shree Janki Sugar Mills Company Doiwala, District Dehradun (Uttar Pradesh).

(2) Sri Rama Sugars and Industries (P) Ltd., Bobbili, District Srikakalam (Andhra Pradesh).

(3) Sri Rama Sugars and Industries (P) Ltd., Seethanagaram, Oistrict Srikakulam (Andhra Pradesh).

(4) The Jaora Sugar Mills Ltd., Jaora Dstrict Ratlam, (Madhya Pradesh).

(5) Seth Govindram Sugar Mills, Mehidpur Road, District Ujjain (Madhya Pradesh).

(6) Motipur Sugar Factory Ltd., Motipur, District Muzaffarpur (Bihar).

The management of the following eight sugar mills also vests in the Central Government under the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 for their failure to commence sugar production by the prescribed date or for having cane price arrears in excess of the prescribed limits:—

(1) Ajudhia Sugar Mills Ltd., Raja-ka-Sahaspur, District Moradabad (Uttar Pradesh).

(2) Deoria Sugar Mills Ltd., Deoria, District Deoria (Uttar Pradesh).

(3) Shree Sitaram Sugar Co. Ltd., Baitalpur, District Deoria (Uttar Pradesh).

(4) Cauvery Sugars & Chemicals Ltd., Pettaivatalai, District Trichy, (Tamil Nadu).

(5) Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Ltd., Ihaksar, District Saharanpur (Uttar Pradesh).

(6) Jijamata Sahakari Sakhar Parkhana Ltd. Shankarnagar, Dusarbid, District Buldhana (Maharashtra).

(7) Shri Keshoraipatan Sahakari Sugar Mills Ltd., Keshoraipatan, District Bundi (Rajasthan).

(8) Seksaria Sugar Mills Ltd., Babhnan, District Gonda (U.P.)

Alleged Cancellation of Programme of Bengali Poetess

6703. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2631 on 10th March, 1981 regarding alleged cancellation of programme of Bengali Poetess and state:

(a) what was the theme of the telecast; and

(b) what were the specific objections of the T.V. authorities and Government?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) Poetry recitation under general literary programme of Doordarshan Kendra.

(b) The telecast was postponed in view of the policy not to project political personalities belonging to different political parties during the period immediately preceding the Lok Sabha Elections.

Engagement of a French Firm to boost Bombay High output

6704. SHRI JYOTIRMOY BOSU:
SHRI CHITTA BASU:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2974 on the 10th March. 1981 regarding engagement of a French firm to boost Bomyay High output and state:

(a) the details of the terms of agreement on the basis of which the French firm is rendering consultancy to the O.N.G.C.;

(b) details of the new offer given by the French firm to extend the agreement with enlarged scope; and

(c) Government's reaction to the said offer?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) As per the four-year agreement signed in April 1977 by the ONGC with the CFP of France for comprehensive consultancy to the ONGC for optimising the development of the Bombay High offshore field, the CFP was to assist the ONGC in data acquisition, reservoir-engineering, laboratory studies, alternative development plans and enhanced recovery methods, etc. The agreement also provided for transfer of technology to the ONGC. The remuneration payable to the CFP in the matter based on man-years of work, provision of computer services, transferring computer software including programme models, etc., was estimated at US dollar 17.4 million net of Indian taxes.

(b) and (c). The CFP have offered to extend this agreement with an enlarged scope. They have asked for remuneration which includes an element of remuneration in terms of oil for production above certain levels. This offer is at present under discussion between the ONGC & the CFP and no decision has been taken as yet.

Violation of provision of MRTP Act by Companies

6705. SHRI JYOTIRMOY BOSU:
SHRI RAM VILAS PASWAN:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) names and particulars of Companies who were charged with violation of the provisions of the MRTP Act during 1980;

(b) the specific charges against each Company concerned; and

(c) the action taken in each case?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) to (c). A Statement is laid on the Table of the House. Place in Library. (*See* LT-2328/81).

Revision of Voter's Lists for Election to Lok Sabha and Assemblies

6706. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the voters' list of Assembly as well as Lok Sabha constituencies will be revised before holding next general election; and

(b) if so, by what time they will be revised?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b). The Election Commission has to take necessary steps under section 21 of the Representation of the People Act, 1950, to get the electoral rolls prepared at the time of General Elections to Lok Sabha and State Legislative Assemblies. At this stage, the Commission is not in a position to furnish any fixed programme for the revision of rolls for such eletcions.

Haryana's proposal for a power plant in public sector

6707. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Haryana Government have sent any proposal to set up power plants in the public sector in the State for Centre's approval;

(b) if so, the details thereof; and

(c) action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAMA MAHAJAN): (a) to (c). The present position of the power generation Projects submitted by Haryana to the Central Electricity Authority is given below:

	Project	Installed Capacity MW	Latest Estimated Cost	Present Status
1		2	3	4
1.	Yamunanagar TPS	4×210	Rs. 285·56 crores	The Project report was examined in CEA and their comments were sent to HSEB whose clarifications and details on some aspects are still awaited. Availability of coal for this project has been established from 1989-90 but confirmation about its transportation has not been received
2.	Daudupur Mini Hydel Project	4×1·5	Rs. 7·47 crores	The revised project report has been received in March 1981 and has yet to be techno-economically appraised.

Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies

6708. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Parliamentary Constituencies as well as Assembly Constituencies will be delimited before holding of next elections to Lok Sabha as well as to State Assemblies;

(b) if so, whether the provision for the same has been finalised; and

(c) if so, details thereof and by what time these will be delimited?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) to (c). The Election Commission in its Report on the General Elections to the House of the People and the Legislative Assemblies 1979-80, has recommended that Articles 82 and 170(3) of the Constitution may be amended to facilitate the delimitation of constituencies while the total number of seats allotted to various States in the House of the People and to the various State Legislative Assemblies may remain unaltered. The question whether an amendment of the Constitution is necessary to facilitate delimitation of constituencies on the lines recommended by the Election Commission is under consideration.

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में विद्युतीकरण

6709. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में अभी तक पूरी तरह बिजली नहीं लगाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में पूरी तरह बिजली लगाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार छठी योजनावधि के दौरान राजस्थान में पूरी तरह बिजली लगा देने का है ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने का दायित्व राजस्थान राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड का है। राजस्थान समेत, देश में शतप्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं ; नए विद्युत केन्द्र स्थापित करना, मौजूदा विद्युत केन्द्रों की कार्यक्षमता, में वृद्धि करना और अधिक पारेषण और वितरण लाइने बिछाना, निर्माण सामग्री आदि की कमी को यथा संभव दूर करना तथा वर्ष प्रति वर्ष ग्राम विद्युतीकरण के लिए परिव्यय में अभिवृद्धि करना । राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरु किया है, जिसके अन्तर्गत उदार शर्तों पर राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यदि अपेक्षित साधन उपलब्ध हुए तो यह आशा की जाती है कि राजस्थान में 1988–89 तक सभी गांव विद्युतीकृत हो जाएंगे ।

(ग) से (ङ). जी, नहीं । ग्राम विद्युतीकरण की योजना समय-समय पर, विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है, जैसे प्रत्येक राज्य में वित्तीय साधन, निर्माण सामग्री की उपलब्धता कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड की संगठनात्मक क्षमता, सम्बद्ध ग्रधसंरचना सुविधाग्रों का विकास ग्रादि ।

Election Commission's Recommendation for Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies

6710. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Election Commission has recommended delimitation of the Parliamentary and Assembly Constituencies including the Metropolitan Constituencies of Delhi; and

(b) if so, whether Government intend to amend the Constitution to facilitate such delimitation of Constituencies?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) The Election Commission in its Report on the General Elections to the House of the People and the Legislative Assemblies 1979-80, has recommended that Articles 82 and 170(3) of the Constitution may be amended so that while the total number of seats allotted to various States in the House of the People and to the various State Legislative Assemblies may remain unaltered, the original position of fresh delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in each State and Union Territory after every decennial census is restored.

(b) The question whether an amendment of the Constituion is necessary to facilitate delimitation of constituencies on the lines recommended by the Election Commission is under consideration.

Investigation against foreign companies under Indian Companies Act

6711. SHRI RAM VILAS PASWAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the names of various foreign companies (branches and subsidiaries) against whom investigations have been conducted by the Department of Company Affairs under various sections of the Indian Companies Act during the last five years; and

(b) the company-wise and section-wise details of the irregularity detected and the action taken during the last five years?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b). The particulars regarding the names of various foreign companies (branches and subsidiaries) which have been inspected under Section 209-A and investigated under Section 237 of the Companies Act, 1956 during the last five years i.e. commencing from 1. 4. 76 to 31. 3. 81 and the company-wise and Section-wise details of the irregularities and the action taken thereon are furnished in the Statements I & II respectively Statements laid on the Table of the House. Placed in Library. (See No. LT-2329/81).

Promotion of Assistant Station Director

6712. SHRI RAMAYAN RAI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to replies given to Unstarred Question Nos. 4125 and 4128 on 16th December, 1980 regarding Promotion of Assistant Station Director and Promotion of Programme Executives as Assistant Directors respectively and state:

(a) what are the reasons to promote those persons as Assistant Station Directors, who were rejected by the UPSC in the direct recruitment for the post of Programme—Executives as well as for the post of Assistant Station Directors;

(b) the reasons why the recruitment rules are not changed in this cultural organisation so that exports and specialists can be appointed on high posts;

(c) whether Government propose to appoint Senior Producers in place of Assistant Directors and would like to reduce the number of Assistant Station Directors;

(d) if so, when it will be materialised; and

(e) if not, what are the reasons?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b). The recruitment rules for promotion to the cadre of Assistant Station Director provide for filling up of the 25 per cent posts by direct recruitment through UPSC and 75 per cent by promotion amongst Programme Executives who have rendered a minimum regular service of five years. In view of the above, the possibility of a Programme Executive applying in the direct quota and not getting selected by the Commission but later on getting promoted as an Assistant Station Director cannot be ruled out. This promotion is also in accordance with recruitment rules and on the stipulated criteria. This is done through a properly constituted Departmental Promotion Committee presided over by a member of the Union Public Service Commission. Recruitment rules to various cadres are framed and amended, as necessary, to provide for recruitment of suitable persons with the required experience and qualifications, in consultation with the Department of Personnel & Administrative Reforms and the Union Public Service Commission. The Staff Artists are contractual employees and not regular Government servants. Their service conditions and promotion channels are quite different from these of Regular Programme staff.

(c) to (e). Government is aware of the lack of Promotional avenues for certain categories of Staff Artists and for the purpose, a Cadre Review Committee has been set up to go into the cadre structure of Staff Artists and make necessary recommendaions. As and when such recommendations are received by the Government, they will be given due consideration. Cadre Review Committee appointed earlier by the Government in respect of regular Government servants, had also made certain recommendations in respect of certain categories of Staff Artists, viz. Producers and Production Assistants. Government have yet to take a final decision on the recommendations of this Committee.

Outcome of Minister's visit abroad

6713. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether during his visit to a number of countries recently, he inter alia happened to discuss plans for supply of rigs for off shore drilling, or setting up of a gas cracker plant and aromatics complex and the long-pending proposal for the take over of the Oil India in which the Burma Oil Company holds 50 per cent equity; and

(b) if so, the details regarding the outcome and the names of the countries visited by him?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b)

1. I had visited France, England, Romania and Italy during the period 25th January—7th February, 1981.

2. I availed of the occassion to discuss cooperation in the field of oil exploration such as supply of equipment with the concerned Government. During my stay in France, I had detailed discussions with CFP (who are already collaborating with ONGC in the Bombay High) regarding further development of Bombay High including the satellite structures. ONGC is now holding discussions with CFP.

3. The visit was not with the specific object of seeking any country's collaboration in setting up of petrochemical units in India. No proposals were, therefore, made to any of these countries in this regard. However, our interest in foreign collaboration was indicated when the subject came up for discussion. Both France and Italy have expressed interest in assisting us in setting up of the petrochemical complexes. An invitation has been extended to the President of ENI of Italy to visit India to discuss the possible areas of cooperation. A team of French experts is also likely to visit India to discuss areas of cooperation.

4. During the course of discussions I informed the British Government that take over of Oil India is under our active consideration.

Action against Newspapers and Periodicals found guilty by Press Council

6174. SHRI ARJUN SETHI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to stop advertisement and newsprint quota of such newspapers and periodicals which have been found guilty by the Press Council; and

(b) whether Government are also considering any other method of bringing the guilty to book?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN. M. JOSHI): (a) and (b). There is a proposal to this effect from the Press Council of India. The proposal involves amendment of the Press Council Act, 1978. Whether such an amendment can at all be effected is under consideration.

किसानों के लिए फिल्मों का प्रदर्शन

6715. **श्री निहाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन करने के साथ साथ सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को कृषि की विकसित प्रणाली और फसल को कीटों द्वारा किये जाने वाले नुक्सान से बचाने के ढंग से संबंधित फिल्मों को दिखाने की व्यवस्था करने का भी है ;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) विभिन्न विकासीय विषयों पर ग्रामीण, पिछड़े, आदिवासी और दूरवर्ती क्षेत्रों में फिल्में दिखाना क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की नियमित गतिविधियों में से एक है। इन फिल्मों में कृषि के उन्नत तरीकों और फसलों को कीटों आदि द्वारा किए जाने वाले नुकसान से बचाने के ढंग से संबंधित फिल्में भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) इस विशिष्ट मद के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया है, किन्तु इसको क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की सामान्य कार्यक्रम गतिविधियों में कवर किया जाता है।

नये रेडियो स्टेशन, स्टुडियो और विदेश प्रसारण के लिए शार्टवेव ट्रांसमीटर

6716. **श्री निहाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में आल इंडिया रेडियो द्वारा कितने और किस-किस स्थान पर नये रेडियो स्टेशन, स्टुडियो और विदेश प्रसारण के लिये शार्टवेव ट्रांन्समीटर स्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) प्रत्येक स्टेशन स्थापित करने में कितनी लागत आयेगी और निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख). छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित आकाशवाणी के नए रेडियो स्टेशनों, स्टुडियो और विदेश प्रसारण के लिए शार्टवेव, ट्रांन्समीटरों की संख्या और उनके स्थान तथा प्रत्येक स्कीम की अनुमानित लागत संलग्न विवरण में दी गई है।

उम्मीद है कि निर्माण कार्य चालू योजना अवधि के दौरान मुकम्मल हो जायेगा ।

विवरण

छठी योजना अवधि के दौरान हाथ में ली जाने वाली ध्वनि प्रसारण योजनाएं।

क्रम संख्या	योजना का नाम	स्थापित करने की लागत (लाख रुपयों में)
1.	**नये रेडियो स्टेशन**	
1	इटा नगर (अरुणाचल प्रदेश)	100.00
2	तुरा (मेघालय)	171.72
3	गंगटोक (सिक्किम)	178.08
4	मदुरै (तमिलनाडु)	172.76
5	आगरा (उत्तर प्रदेश)	148.76
6	जमशेदपुर (बिहार)	109.36
7	6 स्थानों पर एक एक स्थानीय रेडियों स्टेशन कोटा (राजस्थान), दिफू (असम) किओनझर (उड़ीसा), शोलापुर (महाराष्ट्र) आदिला बाद (आन्ध्र प्रदेश) और नागर-कोइल (तमिलनाडु)	240.00
2.	**स्थायी स्टुडियो :**	
1	भागलपुर (बिहार)	65.72
2	कुडप्पा (आंध्र प्रदेश)	59.36
3	गुलबर्गा (कर्नाटक)	64.66
4	सांगली (महाराष्ट्र)	63.60
5	तिरुनेलवेली (तमिलनाडु)	60.42
6	जबलपुर (मध्य प्रदेश)	65.72
7	भद्रावली /शिमोगा (कर्नाटक)	65.72

3. विदेश सेवाओं को समेकित और सुदृढ़ करना।

1 बंगलौर (कर्नाटक)— 50 कि० वा० शार्ट वेव के दो ट्रांसमीटर 150.00

2 अलीगढ़ (उ.प्र.) 250 कि. वा. शार्ट वेव के दो ट्रांसमीटर फेज—2 790.00

3 अलीगढ़ (उ. प्र.) 250 कि. वा. शार्ट वेव के दो ट्रांसमीटर फेज—3 750.00

इंडो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा निर्माण

6717. **श्री निहाल सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडो वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड की इंजीनियरिंग विभाग द्वारा गत दो वर्षों में किन किन वस्तुओं का निर्माण किया गया ;

(ख) क्या इस विभाग द्वारा बनाई गई वस्तुओं का इस्तेमाल स्वयं कम्पनी का माल रखने के लिए किया गया अथवा फर्मों को बेचा गया ; और

(ग) गत दो वर्षों में इस फर्म द्वारा कितने मूल्य का निर्मित सामान बेचा गया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) गत दो वर्षों के दौरान इण्डो वर्मा पेट्रोलियम कंपनी के इंजीनियरिंग प्रभाग ने निम्नलिखित मदों का निर्माण किया था:—

1 इलेक्ट्रोनिक तापमान नियंत्रक

2 बाटलिंग संयंत्रों जैसी विशेष मशीने

3 कायल मोल्डिंग प्रेस एवं हाइड्रोलिक मशीनरी

4 कायोकन्टेनर्स

(ख) कंपनी द्वारा निर्मित वस्तुओं को अन्य फर्मों को बेचा जाता है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा बेचे गए तैयार माल का मूल्य क्रमशः 97 लाख रुपये और 129 लाख रुपये है।

Setting up of a Power Station at Mahuva in Saurashtra based on Natural Gas

6718. SHRI R. P. GAEKWAD: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to set up a Power Station at Mahuva in Saurashtra, based on natural gas;

(b) if so, installed and generating capacity of the power station;

(c) whether Government of Gujarat has approached Government of India for approval of the said power station; and

(d) if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (d). The Project report for setting up of a gas-based thermal power station at Mahuva in Saurashtra with 2 units of 210 MW each was submitted by the Gujarat Electricity Board to Central Electricity Authority. Normally, use of gas as fuel is not favoured as long as it can be used for high value products such as fertilizers. Also, the Tapti fields, from where the gas was envisaged to be utilised for power generation, are yet to be fully appraised and declared commercial. As such, the project report was returned

by Central Electricity Authority to Gujarat Electricity Board in July, 1980.

Italian Government Firms, Offer regarding Thermal plant in India

6719. SHRI R. P. GAEKWAD:
SHRI JANARDHANA POOJARY:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an Italian Government firm ANSALDO had offered to set up a 600-megawatt thermal power plant in India;

(b) if so, what are the details of the said proposal; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal received from M/s. ANSALDO envisages the establishment of an integrated coal mining and power generation project. Two alternatives have been suggested. In the first alternative, a power station of 600 MW generating capacity would be set up along with coal mining development to match the requirement of the power station. In the second alternative, coal is proposed to be produced in excess of the power station requirement and the excess proposed to be exported after beneficiation.

(c) No decision in the matter has been taken as yet.

Intensification of Family Welfare Messages through A.I.R.

6720. SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the steps taken to intensify the family welfare messages through All India Radio during last five years, year-wise and studio-based and O.B. based-wise;

(b) the number of family welfare cells increased since 1970, year-wise and State-wise; and

(c) Government's proposals for the expansion of family welfare cells in A.I.R.?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) All India Radio is fully conscious of the importance of the Family Welfare Programme. Programmes in the form of talks, discussions, symposia, dialogues, interviews etc. are regularly broadcast by AIR Stations to popularise the message of family welfare. These programmes are both studio-based and filed-based. During the last five years the details of programmes broadcast on Family Welfare are as follows:—

Year	No. of Programmes	
	Field-based	Studio-based
1976	2,286	46,551
1977	1,958	21,500
1978	2,416	23,367
1979	3,829	51,574
1980	3,610	58,879

(b) There has been no increase in the number of Family Welfare Cells at Air Stations since 1970.

(c) The Government is considering a proposal for converting the 14 Family Welfare Cells (at present having only a Field Reporter each) at Bhuj, Dharwad, Imphal, Indore, Jammu, Kurseong, Patna; Pondicherry, Pune; Rajkot; Shillong, Tiruchirapalli and Vijayawada, into full-fledgtd

family welfare Cells (each with an Extension Officer, one Field Reporter and one Assistant Editor—Scripts) as well as the question of having a Field Reporter each at some more AIR Centres to intensify the Family Welfare campaign. All India Radio already has full-fledged Family Welfare Units at 22 Stations.

Engagement of Tribal Artistes on Casual basis

6721. SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number and percentage of tribal artistes/talkers/participants, drama voices and announcers booked on casual basis;

(b) whether it is a fact that tribal people are not prepared for even tribal folk lore and talks/messages/announcements even for purely tribal districts; and

(c) if not, what steps Government propose to take to augment the intake of tribal artistes?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) A.I.R does not keep information regarding Casual Artistes indcating whether a person belongs to tribal population or not. As such, the information regarding the number and percentage of tribal artistes/talkers/ participants, drama voices and announcers booked on casual basis is not available.

(b) Stations having a mixed population in their zone are always on the look-out to bring in more and more number of persons belonging to tribal population of the area for presenting tribal folk lore, talks, messages etc. depending on their availability, knowledge and suitability for such assignments. In predominantly tribal areas like Arunachal Pradesh, Manipur, Kohima, Jagdalpur, Ambikapur etc, programmes for various tribal groups are presented mostly by tribals themselves.

(c) Does not arise.

Special Cell for Bagri in A.I.R.

6722. SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bagri is spoken by people of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh on the border area;

(b) whether Government have received requests from any organization/individual for starting cell for "Bagri" in All India Radio, Jaipur;

(c) whether Government have examined the matter in all its details; and

(d) if so, their reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) Yes, Sir. Bagri is spoken by some people in these areas.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). Government have examined the matter. Since the areas where the Bagri speaking population reside is not covered by All India Radio, Jaipur the question of starting a Cell for 'Bagri' in AIR, Jaipur is not justified.

Procurement of computerised fermentor

6723. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Hindustan Antibiotics Limited (Pimpri-Pune, Maharashtra) has procured fully computerised fermentor from abroad at a considerable cost;

(b) if so, when was it actually commissioned; and how many batches are processed in this fermentor every month;

(c) whether it has been useful in improving the strain process of manufacturing of bulk drugs at HAL; and

(d) if so, in which bulk drugs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) Hindustan Antibiotics Limited purchased a fully automatic formentor of 300 lit. capacity as part of R & D pilot plant with the following monitoring systems at a cost of Rs. 16.5 lakhs:

(i) Temperature control and record.

(ii) PH Control and record.

(iii) Oxygen controller.

(iv) Automatic sterilization.

The fermentor was received at site on 27th September, 1980 and installed on 25th October, 1980. Commissioning trials were conducted in the presence of the engineers from manufacturer, M/s. Electrolux, Sweden and their Indian Agents M/s. SICO, Bombay from 25th October, 1980 to 1st January, 1981.

During commissioning trials, one batch of Penicillin was taken. Sterility through out the run was satisfactory, but for improving process, more pilot plant trials are necessary.

उड़ीसा द्वारा मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई

6724. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने मध्य प्रदेश को 5 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का वचन दिया है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने मध्य प्रदेश को 24 सितम्बर, 1979 से बिजली की सप्लाई बन्द कर दी थी ;

(ग) यदि हां तो मध्य प्रदेश को अब तक बिजली की सप्लाई पुनः आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि उड़ीसा सरकार मध्य प्रदेश को दिये गये वचन का पालन करे।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) यह सच है कि उड़ीसा सरकार मध्य प्रदेश को 5 मेगावाट विद्युत की सप्लाई करने को सहमत हुई है।

(ख) और (ग). यह सच है कि विद्युत की सप्लाई 24-9-79 से बन्द कर दी गई थी। जून 1980 के अन्त में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार होने के बाद उड़ीसा सरकार ने विद्युत की सप्लाई चालू नहीं की क्योंकि मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने लगभग 32 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

(घ) चूंकि उड़ीसा से मध्य प्रदेश को विद्युत की सप्लाई राज्य सरकारों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार की गई थी इस मामले का हल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाएगा ।

मध्य प्रदेश द्वारा पेंच तापीय विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली के प्रमुख अंश के आवंटन की मांग

6725. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**
श्री सुन्दर शर्मा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से मांग की है कि वह पेंच तापीय विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली का प्रमुख अंश उसी राज्य को आवंटित करे;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी मांग की है कि इस परियोजना में केवल उसी राज्य के निवासियों को नियुक्त किया जाय ; और

(ग) यदि हां तो इस तथ्य की दृष्टि से कि इस परियोजना को राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) अक्तूबर, 1980 में राज्य सरकार और केन्द्र के प्रतिनिधियों के बीच जिन मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ था उन मुद्दों में, पेंच में प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्र से संबंधित मुद्दों में ये सुझाव भी थे । उस समय इस बात पर सहमति हुई थी कि केन्द्रीय सेक्टर के क्षेत्रीय ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत का आवंटन इन परियोजनाओं के संबंध में सरकार की समग्र नीति के अनुसार ही होगा और यह आवंटन नीति एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए भिन्न नहीं हो सकती । इसी प्रकार इस बाबत भी सहमति हुई कि रोजगार संबंधी मामलों पर विचार केन्द्रीय स्वामित्व के क्षेत्रीय सुपरताप विद्युत केन्द्रों के लिए केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संदर्भ में करना आवश्यक होगा। तथा इस मामले में सरकार की नीति सभी राज्यों पर समान रूप से लागू करनी होगी ।

मध्य प्रदेश में बांगो तथा टोंस पन बिजली परियोजनायें

6726. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बांगों पन बिजली परियोजना के लिये 3×40 मैगावाट की अधिष्ठापित क्षमता और टोंस पन बिजली परियोजना के लिये 3×105 मैगावाट की अधिष्ठापित क्षमता का प्रस्ताव करते हुए परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उनकी स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) यदि हां तो इन परियोजना प्रतिवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है और उनकी स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जी हां। हसदेव बांगों बहुददेशीय परियोजना (3×40 मेगावाट) के विद्युत से संबंधित भाग की 40.80 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना रिपोर्ट मई, 1980 में प्राप्त हुई थी। इसकी जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण / केन्द्रीय जल आयोग में की गई है और परियोजना प्राधिकारियों से परियोजना के आयोजना और डिजाइन के पहलुओं के बारे में कुछ स्पष्टीकरण/ अतिरिक्त अध्ययन भेजने के लिए अनुरोध किया गया है । राज्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए अध्ययनों पर, हाल ही में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में विचार विमर्श किया गया है और आयोजना, सिविल और विद्युत इंजीनयरी के पहलुओं को शामिल करते हुए संशोधित समेकित परियोजना रिपोर्ट की परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है ।

टौंस जल विद्युत परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 1980 में प्राप्त हुई थी। इसमें 390 मैगावाट (3×105+2×15+3×15 मैगावाट) की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना की गई है और इसकी लागत 195.82 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। बाद में, परियोजना प्राधिकारियों ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग के साथ विचार विमर्श किया था। परियोजना के डिजाइन के पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर कुछ स्पष्टीकरण परियोजना प्राधिकारियों द्वारा भेजे जाने हैं।

इन स्कीमों की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद ये स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जाएंगी।

Short term and long term plans to meet power requirements

6727. SHRI HARINATHA MISRA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether in view of steep increase of oil prices and developing undertinties in energy supplies, Government propose to place greater reliance of hydro-power;

(b) what is the potentiality of hydro-electric energy in different parts of the country, and its present utilisation;

(c) whether any short-term/long term plans with requirements of keyinputs like steel, aluminium; cement and explosives for the construction of power plants and transmission and distribution facilities have been prepared; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The working Group on Power set up by the Planning Commission in connection with formulation of Sixth Five Year Plan had recommended a Programme for power development for the Sixth Five Year Plan and drawn up perspective programme for the Seventh Five Year Plan. The Working group had emphasised the importance of accelerated hydro development and recommended high priority to hydro projects. Although the benefits from ongoing and sanctioned hydro projects which will give benefits during the Sixth Plan period will of the order of 4768 MW out of a total additional capacity of 19666 MW, the Working Group on Power recommended maximum feasible hydro development during seventh plan and envisaged a possible contribution of about 15,000 MW from hydro plants out of a total additional capacity of about 28,000 MW envisaged during the Seventh Plan period.

(b) The hydro electric potential of the country was earlier assessed as 42 Million Kilowatts at 60 per cent load factor (25.2 Million Kilowatts continuous). However, according to the preliminary estimate based on the revised studies presently in progress in the Central Electricity Authority, the hydroelectric potential of the country is placed at 75 Million Kilowatts at 60 per cent load factor (45 Million Kilowatts continuous). The region-wise breakup of the above potential and its present utilisation is as under:—

Region	Hydro Electric potential	Potential developed
	(Million Kilowatts Continuous)	
Northern Region	16·8	1·62
Western Region	4·2	0·73
Southern Region	7·8	2·33
Eastern Region	4·3	0·35
North-Eastern Region	12·1	0·04
Total	45·2	5·07

(c) and (d). On the basis of the assessment made by the Working Group on Power for the requirement of steel and aluminium and the assessment made by Central Electricity Authority in consultation with various State Electricity Boards for cement, the requirement of these inputs during the 6th Plan Period are estimated as follows:—

Year	Steel	Aluminium	Cement
		(in lakhs tonnes)	
1980-81	12·00	2·00	36·5
1981-82	14·00	2·28	37·1
1982-83	20·00	2·41	38·1
1983-84	22·50	2·47	38·6
1984-85	27·00	2·50	37·4

Releasing of New Gas Connections

6728. SHRI JITENDRA PRASAD: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are releasing new gas connections from March, 1981; and

(b) if so, the number of pending applications likely to be covered in each of the gas agency in Delhi?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) As per the enrolment plan of the oil companies, a total number of about 99,000 domestic gas connections are expected to be released in the Union Territory of Delhi upto the end of 1982. Agency-wise details are not readily available.

Sanction of Petrol Pump at Rohru, Simla

6729. SHRI JITENDRA PRASAD: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government received applications from some ex-servicemen

and Harijans for opening a petrol pump at Rohru in Simla District of Himachal Pradesh;

(b) if so, the number of such applications received;

(c) the action taken thereon; and

(d) the reasons for which petrol pump could not be sanctioned for Rohru so far and the time by which a final decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) & (b). Retail outlet dealerships (petro/diesel pumps) are awared by concerned oil companies and not by Govt. In response to the advertisement issued by Indian Oil Corporation Limited for opening a retail outlet (petrol|diesel pump) at Rohru in Simla district of Himachal Pradesh, 4 applications were reported to have been received from ex-servicemen and 3 from Scheduled Castes persons.

(c) and (d). Letter of intent has been issued to a person belonging to SC category in 1980. However, the selected dealer is yet to arrange a suitable site for the outlet.

Oil consumption

6730. PROF. MADHU DANDAVATE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state: what is the average annual consumption of oil on (i) transport (ii) industries (iii) agriculture (iv) power generation (v) domestic use and (vi) miscellaneous purposes?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): According to certain studies made in the year 1978, the following is roughly the sectoral consumption of all petroleum products in the country:—

Transport	33%
Industry	28%
Agriculture	10%
Power generation	7%
Domestic use	14%
Other miscellaneous uses	8%

The total consumption of all petroleum products in 1980-81 in the country was about 30.7 million tonnes.

Employees working in Delhi Doordarshan

6731. SHRI RASA BEHARI BEHRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) total number of employees working in Delhi Doordarshan;

(b) how many vacancies are there to be filled up; and

(c) when the vacancies are going to be filled up?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN. M. JOSHI): (a) 511 (including 218 Staff Artistes).

(b) 58 (including 28 of Staff Artistes).

(c) Action to fill up the posts in progress, in accordance with the Recruitment Rules. The vacancies are likely to be filled up very shortly.

Telecast of Orisee Dance, Oriya film on Delhi T.V.

6732. SHRI RASA BEHARI BEHERA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Oriya drama, Orisee dance and Oriya films are not adequately pictured in Delhi Doordarshan; and

(b) a comparative account of the picture of Doordarshan depicting the cultural image of different States of India may please be given?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) No, Sir. During the year 1980, out of a total of 50 dance items telecast from Delhi as many as 12 were of Odissi dance. Similarly, out of 28 feature films telecast during that year, two were Oriya films.

(b) The information is being collected and will be placed on the table of the House.

Effect of increase in coal price on Textile Industry

6733. SHRI R. N. RAKESH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether he is aware that the latest decision of Government to increase coal prices by Rs. 20 per metric tonne will further add to the cost push of the textile industry, which is already hard pressed by a severe strain on account of the escalation in costs arising from price hike in cotton, fuel, oil, electricty charges, dyes, chemicals and mill stored; and

(b) if so, what is the total annual consumption of coal by the textile industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The recent revision of coal prices may add to the costs of textile industry to some extent.

(b) The annual consumption of coal by the textile industry is about 2.25 million tonnes.

News Item Captioned "Boilers Turbo-generators for Neyveli-contract eludes B.H.E.L."

6735. SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item captioned "Boilers, turbo-generators for Neyveli-contract eludes BHEL" published in Economic Times dated 9th March, 1981; and

(b) what are the reasons thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Yes, Sir.

(b) Neyveli Lignite Corporation has placed orders for the import of the Steam generators and tubro-generators at the lowest price after folowing the pescribed procedure of purchase and due techno-economic evaluation of all bids received. Orders could not be placed with BHEL as the offer was not techno-economically the most advantageous and the price difference of the Turbo generators as evaluated was over Rs. 40 Crores.

Import of crude oil and other Petroleum products

6736. SHRI MOHAMMAD ASRAR AHMAD: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the quantity of crude oil, petroleum and other petroleum products imported during the last five years

including current year and the amount paid and the names of the countries from where imported and at what rate;

(b) the quantity of crude oil and other petroleum products produced in the country during the above period; and

(c) the assessed quantity of each such product needed for consumption in the country during the next five years and the quantity to be produced in the country and imported from other countries during this period?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) he quantity and value of crude oil and petroleum products imported during last five years including current year is as follows:—

YEAR	CRUDE OIL		PETROLEUM PRODUCTS	
	Qty. (in million tonnes)	Value (Rs./crores)	Qty. (in million tonnes)	Value (Rs./crores)
1976	13·9	1145·6	2·29	219·7
1977	14·5	1258·9	2·66	273·0
1978	14·9	1243·9	3·92	414·1
1979*	15·4	1786·8	3·93	705·7
1980*	16·0	3026·7	6·42	1708·3

*Provisional

It would not be in public interest to give details in this regard.

(b) The production of crude oil and petroleum products in the country during 197 to 1980 is as follows:

Years	Crude Oil (in million tonnes)	PETROLEUM PRODUCTS (in million tonnes)
1976	8·7	21·2
1977	10·2	22·8
1978	11·3	23·9
1979	12·8	26·4
1980	9·4	23·6

(c) The estimated consumption, expected domestic production and the shortfall to be met by imports in respect of crude oil and petroleum products during the period 1980-81 to 1984-85 is given below:—

(Figures in million tonnes)

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
CRUDE OIL					
Refinery throughput . . .	25·91	31·10	35·30	35·40	42·90
Indigenous Production . . .	10·2	16·9	20·5	21·00	21·30
Imports (including ocean loss) . .	16·97	14·50	15·20	14·50	21·70
PETROLEUM PRODUCTS					
Consumption	30·97	34·80	38·10	40·90	43·60
Domestic Production . . .	24·26	28·90	32·40	32·40	39·90
Imports	7·08	5·90	5·70	8·50	3·70

It is not possible to give product wise details at this stage.

बस्तर जिले में स्थानीय बोली के वृत्त चित्रों का दिखाया जाना

6737. **श्री बी० आर० नहाटा:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश में बस्तर की आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थानीय बोली के वृत्त चित्रों को दिखाए जाने सम्बन्दी योजना के कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है जिससे कि उस क्षेत्र में खर्च की जा रही सरकारी धनराशि का पूरा उपयोग हो सके।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी): जबकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों विशेषकर मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में स्थानीय बोली की डाकुमेंन्ट्री फिल्में प्रदर्शित करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है फिल्म प्रभाग की छठी योजना अवधि के दौरान ग्रामोन्मुखी 16 मिलीमिटर की फिल्में बनाने के लिए दो प्रदेशिक केन्द्र स्थापित करने की एक योजनागत स्कीम है। ये केन्द्र अन्य फिल्मों के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों की ग्रामीण और आदिवासी बोलियों में भी फिल्में बनाएंगे।

उड़ीसा द्वारा मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई

6738. **श्री बी० आर० नाहाटा:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने मध्य प्रदेश को 5 मैगावाट बिजली सप्लाई करने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त बिजली सप्लाई की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) यह सही है कि उड़ीसा सरकार, मध्य प्रदेश को 5 मैगावाट विद्युत की सप्लाई करने को सहमत हो गयी है ।

(ख) जी नहीं । विद्युत की सप्लाई 24-9-79 से बन्द कर दी गई थी । जून, 1980 के अन्त में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार होने के बाद, उड़ीसा सरकार ने विद्युत की सप्लाई चालू नहीं की क्योंकि मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने लगभग 32 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है ।

(ग) चूंकि उड़ीसा से मध्य प्रदेश को विद्युत की सप्लाई राज्य सरकारों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार की गई थी, अत: इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं हल कर लिया जाएगा ।

Allegation against Company Law Board regarding Hindustan Pilkington Glass Works

6739. SHRI INDRAJIT GUPTA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to an article published in "Business Standard" of Calcutta dated 5th March, 1981; captioned Thapers Quit Pilkington';

(b) whether the said article has alleged that the Company Law Board has injustifiably suppressed Thapar's application for reconstruction scheme; and

(c) whether there is any truth in the paper's suggestion that Government are not keen to revive the Hindustan-Pilkington Glass Works?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIVSHANKAR): (a) Yes, Sir.

(b) The allegations that the Department of Company Affairs had unjustifiably suppressed Thapar's application is wholly incorrect. The proposal made by M/s. Ballarpur Industries for purchase of shares of M/s. Hindustan Pilkington Glass Works required consideration both from the FERA and the MRTP angles. This naturally meant some time because inter-departmental consultations were involved. The proposal was still under consideration of the Government when on 17-2-1981 M/s. Ballarpur Industries, on their own withdraw its application.

(c) No, Sir.

Increase in consumption of Diesel and Petrol in Coal field area of Dhanbad

6740. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether there is a sharp increase in the consumption of diesel and petrol in coal field area of Dhanbad, if so; facts in details for the last five years;

(b) whether most of the consumption of the diesel and petrol is in road transport where both coal and rail lines are there; and

(c) whether his Ministry propose to take up with the Ministry of Railways to increase the passenger and goods traffic by train in the coal field and thus save petroleum?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) There has been an increase over the years in the consumption of High Speed Diesel (HSD) and petrol in the Dhanbad district of Bihar. The details of the consumption of HSD and petrol in this district during the

years 1977-78 978 79 and 1979-80 are approximately as under:—

(figures in thousand metric tonnes)

Year	Petrol	High Speed Diesel
1977-78	10·5	52·4
1978-79	11·3	50·7
1979-80	11·7	59·4

Information in respect of the earlier years is not available.

(b) There is a sizeable road movement, especially of trucks carrying coal, from the Dhanbad area. Apart from road transport, diesel is utilised for the water pump engines and for power generation in the coal belt area.

(c) No, Sir. With the overall improvement in the rail movement of goods in recent months, it is expected that the need for road transportation of goods will go down.

Memorandum from the Coal Mines Labour Welfare Workers Association

6741. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether a memorandum dated 11th July, 1980 regarding the long standing just grievances of Coal Mines Labour Welfare Workers Association was received by his Ministry; and

(b) if so, the details of their grievances and the action taken by his Ministry to resolve them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) A memorandum dated the 11th July, 1980 has been received from the Mines Welfare Workers' Association, Dhanbad.

(b) The Association has made some demands in the event of the merger of the Coal Mines Welfare Organisation (CMWO) with Coal India Ltd. The Association has been informed that the demands will be discussed with them in due course. It may be stated that no decision has yet been taken by the Government on the merger of CMWO with CIL.

Recommendations of High Level Committee in respect of Fertiliser Units

6742. SHRI R. L. BHATIA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be be pleased to state:

(a) whether the high level action committee of experts on public sector undertakings has pointed out "organisational gaps" in fertilizers units and suggested immediate introduction of scientific measures for inventory control to enable them to pick up production;

(b) if so, the reaction of Government thereto and what steps are proposed to be taken to set matters right in this direction; and

(c) whether this committee has also suggested the installation of captive power plants for Panipat and Bhatinda Units; if so, how long it will take to put up these plants and ensure optimum production at these Units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b). The Experts Committee on public sector undertakings in its Report on the fertilizer sector has made a number of recommendations covering different aspects of the working of the public sector fertilizer plants. These include operational, financial, marketing, personnel, inventory control and other relevant matters. Government proposes to take suitable action after fully studying the report.

(c) The Committee has suggested the installation of captive power plant for the Panipat fertilizer plant. No decision has so far been taken on this recommendation.

Promotion of Production Assistant and Promotion Policy

6743. SHRI KRISHNA CHANDRA PANDEY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) how many Production Assistants were promoted as Assistant Producers or Producer in All India Radio during the last fifteen years; and

(b) what is the promotion policy of the Government in All India Radio?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) The information desired is not readily available. All India Radio has now 85 stations spread all over the country. To collect information about promotion of Production Assistants from all these stations and that too pertaining to the last fifteen years will be a tremendous and time consuming task which will not be commensurate with the effort involved,

(b) As regards promotion policy for staff artists in All India Radio, this is well defined in the Recruitment Rules for various posts. All promotions are made strictly in accordance with these Rules.

उत्तर राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक

6744. श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की एक बैठक 12 मार्च को ऊर्जा की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन राज्यों ने भाग लिया था ;

(ग) क्या उसमें ऊर्जा के उत्पादन और वितरण की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो बैठक में इस बार में लिए गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) उक्त बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों ने भाग लिया था ।

(ग) उपरोक्त बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था :—

(1) प्रत्येक राज्य तथा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति तथा उत्पादन को अधिकतम करने के उपाय ।

(2) क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजनाओं को चालू करने के बारे में प्रगति ।

(3) विद्युत कटौतियां तथा उनके प्रभावों को कम करने के लिए प्रयास ।

(4) ग्राम विद्युतीकरण ।

(घ) सम्मेलन में विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श हुआ था तथा क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की योजना को अन्तिम रूप दिया गया था । जिन पद्धतियों से परियोजनाओं को समय पर चालू किया जा सकता है, उन पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया था । अतिरिक्त पुर्जों और कोयले की सप्लाई में समन्वय की समस्याओं पर तथा रेलवे वैगनों की उपलब्धता पर भी विचार-विमर्श किया गया था तथा परस्पर सहमत उपायों पर निर्णय लिया गया था । राज्यों में विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों में सुधार में नवीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की गई थी तथा इस संबंध में प्रगति सामान्यत: संतोषजनक थी ।

100 मैगावाट बिजली के उत्पादन के लिए दिल्ली में एक नये बिजली घर की स्थापना

6745. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 100 मैगावाट बिजली के उत्पादन के लिए दिल्ली में एक नया बिजली घर स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे कब कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न विकल्प देते हुए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है । व्यवहार्यता रिपोर्ट के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

पन-बिजली योजनाओं में विदेशी सहयोग

6746. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पन-बिजली के उत्पादन में विदेशियों के साथ भागीदारी करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार इस बारे में किन-किन देशों के साथ बातचीत कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) इस देश के जल विद्युत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कई विदेशी कम्पनियों ने आम रुचि दिखाई है । तथापि, केवल एक विशिष्ट प्रस्ताव कनाडा की एक प्रमुख इंजीनियरी परामर्शदात्री फर्म, मैसर्स सर्वेयर, नेनीगर एण्ड शेनेवर्ट इनकारपोरेटेड (एस०एन०सी०) से, जिसे केरल में इदुक्की बांध के कार्यान्वयन में लगे होने के कारण भारत में कार्य करने का लम्बा अनुभव है, प्राप्त हुआ है । यह प्रस्ताव विशेषज्ञों को भेजने के लिए केनेडियन इन्टरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी (सी०आई० डी०ए०) के माध्यम से 2,50,000 केनेडियन डालर के अनुदान का है । मैसर्स एस०एन०सी० हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल विद्युत परियोजना के अन्वेषणों में सहायता देने का प्रस्ताव किया है । उन्हें उम्मीद है कि यहां 8 से 10 महीने की अवधि में कार्य पूरा कर लेंगे । इस अवधि के अन्त में मैसर्ज एस०एन०सी० तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम संयुक्त रूप से (क) एक क्षेत्र अन्वेषण रिपोर्ट (ख) व्यवहार्यता रिपोर्ट (ग) परियोजना के अनन्तिम अनुमान तथा (घ) परियोजना की निर्माण योजना प्रस्तुत करेंगे । यद्यपि सामान्यत: इन अन्वेषणों में लगभग 24 से 36 महीने का समय लगना चाहिए था, तथापि उम्मीद है कि विदेशी विशेषज्ञों के शामिल होने से यह कार्य 8 से 10 महीने

में पूरा हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप बहुमूल्य समय और मुद्रा की बचत होगी। हमारे देश को होने वाले सुनिश्चित लाभ को, मैसर्ज एस०एन०सी० के सुनिश्चित अनुभव को तथा विदेशी विशेषज्ञों हेतु विदेशीमुद्रा संबंधी कोई दायित्व वस्तुतः न होने की बात को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त परियोजना के अन्वेषण कार्य में उनके सहयोग के लिए वित्त मंत्रालय से परामर्श करके अनुमोदन दे दिया गया है।

Availability of Kerosene in Assam

6747. SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Kerosene scarcity continues unabated in Assam, particularly in rural areas and because of season for examinations, people are compelled to buy it at a price ranging between Rs. Four to Rs. Eight a litre; and

(b) what steps the Indian Oil Corporation (Marketing Division) propose to take to improve the availability position of Kerosene in Assam.

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). During 1980-81, kerosene scarcity had been felt due to inter-mittent closure of Assam refineries as also constraints in transportation of kerosene to Assam and other North Eastern States and Union Territories. Kerosene availability from Bongaigaon refinery is expected to start soon. The oil companies have also been asked to maximise kerosene despatches from outside to the Assam area. The Oil Coordination Committe is monitoring the situation.

Setting up of Polyester Fibre unit at Dhaligaon, Assam

6748. SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bongaigaon Refinery and Petrochemicals Ltd. propose to set up the Polyester Fibre Unit at Dhaligaon (Bongaigaon), and if so, the details thereof;

(b) whether necessary steps for finalising the foreign collaboration for supply of technical know-how and supply of technical consultancy services for providing engineering services have been finalised; and if so, the details thereof;

(c) whether perspective planning had been undertaken for consumption of yarns by handlooms and powerlooms for fabrication in Assam itself to provide a fillip for industrial development and not despatch it outside the State; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir. The capacity of plant will be 30,000 tonnes per annum.

(b) The foreign collaborator for the supply of technical know-how and engineering services for this project has been selected and the terms are being finalised.

(c) and (d). The extent of utilisation of Polyester Staple, fibre in Assam by the existing and proposed spinning mills, and of blended yarn by handlooms and power looms is being worked out

Discussion for oil exploration in Italy

6749. SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether during his recent visit to Italy he had discussion for co-operation in the field of oil including oil exploration, production and refining;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) to (c). The Minister availed of the occasion to discuss generally among other subjects cooperation in the field of oil exploration and production such as supply of equipment. We have extended an invitation to the President of ENI of Italy to visit India to discuss the possible areas of cooperation.

Purchase of diesel and kerosene from Spot Market

6750. SHRI JANARDHANA POOARY:
SHRI M. RAMGOPAL REDDY:
SHRI S. M. KRISHNA:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have floated a global tenders recently to purchase HSD and kerosene from the spot market; which of the countries whose tenders have been accepted;

(b) the quantity of each to be purchased and when delivery expected to be made;

(c) what is the country's high speed diesel requirement for 1980-81;

(d) how much will be met from indigenous production; and

(e) steps taken for optimising the production in the refineries?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). Yes, Sir, Indian Oil Corporation floated a global tender recently for the purchase of HSD and Kerosene from spot market. It would not be in public interest to disclose further details in this regard.

(c) and (d). The country's requirement of high speed diesel oil for 1980-81 is estimated at 10.3 million metric tonnes, out of which indigenous production is estimated at 7.3 million metric tonnes.

(e) Secondary processing facilities and expansion are under implementation at the refineries in Barauni Cochin, Bombay, Visakh and Madras to increase the production of diesel and kerosene.

Per capita consumption of electricity in India as compared to other countries

6751. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what is the national per capita consumption of electricity as on 31st March, 1981, 31st March, 1980, and 31st March, 1979 and the figure for each one of Indian States/Union Territories;

(b) how does it compare with the national per capita consumption in respect of some; (i) European countries (ii) Asian countries and USA and Canada; and

(c) steps taken so far and proposed to be taken to provide more electricity to the consumers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) A statement showing the per capita consumption of electricity in various

States/Union Territories as on 31st March, 1979 and 31st March, 1980 is enclosed (Statement-I).

(b) The per capita consumption of electricity in India is quite less as compared to European countries and other Asian countries. A statement showing per capita consumption of electricity in respect of European countries, Asian Countries and U.S.A. and Canada is enclosed (Statement-II).

(c) The primary responsibility to generate electricity vests with the State Governments/State Electricity Boards. A number of power projects are under execution by the State Electricity Boards. Besides this, a number of Super Thermal Power Stations in Central Sector are under execution to meet the growing needs of the consumers. Rural electrification also is being given considerable importance by the government, in order to provide electricity to more consumers throughout the Country. In the Sixth Plan, it is proposed to electrify one lakh new villages and 25 lakh additional pumpsets in the rural areas.

Statement-I

Annual Per Capita Consumption of electricity during 1978-79 & 1979-80
(Utilities & Non-Utilties)

(In KWH)

Name of the Region/State	1978-79	1979-80*
Northern Region.		
1. Haryana	211.41	201.71
2. Himachal Pradesh	51 31	56.61
3. Jammu & Kashmir	71.05	72.95
4. Punjab	303.14	314 06
5. Rajasthan	92.98	101.46
6. Uttar Pradesh	87.99	86.57
7. Chandigarh	350.89	321.84
8. Delhi	361.89	380.68
SUB-TOTAL	124.07	125.95
Western Region.		
1. Gujarat	231.19	242.50
2. Madhya Pradesh	96.47	95.99
3. Maharashtra	229.61	226.37
4. Goa, Daman & Diu	203.98	258.15
5. Dadra & Nagar Haveli	55.12	53.84
SUB-TOTAL	182.18	183.54

Name of the Region/State	1978-79	1979-80*
Eastern Region.		
1. Bihar	87.46	80.60
2. Orissa	114.70	109.71
3. West Bengal	118.45	114.28
4. A & N Islands	39.00	36.01
5. Sikkim	34.46	15.81
SUB-TOTAL	103.57	98.02
Southern Region.		
1. Andhra Pradesh.	93.02	97.54
2. Karnataka	148.74	146.35
3. Kerala	97.43	99.11
4. Tamil Nadu	184.05	181.03
5. Pondicherry	224.44	219.95
6. Lakshadweep	19.43	26.29
SUB-TOTAL	133.39	133.70
North Eastern Region.		
1. Assam	36.94	35.66
2. Manipur	4.58	6.02
3. Meghalaya	37.50	31.56
4, Naga'and	29.80	30.52
5. Tripura	10.76	12.98
6. Arunachal Pradesh	10.85	11.81
7. Mizoram	6.84	5.82
SUB-TOTAL	31.82	30.89
ALL INDIA	130.94	130.48

*Provisional.

Statement - II

Statement showing per Capital Electricty consumption in respect of European Countries & Escap Countries for the year 1976.

Name of the Country	Per Capita Consumption (KWH)
A European Countries:	
1. France	3711
2. Germany (G.D.R.)	4381
3. Germany (F.R.G.)	4446
4. Hungary	2100
5. Italy	2511
6. Poland	2523
7. Spain	2063
8. Sweden	9525
9. Switzerland	4672
10. U.S.S.R.	3931
11. U.K.	4245
12. Yugoslavia	1718
13. Canada	11148
14 U.S.A.	8974
B Escap Countries:	
1. Australia	4337
2. Indonesia	22.7
3. Iran	348
4. Japan	4014
5. Mangolia	512
6. New Zealand	5896
7. Hongkong	1635
8. Phillippines	307
9. Singapore	1772
10. Nepal	8.2
11. Thailand	214
12 INDIA	119.4

*Figures pertain to 1975.

SOURCE:— *For Countries under 'A'* : Electric energy-Statistics for Europe '1975' Published by United Nation Edition, 1977.

SOURCE:— *For Countries Under 'B'* : Electric power in Asia and the Pacific 1975 and 1976 Published by United Nations, Edition 1978.

Production of Documentary/Feature Films in Regional Languages

6752. PROF NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTIG be pleased to state:

(a) whether Government encourage the production of documentary/feature films in regional languages spoken by a vast majority of the people but not included in the eighth schedule in the Constitution of India;

(b) if so, the names of the films which have been financed by the Government directly either partially or wholly during the last five years, for each one of such languages;

(c) the nature of assistance offered by the Government for this purpose to private producers; and

(d) if not, the reasons therefor and the likely date by which such a decision would be taken?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) to (c). The Films Division produces documentary films in Hindi or English as the basic version. These films are dubbed in all the regional languages included in the Eighth schedule of the Constitution. However, some films have also been dubbed in languages such as Konkani, Khasi, Ladakhi, Manipuri and Nagamese. During the last five years, the Films Division had also produced a film 'Paranye Ni' in Rajasthani dialect on Family Planning and two films "For a Rainy Day" and 'Book of Wealth' were dubbed in Manipuri language. A film on Family Planning in Himachal Pradesh dialect and another film in Nagamese are also under production.

2. To encourage production of films in regional languages, a scheme for setting up of two film production Units in Calcutta and Banagalore covering eastern and southern regions for producing rural oriented films in 16 mm has been included in the Sixth Five Year Plan. The production Units are likely to start functioning during 1981-82. These Units are expected to produce films not only in the regional languages included in the eighth schedule of the Constitution but also rural and tribal dialects of the regions concerned.

3. The Films Division encourages private producers by engaging them for production of documentary films. The National Film Development Corporation also encourages private film production by grant of loans. The loans are given on quality considerations, irrespective of the langauge of the film. One application for production of a film in Mizo language is under consideration of the NFDC.

(d) Does not arise.

Total power consumption in Orissa

6753. SHRI CHITAMANI JENA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what are the details regarding the total power consumption in the State of Orissa;

(b) what are the details regarding the percentage of power that is being utilised by the Central Government industries; and

(c) whether Government propose to allocate any special funds to Orissa for generating any special funds in order to meet the demands of the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Total power consumption in the State of Orissa for the year 1980-81 was about 3105 MU including transmission and distribution losses.

(b) About 28.69 per cent of the power available in Orissa was utilised by the Central Government undertakings.

(c) Provision of outlays for power schemes of the State is made on the basis of the discussion of the States proposals for the Sixth Five Year Plan and the Annual Plan.

Drilling in West Bengal

6754. SHRI R. P. DAS: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the final result of drillings at Radha, Dagogram in West Bengal;

(b) whether a second well is going to be drilled at Radha; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Testing of Radha well in West Bengal by deep drilling rig has not yielded any positive results. Further testing is proposed to be taken up by workover rig. Debagram well drilled by Indo-Stanvac Petroleum Project in 1958 was found dry.

(b) No, Sir, but another well "Abhay-1" located between Radha and Debagram is currently under drilling.

(c) Does not arise.

Work-to-rule resorted by Employees of Koyali Refinery

6755. SHRI S. M. KRISHNA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the loading of tank wagons and petroleum products had been severely crippled as a result of 'work-to-rule' resorted to by the workers of Koyali refinery in March last;

(b) if so, what are the demands of the workers; and

(c) the steps Government propose to take to maintain the uninterrupted supplies to north western region and other areas fed by the Koyali Refinery and against such of the members of the staff of the IOC at Koyali who indulge in obstructing the outgo of products from there?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) to (c). The Gujarat Refinery Kamdar Sangh resorted to 'work-to-rule' agitation from 28-2-1981 as a result of which the supply of petroleum products was adversely affected. The situation improved after the deployment of Home Guards who started the loading and despatch of petroleum products by tank wagons from 14-3-1981. The agitation has been called off on 2nd April 1981. The main demand related to exgratia payment in addition to bonus of 20 per cent permissible under the Bonus Act.

Alleged misappropriation of Funds by M/s. Pure Drinks, (New Delhi), Limited

6756. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3010 on 13th March, 1979 regarding permission to M/s Pure Drinks for calling Public Deposits and to state:

(a) what are the findings of the examination of the complaints received from 2 employees of Pure Drinks (New Delhi) Limited about large scale misappropriation of Company funds; and

(b) what actions is proposed to be taken?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b). Orders were issued for inspection of the books of accounts and re-

cords of M/s Pure. Drinks Company Private Ltd. under Section 209A of the Companies Act, 1956. The Inspection Report has however not yet been received. Actions as warranted under the provisions of the Companies Act, 1956 will be taken on the basis of the review of the Inspection Report when received.

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को पेट्रोल पम्पों का आवंटन

6757. **श्री कृष्ण दत्त सुलतान पुरी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पिछले तीन वर्ष के दौरान आवंटित किये गये पेट्रोल पंम्पों की संख्या क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने इन पेट्रोल पम्पों के आवंटियों से इस आशय का अधिवास प्रमाण पत्र कि क्या वे हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं अथवा किसी अन्य राज्य के, मांगा है और क्या इस बारे में ब्योरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, एक ।

(ख) जी, नहीं ।

हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में तेल छिद्रण कार्य

6758. **श्री कृष्ण दत्त सुलतान पुरी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाडी क्षेत्रों के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां आगामी वर्षों में तेल हेतु छिद्रण –कार्य किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां सर्वेक्षण किये जा चुके हैं और क्या इस बारे में पूरा ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ? और

(ग) इस पर सरकार द्वारा कितना खर्च किये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : यह समझा गया है कि माननीय सदस्य ने हिमाचल प्रदेश और अन्य निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में सूचना मांगी है । उत्तर इस प्रकार है :—

(क) हिमाचल प्रदेश और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के पवतीय इलाकों में विशेष भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य सितम्बर, 1981 से जून 1983 के दौरान किये जाने का प्रस्ताव है । जिन स्थानों में खुदाई कार्य अपनाया जा सकेगा उनका निर्णय इस के बाद ही होगा ।

(ख) भूगर्भ विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण जम्मू और कश्मीर , हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में किये गये हैं । जून, 1981 तक वहां कुल मिलाकर 36 पार्टी वर्ष भूकम्पीय सर्वेक्षण, 16 पार्टी वर्ष गुरुत्व चुम्बकीय सर्वेक्षण और 78 पार्टी वर्ष भूगर्भीय सर्वेक्षण पूरे कर लिये गये हैं ।

(ग) 1980–85 के लिए पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों में खुदाई कार्य और सर्वेक्षणों पर मोटेतौर पर 14.92 करोड रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है ।

हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

6759. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना कब तक की जायेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उस पर कितने व्यय का अनुमान है ;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश में टेलीविजन केन्द्र की मांग के सम्बन्ध में उस राज्य के संसद, सदस्यों द्वारा गत तीन वर्षों में भेजे गये पत्रों की मुख्य बातें सभा पटल पर रखी जायेंगी ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) छठी "योजना" प्रस्तावों (1980–85) में हिमाचल प्रदेश के कसोली में 10 किलोवाट के एक रिले ट्रांसमीटर की स्थापना शामिल है जो जलंधर दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों को रिले करेगा। इस रिले केन्द्र के छठी "योजना" अवधि के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है। कसोली रिले केन्द्र की सेवा परिधि 150 किलोमीटर होगी जिसके अन्तर्गत 13,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आयेगा।

(ख) से (घ). 127.75 लाख रुपए। संसद सदस्यों द्वारा शिमला, कसोली, धर्मशाला और कांगड़ा में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुरोध किये गये हैं। संसाधनों की कमी और उपयुक्त स्थान का अधिग्रहण करने में पेश आई कठिनाइयों के कारण छठी "योजना" अवधि के दौरान केवल कसोली में ही दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर की स्थापना की योजना को हाथ में लेना संभव हुआ।

Names of newspapers/organisations attacked and assulted

6760. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what are the names of newspapers/organisations which were attacked and newspapermen assulted in the last one year, State-wise list;

(b) whether Government of India had taken note of the serious situation and instructed the State Governments to ensure adequate protection to newspaper organisations and to newspapermen so that they can do their work without fear or favour; and

(c) if so, give details of such instructions and the reaction of the respective State Government thereafter.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) to (c). A Statment is attached.

Statement

Certain press reports of alleged man-handling and attacks on journalists have come to the notice of the Government. Journalists like other citizens are entitled to protection of their lives and liberty under the normal laws of the land.

2. Even though no specific instructions might have been issued by the Government to the State Govern-

ments the fact remains that 'public order' is a state subject and it is the reponsibility of the States Government to take necessary steps to provide protection to newspapers/organisations and to newspapermen.

3. Under the Press Council Act, 1978, the Press Council of India has been established with effect from 1-3-1979 for the purpose of preserving the freedom of the Press and of maintaining and improving the standards of newspapers and news agencies in India. It is an autonomous and statutory body; it is the appropriate authority to look into allegations of violations of the freedom of the Press on receipt of a complaint or *suo-motu*.

4. The Press Council has informed that it is seized of the following cases of arrests and manhandling of journalists and inquiries in this behalf are pending:—

(i) Complaint of Shri Vikram Rao, former Secretary General, Indian Federation of Working Journalists regarding the arrest of Shri C. B. Kaul, Correspondent, "Indian Express" Jammu on the charge of filling news reports which might incite communal disharmony.

(ii) Complaint of Shri Vikram Rao, former Secreatry General, Indian Federation of Working Journalists regarding the detention and prosecution of Shri P. K. Jain, Aligarh Correspondent of "Nav Bharat Times" on charges of false reporting.

(iii) *Suo-motu* action under section 13(2) (e) of the Press Council Act, 1978 regarding news item captioned "Alleged Police Excess on Journalists" appearing in "The Hindustan Times" on February 23, 1981.

(iv) Complaint of assault on Shri Narendra Mohan, Editor, "Dainik Jagran" at Lucknow reportedly by a section of the Journalists.

(v) Complaint of assault on the Editor, "Lankesh Patrika". Bangalore by some anti-social elements for certain writings in his paper exposing the misdeeds of these elements.

5. The above cases being at various stages of inquiry, it may be premature to say whether the arrests of Journalists in the said cases had the effect of impinging on the freedom of the Press.

6. Apart from the above cases, some newsreporters with regard to the attack on three newspapers offices viz. "Samaj", "Prajatantra", and Mathrubhumi" at Cuttack and assaulton journalists, by 150 miscreants, have come to the notice of the Press Council. Government of Orissa has informed that the publication of a baseless report in three newspapers of Cuttack on 8-3-81 scandalising some students of S.C.B. Medical College, Cuttack had enraged the students of that college. One of the three newspapers, namely 'Samaj' had published on 9-3-81 an item contradicting the earlier news item but the other two newspapers, namely, 'Prajatantra' and 'Mathrubhumi' did not carry such contradiction on 9-3-81. The students of the Medical College had gone to the offices of the three newspapers and had protested violently against the publication of false news. Timely intervention by the local administration brought the situation under control. However, the newspapers stopped publication for one day to protest against the incident and have since resumed publications. Six Medical College students including President of the College Union had been arrested but subsequently released on bail. Principal of the Medical College had apologised for conduct of his students. Appropriate legal action has been taken against the miscreants. Damage to property is small and nature of violence cannot be conidered to be significant. All preven-

tive measures have been taken by the State Government to ensure that no such untoward incident takes place in future.

7. This incident also highlights the question of right to privacy the citizens. In this case, admittedly, a lady student of the Medical College, Cuttack was scandalised by the publication of a totally false item, damaging her character and reputation. No contradiction was published in the two newspapers. Apparently it is this which provided the reaction of the students. The Government has repeatedly drawn attention, of the Press, to the need to verify the facts before publishing a matter that may adversely affect a citizen's right to privacy.

8. Government of Uttar Pradesh have informed that only one incident of assault on Journalist has come to light in Varanasi recently in which prompt action has been taken and all accused have been arrested. Government of Uttar Pradesh have further informed that all District Magistrates and Superintendents of Police have already been altered to help journalists perform their duties with a sense of freedom and confidence.

9. Government of Pondicherry has informed that one Shri Dev Raj of daily Thanthi Pondicherry lodged a complaint with the police that he was assaulted on 8-12-1980 by S/Shri Saielu, Veerappan, Shri Veera, Bacthavachalam and 20 other advocates in the premises of bar association, Pondicherry when he went there to collect certain news item. A case under Sections 143, 341, 342, 323, 149 and 506 of Indian Penal Code has been registered against the accused persons and the case is under investigation.

बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में बांधों का निर्माण

6761. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य में जिन नदियों पर बांध बनायें जायेंगे उन के नाम क्या हैं ;

(ख) उन पर व्यय के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है और कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने बिजली के उत्पादन के लिए योजनायें बना ली हैं और उन्हें केन्द्र सरकार के पास प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति के लिए भेज दिया है और उन योजनाओं के लिए कितनी कितनी धनराशि की मांग की गई है और क्या इस सम्बन्ध में ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का, उनके लोगों की सोपानबद्धता का तथा इन परियोजनाओं पर खर्चे के लिए सिफारिश की गई राशि का ब्यौरा, जिसे वार्षिक योजना के विचार-विमर्शों के दौरान अंतिम रूप दिया गया था, विवरण में दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त, सतलुज नदी पर नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना (1020 मेघावाट) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और निवेश और लागत का हिस्सा लगाने की तथा परियोजना के कार्यान्वयन की

व्यवस्था करने की त्रिपक्षीय व्यवस्था का अनुमोदन योजना आयोग ने कर दिया है। इस परियोजना से 1985–90 की योजना अवधि के दौरान तथा उस के बाद लाभ प्राप्त होने की आशा है।

(ग) हिमाचल प्रदेश प्राधिकारियों से बानेर (6 मेगावाट), थिरोट (3 मेगावाट); होली (4.5 मैगावाट) तथा नेग्रोगाल (6 मैगावाट) जल विद्युत परियोजनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इन स्कीमों के संबंध में ब्यौरा विवरण 2 में दिया गया है।

विवरण—I

हिमाचल प्रदेश में इस समय निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	नदी/बेसिन	लाभ (मेगावाट) 1980–85 के दौरान	लाभ (मेगावाट) 1985–90 के दौरान	वार्षिक योजना (81–82) पर विचार विमर्श के दौरान योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गई निधि (लाख रु० में) 1980–85	1981–82
राज्य स्कीमें						
आन्ध्रा	15	आन्ध्राखंड/यमुना	15	—	960	190
विन्वा	6	विन्वाखंड/व्यास	6	—	583	141
रोंगटोंग	2	रोंगटोंग नाला/व्यास	2	—	325	41
भावा	120	भाबाखंड/सतलुज	—	120	4600	545
बस्सी विस्तार	15	उहल/व्यास	15	—	138	113
केन्द्रीय स्कीमें						
बैरा स्यूल (केन्द्रीय)	180	बैरा, स्यूल, भालेध	60	—	4600	1751
व्यास नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से						
देहर विस्तार (सांझा)	330	व्यास	330	—	3077	1230
पोंग विस्तार (सांझा)	120	व्यास	120	—	578	197

विवरण—II

हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं की तकनी की जांच की प्रगति

स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	रिपोर्ट/संशोधित रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	वर्तमान स्थिति
नायगाल	6	अप्रैल, 73	1.51	संशोधित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
कोल बांध	600	1976	22.2	संशोधित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
बानेर	6	नवम्बर, 78	4.11	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है ।
होली	4.5	सितम्बर, 79	3.425	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है ।
थिरोट	3	मार्च, 80	4.16	परियोजना प्राधिकारियों से जल संचयन संबंधी आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए हाल ही में अनुरोध किया गया है । उत्तर प्राप्त हो गए हैं और इस समय जांच की प्रोन्नत अवस्था में हैं ।

सिनेमाघरों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

6762. **श्री निहाल सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमाघरों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में इस सभा के सामने भूख हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उन्हें पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : जी हां । न्यू सिने एम्पलाईज यूनियन रजिस्टर्ड के लगभग एक दर्जन प्रतिनिधियों ने सूचना और प्रसारण मंत्री के निवास स्थान के सामने धरने का

आयोजन किया था । उनके आगमन के कुछ ही घंटों के अन्दर, मंत्री जी उस समय अपने निवास स्थान से बाहर थे जब कर्मचारी धरना देने के लिए आए थे, वापस आने पर उनसे मिले और उनको बताया कि मंत्रालय सिने कर्मी विधेयक, जो सिनेमाघरों के कर्मचारियों को भी कवर करेगा, को पेश करने का पहले ही निर्णय ले चुका है । प्रतिनिधि इससे सन्तुष्ट हो गए और तुरन्त वहां से चले गए ।

Non-declaration of dividend by Sugar Mills in Tamil Nadu

6763. SHRI D. S. A. SIVAPRAKASAM: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many Sugar Mills in Tamil Nadu State have not declared any dividend so far since they started production;

(b) whether Aruna Sugar Mills is one of them; and

(c) if so, the reasons for non-declaration of the dividend?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIVSHANKAR): (a) According to the information available with the Ministry of Agriculture, Department of Food, there are 22 sugar mills operating in Tamil Nadu. Of these, 9 are in the cooperative sector, 3 are owned by two Government companies and 10 are owned and operated by 10 non-Government companies. 9 of the 10 non-Government companies have declared dividend for one or more years since they started production. The 10th non-Government company, namely, M/s. Palar Sugars Pvt. Ltd., has not declared dividend during any of the years 1971 to 1978. The two Government companies operating the 3 sugar mills have not declared any dividend since they were registered in 1974 and 1976 respectively. Sugar mills in the cooperative sector are not registered under the Companies Act and as such information about the dividend declared by them is not available in this Department.

(b) No, Sir. Aruna Sugar Mills has declared dividend during a number of years.

(c) Does not arise.

Capital investment in Birlas Industries

6764. SHRI RAJESH KUMAR SINGH:
SWAMI INDERVESH:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state the total share capital investment made up-to-date in the Industries run by Birlas in India and abroad?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): The aggregate paid-up capital (in 1979) of the companies in India belonging ot the Birla Group, as per registrations under section 26 of the MRTP Act as on 31-12-1979, amounted to Rs. 156.19 crores. The aggregate value of investments made by these companies in the equity capital of the joint ventures abroad as on 1-1-1981 was Rs. 11.34 crores.

High salaries to Birla Executives

6765. SHRI RAJESH KUMAR SINGH:
SWAMI INDERVESH:

Will the Minister LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it has come to the notice of Government that the Directors and Executives of Birlas are being paid very high salaries and other amenities far in excess of what is prescribed by the Company Law Board;

(b) whether Government propose to take any action against Birlas in the light of Company Law; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) to (c). The administrative guidelines prescribed by the Government ordinarily apply to the Managing/Wholetime Directors or Managers of public limited companies and private companies which are subsidiaries of public limited companies. The remuneration payable to other Company Executives does not require approval of the Central Government under the Companies Act, 1956 except where such Executives come within the purview of Section 314(1B) of the Companies Act, 1956.

No separate information with regard to the violations, if any, of the sanctions issued by the Government in respect of the managerial personnel of the companies belonging to the Birla Group is available in the Department.

The violations of the sanctions etc. issued by the Central Government is a matter which would generally be looked into by the statutory auditors of the companies and in case of any such violation they are expected to qualify their report on the basis of which necessary action is taken by the Department. The Department looks into this matter independently also, particularly during the course of inspection under Section 209A and investigations under Sections 235/237 of the Companies Act, 1956. The Registrars of Companies may also look into these points during the course of technical scrutiny of the balance sheets of the companies.

Amount spent by Birlas on Executives

6766. SHRI RAJESH KUMAR SINGH:
SWAMI INDERVESH.

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that huge amount is spent on the executives of Birlas by their Companies on account of tours, housing, lodging, boarding and other amenities;

(b) what is the amount spent by Birlas on each executive on the heads mentioned in para (a) above; and

(c) whether Government propose to impose ban on such expenditure and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b). It is presumed that the Hon'ble Members are having in view employees other than Managing/Wholetime Directors as 'executives'. As per registrations under Section 20 of the MRTP Act, 1969, as on 31st December, 1979, there were 70 companies belonging to the Birla Group. Each of these companies may be employing several Executives. The data in regard to the amount spent on the Executives (other than Directors etc.) by companies on account of tours, housing and boarding and lodging and other amenities is not required to be furnished under the provisions of the Companies Act and is, therefore, not available with this Department. However, Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 provides that the report of the Board of Directors attached to the balance sheet of a company shall include a statement showing the name of every employee of the company who, during the year was in receipt of remuneration (including perquisites like housing, use of company's car etc.) in the aggregate of not less than Rs. 3000 per month.

(c) There is presently no proposal under consideration to place a ban on the expenditure of the type referred to by the Hon'ble Members in relation to such employees. Under

the Companies Act, 1956, only the remuneration (including perquisites of housing, use of company's car, etc.) payable to the Managing/Wholetime Directors/Managers of public limited companies and private limited companies which are subsidiaries of public limited companies requires approval of and fixation by the Central Government. The remuneration payable to the Executives does not require approval of the Central Government except where such Executives come within the purview of Section 314(1B) of the Companies Act.

Losses shown by Southern Bottlers (Pvt.) Ltd., Patiala

6767. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Balance Sheet of Southern Bottlers (Private) Limited, Patiala shows a cumulative loss of Rs. 51.9 lacs;

(b) whether it has advanced Rs. 39.4 lacs as interest free loans to Charanjit Singh and Daljit Singh without stipulation for repayment;

(c) whether under these circumstances the creditors are safe; and

(d) the reasons for which the Registrar of Companies does not file a winding up petition under Section 439(1)(c)?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) Yes, Sir. The balance sheet of M/s. Southern Bottlers (Private) Limited for the year ending 31st August, 1979 showed a cumulative loss of Rs. 51.90 lakhs.

(b) According to the said balance sheet a sum of Rs. 39.44 lakhs has been shown as debts due from Shri Charanjit Singh and Shri Daljit Singh. There is, however, no indication in the said balance sheet whether these debts are interest free and without stipulation for repayment.

(c) As per the said balance sheet, the company had tangible assets of Rs. 83.63 lakhs as against its total liabilities of Rs. 130.58 lakhs (i.e. secured loan of Rs. 9.71 lakhs and unsecured loan of Rs. 1.26 lakhs and current liabilities of Rs. 119.61 lakhs which includes a sum of Rs. 101.09 lakhs advanced by Group companies who are the major creditors). The net worth of the company was, thus negative.

(d) The Registrar of Companies, Punjab, Jullundur with whom the company is registered has issued a show cause notice to the company as to why action under Section 433(e) read with Section 439(5) of the Companies Act, 1956 should not be taken for winding up of the Company.

Alleged violation of companies laws by M/s. South India Corbonic Gas Industries Ltd.

6768. SHRI SATISH PRASAD SINGH:
SHRI D. M. PUTTE GOWDA:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is true that M/s. South India Carbonic Gas Industries Limited, Madras has violated companies laws under Section 417 of the Companies Act;

(b) if so, the action taken by Government against this company; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) The company had contravened the provisions of Section 417 of the Companies Act, 1956 by not depositing in the manner prescribed under law the amounts received by it as security deposits from its employees for the years ended 31-10-77 and 31-10-78. The amounts involved in respect of the aforesaid years were Rs. 14,575/- and Rs. 15,666/- respectively. These

outstandings were, however, deposited by the Company in the Bank of India, Madras in December, 1979.

(b) and (c). The matter is under consideration of the Regional Director.

Financial help by Italian Banks for Thal Vaishet Fertilizer Project

6769. SHRI BHIKU RAM JAIN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several banks in Italy had expressed willingness for financing the Thal Vaishet gas based fertilizer project for which the World Bank had denied loan;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). M/s Snamprogetti of Italy have forwarded the offers of Bankers Trust Company of Italy for financing the foreign exchange requirements of the Thal Vaishet fertilizer project.

(c) The offers are being examined by the Government.

Loss sustained by Southern Bottlers Pvt. Ltd.

6770. SHRI SHIBU SOREN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the paid up capital of Southern Bottlers Pvt. Ltd., Patiala;

(b) what is the accumulated loss of the Company;

(c) what are the loans taken by Shri Charanjit Singh and Shri Daljit Singh from the Company; and

(d) if the losses of the Company is far excess of the paid up capital the reasons for not taking action to winding up the Company?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) to (c). As per the balance sheet of M/s. Southern Bottlers (Private) Ltd., Patiala for the year ending 31st August, 1979, its paid-up capital was Rs. 4.65 lakhs and total accumulated loss was Rs. 51.90 lakhs. The debts due on that date to the company from Shri Charanjit Singh were Rs. 25.02 lakhs and from Shri Daljit Singh were Rs. 14.43 lakhs.

(d) The Registrar of Companies, Punjab, Jullundur with whom the company is registered has issued a show cause notice to the company as to why action under Section 433(e) read with Section 439(5) of the Companies Act, 1956 should not be taken for winding up of the company.

STATEMENT CORRECTING REPLY TO U.S.Q. No. 7369 DT. 17-4-1979 *RE.* RELEASE OF RAW MATERIALS TO M/S. I.D.P.L. PFIZER AND HOECHST

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): I invite attention of the House to reply given to Unstarred Question No. 7369 in this House on 17th April, 1979. In reply to part (a) of the Question, details of currently canalised raw materials (drugs) given to I.D.P.L, Pfizer and Hoechst during 1976-77 and 1977-78 were given in a Statement. In that Statement, under the heading 'I—IDPL', against S. Nos. 4 to 6, for the words "Streptomycin", the words 'Erythromycin' may be read. The typographical error which was detected at the time of fulfilling assurance with regard to the reply is regretted.

I, therefore, crave the indulgence of the House to the extent mentioned above.

12 hrs.

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

FIRING ON FARMERS OF NIPPANI, KARNATAKA, AGITATING FOR HIGHER TOBACCO PRICES

(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Habour): I seek your permission... (*Interruptions*).

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur): I have submitted an adjournment motion... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Please sit down.

SHRI NIREN GHOSH (Dum Dum): On the question of remunerative price for tobacco growers and their movement...

MR. SPEAKER: I have admitted a calling attention tomorrow. (*Interruptions*).

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I seek your permission. If I obey the Chair, I never get a chance! (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You were not here, Mr. George, when I explained to this House that we are going to have something more than that. Tomorrow I am calling the Business Advisory Committee and we are fixing a date for discussion. It may be tomorrow, it may be day after, on some sort of consensus, so that in that context we can discuss it. For tobacco, this is only a question of remunerative price.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is the Commerce Ministry's affair; the Union Government is responsible for fixing a remunerative price.

MR. SPEAKER: That is why I am trying to bring a calling attention tomorrow because the Minister was not there. I explained it early morning, Mandalji. I had no option because the Minister was not here.

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : हम लोगों को पहले सुन लीजिए, फिर आप तय कीजिए... (**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल बुला लिया है डिशकशन के लिए । ...

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : हिन्दुस्तान के किसान मारे जायं, कत्ल किए जायें... (**व्यवधान**) ...

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया . . .

श्री जार्ज फर्नान्डीस: यह मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया आप को। मैंने लिख भी दिया था ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस: बन्दूक के जरिए अगर किसानों की समस्या को हल करना चाहते हैं तो हम लोग सदन में आकर क्या करें?

एक माननीय सदस्य: इस पर ऐडजर्नमेंट मोशन मंजूर कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : एडजर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता ।

श्री मनी राम बागड़ी: कामरोको प्रस्ताव मंजूर होना चाहिए ।

MR. SPEAKER: I cannot do it.

(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I seek your permission. Obeying the Chair will not mean anything at all! I have been seeking your permission from the beginning.

अध्यक्ष महोदय : आप वही बात फिर करेंगे कि यहां तो ले ली वहां नहीं ली ।

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Why do you want to put me in an awkward position unecessarily? I cannot have two rules. Can I have?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I will say something very different.

अध्यक्ष महोदय: सुनूंगा, सब की सुनूंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक कर के सब को सुनूंगा । आप बैठिए, मैं सब की सुनता हूं ।

श्री धनिक लाल मंडल: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह हैं कि आप ने बार बार कहा है और हम लोग उस से सहमत हैं । . . .

अध्यक्ष महोदय : आप कौन से मुद्दे में उठाना चाहते हैं ?

श्री धनिक लाल मंडल : यह 56 से लेकर 60 तक आप देख लीजिए । यह जो ऐडजर्नमेंट मोशन हैं । . . .

अध्यक्ष महोदय : उस का डिस्कशन नहीं हो सकता ।

श्री धनिक लाल मडल : मैं आप को री-कंसिडर करने के लिए कह रहा हूं । आप कृपा कर के मेरी बात सुन लीजिए ।

MR. SPEAKER: Discussion on the floor of the House cannot be allowed.

श्री धनिक लाल मंडल : एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। . . . (**व्यवधान**) . .

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोलते है, आप बैठिए ।

श्री धनिक लाल मंडल: आप ने जो निर्णय लिया है . . .

PROF. K. K. TIWARY (Buxar): I want to know the fate of my motion about West Bengal

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले इन को एलाऊ किया है । आप की बात भी सुनूंगा । मैंने कब इनकार किया है ? बीच में क्यों बोलते हैं ?

श्री धनिक लाल मंडल : ऐडजर्नमेंट मोशन . . .

अध्यक्ष महोदय : ऐडजर्नमेंट मोशन पर मैं कोई बात सुनने वाला नहीं हूं ।

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने जो ऐडजर्नमेंट मोशन दिया और आप ने जो उस पर निर्णय किया है वह मुझको मालूम है । मैं उसी संदर्भ में .

अध्यक्ष महोदय: नहीं और कोई बात नहीं।

No, Sir. Look here. I would again quote page 30 of the *Handbook for Members*:

> "Once a member is informed of the Speaker's decision withholding his consent, no discussion or point shall be permitted to be raised in the House either on the subject-matter of the notice or the reasons for disallowance thereof."

श्री धनिक लाल मंडल : हम आप को नियम बता देते हैं । सुन लीजिए । आप दूसरे की बात भी कभी कभी सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय: मैं सुनता हूं ।

. . . (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : आप यह बताइए कि आप का अधिकार कैसे है ?

श्री धनिक लाल मंडल: मैं आप को सुना दे रहा हूं कि मेरा अधिकार कैसे होता है ? आप नियम 60 का परन्तुक (2) पढ़ लीजिए—

"परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष उस में उल्लिखित मामले के बारे में पूर्ण तथ्यों से अवगत न हो . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अवगत हूं ।

श्री धनिक लाल मंडल : एक मिनट सुन लीजिए ।

"तो वह अपनी सम्मति देने या इन्कार करने से पूर्व उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़ कर सुना सकेगा और सम्बन्धित मंत्री और / या सदस्यों से तथ्यों पर संक्षिप्त विवरण सुन सकेगा और उस के बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय देगा ।"

तो मेरा अधिकार बन जाता है कि आप से निवेदन करूं ।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मेरी बात सुनिए—

No; not allowed. Disallowed.

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : आप स्पीकर रहे हैं और फिर यह जिद करते हैं ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, आपने कहा इस सम्बन्ध में आप ध्यानकर्षण प्रस्ताव भी ले रहे हैं और उसके बाद आवश्यकता हुई तो कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशन रखने पर विचार किया जाएगा । मैं यह कहना चाहता हूं जो ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव था या डिबेट का जो मामला था वह आज तक था और अब जो वहां पर परिस्थिति पैदा हो गई है उसमें 11 आदमी मारे गएहैं और 600 घायल हुए हैं । इसके पहले भी सरकार द्वारा वहां पर गोली चलाई गई है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, एडजर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता ।

श्री राम विलास पासवान : अब जो स्थिति है उस र बहस जारी है । हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, आप तत्काल इस पर बहस करवायें ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं । यह तो सरकार जाने । (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मेरा औचित्य का प्रश्न है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बारी बारी से सभी को बुला रहा हूं ।

व्यवधान**

MR. SPEAKER: Nothing is going on record without my permission.

*(Interruptions)***

MR. SPEAKER: I will allow you one by one.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा औचित्य का प्रश्न है कि यह जो तमाखू की कीमतों का मामला है वह केन्द्र से जुड़ा हुआ है । आपने शायद यह कहा कि मंत्री महोदय यहां नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : थे नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसलिए इस मामले पर सरकार से जल्दी बयान नहीं लिया जा सकता है । मेरा निवेदन है कि...

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यहां थे नहीं । मेरे पास पहले से था ।

I have already taken a decision.

लेकिन अब कल के लिए मैंने इसको कर दिया है, जहां तक कि भाव का प्रश्न है । ला ऐंड आर्डर स्टेट सब्जेक्ट है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, एक पहलू और भी है ...

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions)***

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप यह बताइये कि रिकार्ड पर क्या जा रहा है और क्या नहीं जा रहा है ?..

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कहूंगा वह जायेगा । आपने जो पहले कहा था वह गया था, अब जो बोल रहे हैं वह नहीं गया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं । मगर

**Not recorded.

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

अब तक जो बोला हूं वह रिकार्ड पर गया है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने इजाजत दी थी, आपसे बात हो रही थी तब रिकार्ड पर गया था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह जो इशारों में बातें हो रही हैं रिपोर्टर्स से...

अध्यक्ष महोदय : मैं बिलकुल बोलकर करता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या बोल कर रहे हैं आप ?

अध्यक्ष महोदय : बोल कर करता हूं । जब मेरी पर्मीशन होती है तब रिकार्ड होता है, जब मेरी पर्मीशन नहीं होती है तब रिकार्ड नहीं होता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमको भी तो पता लगे कब आपने पर्मीशन दी और कब पर्मीशन नहीं दी ।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप उनको इशारा करते हैं, हमको तो करते ही नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यहां से नजर नहीं आता है, मैं तो बोल कर करता हूं । पूछिये ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I had been a member of the Tobacco Board representing this House, twice. The Nippani area of tobacco growers had been in great difficulty for decades. They have been sucked.

MR. SPEAKER: What do you want to say?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: My submission is that the Commerce Ministry have been sitting over it. Representations have been given through the Tobacco Board. The whole responsibility squarely falls on the Commerce Ministry.

MR. SPEAKER: No. That is why, I have asked them...

(Interruptions)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am not going into the law and order subject. Due to the stupidity of the Commerce Ministry 11 lives have had to be sacrificed. Therefore, an adjournment motion is the only fit thing.

MR. SPEAKER: If you justify your adjournment motion, then we will see. How will you justify?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Rule 56...

MR. SPEAKER: I cannot do it. Not allowed. Now, Mr. Fernandes.

SHRI GEORGE FERNANDES: This issue had been going on for the last three weeks. In these three weeks the Government of India, the Commerce Ministry and all other concerned with fixing the price of tobacco had an opportunity to look into the matter. The farmers blocked the national highway. The matter was not only concerning... *(Interruptions)*

MR. SPEAKER: What do you want to say now? What is the point which you want to make to me?

SHRI GEORGE FERNANDES: The point which I want to make is that Parliament must consider this question. You must accept our adjournment motion.

MR. SPEAKER: No, adjournment motion is not allowed.

SHRI GEORGE FERNANDES: You must listen to me on why the adjournment motion is given notice of. It is not merely a question of prices now. There are inter-State issues involved. The question of National Highway is also involved.

MR. SPEAKER: I have explained to you that it has two aspects. One is the prices and the other is the law and order problem.

SHRI GEORGE FERNANDES: It is not a question of law and order. It was the most peaceful demonstration that could ever have been organised.

MR. SPEAKER: Now, I am not allowing. Nothing is going on record. Prof. Dandavate.

(*Interruptions*)**

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, when I and George Fernandes met you in your Chamber, you had already agreed a few days back that a Call Attention motion would be admitted on that issue. The only reason that you also stated in the House is that because the Minister for Agriculture was out of India, you did not allow that. Sir, it has been the convention in this House that even if the Cabinet Minister is out of India or is not in town, even then there is the collective responsibility and I quote a precedent. On one occasion...

MR. SPEAKER: No, Professor...

PROF. MADHU DANDAVATE: When I was Railway Minister I had handled a Call Attention motion of the Law Ministry.

MR. SPEAKER: You want it to be handled properly. That is all.

PROF. MADHU DANDAVATE: Therefore, it is a collective responsibility. With your permission I am saying that. And now if you had allowed a Call Attention motion to be answered by some other Minister, there would have been a restraint on the Karnataka Government and this situation of firing would not have arisen at all. And, therefore, an adjournment motion has been given.

SHRI GEORGE FERNANDES: You must accept our adjournment motion.

MR. SPEAKER: No, Sir. I cannot do it. (*Interruptions*)

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): My point is that the prices of tobacco are directly related to the Ministry of Commerce. Therefore, when you are deciding on the Call Attention...

MR. SPEAKER: The Commerce Minister was not here and that was why I had kept it pending...

SHRI HARIKESH BAHADUR: My point is that at that time itself that could have been discussed because the Commerce Minister was here. But you did not allow that matter. That was why all these things have happened and many people have been killed...

MR. SPEAKER: At that time we thought that it was concerning the Agriculture Minister.

SHRI HARIKESH BAHADUR: Today many people have been killed...

MR. SPEAKER: No. Now, Shri Parulekar.

(*Interruptions*).**

MR. SPEAKER: That is all right.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing should be recorded.

(*Interruptions*).**

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Mr. Speaker, Sir, I would like to invite your attention to a precedent. You had granted the adjournment motion on the deaths due to drinking in Haryana which was a State subject. If that can be a matter for adjournment motion, don't you think it is a more serious matter than the deaths due to drinking...

MR. SPEAKER: I have to explain to this House that for the last four or five days we have had something going on in this House and if you want me to apply two standards for things like this, then where do I stand?

(*Interruptions*).

**Not recorded.

MR. SPEAKER: No.

(*Interruptions*)**

MR. SPEAKER: No, I cannot.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: जार्ज साहब, इसे इतना छोटा मत करिए ।

Don't try to make my position small.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You have forced my hands. Now, do not try to put me behind.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Do not try to hustle me either way.

(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके हिसाब से चलूंगा अब आप मुझे मजबूर कर रहे है दूसरी तरफ चलन के लिए मैं नहीं कर सकता हूं ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You read out the motion.

MR. SPEAKER: Not allowed. (*Interruptions*)**

(*Interruptions*)**

PROF. K. K. TEWARY: I gave notice under Rule 184. We wanted discussion...

अध्यक्ष महोदय : टूमारो बी. ए. सी. को मोटिंग हो रही है । बी. ए. सी. को मोटिंग कल हो रही है । बी. ए. सी. डिसाइड करती है यह काम ।

PROF. K. K. TEWARY: That is all right. (*Interruptions*)**

अध्यक्ष महोदय : आप थे नहीं, सारा समझा दिया था ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कल बी. ए. सी. की मीटिंग हो रही है । उस में डिसाइड करेंगे । डेट एपान्ट करेंगे ।

(व्यवधान)**

MR. SPEAKER: Nothing will go on record without my permission.

12.15 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

PETROLEUM AND NATURAL GAS (AMDT.) RULES, 1981 AND NOTIFICATION UNDER OILFIELDS (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 1948.

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 1981 (Hindi and English versions) published in Notification No. GSR 211(E), in Gazette of India dated the 26th March, 1981, under section 10 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948.

(2) A copy of Notification No. S.O. 219(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 26th March, 1981 regarding enhancement of the rate at which royalties shall be payable in respect of mineral oils and making certain amendments in the Schedule to the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, issued under sub-section (4) of section 6A of the said Act.

[*Placed in Library. See* No. LT-2292/81].

COMPANIES (ACCEPTANCE OF DEPOSITS) AMDT. RULES, 1981

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): I beg to lay on the Table a copy of the Companies (Acceptance of Deposits) (Amendment Rules, 1981 (Hindi and English versions) published in Notification No. GSR 187(E) in Gazette

---

**Not allowed.

**Not recorded.

of India dated the 20th March, 1981, under sub-section (3) of section 642 of the Companies Act, 1956. [*Placed in Library. See* No. LT-2293/81].

DETAILED DEMANDS FOR GRANTS, 1981-82 OF MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BIRENDRA SINGH): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of Ministry of Rural Reconstruction for 1981-82. [*Placed in Library. See* No. LT-2294/81].

REVIEW AND ANNUAL REPORT OF REHABILITATION INDUSTRIES CORPORATION LTD., CALCUTTA FOR 1979-80 WITH STATEMENT FOR DELAY

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Review by the Government on the working of the Rehabilitation Industries Corporation Limited, Calcutta, for the year 1979-80.

(ii) Annual Report of the Rehabilitation Industries Corporation Limited, Calcutta, for the year 1979-80 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above papers. [*Placed in Library. See* No. LT-2295/81].

DETAILED DEMANDS FOR GRANTS, 1981-82 OF MINISTRY OF AGRICULTURE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of Ministry of Agriculture for 1981-82. [*Placed in Library. See* No. LT-2296/81].

NOTIFICATIONS UNDER CENTRAL EXCISE RULES, 1944 AND CUSTOMS ACT, 1962

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): I beg to lay on the Table:

A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under the Central Excise Rules, 1944:—

(i) GSR 242(E) published in Gazette of India dated the 31st March, 1981 together with an explanatory note making certain amendment to Notification No. 69/81-CE dated the 25th March, 1981.

(ii) GSR 263(E) published in Gazette of India dated the 1st April, 1981 together with an explanatory note regarding continuance of the concessional rate of duty applicable to gas cylinders of Indian Standards specifications, IS: 7285-1974 or IS: 7312-1974 beyond 31st March, 1981. [*Placed in Library. See* No. LT-2277/81].

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:—

(i) GSR 223 (E) published in Gazette of India dated the 28th March, 1981 together with an explanatory memorandum regarding extension of the exemption granted under Notification No. 76/78 upto 31st March, 1982.

(ii) GSR 224(E) published in Gazette of India dated the 28th

March 1981 together with an explanatory memorandum regarding extension of validity of notification No. 84/Customs dated the 19th April, 1980 exempting glass shell, when imported into India for the manufacture of electric lamp, from basic customs duty as is in excess of 10 per cent *ad valorem*, upto 31st December, 1981.

(iii) GSR 225(E) and 226(E) published in Gazette of India dated the 28th March, 1981 together with an explanatory memorandum regarding extension of validity of notification No. 200-Customs dated the 28th September, 1979 and 52-Customs dated the 1st March, 1981 upto 31st March, 1982.

(iv) GSR 260(E) published in Gazette of India dated the 1st April, 1981 together with an explanatory memorandum regarding rates of exchange for conversion of seventeen foreign currencies mentioned in the Notification into Indian currency or *vice-versa*.

(v) GSR 267(E) published in Gazette of India dated the 1st April, 1981 together with an explanatory note regarding continuance of total exemption of import duty on steel tubes meant for use in the manufacture of gas cylinders conforming to IS: 7285-1974 or IS: 7312-1974 beyond 31st March, 1981.

(vi) GSR 268(E) published in Gazette of India dated the 1st April, 1981 together with an explanatory note regarding continuance of total exemption of auxiliary duty on steel tubes meant for use in the manufacture of gas cylinders conforming to IS 7285-1974 or IS: 7312-1974. [*Placed in Library. See* No. LT-2298/81].

*(Interruptions)***

12.17 hrs.

At this stage, Shri George Fernandes and some other hon. Members left the House

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

(i) MINUTES

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI (Sitapur): I beg to lay on the Table Minutes (Hindi and English versions) of the sittings of the Committee on Papers laid on the Table relating to their Seventh Report.

(ii) SEVENTH REPORT

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: I beg to present the Seventh Report (Hindi and English versions) of the Committee on Papers laid on the Table.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

SIXTEENTH REPORT AND MINUTES

SHRI BANSI LAL (Bhiwani): I beg to present the Sixteenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings on Damodar Valley Corporation tnd Minutes of the sittings of the Committee relating thereto.

MR. SPEAKER: Now we take up Calling Attention.

Shri Rasheed Masood, Shri Rasheed Masood, Shri Rasheed Masood. He is not here.

Kumari Pushpa Devi Singh, Kumari Pushpa Devi Singh

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : स्पीकर साहब, मेरा नाम इसमें सब से पहला है ।

**Not recorded.

[شری رشید مسعود (سہارنپور)

سپیکر صاحب میرا نام اس میں سب سے پہلے ہے -]

अध्यक्ष महोदय : मैंने तीन दफा आप का नाम पुकारा था।

श्री रसोद मसूद : मैंने सुना नहीं।

شری رشید مسعود : میں نے سنا نہیں -

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप का नाम लिया था।

श्री रशीद मसूद : मैंने तो इसलिए वाक-आउट भी नहीं किया था क्योंकि मुझे यह पढ़ना था।

[شری رشید مسعود : میں نے تو اس لئے واک آوٹ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے یہ پڑھنا تھا -]

MR. SPEAKER: All right, he says he has not walked out.

12.20 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED STRANDING OF 400 INDIAN SEAMEN AT BASRAH PORT SINCE OUTBRAK OF IRAN-IRAQ WAR

SHRI RASHEED MASOOD (Saharanpur): Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:—

"The reported stranding of about 400 Indian crewmen abroad 22 mechanised vessels of India at Basrah port since the outbreak of Iran-Iraq war and the measures taken by the Government to bring them back."

(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : चेम्बर में आकर बात कीजिए, कालिंग अटेंशन यहां डिस्कस नहीं होती है।

12.21 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARSIMHA RAO): Sir,

Following the outbreak of the Iran-Iraq conflict on September 22, 1980, three Indian ships and 22 mechanised sailing vessels are presently stranded in the war zone. After earlier evacuations, the number of remaining crewmen presently stranded is 402. In addition, a large number of foreign ships have also been stranded.

The Government of India are fully seized of the problems caused by the stranding of vessels and crewmen in the war zone. The Director General of Shipping has been in touch with the owners of the ships, as well as with the All India Sailing Vessels Association, in order to arrange the evacuation of the crewmen. As early as October 7, 1980, the owners of the sailing vessels were advised by the Director General of Shipping to repatriate their crew. Approximately 100 seamen have since been repatriated.

Sir, I am adding to the information that has been sent already in the written statement. This is based on the latest report we got this morning.

We have since received from the Director General of Shipping precise figures of seamen who are stranded and those who have been repatriated from the ports of Basrah and Fao. I had mentioned the figure of repatriated of seamen as approximately 100. The actual figures are as follows: from the more disturbed port known as Fao, 88 crew members pertaining to six sailing vessels that were stranded have already been repatriated. Another 110 members of the crew are now in the process of being repatriated both from Basrah and Fao. The total number of crew members thus either already repatriated or in the process of being repatriated is 198.

[Shri P. V. Narasimha Rao]

Other shipowners have preferred to wait and watch, in the hope that the situation would improve sufficiently to enable the vessels and the crewmen to sail out together.

Some seamen of the sailing vessels are still in the zone only because the owners of the vessels, despite our advice, have been unwilling to take action for their repatriation. Despite the hostilities taking place during the last several months, there have been no reports of loss of life or injury to Indian seamen.

Our Consultate in Basrah has been in regular contact with Iraqi authorities and has taken all possible steps for the protection and welfare of the crewmen. Some reports had also been received by us that the Indian crew may be facing financial difficulties. On immediate enquiries made by us, we were assured by our Consul General in Basrah that the Indian crew were being well looked after. We have told the Consul General that in case any finances are required Government will assist the shipowners to make necessary financial remittances. The Director General of Shipping has instructed our Consul General in Basrah to repatriate at Government expense, any seamen who wishes to be repatriated or who, in the opinion of the Consul General would require repatriation. We have recently obtained the agreement of the Iraqi authorities to waive the fine of 100 dinars per head imposed earlier on our seamen seeking exit visas.

The owners of the sailing vessels have suggested that they should be permitted to sail their vessels out at high tide under their own risk. However, even though the vessels are of shallow draught, our Consulate has advised that it would be highly unsafe to attempt the passage before the channel is cleared of mines. There is also no guarantee that the vessels may not come under fire during the passage. The presence of bridges and other obstructions across the Shatt-al-Arab waterway makes it also hazardous to attempt a passage at this time. This point has been conveyed to the owners of the sailing vessels. The owners have again been advised that they should initiate action for the repatriation of the remaining seamen.

The Special Emissary of the U.N. Secretary-General, Mr. Olaf Palme, has also been engaged in active efforts to clear the Shatt-al-Arab waterway of ships stranded in the wake of the conflict. He has sought the assistaince of the International Red Cross in this regard. The Government of India have also been in direct touch with the Inter-National Red Cross.

Sir, as the House is aware, the Government of India is engaged, jointly with some other countries, in efforts directed towards bringing about a s olution to the vexed problem between Iraq and Iran. The future of the vessels stranded in the Shatt-al-Arab is linked to this whole problem. I can only assure the House that Government will spare no efforts to ensure the safety of the stranded seamen and the repatriation of those who desire to be repatriated.

श्री रशीद मसूद : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब का बयान देखकर अफसोस भी होता है और ताज्जुब भी । ताज्जुब इस बात का है कि शायद हमारी हुकूमत ने यह उसूल बना लिया है कि जिस तरीके की इन्फार्मेशन सप्लाई कर दी जाएगी, उसको उसी तरीके से पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया जाएगा, इसके अलावा कोई कोशिश नहीं की जाएगी कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ।

इस बयान को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें बहुत सी बातें सैल्फ-कंट्राडिक्ट्री हैं । एक हिस्सा पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि बहुत मदद दी जा रही है, जो लोग 7–8 महीने से बसरा में फंसे हुए हैं और दूसरा पैराग्राफ

पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जहां से चालू हुए थे, वहीं के वहीं हैं, कोई सुधार नहीं हुआ है । इसको पढ़ने से यह अंदाज होता है कि हमारी हुकूमत उन लोगों को जान के मुतालिक इतनी फिक्रमंद नहीं है, जितनी वेसल ओनर्स, जो जहाज के मालिक हैं, उनके लिए फिक्रमंद है, ताकि उनके जहाज तबाह न हों ।

एक बात काबिले तारीफ है, इसके लिए मिनिस्टर साहब की तारीफ करनी होगी कि जो जहाज कम्पनियां अपनी ओन-रिस्क पर जहाज निकालना चाहती थीं, जिसमें हमारे आदमियों का भी रिस्क था, इसके लिए उन्हें इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उन जहाज मालिकों को मदद की जाए और उनको यहां से लाया जाए, इसके बारे में मिनिस्टर साहब ने क्या किया ? हमारी सरकार बैंकों का नेशनलाइजेशन तो कर सकती है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचने के लिए "मारुति" का नेशनलाइजेशन तो कर सकती है, लेकिन इतने आदमियों की जान बचाने के लिए वैसल ओनर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकती, कोई दबाव नहीं डाल सकती । अभी तो आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने कहा कि उन लोगों को बराबर खबर रख रहे हैं, प्रोटेक्शन वैल्फेयर आफ ह्यूमन किया जा रहा है । वैलफेयर क्या हो रहा है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । एक खत जो वहां के लीडर आफ पियन ने अपने मालिक को लिखा है वह मैं पढ़कर सुना रहा हूं । यह हिन्दुस्तान टाइम्स है 27 मार्च का, इसमें लिखा है कि --

"We are starving here and the danger of being bombed looms large over our heads."

यहां आप कह रहे हैं कि वे बिल्कुल महफूज हैं, उनको सभी चीजें दी जा रही हैं और जो लोग वहां पर मौजूद हैं वे लिख रहे हैं कि हम फाके की हालत में आ गए हैं । मैं नहीं समझता कि दोनों में कौन-सी चीज सही है । आप सही कहते हैं या ये सही कहते हैं, लेकिन मुझे तजुरबा है, जब मैं 2–3 बार बाहर भेजा गया हूं, वहां पर मैंने देखा है कि हमारी जो एंबेसीज हैं, उनकी तरफ से हमारे नेशनल्स को सही तरीके से नहीं देखा जाता, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता । इसलिये मुझे यकीन है कि यह खत ज्यादा सही है बनिस्पत उस इन्फर्मेशन के जो कि आपको सप्लाई की गई है । लिहाजा आप इसको देखिए, मामला यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं ।

आपने कहा है कि ज्यादातर लोग आ गए हैं, रिपेट्रिएट कर दिए गए हैं और थोड़े से रह गए हैं ।

"....Some seamen of sailing vessels are still in the zone only...."

इसमें आपने "सम" शब्द का प्रयोग करके यह जाहिर करने की कोशिश की है कि कुछ आ गए हैं । आपने ऊपर के पैराग्राफ में बताया कि 81 आदमी आ गए हैं 483 में से और अब आप कह रहे हैं कि 86 आ गए हैं, शायद 5 और आ गए हों, आपकी जानकारी सही हो, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 81 आदमी आए हैं । अगर 483 में से 86 आ भी गए हों तब भी बाकी तो फंसे हुए हैं । वे लोग तो जिस हालत में होंगे, लेकिन, उनके घरवालों की यहां क्या हालत है इसको आप देखिए । यहां यह चल रहा है कि 7 महीने से हम यह बात चला रहे हैं, 7 अक्तूबर से यह बात चल रही है । कितने दिन में यह मामला हल हो जाएगा ? चार साल में पांच साल में या छः साल

[श्री रशीद मसूद]

में? जब यह गवर्नमेंट रहती है तब तक क्या यह हल हो जाएगा ? उन लोगों का क्या होगा जो बेचारे सफर कर रहे हैं, साइकोलोजिकल तौर पर जो बेचारे खत्म हो गए हैं, जिन के दिमाग में हर वक्त फिक्र लगा रहता है और जिन के घर वाले भी परेशान रहते हैं ?

यह भी कहा गया है कि हमारे लोग ही फंसे हुए नहीं हैं ।

"A large number of foreign ships have also been stranded."

हमारा मतलब किसी दूसरे मुल्क वालों से नहीं है । उनके कितने शिप हैं इसमें हमें दिलचस्पी नहीं है । दिलचस्पी हमारी सब से ज्यादा अपने यहां के लोगों में होनी चाहिये । वैसल्ज का क्या होता है वह उनके मालिक जानें । इसमें हमें पड़े रहना नहीं चाहिये कि हालात नार्मल हो जाए और वैसल्ज के साथ वे भी आ जाएं । वैसल्ज का कुछ भी हो यह उनके मालिक जानें । लेकिन इन लोगों को लाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ।

आपने यह भी कहा है कि आपने काउंसिल जनरल को इंस्ट्रक्शंज दी हैं कि जो लोग आना चाहते हैं उनको लाएं । लेकिन मेरी इत्तिला के मुताबिक अभी तक उनकी कोई मदद नहीं हो रही है । यह चीज 27 मार्च के इस अखबार में भी छपी है और दूसरे अखबारों में भी छपी है । इसमें भी आपने यह रखा है कि काउंसिल जनरल जिनका समझते हैं कि वे जाने के लायक हैं वे ही आएं या जो खुद आना चाहते हों, उनको लाएं । यह जिद की बात नहीं होनी चाहिये कि जिन को काउंसिल जनरल चाहें लाना वही सिर्फ आ सकते हैं । इस शर्त को आप न रखें । जो भी हैं उन सब को लाएं । यह जाहिर बात है कि वहां कोई भी रहना नहीं चाहेगा । आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी मौत के मुंह में रहना नहीं चाहेगा । वहां बमबारी हो रही है । वे होम सिक भी फील कर रहे हैं । फंसे हुए हैं । इसकी सीरियसनैस को आप समझें । हर कीमत पर आप उन को निकालें । वैसल वालों के साथ सख्ती करनी पड़े तो वह भी करें । खुद अपने पास से पैसा देना पड़े तो वह भी करें । वैसल्ज को छोड़ना पड़े तब भी आप उनको निकालें । जहाज वापिस लाने वाली बात आप छोड़ें । जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं यह आप बताएं ।

شری رشید مسعود (سہارنپور) :

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب- منسٹر صاحب کا بیان دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے اور تعجب بھی - تعجب اس بات کا ہے کہ شاید ہماری حکومت نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ جس طریقے کی انفارمیشن سپلائی کر دی جائیگی اس کو اسی طریقے سے پارلیمینٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اسکے علاوہ کوئی کوشش نہیں کی جائیگی کہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے -

اس بیان کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اس میں بہت سی باتوں سیلف کانٹریڈکٹری ہیں - ایک حصہ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت مدد دی جا رہی ہے جو لوگ سات آٹھ مہینے سے بصرہ میں پھنسے ہوئے ہیں اور دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے چالو ہوئے تھے وہیں کے وہیں ہیں کوئی سدھار نہیں

کے لیڈر آف پین نے اپنے مالک کو لکھا ھے وہ میں پڑھ کر سنا رھا ھوں - یہ ھندوستان ٹائمس ھے ۲۷ - مارچ کا اسمیں لکھا ھے کہ—

"We are starving here and the danger of being bombed looms large over our heads."

یہاں آپ یہ کہہ رھے ھیں کہ وہ بالکل محفوظ ھیں انکو سبھی چیزیں دی جا رھی ھیں اور جو لوگ وھاں پر موجود ھیں وہ لکھ رھے ھیں کہ ھم فاقے کی حالت میں آ گئے ھیں - میں نہیں سمجھتا کہ دونوں میں سے کونسی چیز صحیح ھے - آپ صحیح کہتے ھیں یا یہ صحیح کہتے ھیں لیکن مجھے تجربہ ھے جب میں ۲-۳ بار باھر بھیجا گیا ھوں وھاں پر میں نے دیکھا ھے کہ ھمارے جو ایمبیسی ھے اسکی طرف سے ھمارے نیشنلس کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا جاتا کوئی انٹریسٹ نہیں لیا جاتا - اس لئے مجھے یقین ھے کہ یہ خط زیادہ صحیح ھے یہ نسبت اس انفارمیشن کے جو کہ آپ کو سپلائی کی گئی ھے - لہذا آپ اس کو دیکھئے معاملہ یہ نہیں ھے جو آپ سمجھ رھے ھیں -

آپنے کہا ھے کہ زیادہ تر لوگ آ گئے ھیں ریپیٹریٹ کر دیا گیا ھے اور تھوڑے سے رہ گئے ھیں -

"Some seamen of sailing vessels are still in the zone only."

ھوا ھے - اسکو پڑھنے سے یہ اندازہ ھوتا ھے کہ ھماری حکومت ان لوگوں کی جان کے متعلق اتنی فکر مند نہیں ھے جتنی ویسل اونرس جو جہاز کے مالک ھیں انکے لئے فکر مند ھے تاکہ انکے جہاز تباہ نہ ھوں -

ایک بات قابل تعریف ھے اس کے لئے منسٹر صاحب کی تعریف کرنی ھوگی کہ جو جہاز کمپنیاں اپنی اون رسک پر جہاز نکالنا چاھتی تھی جس میں ھمارے آدمیوں کا بھی رسک تھا اسکے لئے انہیں اجازت نہیں دی گئی - لیکن ان جہاز مالکوں کی مدد کی جائے اور انکو یہاں سے لایا جائے اسکے بارے میں منسٹر صاحب نے کیا کیا - ھماری سرکار بلکوں کا نیشنلائزیشن تو کر سکتی ھے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے ماروتی کا نیشنلائزیشن تو کر سکتی ھے لیکن اسکے آدمیوں کی جان بچانے کے لئے ویسل اونرس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتی کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتی - ابھی تو آپ صرف ریکوسٹ کر رھے ھیں آپنے کہا کہ ان لوگوں کی برابر خبر رکھ رھے ھیں - پروٹیکشن ویلفیئر آف ھیومین کیا جا رھا ھے - ویلفیئر کیا ھو رھا ھے اسکا ایک اور اداھرن میں آپکے سامنے رکھنا چاھتا ھوں - ایک خط جو وھاں

[شری رشید مسعود]

اس میں آپنے ‘‘سم’’ شبد کا پریوگ کرکے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ آ گئے ہیں - آپ نے اوپر کے پیراگراف میں بتایا کہ ۸۱ آدمی آ گئے ہیں ۴۸۳ میں سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ۸۶ آ گئے ہیں شاید ۵ اور آ گئے ہوں آپ کی جانکاری صحیح ہو لیکن میری جانکاری کے انوسار ۸۱ آدمی آئے ہیں- اگر ۴۸۳ میں سے ۸۶ آ بھی گئے ہوں تب بھی باقی تو پھنسے ہوئے ہیں - وہ لوگ تو جس حالت میں ہونگے لیکن انکے گھر والوں کی یہاں کیا حالت ہے اسکو آپ دیکھئے- یہاں یہ چل رہا ہے کہ سات مہینے سے ہم یہ بات چلا رہے ہیں ۷ اکتوبر سے یہ بات چل رہی ہے - کس دن میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا - چار سال میں پانچ سال میں یا چھ سال میں - جب تک یہ گورنمنٹ رہتی ہے تب تک کیا یہ حل ہو جائے گا- ان لوگوں کا کیا ہوگا - جو بے چارے سفر کر رہے ہیں سائیکولوجیکل طور پر جو بے چارے ختم ہو گئے ہیں جن کے دماغ میں ہر وقت فکر لگا رہتا ہے اور جن کے گھر والے بھی پریشان رہتے

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے لوگ ہی پھنسے ہوئے نہیں ہیں -

"A large number of foreign ships have also been stranded."

ہمارا مطلب کسی دوسرے ملک والوں سے نہیں ہے - ان کے کتنے شپ ہیں اس میں دلچسپی نہیں ہے - دلچسپی ہماری سب سے زیادہ اپنے یہاں کے لوگوں میں ہونی چاہئے - ویسلز کا کیا ہوتا ہے وہ ان کے مالک جانے - اس میں ہمیں پڑے رہنا نہیں چاہئے کہ حالت نارمل ہو جائے اور ویسلز کے ساتھ وہ بھی آ جائیں - ویسلز کا کچھ بھی ہو یہ ان کے مالک جانے - لیکن ان لوگوں کو لانے کے لئے آپ کیا قدم اٹھا رہے ہیں -

آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے کونسل جنرل کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو لائیے - لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی تک ان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے - یہ چیز ۲۷ مارچ کے اس اخبار میں بھی چھپی ہے اور دوسرے اخباروں میں بھی چھپی ہے - اس میں بھی آپ نے یہ رکھا ہے کہ کونسل جنرل جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ جانے کے لائق ہیں وہ ہی آئیں یا جو خود آنا چاہتے ہوں ان کو لائیں - یہ ضد کی بات نہیں ہونی چاہئے کہ جن کو کونسل جنرل چاہیں لانا وہی صرف آ سکتے ہیں - اس شرط کو آپ نہ رکھیں - جو بھی ہیں ان سب کو لائیں - یہ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی بھی رہنا نہیں

چاہے گا - آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی موت کے ملبہ میں نہیں رہنا چاہے گا - وہاں بیماری ہو رہی ہے - وہ ہوم سک بھی فیل کر رہے ہیں - پھنسے ہوئے ہیں - اس کی سیریس نیس کو آپ سمجھیں - ہر قیمت پر آپ اُن کو نکالیں - ویسل والوں کے ساتھ سختی کرنی پڑے تو وہ بھی کریں - خود اپنے پاس سے پیسہ دینا پڑے تو وہ بھی کریں - ویسلز کو چھوڑنا پڑے تب بھی آپ ان کو لائیں - جہاز واپس لانے والی بات آپ چھوڑیں - جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ بتائیں -]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरे बयान पर ताज्जुब करने की कोई वजह नजर नहीं आती है । आनरेबल मैम्बर वैसे ही ताज्जुब करने के आदी हैं तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं । साफ तौर से मैंने तादाद दी है—

श्री रशीद मसूद : अफसोस की बात है ।

شری رشید مسعود : افسوس کی بات ہے -

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अफसोस के लिए तो बिल्कुल मुकाम नहीं है ।

198 लोगों के बारे में मैंने बताया है कि कुछ लाए गए हैं और कुछ लाए जा रहे हैं । उनका मसला हल हो गया । मैंने यह भी साफ कहा है कि जो आना चाहेंगे उनको लाने के लिए हमने यहां से अहकाम जारी कर दिए हैं । सवाल यह है कि वे आना चाहते हैं या नहीं ? यह इतना आसान काम नहीं है । इतना आसान सवाल नहीं हैं । वे वहां तनख्वाह पा रहे हैं । अपनी मुलाज़मत छोड़ कर आना चाहेंगे ? मुलाज़मत उनको छोड़नी पड़ेगी ? वहां वे रहना चाहेंगे ? यह तभी मालूम हो सकता है जब हम कुछ उसकी जांच करें । ऐसा लगता है कि सभी लोग अपनी ख्वाहिश से आना नहीं चाहते । इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मामले में कितना सरकार से हो सकता है उस में वह कोई कसर उठा नहीं रखेगी और न उठा रखी गई है । हमने यह भी साफ कहा है कि जिस के पास पैसे आने के लिए न हो तो उसको अपने खर्चे से हम यहां ले आएंगे और इसके बाद पैसा को जहां से वसूल करना है कर लेंगे । यह सब कहा जा चुका है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कल यानी आठ तारीख को मैं खुद बगदाद जा रहा हूं । मुझे इस मामले की पूरी जांच करने का मौका मिलेगा । मैं यकीन दिलाता हूं कि जितने फैक्ट्स हैं, वाकात हैं उनकी पूरी-पूरी मैं तहकीक करूंगा और जो भी आगे करना बाकी है—अगर कुछ हो—तो वह भी करवाने की कोशिश करूंगा ।

SHRI RASHEED MASOOD: Sir, I walk out in protest agains the firing on the farmers in Karnataka.

Shri Rasheed Masood then left the House.

KUMARI PUSHPA DEVI SINGH (Raigarh): Sir, I have gone through the Statement of the Minister and still some doubts prevail in my mind. So, I seek some clarifications from the Minister.

(1) What has the Government done to the families of these 402 crewmen who have got stranded in Iraq? What is the amount of relief that has been rendered to the stranded crewmen families?

(2) What is the guarantee of safety of vessels that are going to be left in Iraq?

[Kumari Pushpa Devi Singh]

(3) Six vessels were destroyed in the war which were owned by ordinary individuals whose only source of income for the whole family was from these vessels. What relief or compensation of facilities is the Government giving them for starting their trade again?

(4) Is the Government aware that after the month of April, it is not possible for these vessels to come out of the Gulf areas and be back in India? If so, when does the Government expect these vessels to leave the Gulf area? The six vessels which have got destroyed during the war are not covered by war insurance. Will the Government of India help these owners to get adequate compensation from the Iraq-Iran Government?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: In fact a question on this very subject is being answered by my colleague, the Minister for Shipping the day after tomorrow. Actually, that Ministry has been dealing with this matter. Maybe, in order to do equal justice to both the Ministries, this time, I have been asked to answer the Call Attention!

Sir, the point in so far as the External Affairs Ministry is concerned is that we have issued appropriate instructions to the person on the spot, namely, our Consul-General in Basrah.

I have already explained what has to be done with the vessels which have not been able to gone out of Shatt-at-Arab and are stranded there. Unless one feels sure that the safety of the vessels and the safety of the crew is ensured, their clearance will not be easy. It should not be permitted. We have not permitted it. We have advised them against clearing of the vessels and sailing them out.

There is a long list of measures. For instance, it may be further clarified that under the M.S. (Distressed Seamen) Rules, 1960 extended to sailing vessels by the then Ministry of Transport and Communications Notification No. 3144 dated 17.12.1960, all repatriation expenses in respect of distressed seamen are to be recovered from the owners or agents of the sailing vessels. In view of the above position and, since the D.G. Shipping has to separate funds for meeting the cost of repatriate of crew of sailing vessels stranded or lost at Basrah and FAO, D.G. Shipping had held a series of meetings with the President of All-India Sailing Vessels Industry Associations and owners/representatives of sailing vessels involved to consider problems regarding eventual repatriation of the crew of these sailing vessels. Thus, as I have said in the Statement, he has given instructions. The Consul-General could send the seamen at his own expenses and later on, it will be reimbursed in whatever manner that is possible. This is the position.

With regard to the lives of these people, as I have said, they are safe. We have got reports. For six or seven months they have been there and according to our information they have been looked after well. There is no reason to be worried. Naturally, their families here would be worried. That is understandable. But the position as we know, in regard to the well being of these people is as I have stated.

SHRI M. RAMAGOPAL REDDY: (Nizamabad) She has asked whether the ships were insured or not.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I do not know that. This is a question which the Ministry of Transport and Shipping should answer. I have not got the details. If the hon. Member wants, I can got all the details and send them on to him.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि वे लोग स्वेच्छा से वहां हैं, और इसी बात के बारे में हम लोगों को सब से ज्यादा शंका है । पिछले कुछ दिनों के अखबारों में साफ तौर से इंगित है कि रेलिंग वेसल्ज एसोसियेशन ने भारत सरकार को

पत्र लिख कर यह आरोप लगाया है कि भारत सरकार उन्हें वापस लाने में अक्षम रही है, दूसरे, व लोग भूखमरी की स्थिति में हैं और तीसरे, डी जी, शिपिंग और विदेश मंत्रालय को कई बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है।

दिनांक 20 नवम्बर, 1980 के अनस्टार्ड क्वेश्चन नं० 464 के जवाब में मंत्री महोदय ने क्या कहा था, वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। प्रश्न यह था :—

"(a) whether many ships which were stranded in Iraq and Iran border during the recent conflict were badly damaged;

(b) if so, the total number of Indian ships stranded and damaged;

(c) how many of their crew members were killed;

(d) how many of them have been released or are still under their possession;

(e) whether any compensation has been asked; and

(f) if so, the reaction of Government thereto?"

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह क्वेश्चन कब का है?

श्री राम विलास पासवान : 20 नवम्बर, 1980 का। 26 फ़रवरी, 1981 को पूछे गए एक अनस्टार्ड क्वेश्चन का जो जवाब दिया गया, वह भी मैं अभी पढ़ कर सुनाऊंगा।

जवाब में (सी) और (डी) को क्लब कर दिया गया है और कहा गया है :—

"(c) & (d) No crew members on these vessels is reported killed. However one Indian cadet on board one of the ships is missing and no information is yet available about him."

गवर्नमेंट के रीएक्शन के बारे में यह जवाब दिया गया है :—

(e) & (f) Damage to or loss of ships abandoned in war zone under stress or inescapable circumstances are covered by war risk insurance."

26 फ़रवरी, 1981 का अनस्टार्ड क्वेश्चन नं० 1570 इस प्रकार है :—

"(a) the details of the Indian Vessels destroyed in Iran-Iraq conflict according to latest information; and

(b) the number of persons killed or missing?"

इस क्वेश्चन के जवाब में बताया गया है :—

"(a) The following six Indian sailing vessels are reported to have been destroyed:...

(b) No Indian personnel are reported killed. Only one Indian Cadet named Shri J. R. T. Anbu is missing."

मंत्री महोदय ने कुबूल किया है कि छः भारतीय सेलिंग वेसल्ज़ डेस्ट्राय हो गए।

विदेश मंत्रालय की 1980–81 की रिपोर्ट में कहा गया है :—

"बहुत से भारतीय समुद्री जहाज और जलयान शत-अल-अरब में फंस गए। उनमें से 9 जलयान और जहाज या तो डूब गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकांश जहाजों और जलयानों के कर्मीदल के सदस्यों को भारत प्रत्यावर्तित कर दिया गया अथवा किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। सिर्फ़ थोड़े से कामचलाऊ अमलों को जहाजों पर रखा गया।"

मेरे कहने का मतलब यह है कि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में जो यह कहा हैं कि

[श्री राम विलास पासवान]

वहां पर वे लोग स्वेच्छा से हैं, मैं उसको गलत तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वह तथ्यों से परे हो सकता है । हमारे यहां नान-एलाइनमेंट, गुट-निरपेक्षता, की बात चल रही है, लेकिन हमने हमेशा यह देखा है कि भारत की गुट-निरपेक्षता की जो थ्यूरी रही है, उसके मुताबिक हम कुछ खोते ही रहे हैं। भले ही हमारा नाम गुट-निरपेक्ष देशों में हो, लेकिन नैशनल इन्ट्रस्ट्स के मामले में हमको कहीं न कहीं कमजोरी नजर आती है । हमें डाउट है कि कहीं यह मामला तो नहीं हैं कि इराक और ईरान के साथ हमारे जो सम्बन्ध हैं, उनमें तेल का जो स्थान है; हालांकि तेल का आयात घट कर कितना हो गया है, यह हम सब को मालूम है----, उसके कारण हम झुक रहे हैं, अपने अधिकारों की उपेक्षा कर रहे हैं और वहां पर फंसे हुए अपने आदमियों के बारे में जितने जोर से हमें बात कहनी चाहिए, वह नहीं कह रहे हैं ।

मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय वहां जा रहे हैं, नान-एलाइन्ड देशों की टीम वहां जा रही है, और वहां पर इस मामले को रखा जाएगा। मैं मंत्री महोदय से अपेक्षा करूंगा कि जो नान-एलाइन्ड टीम वहां जा रही है, वह इस मामले को प्राथमिकता देगी । मंत्री महोदय को सदन को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह टीम इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और इसको प्राथमिकता देगी ।

यू एन ओ के सेक्रेटरी-जैनेरल ने कहा है कि उन्होंने अपील की, लेकिन उनकी अपील को इराक ने नहीं माना । जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनके बारे में उन्होंने अपील किया था और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो यू एन ओ का झंडा है उस झंडे को गाड़ करके दोनों देश यह समझें कि यह यू एन ओ का झंडा है और इसको निकाला जा सकता है लेकिन वह भी इराक के द्वारा नहीं माना गया । तो ये सारी परिस्थितियां हैं और जैसा कि माननीय सदस्यों ने कम्पेन्सेशन का मामला उठाया, उसके अलावा और सारी चीजें हैं, एम्बैसी के रोल का जिक्र किया गया और ये जो छः पोत ध्वस्त हुए क्या उनमें आदमी नहीं थे ? आदमी थे तो कितने थे? उसका कहीं हमारे सामने जिक्र नहीं आया । जो आदमी मिसिंग हो रहे हैं, उसके बारे में जो मंत्रीजी का जवाब 80 से लेकर आज तक चलता चला आ रहा है कि मिसिंग हैं तो कहां हैं, गिरफ्तार हैं या मारे गए हैं, कहीं न कहीं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी रहनी चाहिए, कब तक आप उनको खोज कर निकालेंगे ? कब तक बताएंगे कि जो आदमी मिसिंग हैं वहां कहां हैं, किस अवस्था में हैं ?

इसलिए यह बहुत ही गंभीर मामला है और अभी तो ब्रिटेन के साथ भी आपका मामला फंस सकता है जो ब्रिटिश नेशनलिटी का ऐक्ट वहां आ रहा है उसको लेकर । तो निश्चित रूप से मंत्री महोदय को इन सारे मामलों में जो विदेश से संबंधित मामला है, अपने स्टेंड को साफ करना चाहिए । मैं माननीय मंत्रीजी से चाहता हूं कि जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, चाहे नान-एलाइन्ड टीम का मामला हो या मिसिंग आदमियों का मामला हो या 6 पोत जो ध्वस्त हुए हैं उनमें जो मारे गए हैं उनके परिवार को मुआवजे का मामला हो, इन सारी बातों को सरकार गंभीरतापूर्वक ले और सदन को इसके बारे में आश्वस्त करे ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : पहले तो मैं यह साफ कर दूं कि जो हमारी टीम जा रही है वह इसके लिए नहीं जा रही है, किसी और काम के लिए जा रही है ।

श्री राम विलास पासवान : आपकी नहीं, नान-इलाइन्ड टीम के लोग जा रहे हैं ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : तो मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूं । आप जानते हैं कि नान-इलाइन्ड कान्फ्रेंस की तरफ से जो चार विदेश मंत्रियों को वहां जाने के लिए कहा गया

है उनमें मैं एक हूं। मैं उस काम के लिए जा रहा हूं। लेकिन मैंने यह कहा कि संयोग से चंकि थे कल जा रहा हूं तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर के बताऊंगा। यह मैंने कहा।

दूसरी बात यह है कि मेरे जितने वक्तव्य यहां दिए जा चुके हैं उनमें आपस में कोई विरोध नहीं है। जो आदमी मिसिंग हैं उसको मिसिंग ही कहा जायगा, उसको मरा हुआ कभी नहीं कहते। एविडेंस ऐक्ट में तो यह है कि सात साल तक हम यह नहीं कह सकते। उसके बारे में कयास नहीं कर सकते कि वह मर गया। इसलिए मिसिंग जो है उसको मिसिंग ही कहना पड़ेगा जब तक कि हमारे पास यह सूचना न हो कि उसका देहान्त हो गया है क्योंकि कानूनी परिणाम उसके कुछ और होते हैं। इसलिए हमको सही सही तौर पर बात कहनी पड़ती है।

फिर इसके बाद...

श्री राम विलास पासवान : उनको अंडर प्रोटेक्शन लाया जा सकता है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उनको लाया जा सकता है। उसके बारे में हम यहां से हुक्म दे चुके हैं। यहां से अपने कौंसिल-जनरल को कह चुके हैं कि अपने खर्चे से उनको यहां भेज दीजिए। चुनाचे 198 लोगों का इंतजाम हो चुका है और लोग जो आना चाहते हैं उनको भी भेज दिया जायगा। उसके बारे में कोई शंका की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : 6 पेंत जो ध्वस्त किए गए उसमें कितने आदमी मारे गए?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : नहीं, नहीं, उसमें नहीं हैं। उसके बारे में मैं वक्तव्य दे चुका हूं।

श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह तो ठीक ही है, मगर मैं उसमें कुछ और सुझाव दे रहा हूं।

402 फंसे लोग जो खजूर लेने के लिए गए थे उसके बारे में सुना है कि खजूर आज तक सेलिंग वेसेल्स के अलावा और किसी तरह से भारत में आयात नहीं हो सकता। वह बड़े जहाज में नहीं आना चाहिए क्योंकि छोटे जहाज को महत्व देना चाहिए। इसके लिए शासन को ध्यान देना चाहिए।

दूसरे, 100 दीनार एक आदमी को फाइन होता है। ईराक गवर्नमेंट ने वह फाइन माफ कर दिया है लेकिन सेलिंग वेसेल्स का फाइन माफ नहीं किया है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है?

तीसरा यह है कि ये वेसेल्स पूरे जगत में फिरते रहते हैं। कब क्या हो जाय पता नहीं रहता। इस वास्ते इन वेसेल्स का और सीमेन का बीमा करने के बाद ही उनको समुद्र में उतरने की अनुमति देनी चाहिए। जब तक उनका बीमा न हो जाय उनको समुद्र में उतरने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि 402 फंसे हुए लोगों के परिवारों को आप क्या सहायता दे रहे हैं तथा उनको वहां से निकालने के लिए तत्परता के साथ क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं कह चुका हूं कि उनको वहां से लाने की तत्परता से कार्यवाही की जा रही है और की जायेगी।

माननीय सदस्य ने जो दूसरे सुझाव दिए हैं वह शिपिंग मिनिस्ट्री से संबंधित हैं और मैं आशा करता हूं कि उस मिनिस्ट्री में इन पर विचार होगा।

12.51 hrs.

STATEMENT RE. OUTCOME OF INTER-GOVERNMENTAL MEETING FOR REVIEW OF INDO-BANGLADESH AGREEMENT ON SHARING OF GANGA WATERS AT FARAKKA

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): The 1977 Indo-Bangladesh Agreement on sharing of the Ganga Waters at Farakka and Augmenting its Flows provides for a Review by the two Governments at the expiry of three years from the date of coming into force of the Agreement. Accordingly, Bangladesh and India held meetings at Ministerial level in November 1980 in Dacca in January 1981 in New Delhi and from 2nd to 4th April 1981 in Dacca to undertake the Review. The task was completed during the meeting last week in Dacca. Though major diffrences on a number of crucial questions persisted, it was possible to arrive at an agreed covering review statement.

Part 'a' of the 1977 Agreement provides for an interim arrangement for sharing of Ganga waters at Farakka for a period of five years. Part 'B' of the Agreement required the Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission to carry out investigations and studies of schemes proposed by either Government for the augmentation of the dry season flows of the Ganga with a view to find an economic and feasible solution. The Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission was required to submit its recommendations to the two Governments within a period of 3 years.

In respect of Part 'A' of the Agreement, Bangladesh and India noted in the Review that the "sharing arrangements at Farakka had been fully implemented in conformity with the provisions of the Agreement". The Review thus establishes that India fully honoured her obligations. There were differences between the two delegations in regard to the impact of the sharing arrangements. The Indian delegation produced conclusive evidence to establish that there is an urgent need for a larger share of flows for Calcutta Port. It was also demonstrated how the clause guaranteeing minimum releases to Bangladesh had a very adverse impact on Calcutta Port in the dry season following the poor monsoon of 1979. It was the contention of the Bangladesh delegation that the diversion of waters at Farakka had a negative impact on Bangladesh in respect of agriculture, fishery; salinity, etc. The Indian delegation was, however, able to demonstrate on the basis of statistics published by Bangladesh that there was no adverse impact on Bangladesh.

In regard to Part 'B', both the sides "noted the fact that the Joint Rivers Commission could not submit its recommendations" as required in Article IX of the Agreement. Though the two sides held different views as to the causes, the Indian side showed during the Review that the stand adopted by Bangladesh in the Joint Rivers Commission thwarted even commencement of the studies. Moreover, despite the act that the Agreement specifically required the Joint Rivers Commission to submit augmentation proposals within a period of 3 years, it became apparent that Bangladesh did not wish to cooperate in the task of the Joint Rivers Commission. These factors explain the reasons for non-implementation of Part 'B' of the Agreement.

The mandate of the Joint Rivers Commission expired in November 1980 without any progress being made in regard to implementation of Part 'B' of the Agreement. It has to be seen if a solution can be found outside the 1977 Agreement. The Review noted that the question of augmentation "would have to be decided upon by the two Governments at a high political level."

12.55 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) *Need for a Super-fast train between Lucknow and Allahabad*

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) :उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर रेल मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

लखनऊ और इलाहाबाद के मध्य कोई अति द्रुतगामी रेलगाड़ी नहीं चलती जिससे यात्रियों को बड़ी ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों महानगरों के मध्य केवल एक रेल गाड़ी एक्सप्रेस चलती है। यह रेलगाड़ी इलाहाबाद से प्रातः 4.45 बजे छूटती है और लखनऊ 9.45 बजे पूर्वाह्न पहुंचती है। इस प्रकार 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी पांच घंटे में तय करती है। गत पहली नम्बर से इसके विराम स्टेशनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है जिससे इसके द्वारा यात्रा करने पर अधिक समय लगता है। इलाहाबाद से कानपुर की दूरी लगभग उतनी ही है जितनी इलाहाबाद से लखनऊ की। परन्तु इलाहाबाद से कानपुर केवल ढाई घंटे में पहुंचा जा सकता है, जबकि इलाहाबाद से लखनऊ पहुंचने में पांच घंटे लग जाते हैं।

लखनऊ प्रदेश की राजधानी है परन्तु प्रान्तीय सरकार के महत्वपूर्ण कार्यालय इलाहाबाद में स्थित हैं। हाईकोर्ट, लोक सेवा आयोग, शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, गवर्नमेंट प्रेस आदि अनेक महत्वपूर्ण राजकीय संस्थायें इलाहाबाद में स्थित हैं। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी इलाहाबाद से लखनऊ जाते हैं और वापिस आते हैं। इलाहाबाद की ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्ता पर यहां कुछ कहना आवश्यक है। हजारों यात्री प्रतिदिन यहां आते हैं। अति द्रुतगामी रेलगाड़ी के अभाव में इन तमाम यात्रियों को बड़ी ही कठिनाई का अनुभव हो रहा है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि इलाहाबाद एवं लखनऊ के मध्य यदि एक अति द्रुतगामी रेलगाड़ी चला दी जाए जो इलाहाबाद से प्रातः लगभग 6.30 बजे छूटे और लखनऊ लगभग 9.30 बजे पूर्वाह्न पहुंच जाये और मार्ग में केवल एक स्थान रायबरेली जिला मुख्यालय पर रुके और इसी प्रकार वह लखनऊ से सायं 5.30 बजे चल कर केवल रायबरेली रुकती हुई 8.30 बजे इलाहाबाद पहुंच जाये।

मैं सानुरोध आग्रह करूंगा कि माननीय रेल मंत्री जी इस संबंध में व्यक्तिगत रुचि लें और इलाहाबाद तथा लखनऊ के मध्य अति द्रुतगामी रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था करें जिससे दोनों महानगरों के यात्रियों को होने वाली असुविधाओं अनेक एवं कष्टों का निराकरण हो सके।

(ii) *Essential facilities for the employees of Natural Institute of Sheep Development in Rajasthan.*

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Some of the Members of Parliament went to Avikanagar in Rajasthan to find out the activities of the National Institute of Sheep Development.

We are glad to see the results of experiments done in these rain-fed sandy areas to raise perennial grasses. The Institute attempted to have three-tier system of raising fodder, that is raising grass, fodder shrubs and fodder trees. It is really adoptable in similar areas in the country.

This Institute has succeeded in developing sheep and goat breeds. But, there is a great gap between research and propagation. It should be filled up.

Due to the uncertainty of electricity the Institute is experiencing some

[Shri Rajagopal Naidu]

difficulty in carring experiments. It is said that a generator is supplied but it should be strengthened as the supply as we have seen, was not satisfactory.

There are about 50 vacancis of Senior Scientists. It is learnt that due to lack of facilities the Scientists are not joining there. This must be looked into.

One thing is definite. There are no education facilities for the children of the employees of the Institute and there is no regular bus from that Institute to Jaipur which is a must.

I urge the hon. Minister of Agriculture to try to redress the grievances of the employees so that they may put their heart and soul into the research work.

(iii) *Need for a separate Archaeological Circle in Orissa.*

SHRI CHINTAMAN PANIGRAHI (Bhubaneswar): Sir, Orissa Government is pursuing with the Education Ministry of the Central Government for the last several years for creation of a separate Archaeological Circle for Orissa State. There are now 66 centrally protected mounments in Orissa including Lord Lingaraj Complex and Lord Jagannath Complex which consists of about 100 temples and structures with valuable sculptures. Because of sub-circle offices important works like documentation, survey. exploration and excavation rarely get the attention they deserve. Besides; the world famous Sun temple at Konark and historical Budhist sculpture at Lalitgiri, Udaigiri; Ratnagiri and at other places justify the claim of State for having an independent Archaeological Circle which needs immediate consideration of the Government of India. When the Eastern Circle is now being proposed to be bifurcated, I urge upon the Central Government to create an independent circle or Orrisa State.

13 hrs.

(iv) *Needs for conversion of Dabhol Port into a major port.*

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR Ratnagiri): The unsatisfactory living conditions in Bombay city have reached a bursting point and to alleviate the situation the Government has taken up the twin Bombay scheme and unless means for a permanent stoppage of the concentration of industries and population is found out and worked out, the fearful consequences are bound to reappear in large proportions in a few years. To effect, therefore, a lasting solution, a place will have to be found out which will offer better, abundant and still cheaper facilities than the present Bombay or twin Bombay ever could.

Taking into consideration all the requirements of a modern industrial town, development of Dabhol Port on the West Coast of Maharashtra in the Ratnagiri district offers to be the most suitable and yet an attractive and economical place for this diversion and once a nucleus is found, the industrialists and traders will flow to this place.

Sir, there are various predominant factors which would prima facie show the necessity for the development of Dabhol port by converting it into major port by including it under centrally sponsored scheme. This port is only 90 miles South of Bombay and was previously foremost for sea borne international trade. Extract of Dagh Register shows that the Dutch had found a depth of 18 fathoms i.e., 108 feet. According to latest marine survey the depth is 55 feet and is more than that of an other port in India. The length of this deep portion is about three miles and breadth about 1/2 a mile. This port is suitable for building and anchoring the largest ships the world would have. Vice-Admiral (Retd.) Soman after survey of this Port has observed: 'Dabhol creak lends itself most ad-

mirably for development as a port and with suitable dredging initially and with minimum maintenance dredging thereafter, the creak can be developed into a deep water port capable of eventually berthing 100 ships.'

Koyana plant is a distant of 35 miles from this place. The hills on both sides of the port are an advantage from defence point of view. West Coast railway line would be passing from a distance of 25 miles to 30 miles from this place. Jetty for vessels has been constructed at this port by State Government by spending lakhs of rupees. There is ample land on both sides of creak and that too on the healthiest plateau of Konkan. Cheap labour is also available.

I, therefore, request the Hon. Minister of Shipping and Transport to consider the feasibility of converting Dabhol Port into a major port and appoint a committee to study this project. I may mention here that the steps as suggested, if taken immediately, will have a solubrious effect on the minds of people of Konkan who have been ignored and totally neglected in all respects during all the years.

(v) ALLEGED MIS-RECORDING OF INFORMATION re RELIGIOUS AND LINGUISTIC MINORITIES IN THE RECENT CENSUS.

SHRI G. M. BANTAWALLA (Ponnani): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the recent 1981 Census was the 12th in the decinnial series of data on population in India. It is rather unfortunate that this massive operation, which will form the basis of all planning exercises, suffers from serious drawbacks with respect to full coverage and accuracy of recorded information. There are widespread complaints of irregularities in the nature of ommissions and recordings contrary to information given, particularly with respect to religious and linguistic minorities.

While there are serious complaints of enumerators not having visited a number of villages and localities, many have used blank paper sheets of paper. There are complaints of columns being wrongly filled, left blank or filled in pencil.

Urdu has been the worst victim. In UP for example, a large number of enumerators insisted on recording no language other than Hindi on the plea that Hindi is the official language. In view of the increasing number of complaints from all over the country that Urdu has not been recorded as mother tongue, General-Secretary of Anjuman-e-Tarqqui-e-Urdu, has demanded a fresh Census and revision of the linguistic column throughout the country.

I have to urge upon the Government to take steps to varify and revise, and to ensure accuracy and adequacy of information relating to religious and linguistic minorities in general and with respect to Urdu in particular. I request the Government to make a statement in the House.

(vi) REPORTED RISE IN PRICES OF VANASPATI.

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak): Sir, under rule 377, I wish to raise the following:

It is reported that the prices of Vanaspati have been increased by the Vanaspati manufacturers unilaterally by Rs. 3.15, to Rs. 210.40 per tin of 16.5 Kgs. This hike has come after a lapse of only one month. This is done by the manufacturers when talks are being continued between Government and manufacturers. Hence I urge upon the Government to see that steps are taken to protect the interests of the consumers by importing sufficient quantum of imported oil and making proper distribution of the available stocks in the country.

(vii) RELIEF TO FARMERS FOR THE DAMAGE TO CROPS CAUSED BY HAILSTORMS RAJASTHAN AND UTTAR PRADESH.

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): Sir, I wish to raise the following under rule 377:

There have been reports from various places in the country, particularly some districts of U.P. and Rajasthan where hailstorms have inflicted serious damage to wheat crops which were ready for harvesting. I urge the Central Government to intervene at this stage in helping the poor farmers in the form of suspending recoveries of revenue for the time being, and also provide *ad hoc* financial help to the affected farmers according to their damage.

MR. DEPUTY SPEAKER: The House now stands adjourned till 2.05 p.m.

13.07 hrs.

The Lok Sabha adjourned, for Lunch, till Five minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assumbled after Lunch of eleven minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-CHAIRMAN *in the Chair.*]

DEMANDS FOR GRANTS, 1981-82— *Ministry of Labour—contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up further discussion and Voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Labour. Shri Mool Chand Daga was on his legs.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : हमारा संविधान जो हमारे अरमान हैं उनको मूर्तरूप देने का एक अस्त्र है । यदि श्रम मंत्री जी इस अस्त्र का मजबूती और दृढ़ता के साथ उपयोग नहीं करेंगे तो हिंसक क्रान्ति होने की पूरी सम्भावना है । इस वास्ते मेहरबानी करके दीवाल पर लिखे हुए इस वाक्य को आप पढ़ लें ।

मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है । लगता है वह श्रम मंत्री जी की लिखी हुई नहीं है । इस में केवल गोष्ठियों, परिचर्चाओं और चर्चाओं का ही विवरण दिया गया है । हिन्दुस्तान की जनता क्या चाहती है ? राज बदल जाए यही वह नहीं चाहती है । वह चाहती है कि समाज बदले और एक शोषणविहीन समाज की स्थापना हो । जब तक ऐसा नहीं होता है लोगों का शोषण होता रहेगा । संविधान की धारा 23 में यह कहा गया है :

"Traffic in human beings and *begar* and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law."

इसके बाद सरकार ने एक कानून बनाया

The Bonded Labour System (Abolition) Act.

जोकि 1976 में लागू हुआ । इस कानून के लागू होने जाने के बाद भी आज हिन्दुस्तान में 23 लाख बांडिड लेबर हैं । यह मेरा नहीं आप ही का आंकड़ा है । आंध्र में इस बांडिड लेबर की कुल संख्या आपने 3 लाख 25 हजार बताई है, बिहार में 1 लाख 11 हजार, गुजरात में 1 लाख 71 हजार, कर्नाटक में 1 लाख 93 हजार, मध्य प्रदेश में 4 लाख 67 हजार और हमारे यहां राजस्थान में 67 हजार । कई प्रांतों का इसमें जिक्र नहीं है । कुल आंकड़ा आपने 22 लाख 40 हजार का बताया है ।

What is bonded labour?

"Like other agricultural labourers they cannot participate in the labour market by freely selling their labour. A bonded labourer is a human animal and to the landlord he means no more than a buffalo.

The principal reason for forfeiting his rights is that he has taken a loan from the moneylender-cum-farmer and entered into an agreement that he would work for the farmer until the debt is declared repaid."

जब मैंने प्रश्न पूछा तो आपने उत्तर दिया कि

60 per cent of bonded labour belong to scheduled castes. 43.1 per cent of bonded labour are from scheduled tribes.

और मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि बोंडेड लेबर पर अभी 'हिन्दुस्तान' में एक आर्टिकल निकला था "गुलामी के अवशेष बंधुआ मजदूर" हिन्दुस्तान में अगर तिवारी जी जैसे श्रम मंत्री और श्रीमती राम दुलारी सिन्हा जैसी श्रम राज्य मंत्री हों और देश के आजाद होने के बाद भी अगर बंधुआ मजदूर देश में हों तो उनकी क्या हालत हो सकती है, इसका आप स्वत : अनुमान लगा लीजिये । उस आर्टिकल में लिखा है, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा ।

"एक बड़ा मालिक किसान वर्ग ऐसा भी है जहां बंधुआ मजदूर गाहे-बगाहे शारीरिक शोषण भी सहता है—मालिक के थप्पड़, जूतों, लातों, घूसों की मार । गांव के जाने माने लोग या बहुमत उसकी सहायता नहीं करते, क्योंकि वह मालिक का बंधुआ है और सदियों से चले आ रहे घिनौने सामंती वातावरण में उसे पीटने का मालिक को नैतिक अधिकार मिल गया है । विद्रोह की स्थितियां सामान्यत: पैदा नहीं होती हैं, पैदा हों, तो कुचल दी जाती हैं ।" इस प्रकार का बोंडेड लेबर अगर देश में हो तो कितने दुख की बात है । आपने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है ? बड़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि श्रम विभाग है और उसकी तारीफ भी करनी चाहिये । लेकिन मुझे दुख है कि श्रम विभाग किस प्रकार से काम करता है । श्रम विभाग का नाम रख दो परिचर्चाओं और गोष्ठी का विभाग । बोंडेड लेबर के लिये आपने क्या किया ? बोंडेड लेबर के लिये लिखा है, इस चैप्टर को देखिये । पहले हुई सेक्रेटरीज की मीटिंग/उसके बाद मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और उसके बाद सबजेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई । 1966 में बोंडेड लेबर कानून हमने पास किया था, हमने सोचा था कि यह कुप्रथा समाप्त हो जायगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को आपने इस कानून का उल्लंघन करने के अपराध में चालान किया ? जनता पार्टी का राज्य आया, राजस्थान में मुझे पता है कि बोंडेड लेबर्स के लिये जिनके खिलाफ मुकदमे किये गये थे जनता पार्टी की सरकार ने उन मुकदमों को वापस ले लिया । लेकिन 1980–81 में कितने बंधुआ मजदूरों को आपने शिक्षित कर दिया ? कितनों को आपने मुक्ति दिला दी ? कितनों का आपने ऐक्ट के अधीन चालान कर दिया ? केवल किताबों में लिखने से ही काम नहीं होता । मिनिस्टर्स ने लिख दिया कि हमारी हैसियत नहीं है पैसा देने की । स्टेट्स ने यह लिख दिया । गवर्नमेंट इज अगेन कंसीडरिंग । आप इंट्रोडक्टरी और जनरल चैप्टर पढ़ लें । हर बात विचाराधीन है । धीरे धीरे चलने की गति ने आपने किस स्थान पर पहुंचा दिया है । अगर आपके चलने की यही गति रही तो हम शोषण-विहीन समाज की स्थापना नहीं कर सकते , जिसकी जिम्मेदारी आप पर है, और इस जिम्मेदारी को आपको निभाना होगा ।

अब मैं आपको दूसरा ऐक्सप्लायटेशन बताता हूं ।

आज हमारे देश में बच्चों की क्या हालत है, उनका किस प्रकार से शोषण होता है ? हमारे क्षम मंत्री बहुत अच्छा भाषण देते हैं । मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा है :—

"The Labour Minister informed us that according to 1971 census the total number of children employed was estimated to be 10.7 million based on the National Sample Survery Working Group and in 1978 the number had gone upto 16.3 million."

जहां तक हमारे कांस्टीट्यूशन का सम्बन्ध है, आर्टिकल 24 में कहा गया है :—

[श्री मूल चन्द डागा]

"No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment."

आर्टिकल 39 (एफ) में कहा गया है :—

"That children are giving opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment."

हमारे भूतपूर्व श्रम मंत्री ने मेरे एक प्रश्न का बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उनके उत्तर को मैं पढ़ रहा हूं :—

"सरकार ने बाल श्रमिकों की समस्याओं की जांच करने के लिए श्री एम एस गुरुपदस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने असंगठित क्षेत्र में बाल-श्रमिकों और घरेलू नौकरों के रूप में काम करने वाले बालकों की समस्याओं का ध्यान रखा। समिति का यह विचार है कि हालांकि बाल-श्रमिकों की संख्या अधिक है, लेकिन उन्हें वे अधिकार और हैसियत नहीं दी गई है, जो कि घरेलू नौकरों को मिलनी चाहिए। इस समिति ने कुछ सिफारिशें की है, जो अब हाल ही में नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति के विचाराधीन है। गुरुपदस्वामी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच करने के पश्चात् ही बाल-श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए कानून बनाने की वांछनीयता और आवश्यकता पर विचार किया जाएगा।"

हमेशा यही कहा जाता है कि विचार किया जायेगा। यह कितने दुख की बात है कि तीस साल के बाद भी गवर्नमेंट यही बात कहे कि हम विचार करेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do you recommend removal of these two words from the dictionary.

SHRI MOOL CHAND DAGA: They have said in their Report that it is under consideration. Everything is under consideration.

I am quoting from the Report of the National Labour Institute. It says:

"Children are most vulnerable to explanation and abuse. This stengthens the evil of exploitation in the society at large. As Mitra rightly observed "very low wages at young ages are not helpful in securing high wages at higher ages and, therefore, wages tend to rise slowly, thus undermining productivity. A ready and plantiful supply of cheap labour which can be used for constantly undercutting demands for higher wages from adults in the unorganised and even the organised sector can be a menace to industrial production."

They have said how the children are exploited.

उपाध्यक्ष महोदय, इतना समय नहीं है कि मैं आपकी सेवा में सारी बातें रखूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है। मैं इस विषय में भूतपूर्व मंत्री, श्री जे वी पटनायक, का उत्तर पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। चार महीने या दो साल पहले जो जवाब दिया जाता है, वही जवाब फिर दोहरा दिया जाता है।

Part (b) of the answer reads:

"The Government had set up a Committee last year to look into various problems connected with the employment of children, and its report has since been received. A majority of the working children are employed in the sectors where their remuneration and working conditions are unregulated and the existing legal framework does not substantially cover the children engaged in agriculture and other allied sectors. The above Committee in its report has made certain recommendations in this regard also. The report of the Committee is under consideration."

तो यह लेबरर के बारे में मैंने बताया कि लेबरर्स की क्या हालत हो रही है।

एक प्रश्न का जवाब देते हुए हमारे श्रम मंत्री जी ने बड़ा दुख जाहिर किया है और बड़ी सिम्पैथी दिखायी है?

In reply to Starred Question No. 893, which was answered on 7th August 1980, it was stated:

"There is no denying the fact that many children are made to work under conditions detrimental to their health and development. There is no precise estimate of the number of children actually working. Based on the national sample survey, the number of working children in March 1978 was estimated at 16.3 million. Bulk of the child labour is in the rural area; most of the working children fall under the category of unpaid family workers who are employed in agriculture, cottage type industries and other traditional occupations."

आजकल बच्चों की हालत होटलों में, दूकानों में और घरों में क्या हो रही है? उन का वहां जो शोषण होता है उस से उनकी रक्षा करने वाला कोई है या हम किसी प्रकार से उनको उस शोषण से बचा सकते हैं?

अब मैं आप के सामने एक बात मिनिमम वेजेज के सिलसिले में बताना चाहता हूं। यह मेरा तीसरा प्वाइंट है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I hope you are coming to the last point.

SHRI MOOL CHAND DAGA: I am finishing. I know it is not plensant to hear all these. I know that very well.

लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं ये बातें आप के ध्यान में लाऊं। आगे तो आप की इच्छा पर है।

आप यह सोचिए कि क्या इन के मिनिमम वेजेज का स्टैंडर्ड है और यह मिनिमम वेजेज कहां लागू होता है? इस के बारे में मैं ने बहुत अध्ययन किया तो मालूम हुआ कि यह मिनिमम वेजेज तो केवल नाम के लिए है।

It is a dead letter. This article in the Economic and Polotical Weekly says:

"The National Commission on Labour has reported in 1969 that till then the Minimum Wages Act had 'remained a dead letter in every State. For later years we have the findings of the Rural Labour Enquiry, 1974-75, to the effect that only about 2 per cent of agricultural workers were even aware of the Minimum Wages Act."

अब इस मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू करने का सवाल ही क्या पैदा होगा? इसके लिए तो आप के पास कोई रास्ता ही नहीं है। आप ने भी उस के लिए बहुत कुछ जाहिर किया है, बहुत सी बातें मंत्री महोदय ने जगह-जगह कही हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा। आप मेहरबानी कर के बताइए कि इस ऐक्ट के तहत 1980-81 के अंदर कितने आदमियों का चालान हुआ है और सजा हुई है? एक भी इंस्टैंस वह बताएं। तो यह मिनिमम वेजेज ऐक्ट केवल स्टैचूट पर है। आप की गवर्नमेंट क्या कह रही है—

It is said "it is under consideration". Everything is under consideration. May God help us. The question is about the effective implementation of the Minimum Wages Act. How is it being implemented?

Sir, kindly give me another two or three minutes so that I may sum up my speech. First they call a meeting of the Secretaries. It is in the month

[Shri Mool Chand Daga]

of April 1980. It is under consideration. Then there is a meeting of the Labour Ministers in July. They set up a small body of the Ministers. What is the result? It is still under consideration. Everything is under consideration.

यह आपका अलग ही तरह का विभाग है। यहां पर जो चर्चायें होती हैं, जो निर्णय होते हैं ।

Everything is under consideration and they go on holding meetings after meetings of Secretary, Deputy Secretaries, Joint Secretaries the Minister and the Labour Ministers of all States come.

जहां तक पार्टिसिपेशन आफ लेबर की बात है हमारा संविधान क्या कहता है ?

Article 43A of the Constitution says:

"The State shall take steps, by suitable legislation or in any other way, to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organisations engaged in any industry."

वर्कर्स पार्टिसिपेशन पर हमारे मिनिस्टर साहब क्या जवाब दे रहे हैं? इट इज अण्डर कंसिडरेशन । मैंने यह सोचा कि यह अण्डर कंसिडरेशन का जो चैप्टर है, इसको रखा ही न जाए तो बहुत अच्छा होगा ।

This is the answer of Shrimati Ram Dulari Sinha:

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr Daga, my request to complete your speech is also under consideration, I think.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Shrimati Ram Dulari Sinha said:

"The Sub-Committee of the Standding Committee of Labour Ministers at its meeting on the 12th January 1981, had, inter alia, recommended legislative support to the schemes of workers' participation in management. Further action in this regard is being considered by Government."

Shri Pranab Mukherjee said on 4th February 1981 as follows:

"This is imperative in the interests of higher production and productivity, industrial peace and social and political progress. That is why workers' participation has specifically been included as an important part of the 20-point programme for economic and social development launched by the Government."

Should I read the whole article?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will not permit you.

श्री मूल चन्द डागा : हम लोग जो राजनीतिज्ञ हैं, जो तथाकथित नेता बन जाते हैं हम जो जनता से कहते हैं कि आप देश को बनाने वाले हो, यह बातें हम क्यों करते हैं? आप देखिए यह पार्टिसिपेशन की जो बात है वह भी अण्डर कंसिडरेशत है, क्या पब्लिक सेक्टर में हम इसको नहीं कर सकते है? तमाम आर्टिकल्स की कटिंग्ज मेरे पास मौजूद हैं, आपकी इजाजत से मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा ।

In Making Participation Work, it is stated as follows:

"The scheme on workers' participation in industry which forms a part of the twenty point economic programme is a further step in that direction so that human energies and motivations could be channelized through collective action into productive pursuits."

वह गांव में रहने वाला आखिर मजदूर जो गावों में रहता है और मे अपना खून पसीना बहाता है उसको भी तो हिस्सेदार बनाइए, वह भी मालिक बने, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने संतुलन अपने व्यवहार

में अपना रखा है और संतुलन जब तक व्यवहार में रहेगा, तब तक कोई काम नहीं हो सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि कठिनता के साथ संविधान में जो आर्टिक्लस हैं, उनका अनुपालन करना पड़ेगा । इन्डस्ट्रियलिस्ट की ओर भी देखा जाए, यहां पर एक्सप्लायटर्स का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां तक वर्कर्स के पार्टिसिपेशन का सवाल है, यदि यही स्थिति रही तो वह किस प्रकार से रह सकता है ।

You always say about the National Wage Policy..equal pay for equal work.

संविधान में नेशनल वेज पालिसी के बारे में लिखा हुआ है।

It is also under consideration. So, where do you reach?

आज तक आपकी नेशनल वेज पालिसी नहीं बनी है और उसके ऊपर आर्टिकल्स के आर्टिकल्स निकल गए हैं । हर जगह अखबार वाला कहता है कि नेशनल वेज पालिसी बनानी चाहिए । तो मुझे यह कहना पड़ता है कि अभी नेशनल वेज पालिसी नहीं बनी है । इसके लिए आपको तत्परता के साथ कदम उठाने होंगे और अगर कदम नहीं उठाए गए तो हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत बुरी हालत होगी तथा देश की और हालत खराब होगी । क्योंकि जो झगड़े होते हैं उनका सबका एक ही यह कारण है। जो गांव में मशीनों पर काम करता है यदि उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया गया तो लोग कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और वह हमारे भरोसे नहीं रहेंगे। संविधान टूट जाएगा और संविधान पर दूसरे हस्तक्षेप करेंगे । यदि संविधान के आर्टिक्लस को निभाना है तथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को निभाना है, अपने शरीर को मोटा नहीं करना है, जिन लोगों के शरीर पर चर्बी नहीं है; उनको चर्बी देनी चाहिए और जिन पर चर्बी चढ़ी हुई हैं, उसको कम करना चाहिए । यदि नहीं किया गया तो यह सारा ढांचा बिगड़ जाएगा ।

हिन्दुस्तान में मजदूर और गरीब लोग रहते हैं। यह गरीबों का देश है। जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा है कि 30 करोड़ लोग पावर्टी लाइन से नीचे हैं । इसी प्रकार की खबर योजना भवन से आती हैं, लेकिन उन लोगों को ऊपर उठाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । मैं चाहता हूं कि आप को अपने कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए, लेकिन मंत्री जी का उत्तर होगा कि यह स्टेट सब्जैक्ट है, हम लोग तो केवल गाइड करते हैं । जाने दीजिए, आप स्टेट की बात, मैं आपसे दिल्ली के बारे में पूछता हूं, यहां पर तो आका राज है। आप यहां पर जो करते हैं, मैंने सबको देखा है । हिन्दुस्तान में कोई राज्य ऐसा नहीं है, केवल पंजाब के सिवाय जहां न्यूनतम मजदूरी के कारण सभी खेतिहर मजदूर गरीबी को रेखा से नीचे रहते हैं । आपकी लिस्ट के मुताबिक चार हजार रुपये से ऊपर मिलने वाला गरीबी की रेखा के नीचे नहीं रहता । त्रिपुरा में 2,628 रु० मिलते हैं, बिहार में 2,575 रु० मिलते हैं, उड़ीसा में 2,535 रु० मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में 1, 742 रु० मिलते हैं, केरला में 1,721 रु० मिलते हैं और महाराष्ट में 1,632 रु० मिलते हैं –यदि मैं इन सारे आंकड़ों के बारे में कहूं तो इतना समय नहीं है और फिर घंटी बज जाएगी ।

[श्री मूलचन्द डागा]

अब आप ट्रेड-यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रिज रिलेशन्स एक्ट के बारे में लें, आप कब से कह रहे हैं कि यह विचाराधीन है । आपने अभी तक ट्रेड यूनियन एक्ट नहीं पलटा और न ही इन्डस्ट्रिज रिलेशन्स एक्ट को पलटा—आप लोग क्या कर रहे हैं, पहले सैक्रेटरीज की मीटिंग होगी, फिर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मंत्री तथा सैक्रेटरी बैठ कर के बात करते हैं । फिर हमारे भाषण छपते हैं और अखबारों में और रेडियो में आ जाता है कि आज यह मीटिंग हुई, जुलाई के अन्दर मंत्रियों की मीटिंग हुई और अप्रैल के अन्दर सैक्रेटरीज की मीटिंग हुई । उस के बाद सब-कमेटी बन जाती है और फिर वह सब-कमेटी मामले पर विचार करती है । अगर यही हमारे काम करने का ढंग रहा, तो कैसे हम प्रगति कर सकते हैं । मेरी ख्वाहिश तो यह है कि एक मिनट के अन्दर निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए और जो भी निर्णय लिया जाए, उस को सख्ती से लागू करना चाहिए । अगर उस को लागू नहीं कर सकते हैं, तो संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान को अलग फेंक देना चाहिए । संविधान बनने के 32 वर्ष बाद भी ऐसी स्थिति है ।

अब सैफटी के बारे में परसों ही अखबार में निकला है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Daga, you have already taken 28 minutes. Kindly conclude now.

SHRI MOOL CHAND DAGA: I am a bonded labour. Bonded labour has got no liberty.

I will take a minute or so and finish.

उन्होंने लिखा है :

"We have also met the Lt. Governor, Mr. Khurana,....Nine accidents have taken place..."

9 ऐसे केसेज हो गये हैं । आज भी जो थ्रेसर्स पंजाब और हरियाणा में लगे हुए हैं, सुन्दर सिंह जी, आप के प्रदेश में जो लोग इन थ्रेसरों में काम कर रहे हैं, वहां गरीब मजदूरों के हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं । तिवारी जी, आप कृपा कर के यह बताइए कि किसी एक आदमी को भी आप ने कम्पेन्सेशन दिया है । आप भी अखबारों में पढ़ते होंगे कि कई आदमी इस तरह से विकलांग हो चुके हैं और विकलांग होने के बाद उस गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है । कोई कानून नहीं बना है । तो उसका शोषण होता है और जिस समाज में शोषण हो, वह समाज कैसे अच्छा कहा जा सकता है । कहा तो यह जाता है कि हम सारे समाज को दासता और विषमता से मुक्त कर के मनुष्य-मनुष्य के बीच में मधुर सम्बंध स्थापित करेंगे ताकि वह जीवन का आनन्द ले सके । ये सुन्दर सुन्दर वाक्य हैं । यह भावना है और कल्पना है । यह केवल आप का चिन्तन है । तिवारी जी, मैं आप से कहना चाहता हूं कि सब से इम्पोर्टेन्ट पोर्ट-फोलियो आप के पास है और इस में केवल आप मीटिंगें ही न करें, आप इन के दायरे के बाहर आएं और इन के लिए कुछ काम करें, अन्यथा ये सब कानून ऐसे ही पड़े रह जाएंगे । आप के जो कानून हैं, उन को मैंने पढ़ा है । .. (व्यवधान) ..

अब मैं एक मिनट में खत्म करने वाला हूं । आप ने पालेकर की रिपोर्ट निकाली जर्नेलिस्ट्स के लिए लेकिन आप टाइम्स आफ इंडिया से पूछिये कि वह इस के बारे में क्या कर रहा है । आज तो कई बेचारे जर्नेलिस्टों का पत्ता ही साफ हो गया है । ये जो हमारे जर्नेलिस्ट्स हैं, ये हमारी आंख और कान हैं लेकिन इनकी हालत क्या है । प्रेस को चौथा खंभा कहा गया है, जिस पर डेमोक्रेसी आधारित है । न्यायपालिका, एक्जीक्यूटिव और

लेजिस्लेटिव के अलावा यह चौथी ताकत है डेमोक्रेसी के लिए लेकिन आप यह देखिये कि इन जर्नलिस्टों और नान-जर्नलिस्टों की क्या हालत है। आप का जो जो टाइम्स आफ इंडिया है और दूसरे जो अखबारों के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उन से पूछिये कि वे इन के बारे में क्या कर रहे हैं । नहीं तो, आप की यह रिपोर्ट जो है, यह किस काम की है । यह जो आप का चिन्तन है, मेहनत और चिन्तन कर के जो आप के बाल सफेद हो गये हैं, जब तक इस चिन्तन को कार्य रूप में परिणत नहीं किया जाएगा, तब तक इस का क्या फायदा है । भगवान करे आप में इतनी शक्ति आए कि आप इन के लिए काम कर सकें और जो आप के इतने सारे कानून हैं, उन को आप सख्ती से लागू कीजिए और 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत हिन्दुस्तान जो एक ऐसा देश बनावें, जिसमें एक गरीब और मजदूर भी यह कहने लगे कि यह राष्ट्र हमारा है और हम इस देश के मालिक हैं और हम इस देश को बनाने वाले हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call Mr. Kandaswamy, I wish to say that every hon. Member from the ruling party shall not take more than 10 minutes. As regards other parties, the time has already been fixed. The Minister will reply to the debate at 5 P.M. today.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay North Central) Kindly extend the time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not possible.

*SHRI M. KANDASWAMY (Tiruchengode): Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir, on behalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam, I wish to make a few suggestions on the Demands for Grants of the Ministry of Labour which is responsible for laying down the policy in respect of labour matters including industrial relations, cooperation between labour and management, settlement of disputes, regulation of wages uniformly throughout the country and other conditions of work and safety, labour welfare, social security besides development and administration of employment service and training of craftsmen on a national basis.

It has become increasingly common that the industrial establishments do not work within the framework of labour laws and they have relegated the statutory labour welfare measures to the dustbin. To quote an example, there is the SSM Processing Unit in Kumarapalayam in Salem District of Tamil Nadu, having a workforce of nearly 1200. This unit is about 12 years old. There is neither any master-roll nor any time-cards for the workers in this unit. The ESI and the PF facilities are not being given to the workers. The unit is above all the labour laws of the country. The only reason for this callous treatment of workers is that the Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M. G. Ramachandran, happens to be an intimate friend of the owner of this unit. The owner is impervious to the imperative needs of industrial workers whose fundamental rights are protected under the laws of the land. For the last one month there is strike in this unit. The Government of Tamil Nadu has not taken any initiative to settle the dispute. It looks that the management is deriving inspiration from the ineptitude of the Government of Tamil Nadu. In a violent outburst, intended to break the trade union, encouraged by the State Government one of the workers has been injured severely and he is in a critical condition. The recalcitrant attitude of the management even in regard to the conciliation efforts can only be explained by the State Government's complicity in the whole affair.

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri M. Kandaswamy]

The conciliation efforts made twice or thrice have not evoked any response from the management because it is emboldened by the friendship of the owner with the Chief Minister, M.G.R. I demand that the Labour Department should be empowered by the force of a statute that the summons for conciliation should be responded on the threat of legal action for any inaction.

The hon. Member who preceded me referred to the contract labour system prevalent both in the public and in the private sectors. The contract labour system is worse than the bonded labour, about the eradication of which we seem to be voasting incessantly. In the Seshasayee Paper Board unit in Pallipalayam, Salem District, we have nearly 3000 contract labourers. There are regular workers for the same kind of job. Such an invidious distinction between the contract labour and the regular workers doing the same kind of job should be ended forthwith. The State Government has 51 per cent shares in this industrial venture and yet the contract labour system is being perpetuated. The insensitivity of the State Government towards the problems of contract labour has to be condemned. The Government of India has to take immediate steps for abolishing contract labour from the country.

Many industrial establishments do not remit their share of Provident Fund under the Profit Fund Scheme. The Ramanujam Committee constituted to make recommendations for revamping the PF organisation has submitted its report and I demand that action should be taken immediately to ensure that the managements responsible for huge arrears are brought to book.

I am sorry to say that the ESI Dispensaries and Hospitals woefully lack in essential drugs. Besides, malpractices are galore in many of these hospitals. In the ESI Hospitals and Dispensaries around Madras the worker who goes to get a medical certificate on the ground of his sickness is asked to pay Rs. 5 or Rs. 2 for such a medical certificate. Even for giving good medicines money is demanded. The Government should take energetic steps to root out such malpractices from the ESI Hospitals which are to help the workers in their sickness.

In the matter of gratuity, I understand that there is a court ruling that the worker has to put in continuous work for 240 days to become eligible for 15 days' gratuity. This is quite unreasonable. If it is necesary the Government should amend the concerned law to ensure that 240 days' work is not insisted upon for earning 15 days' gratuity. I am sure that the Government will take immediate action in this matter.

The economy of the country is in the hands of our workers. Unless productivity is increased we have no redemption. In 1979 out of the total loss of time 80 per cent was due to strike and 20 per cent to lock-out. In 1980 out of the total loss of time 54 per cent was due to strike and 46 per cent due to lock-out. The duration of lock-out has increased because of paucity of power. The Government should ensure continuous supply of power so that the industries produce more with the cooperation of workers.

Throughout the country there are 633 Employment Exchanges, on the live registers of which about 1.60 crores have registered themselves seeking employment. The Government should not only formulate purposeful schemes but also implement them on a war-footing before the situation goes out of the hands of Government.

The exploitation of child labour is widely prevalent throughout the country. In Tamil Nadu in Sivakasi, where the match industries are concentrated, this problem is acute. The children

who are easily susceptible to serious impairment of health are being employed in matches and match-boxes manufacturing where chemicals are used. They are becoming victims of vicious diseases. The Government of India should enact a law abolishing child labour in such dangerous industries.

Supporting the demands for grants of the Labour Ministry and thanking the Chair for giving me an opportunity to say these words, I resume my seat.

15 hrs.

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि मैं श्रम विभाग के बारे में कुछ कहूं, आपका और सदन का ध्यान मैं इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगी कि माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता जनता शासन के हाथों में सौंपते समय देश में जो श्रमिक शान्ति और उत्पादन वृद्धि का ठोस धरातल छोड़ा था जनता पार्टी के लगभग तीन वर्षों के शासन में देश में श्रमिक अशान्ति का युग पुनः शुरू हो गया जिस के फलस्वरूप न केवल देश के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ते हुए आन्दोलन और श्रमिक दिवसों के नष्ट होने के कारण प्रत्येक स्तर पर उत्पादन गिरा, अपितु अनुशासनहीनता भी बढ़ी । परिणामतः माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पुनः देश की जनता ने उन में अपना विश्वास व्यक्त किया और उन्हें जनता पार्टी शासन द्वारा श्रमिक अशांति और महंगाई, अनुशासनहीनता एवं अराजकता से परिपूर्ण सत्ता विरासत में मिली । आज देश में श्रमिक अशान्ति का वातावरण है । इस पर काबू पाने के लिए हमारी माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रयास कर रही हैं उसकी प्रशंसा किए बगैर मैं नहीं रह सकती हूं । यह उनकी दूर दर्शिता और श्रमिकों के प्रति उनके विशेष लगाव का प्रतीक है ।

इस थोड़े से समय में न केवल श्रमिक शान्ति का वातावरण पूरे देश में बना है, अपितु हर क्षेत्र में अधिकाधिक श्रमिक दिवसों का उपभोग कर उजड़ी हुई उत्पादन व्यवस्था में स्थिरता आई है । इस सब के लिए मैं श्री नारायण दत्त तिवारी और श्रीमती राम दुलारी सिन्हा की भी सराहना करना चाहूंगी जिन्होंने अपने कुशल मार्गदर्शन से देश में श्रमिक शान्ति के लिए उल्लेखनीय वातावरण और ठोस धरातल बनाया है। श्रम विभाग ने बन्धुआ मजदूरों को मुक्ति दिला कर उनके पुनर्वास के लिए छठी योजना में 25 करोड़ रुपये रखे हैं । 1981-82 के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान कर उन्हें शासकीय सेवाओं में चालीस वर्ष की आयु तक भर्ती करने की जो व्यवस्था की है, वह इस बात की परिचायक है कि वर्तमान सरकार बन्धुआ मजदूरों को वास्तव में अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है । श्रम विभाग ने देश के सब से बड़े ग्रामीण कृषक वर्ग को संगठित करने की जो योजना बनाई है और जिस को 1981-82 में केन्द्रीय विधान के रूप में लागू करने की योजना है वह भी इस बात का प्रमाण है कि सरकार ग्रामीण और कृषि कार्यों में लगे करोड़ों श्रमिकों के कल्याण और उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने तथा समान कार्य के लिए समान वेतन अर्थात मजदूरी वितरण में महिलाओं के उत्पीड़न की ओर सजग हैं और प्रयास भी कर रहे हैं । किन्तु विभिन्न राज्यों से इसके प्रभावी परिणाम अभी सामने नहीं आए हैं । अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह महिला श्रमिकों के लिए पग उठाए । सरकारी क्षेत्र के संस्थानों के फालतु घोषित किए गए कर्मचारियों को दूसरे रोजगार प्रदान करने के सरकारी प्रयास भी सराहनीय हैं । मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह इस में और तेजी लाने का प्रयास करें । सरकार ने

[श्रीमती ऊषा वर्मा]

अपंग व्यक्तियों और युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को रोजगार के जो अवसर प्रदान किए हैं वह भी सराहनीय तो हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में उन्हें शत प्रतिशत रोजगार के अवसर प्रदान कर सरकार अपने दायित्व का निर्वाह कर एक कीर्तिमान स्थापित करे। अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में विकलांग श्रमिकों के लिए जो योजनाएं घोषित की गई हैं उनको मूर्त रूप देना परम आवश्यक है। श्रम विभाग ने अनुसूचित जाति और जन जाति के उम्मीदवारों के लिए अध्ययन सुविधायें प्रदान करने और मार्गदर्शन करने तथा रोजगार के जो अवसर प्रदान किए हैं वह भी एक सराहनीय कार्य है।

केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी और केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री श्रीमती राम दुलारी सिन्हा ने 23 दिसंबर 1980 को क्रमशः इस सदन और राज्य सभा में पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के कल्याण के लिए वर्णित पालेकर आयोग की सिफारिशों को लागू करके और बड़े पत्र समूहों द्वारा अंशकालिक संवाददाताओं की छटनी को अवध मानने की घोषणा करके यह सिद्ध कर दिया था कि केन्द्रीय सरकार देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की सब से बड़ी हामी है। इस अवसर पर मैं केन्द्रीय श्रम मंत्री माननीय श्री तिवारी जी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से खींचना चाहूंगी कि उनके द्वारा सदन में और सदन के बाहर अंशकालिक संवाददाताओं की छंटनी को रोकने के लिए जो घोषणाएं हैं उसको कार्यरूप देने के लिए वह कोई कानून बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो कब तक? साथ ही रेल स्टेशनों पर काम करने वाले लगभग साढ़े 5 लाख पोर्टर्स, वैंडर्स, वीयरर्स के लिये कानून बना कर संरक्षण दिया जाय जिससे वह अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।

15 hrs.

श्रीमती प्रमिला दंडवते : (बम्बई उत्तर मध्य) : डिप्टी स्पीकर साहब, आज अपनी इस सरकार में श्रम मंत्रालय की जैसे दाई के पास बच्चा बड़ा होता है, वैसी ही इसकी हालत है। और अभी डागा जी ने भाषण किया सारी चीजें अन्डर कन्सीडरेशन हैं। उस पर कुछ आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि दाई बेचारी क्या कर सकती है बच्चे की सदा मांग ही रहती है, अन्डर कन्सीडरेशन ही रहती है। यह मंत्रालय एक वेटिंग रूम हो गया है मिनिस्टर्स के लिये। एक साल में 3 मंत्री बदल गये, और हर एक की आशा है कि कौन से प्रांत में मुख्य मंत्री बनें। पहले पटनायक साहब थे वह उड़ीसा में मुख्य मंत्री बन कर चले गये, उसके बाद अन्जैया जी आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री बन कर चले गये, और हमारे वर्तमान श्रम मंत्री जी अभी अतम हो कर आये हैं, खुशी है कि वह इस समय सदन में मौजूद हैं। इसलिये जो प्रस्ताव होते हैं कम से कम एक साल में अन्डर कंसीडरेशनका प्रोग्राम न रह कर काम हो जाया करे। अगर दाई बच्चे को अपने गले लगा ले तो अच्छा हो सकता है।

पालेकर अवार्ड एक अच्छी बात हो गई। हमारे जर्नलिस्ट इस अवार्ड के लिये कितने सालों से राह देख रहे थे। लेकिन अभी तक उसका इमप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। पार्ट टाइम जर्नलिस्ट्स को सिस्टेमेटिकली काम से निकाले जाने की व्यवस्था हो रही है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि एक तो सरकार को गाइडलाइन्स तुरन्त देनी चाहिये कि इसको किस प्रकार से इमप्लीमेंट किया जाये। बिना देर लगे इस अवार्ड का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिये। दूसरे एक अथोरिटी क्रीएट करनी चाहिये जिसके जरिये इस अवार्ड का इम्प्लीमेंटेशनदेखा जा सके। पार्ट टाइम जर्नलिस्ट्स का प्रोटेक्शन भी होना चाहिये। और इतना ही नहीं एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम होना चाहिये

कि कहां तक यह हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पालेकर अवार्ड किताब की शक्ल में पड़ा रहेगा और फिर जर्नलिस्ट्स को अपने संगठन के जरिये जो मांगें मंजूर हो गई हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिये कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी। मुझे लगता है जर्नलिस्ट्स, जैसे डांगा जी ने भी कहा, हमारे लोकतंत्र के लिये बहुत ही महत्व का काम करते हैं, और उनको अगर सरकार की ओर से असंतुष्ट रखा जाता है तो अपनी इच्छा से वह बहुत बड़ा काम कर सकते हैं जिससे सरकार को भी चोट लग सकती है। इसलिये उनको असंतुष्ट नहीं रखना चाहिये।

रिपोर्ट में कहा गया है मनडेज लोस्ट पिछले 5 साल में कितने हो गये? मैन डेज लौस्ट के बारे में मैं डिसप्यूट नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि आज खाने की चीजों के दाम काफी बढ़ गये हैं, प्राइस इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है। यूनियन राइवैलरीज की वजह से खतरा हो रहा है। किसी को एन० एस० ए० में बन्द किया जा रहा है। ऐसी हालत में जो शांति दिखाई दे रही है वह एक ज्वालामुखी है, अगर रिप्रैसिव मेजर्स से आप शांति बनाये रखना चाहते हैं तो वह आपको शांति से बैठने नहीं देगा और कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिये इंडस्ट्रियल पीस देश के लिये, प्रोडक्शन के लिये बहुत जरूरी है और वर्कर्स का सहयोग लेना अति आवश्यक है। अगर ऐम्प्लायर, वर्कर और सरकार तीनों एक साथ मिल कर कुछ सुझाव अगर तैयार करते हैं तो देश का प्रोडक्शन बढ़ाने में किसी को विरोध नहीं होगा। अगर यह करना है तो रिप्रेसिव मेजर्स से नहीं कर सकते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Dandavate, you have lost five minutes.

PROF. MADHU DANDAVATE: At least give her five minutes more.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am giving. Your request is conceded.

श्रीमती प्रमिला दंडवते: अगर सरकार नैशनल ट्रिपार्टाइट कांफरेंस के अलावा हर एक मेजर इंडस्ट्री में ट्रिपार्टाइट बाडी की स्थापना करे और उसके जरिये अलग अलग प्रकार के मजदूरों के सवालों को हल करे, तो उससे बड़ी मदद मिल सकती है। यही नहीं, लास आफ प्राडक्शन के बिना डिसप्यूट्स को हल करने के लिए एक क्रेडिबल मशीनरी बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर लोगों में सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी और उनमें यह भावना पैदा होगी कि यह सरकार मैनेजमेंट के साथ सहयोग कर के काम कर रही है या किसी एक यूनियन की सहायता से दूसरों को पीटने का काम करती है, तो फिर इंडस्ट्रियल अनरेस्ट अवश्य बढ़ने वाला है।

वर्कर्ज के लिए एक एफिशेंट पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का बहुत महत्व है। अगर सरकार द्वारा खोली गई दुकानों से उनको जरूरत की चीजें नहीं दी जाती हैं, तो उनका असंतोष बढ़ जाता है।

जब कोई सरकार बनती है, तो वह किसी एक पार्टी की होती है, किसी एक यूनियन की नहीं होती है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यूनियन राइवेलरी न बढ़े। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहती हूं। मोदीनगर में टैक्सटाइल वर्कर्ज में हिन्द मजदूर सभा की यूनियन के 14,000 सदस्य हैं, जबकि इन्टक के 55 सदय हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री, श्री दीक्षित, पहले इन्टक के अधिकारी, आफिलेसबियरर, थे, इस लिए वह इस बात पर अड़े रहे कि इन्टक के साथ ही बात होनी चाहिए। 114 दिन तक यह स्ट्राइक चलता रहा।

इससे भी दुख की बात यह है कि मोदीनगर के टैक्सटाइल वर्कर्ज की बीवियों पर हमला हुआ है। पुलिस ने 75 महिलाओं पर हमला किया। यूनियन राइवेलरी की वजह से ऐसा हुआ है। इस में दो महिलाओं का एबार्शन हो गया। यूनियन के दफ्तर में जा कर उन पर लाठी चलाई गई। उनके पेटीकोट ऊपर कर के

[श्रीमती प्रमिला दंडवते]

उनको गलत प्रकार से मारा गया। उन महिलाओं को ले कर हम प्रधान मंत्री के पास गए, लेकिन आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है। मोदी के द्वारा जो पत्र निलकता है, उसमें कहा गया है कि पुलिस ने महिलाओं को नहीं मारा। पुलिस कहती है कि 55 पुलिस वालों को महिलाओं ने मारा। यह तो होम मिनिस्ट्री का काम है कि वह ऐसी पुलिस को निकाल दे, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है, वह लोगों की सुरक्षा क्या करेगी।

छत्तीसगढ़ में श्री नियोगी को एन०एस०ए० में गिरफ्तार किया गया था। वहां पर 9,000 मजदूरों को काम से निकाल दिया गया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has already been released.

श्रीमती प्रमिला दंडवते : लेकिन 9,000 वर्कर्ज को अभी तक काम पर नहीं लिया गया है। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इसकी तरफ ध्यान दें।

आज देश में 79 परसेंट पापुलेशन देहात में हैं और 83 परसेंट वर्क फोर्स भी वहां पर है। जनवरी, 1978 में रूरल अनआर्गनाइज्डलेबर की समस्या पर विचार करने के लिए एक कांफरेंस हुई थी। उसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी और पर्मानेंट बाडी बगैरह बनीं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लेबरर्ज के बारे में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार उन लोगों को आर्गनाइज करने के लिए क्या कदम उठा रही है। उनको आर्गनाइज करना चाहिए। उनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। 94 परसेंट महिलाए अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में हैं। उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है। जहां तक उनका सम्बन्ध है, ईक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। उन पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उनके लिए शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग और एप्रेन्टिसीशिप की कोई व्यवस्था नहीं है। 81.4 परसेंट महिलाएं एग्रिकल्चर के क्षेत्र में काम करती हैं। मैकेनाइजेशन के कारण उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। मैं एक मिसाल देना चाहती हूं। केरल में कायर इंडस्ट्री में मशीनरी लगाई गई। चूंकि स्त्रियों को उसकी ट्रेनिंग नहीं है, इस लिए उन्हें काम से हटाया जा रहा है। हमने आर्गनाइज्ड सेक्टर में यह नीति बनाई है कि रेशनलाइजेशन विदाउट महिलाओं टियर्ज। मैं समझती हूं कि जहां तक को एप्लायमेंट का सम्बन्ध है, उसमें भी इस नीति को लागू करना चाहिए। जनता पार्टी के समय में प्लानिंग कमीशन ने पहली बार यह मन्जूर किया कि विमेन्ज एम्पलामेंट शुड बि गिवन स्पेशल एटेन्सन। महिलाओं की एम्पलायमेंट के सवाल को सारे देश की एम्पलायमेंट के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों कि उन की प्रबलम अलग हैं, उन में एजुकेशन नहीं पिछली ट्रेनिंग नहीं और उन का एक ट्रेडीशनल रोल जो समझा जाता है उस की वजह से उन की हालत बहुत बहुत खराब है।

आज मैं यह कहना चाहती हूं कि एम्पलायमेन्ट गारंटी स्कीम महाराष्ट्र में जैसे चलती है वहां पर तनख्वाह क्योंकि कम मिलती है इसलिए

62 per cent of women are working in Maharashtra Employment Guarantee Scheme.

वहां पर पहले केन्द्र सरकार ने जो फूड फार वर्क की स्कीम शुरु की थी। उस की वजह से प्रति दिन एक किलो अनाज लोगों को मिल रहा था। वहां की महिलाओं ने कहा कि आप यह अनाज हमें दें तो हम उस से अपने बच्चों का पेट भर सकती हैं, वरना पैसा मिलता है तो पैसे से घर के लोग शराब पीते हैं। यह उन की मांग वहां पर रही है।

लेकिन सरकार ने वह अनाज देना बन्द कर दिया है और महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह प्रोक्योर करें। प्रोक्योर करने के लिए वहां की सरकार के पास ताकत नहीं है क्योंकि कि बाहर के जो व्यापारी हैं, होलसेल डीलर्स हैं वे जितनी सपोर्ट प्राइस है उस से ज्यादा पैसे देकर ज्वार बाजरा खरीद रहे हैं। आज 8 तारीख है, आज महाराष्ट्र में एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम के अन्तर्गत काम करने वाली महिलाओं और पुरुषों का एजीटेशन चल रहा है। जैसे निपाणी में एक एजीटेशन चल रहा है और महाराष्ट्र के अंदर और जगहों में चल रहा है। जब वहां पर अनाज दिया जा रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंन्ट ने जो एक एड के अन्तर्गत दिया था उस में हर किलो के पीछे 30 पैसा काटा जा रहा था। ऐसे काट-काट कर 2 करोड़ से ज्यादा रुपया इकट्ठा हुआ है। वहां की महिलाओं की मांग है कि हमारे लिए उस से हास्पिटल बनाइए, मेडिकल एड दीजिए और बाकी सारी वेलफेयर स्कीम जो है उस के लिए वे मांग कर रही हैं। अभी तक उस के लिए गवर्नमेंन्ट ने यही कहा है कि इट इज अंडर कंसिडरेशन। मेरा यह कहना है कि यह कंसिडरेशन की बात बन्द कर के उस के ऊपर कार्यवाही की जाय। लेबर मिनिस्टर से मेरी प्रार्थना है कि वह इस बात को देखें कि यह जो फूड फार वर्क स्कीम है उस के अंदर महिलाओं को अनाज की जरुरत है। वे कहती हैं कि हमें अनाज दीजिए। आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है क्योंकि कि ऐसा समझा जाता है कि :—

They are not economic asset to the family. On the contrary, they have become a liability.

मेरी यह मांग है कि स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार बन्द हो, और स्त्रियों को शिक्षा, स्त्रियों को हेल्थ, उन की एम्पलायमट इन सब की व्यवस्था के लिए

National Commission on Women (with statutory power) is a necessity.

इसके लिए मैंने पहले कितनी ही बार यहां पर मांग की थी। मुझे खुशी है कि कल कांग्रेस (आई) की महिलाओं ने भी जो मेरी मांग रही है उस का पूरा पूरा समर्थन किया है। तो मुझे आशा है कि उन की मांग की वजह से ही क्यों न हो उन की वजह से ही यह हो जाता है तो मुझे उस में खुशी है। इस सदन में बार बार यह मांग की है। पूरे देश में अलग अलग महिलाओं ने यह मांग की है। नेशनल स्टेटस आफ वीमेन्स कमेटी ने 1975 में नेशनल कमीशन आन वोमेन्स विद स्टेचयूटरी पावर ऐट सेन्ट्रल ऐंड स्टेट लेवेल की मांग की थी। मुझे लगता है कि यह करना बहुत जरुरी है।

आखीरी बात कहना चाहती हूं कि नेशनल वेज पालिसी एक होनी चाहिए लेकिन ये सारी बातें इन कंसल्टेशन विद आल दि ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशन्स होनी चाहिए। दूसरे ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशन्स में राइवलरी को करना है तो यूनियन की रेकग्नीशन सिर्फ वेरिफाइड मेम्बरशिप से नहीं होनी चाहिए बल्कि उस के लिए बैलट वोटिंग लिया जाय और जिन को वर्कर चाहते हैं उस यूनियन के साथ आप बात करें। यह होगा तो मोदी नगर में जो बात हुई है वह बार बार-दोहरायी नहीं जायगी। मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह बांडेड लेबर, महिला श्रमिक और चाइल्डलेबर इन के बारे में सारी यूनियनों से बातचीत कर के देश में कुछ ऐसी पालिसी बनाएं और उन को न्याय दिलाने की व्यवस्था करें तो देश का प्रोडक्शन जरूर बढ़ेगा

SHRI B. K. NAIR (Quilon): Sir, I rise to support the Demands for Grants put up by the Ministry of Labour. Right from the beginning the opposition parties have been throwing the challenge on our face and asking us whether ours is a Government that works, as if their performances is in doubt. They say that India Government is a non-performing Government and so on and so forth. That is the type of allegation that they resort to. Now, Sir, looking to the actual results what we find is this. After the coming into power of this Government, the labouring class, the kisans and the agricultural workers do not share this type of criticism of the Government. If you look at the working days lost during the last few years, what do you find? There were substantial losses of man-days during the Janata Government rule. During the first year of the Janata rule, that is, 1977-78, the man-days lost was 29.73 million. In 1978-79, it was 39.36 million, in 1979-80, it was 43.87 million and it has suddenly come down to 12.91 million this year. We should be happy to know about it. I entirely agree that we should not lose even a single manday. Now, the steep fall in the number of manday lost certainly indicates that the working class, labour class, the rural kisans and the industrial workers have accepted the present Government's policies, accepted that everything is all right and they have accepted the performance of the present Government. The Janata Government held out many promises to the workers. Their manifesto said that they were going to build paradise for the workers. They said that the workers should be given a bonus of 8-1/3 per cent which Shrimati Indira Gandhi had denied or deducted during the Emergency period. Then they said that those who had been removed from service during the Emergency period would be taken back and given employment. They had offered bonus and the right to strike to the Railway workers, Defence personnel and the P & T workers. Now, what was the performance of the Janata Government? What did Prof. Madhu Dandavate and Mr. George Fernandes do? They believed in Rolling Plan. They had converted the Five Year Plan into a Rolling Plan. Their Ministers believed in Rolling Plan and they went on rolling. Mr. George Fernandes the then Minister for Industry, had offered repeatedly that he would resign unless bonus was paid to the Railway workmen. So many assurances were given in favour of workmen. But what happened?

AN HON. MEMBER: What have you done for the workers?

SHRI B. K. NAIR: You better ask the workers. They will tell you what we have done for them. Mr. George Fernandes and other opposition Members were telling that they were committed to payment of bonus when the Railway workers and the P&T employees went on strike in 1974. But when they came to power, what was their performance? The performance was nil in this matter. They held out several promises to the workers and the labourers. But nothing was done for them. But the present Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi did not hold out such sweet promises. But she did call upon the nation to do hard work just as her illustrious father, Pandit Jawaharlal Nehru, told the nation that the generation was condemned to hard labour for the future generation. We cannot build up our nation for the future without sacrifice and discipline. I do not say that they would not get everything that they deserve. Mr. Daga mentioned that the picture for the entire world is going to be gloomy.

AN HON. MEMBER: What are you going to do for that?

SHRI B. K. NAIR: We are now turning the corner and I believe that in a year or two the Government and the country will be reaching the take-off stage in every field.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Daga wanted that the words "under consideration" should not be put but some other words should be used.

SHRI B. K. NAIR: During the Congress-I regime the foodgrain production has reached the highest level. In the production of steel, coal, power generation, the position is quite good. They are picking up well. I am sure that within the period of two years we will be able to reach the take-off stage in these items. The only difficulty is in the production of petroleum products. We are importing petroleum products. But we will also find a solution for that. The exploration activities in this field have been encouraging and are proving fruitful.

Now, Sir, there are so many acts and legislations. We have got umpteen Labour Acts in the country. But they are not enforced or implemented. They are only on paper. When the question of implementation of these Acts comes, we are lacking in this. Sir, there was a law passed for the plantation workers in 1951. 30 years have passed since then. An assurance was given that within 12 years' period all the workers would be provided with facilities for their dwelling, medicine and schooling for their children. The position is not better than what it was thirty years ago. It is still the same. The State Governments say that they do not have the implementation machinery; they do not have the jeeps for the inspectors to go about. The implementation is just zero.

Now, we are going to introduce a legislation for the rural labour, but what is the experience of Kerala. The law is there for the agricultural labour, but is it being implemented? It has mostly remained on paper. There is a provision for provident fund, but it has not been enforced. Even the registration of the workers is not taking place. We can say that we have such a legislation, for a big talk, it is all right, but I must tell the House that these labour laws are going to remain only on paper. The rural labour laws would be applicable to thirty crores of people, but where is the machinery to implement them? Let us not live in the world of dreams. We must try to do things in practical terms.

Then, there are a lot of people engaged in fishing. There is no law even for registering them, and indicating who the owners are and who the workers are. These workers are all the time running the risk of their lives throughout their employment. Nobody knows whether they would come back after their day's work. The women folk live in anxiety all the time. There is no law in respect of them in this country in spite of the fact that they are contributing Rs. 250 crores of foreign exchange by way of exporting marine products. I suggest that the Government should seriously think of having some legislation for registering these people and providing them with minimum assurance and security. I suggest that a welfare fund should be created for them based on a cess collected from export of marine products. As I said, we are exporting fish and marine products quite a lot and if we charge a nominal levy on these exports, we can collect a lot of money which could be utilised for the welfare of these people and for safeguarding their interests.

Then, Sir, some attempt is being made to legislate for the welfare of the circus workers. They provide a lot of entertainment to the people and it has got its roots in Kerala. I am particularly concerned about these people because I happen to be associated with them as patron of their union. There are thirty thousand of such people and a substantial number of them are children between the age of eight and fourteen years. It is particularly the performance of these children that the spectators enjoy the most. What legislative measures have we provided for them? These people live just like other animals. The difference only is that while the animals live inside the cage, they live outside it. That is how the owners treat them. Anything can happen to them; they may meet with an accident and may even die, but there is no security for them. Therefore, it is very important that

[Shri B. K. Nair]

some serious efforts should be made to look after their interests. And it is not very difficult to implement such legislation, because the number is very limited and the area of operation is also limited. They are only towns and cities, but the State legislation cannot help, it is only the Central legislation that should be there. There should also be some machinery for looking after its implementation.

The hon. lady Member referred to the multiplicity of labour unions. So many labour unions are there. It is a disease that has spread in our country. Crores of people are there in our working force, but what is the percentage that is organised? The trade union leaders make a show as if the entire world is behind them. According to the returns submitted to the Registrar, not more than 65 lakh workers are organised. These people agitate not for the sake of thirty crores of people who constitute the labour force, but for people like those working in Life Insurance Corporation, Indian Airlines, Reserve Bank, etc. Such organised people are the privileged category. An LIC clerk gets Rs. 3000 and odd per month. They go on strike with the demand that such people should be given more. Should not they have a national view? Thirty crores of people do not have even drinking water. Why should we agitate and support this privileged class of people? These people seek the perpetuation of their privileges. Is there any justification for such emloyees, the privileged group of people to go on strike and clamour for more? They say employees in the BHEL are getting more. The BHEL people will say, 'LIC people are getting more, so give us that.' Where is the end? Everybody is looking up. Railway people say, 'Look at the public undertakings. They are getting more than we. So we must get that.' So everybody is looking up and everybody is trying to justify. So, should we not have a national view? We talk of labour class in the country. When are we having in view? Are we having a view of that Daridranarain, the man who works with Charkha in the village industries? No, Sir. We are looking to the people who will give us the maximum publicity in the Press—the newspaper people, Reserve Bank, LIC people.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. N..., is there any temple for the Daridranarain?

SHRI B. K. NAIR: No, Sir. Temple is in our hearts, Sir.

I have a small suggestion about how to eliminate division on the labour front. They are already having five Central Trade Unions and fortunately we will be having one more under Mr. Dange. He will be having soon a small group. And the definition is that if an organisation has five lakh membership spread over five industries and spread over four or five States, then it is a National Union. The interesting thing is that it is mainly to become MPs, MLAs and to get berths in the committees. Can you believe Sir, only 60 lakhs of our workers are organised and that number has remained all the time static? No improvement. But the leaders are satisfied. I am not blaming, Sir. It is a very limited and narrow view of the whole thing. I am suggesting one solution for that and I think it will be acceptable to the Minister. That is every worker in an industry should be obliged to become a Member of any one Union. Secondly do not register more than three Unions in an industry. Then once a worker has become a Member of the Union, he cannot change the Union before six months. And once he changes, he remains in that Union.

So far we have been discussing about the obligations of so many people to so many trade unions, to the Government, units of industry and all that. But what about workers' obligations to the Union. He has an obligation just as a citizen has an obligation to cast vote and become voter. Worker to be a voter should be a Member of some Union and then having

become a Member of the Union, he should not change it. He should remain Member of the Union at least for six months. And once he changes his Membership, he should remain in that Union for at least six months. How to enforce this is a different thing. May be it depends on the employer. But that way we make it conditional employment in that industry.

Then every Union should be called upon to have elections once a year and the worker can opt for a particular union. But if he remains a member of a particular Union for a long time, there may not be any need or occasion for referendum. But personally if you ask me Sir, I am for secret ballot. But secret ballot should be only confined to members of the Union. Now about the role of employers. I don't like the idea of check-off, since it goes against the very spirit of trade-unionism. But the employer has a role to play in seeing to it that every employee remains a member of one union or the other. No person who is not a member of any union should be permitted to enjoy its benefits. He should draw the rights after fulfilling the duties. This sort of a scheme can be attempted.

I would suggest to the Minister of Labour to consider these aspects and try to evolve a sort of guideline for this purpose, to enforce discipline in the labour front.

15.31 hrs.

(SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*).

श्री दयाराम शाक्य (फर्रुखाबाद): श्रीमन् इस से तो कोई इंकार नहीं कर सकता है कि प्रत्येक देश की समृद्धि में उस देश के कर्मचारी और श्रमिक देश की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं। परन्तु आज हम हर जगह पर इंडस्ट्रियल अनरेस्ट देख रहे हैं। अगर देश के कर्मचारी और श्रमिक वर्ग का ध्यान नहीं रखा जाता है उसकी वास्तविक मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो वे शांति के साथ कार्य नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार से देश के उत्पादन को और देश की समृद्धि को हानि पहुंचती है, उसमें रुकावट पैदा होती है।

अभी हमारे बन्धु ने कहा कि आई० टी० आई०, बी० ई० एल०, एच० एम० टी०, एच० ए० एल० के कर्मचारियों ने यह मांग की कि दूसरे स्थानों पर तनख्वाहें ज्यादा हैं इसलिए उनको भी ज्यादा तनख्वाहें और सुविधाएं दी जानी चाहिएं। किन्तु उनकी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह समस्या 1978 में उठी थी और उस समय सरकार और आई० टी० आई० बी० ई० एल०, एच० एम० टी० और एच० ए० एल० में और कर्मचारियों में एक समझौता हुआ था कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान में सुविधाएं दी जाती हैं, तनख्वाहें बढ़ायी जाती हैं तो दूसरे संस्थानों में भी वही सुविधाएं और तनख्वाहें दी जाएंगी। परन्तु एक संस्थान बी० एच० ई० एल० में अधिक सुविधाएं देने के पश्चात् भी उस समझौते को बाकी प्रतिष्ठानों में लागू नहीं किया गया और वे सुविधाएं अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को नहीं दी गयी। उस समझौते का लाभ अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को देने के बजाय वह समझौता तोड़ा गया। अगर ऐसी बात होगी तो कर्मचारियों और सरकार के बीच या मालिकान के बीच जो समझौता होगा तो कर्मचारी कैसे भविष्य में उस पर विश्वास कर काम करेंगे। उनके मन में जब अविश्वास की भावना रहेगी तो वे शांति से काम नहीं कर सकते हैं। वे हमशा यही मांग करते रहेंगे कि अमुक ज्यादा पाते हैं, हम को उतना नहीं मिलता है।

जब तक आप कोई नेशनल वेज पालिसी लागू नहीं करते हैं तब तक जो समझौता हुआ है उसको तो आपको लागू करना चाहिए और जो

[श्री दया राम शाक्य]

मालिकान समझौते को लागू नहीं करते हैं उनका प्रोसीक्युशन होना चाहिए । लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह वास्तव में एक लज्जा की और निंदा की बात है। यह ठीक है कि आप देश के लिए एक नेशनल वेज पालिसी लागू करें लेकिन जब तक आप इसको लागू नहीं करते तब तक आपको कर्मचारियों को लिविंग वेज देने चाहिएं । इसीलिए अशांति पदा होती है कि अमुक स्थान पर कर्मचारी ज्यादा पाते हैं और हम कम पाते हैं।

जब तक आप नेशनल वेज पालिसी लागू नहीं करते तब तक आपको उनको बोनस देना चाहिए । सारे देश में अनेक वर्षों से कर्मचारी बोनस के लिए मांग करते आये हैं और सरकार ने इसको टाला है। बोनस एक डेफर्ड वेज है। इसको सरकार को विलम्बित वेतन के रूप में मानना चाहिए और अपने कर्मचारियों को बोनस देना चाहिए । जिन कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जा रहा है उन कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाना चाहिए । बहुत सी जगहों पर सरकार इसको नहीं दे रही है। बहुत से स्थानों पर सरकार ने इसको प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक कर दिया है । यह नहीं होना चाहिए ।

प्राय: यह देखा जाता है कि अधिकारी जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फण्ड मिल जाता है मगर जब एक साधारण कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको सालों पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फण्ड नहीं दिया जाता है । यह स्टेंडिंग आर्डर होने चाहिएं कि उनको तुरन्त इनका भुगतान हो और इनको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए जैसे ही कर्मचारी रिटायर होता है । उनको प्रोविडेंट फण्ड मिलना चाहिए, उसे पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए।

आज अनेक यूनियन और फेडरेशन ऐसे हैं जिनके साथ कर्मचारियों का बहुमत है लेकिन फिर भी सरकार उनको मान्यता प्रदान नहीं कर रही है, जिससे लेबर अनरेस्ट पैदा होता है, श्रमिक असंतोष पैदा होता है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए प्रैक्टिकल वैरीफिकेशन कराया जाए और देखा जाए कि किन यूनियन के साथ कर्मचारियों का बहुमत है और उनको मान्यता दी जाए । इस मामले को सरकार काफी अरसे से टाल रही है । मेरा अनुरोध है कि प्रैक्टिकल वैरीफिकेशन के बाद जिन यूनियन्स ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं, उन्हें मान्यता प्रदान की जाए ताकि लेबर अनरैस्ट दूर हो।

एल० आई० सी० के बारे में कहा गया। वहां पर हड़ताल चल रही है। न्यायालय के आदेश को सरकार ने नहीं माना है। सरकार की कोशिश है कि न्यायालय का आदेश लागू न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। परंतु उसका इंप्लीमेंटेशन भी सरकार नहीं कर रही है जिससे हड़ताल चल रही है और करोड़ों का नुक्सान हो रहा है। इसकी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मेरा अनुरोध है कि न्यायालय के आदेश को माना जाना चाहिए।

श्रमिकों के बारे में मेरा निवेदन है कि जो कांट्रेक्ट बेसिस पर या डेली वेजेज पर लेबर काम करते हैं अनेक वर्षों तक काम करने के पश्चात् उनको नौकरी से अलग कर दिया जाता है और इस अवस्था में निकाला जाता है जब वे कहीं और काम करने की स्थिति में

नहीं होते इसलिए मेरा अनुरोध है कि इनके लिए एक कानून बनना चाहिए ताकि कांट्रेक्ट बेसिस पर और डेली वेजेज पर काम करने वाले कर्मचारियों को निकाला न जा सके, तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ सकता है।

आज हम देख रहे हैं कि कर्मचारियों के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं उन्हें मेडिकल फेसिलिटीज नहीं दी जाती हैं। आवास सुविधा न होने की वजह से मीलों दूर से कर्मचारी काम पर आते हैं। हम चाहते हैं कि वे समय पर काम पर पहुंच सकें, परंतु मीलों दूर से आने के कारण यह संभव नहीं हो पाता जिससे काम समय पर नहीं होता। मेरा अनुरोध है कि कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की जाए और उनके लिए लोन आदि की व्यवस्था की जाए जिससे वे अपना मकान बना सकें।

अंत में मैं एक-दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज हर जगह समाजवाद की होड़ लगी है। हर जगह राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है लेकिन समाजवाद के नाम पर जितने भी प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उनमें से कितनों से सरकार को लाभ प्राप्त हुआ है? इसलिए मेरा अनुरोध है कि उद्योगों का राष्ट्रीकरण न कर के राष्ट्र का औद्योगीकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण एवं श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इससे श्रमिकों में यह भावना पैदा होगी कि हम स्वयं उद्योग में भाग ले रहे हैं। श्रमिकों की उद्योगों में भागीदारी होनी चाहिए और सरकार को उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे वे अच्छी तरह से काम कर सकें और उनको प्रोत्साहन मिल सके। इससे राष्ट्र की समृद्धि होगी और देश आगे बढ़ेगा वगैर इसके यह काम नहीं हो सकता।

इतने सुझाव मैंने माननीय श्रम मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और मुझे विश्वास है कि वे इनकी ओर ध्यान देंगे क्योंकि मैंने उनकी कार्यक्षमता प्रदेश में मंत्री के तौर पर मुख्य मंत्री के तौर पर देखी है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वे इन सुझावों पर ध्यान देंगे और इन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति जी, श्रम विभाग के अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, श्रम विभाग देश का एक ऐसा विभाग है, जहां से रोजगार की नीति तय होती है, नीति निर्धारण होता है। इसलिए यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता बहुत है। लेकिन मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो लेबर पालिसी हमारी रही है वह काफी इफैक्टिव नहीं रही है। यही कारण है कि आज बेरोजगारी की समस्या देश में पैदा हो गई है। हमारे देश में 14 करोड़ परिवार हैं। उन में से तीन से पांच करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन में एक-एक शिक्षित बेरोजगार अवश्य मौजूद होगा। जिस देश के 14 करोड़ परिवार में से पांच करोड़ परिवार एक एक नौजवान चाहे वह बी ए हो या मैट्रिक हो या उसने हाई स्कूली शिक्षा प्राप्त की हो, बेकार हो तो कितनी भयानक स्थिति देश के सामने है यह आप स्वयं सोच सकते हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है। इसको नजरंदाज करके नहीं चला जा सकता है। आगे चल कर बेरोजगारी की और भी जटिल समस्या का सामना करना पड़ेगा।

श्रीमती प्रमिला दंडवते बोल रही थीं कि श्रम विभाग ने कुछ नहीं किया। मैं उनके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। ये उनकी हकूमत के समय के आंकड़े हैं।

[श्री राम स्वरूप राम]

जिन बैंचों पर वह बैठी हैं और प्रो० मधु दण्डवते बैठे हैं उनके मंत्रित्वकाल के हैं । उस समय जितने लेबर डिसप्यूट हुए, देश का उत्पादन गिरा चाहे खेती का हो या फैक्ट्री का, किसी भी व्यवसाय का हो उतना पहले कभी नहीं गिरा । इसका कारण यह था कि लेबर डिसटर्बेंस बहुत ज्यादा हुए थे, और हर जगह हुए थे । अभी भी पश्चिम बंगाल में लेबर डिसटरबेंसिस बहुत ज्यादा हो रहे हैं । जहां जहां हमारी हकूमत है, श्रीमती इंदिरा गांधी की बनाई हुई सरकारें हैं चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो वहां पर लेबर डिसटरबेंसिस कम हैं । लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल में लेबर डिसटरबेंसिस पराकाष्ठा पर हैं । मैं 1979 के कुछ आंकड़ों को 1980 के आंकड़ों से तुलना करके इस बात को सिद्ध करना चाहता हूं । 1980 में श्रमिक स्थिति में सुधार हुआ है । इसका कारण यह है कि 1980 के दौरान हड़तालों तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रमिक दिनों की संख्या 129.1 लाख दिन है जबकि 1979 में यह 438.7 लाख श्रम दिनों की थी । राज्यों में पश्चिम बंगाल में सब से अधिक यानी 36.1 लाख श्रम दिनों की हानि हुई । महाराष्ट्र में 24.9 तमिलनाडु में 24.1 और उद्योग ग्रुप में विनिर्माण उद्योगों में सब से अधिक यानी 105.7 लाख श्रमिक दिनों की हानि हुई । ये 1980 के आंकड़े हैं । 1980 में हड़तालों और तालाबन्दियों का कारण कार्मिक छंटनी तथा अनुशासनहीनता है ।

महात्मा गांधी की जो परिकल्पना थी उसको यदि मंत्री महोदय ने श्रम नीति में जोड़ा होता तो इतनी ज्यादा डिसटरबेंसिस नहीं होतीं । उनके उपदेशों को श्रम नीति में समायोजित नहीं किया गया । महात्मा गांधी कहते थे कि पहले कर्त्तव्य का पालन करो, अधिकारों की बात बाद में करो । उसकी चिन्ता मत करो, कर्त्तव्य पालन करो । कर्त्तव्य पालन करते करते देखोगे कि अधिकार तुम्हारे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं । हम ने श्रम नीति के सिद्धान्त बनाते समय सब से पहले यही लिखा कि श्रमिकों को झगड़ा करने, प्रदर्शन करने, उपद्रव करने और मांग करने का अधिकार सब से पहले होगा । प्राइवेट सैक्टर या पब्लिक सैक्टर की कोई फैक्ट्री हो हमारे मार्क्सवादी भाई यहां बैठे हुए हैं, जार्ज फर्नान्डीस साहब बैठे हुए हैं, वे सब से पहले यूनियनें बनाने लग जाते हैं । सिर्फ यूनियन बना कर बठे हुए हैं । भारतीय जनता पार्टी का तो मज़दूरों से कोई सम्बन्ध ही नहीं है । उनकी सदा मज़दूर विरोधी नीति रही है । राय साहब बैठे हुए हैं, आप एक उदाहरण बता दें बिहार में जहां एक भी फक्ट्री ने आमदनी की हो और वहां मज़दूरों का हक न मिला हो ? लेकिन जो फैक्ट्री पब्लिक सैक्टर में नई बनी है उसमें लेबर हड़ताल कराने की क्या जरूरत है ? मंत्रीमहोदय आप गांधी जी की परिकल्पना श्रम नीति में लाइये कि कर्त्तव्य का ज्ञान सीखो, अधिकार पीछे पीछे आते हैं । लेकिन हमारे विरोधी भाई अधिकार की बात पहले करते हैं चाहे प्रोडक्शन हो न या हो । इसमें आपको सुधार करना चाहिये ।

दोनों तरफ़ के माननीय सदस्य लेबर की बात करते हैं, लेकिन खेतिहर मज़दूर की कोई बात नहीं करता क्योंकि वह आर्गेनाइज्ड सैक्टर नहीं है, उनको तनख्वाह नहीं मिलती माननीय जार्ज फ़र्नैन्डीस एक दिन भी खेत मज़दूरों की मीटिंग नहीं कर सकते माननीय राय साहब उनकी मीटिंग नहीं कर सकते । लेकिन हमारी पार्टी ने कहा, कांग्रेस ग्रामीण श्रम आयोग के गठन की मांग की, आप 14 मार्च 1980 का "नवभारत टाइम्स" देख लें । अखिल भारतीय कांग्रेस (आई) के श्रमिक सैल ने मांग की कि राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित किया जाये । हम राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग के गठन की मांग करेंगे । पता नहीं हमारे उस प्रस्ताव पर मंत्री महोदय का ध्यान गया है या नहीं ? मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उसको मानें ।

कृषि एक बहुत बड़ा उद्योग है जिसमें 80 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं और ऐग्रो लेबर की आबादी 43 प्रतिशत है। खेतिहर मजदूर गांवों में जमींदारों के यहां काम करते हैं, उनका शोषण आज तक हो रहा है। उनकी मजदूरी देखिये। जब मिनिमम वेजेज की बात कही गई, 1974, 75, 76 में कही गई थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी का इरादा था कि जब तक 43 प्रतिशत लोगों की स्थिति में सुधार नहीं लायेंगे तब तक समाजवादी समाज नहीं बना सकते। उनके मिनिमम वेजेज की बात आयी, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम उन्होंने देश में चलाया, लेकिन विपक्ष में बैठने वाले लोग चाहे माननीय उन्नीकृष्णन हों या माननीय जार्ज फर्नान्डीस हों, सबने कहा कि इन्दिरा जी तानाशाह हो रही हैं। यह कुलकों की और ब्लैक मार्केटियर्स की सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि यह सारा कार्यक्रम ठीक नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 43 प्रतिशत ऐग्रो लेबर्स की स्थिति में सुधार करने की हमारी सरकार की मंशा है, और आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से है, 1974 से ले कर आज तक का इतिहास आप उठा कर देख लें। हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में भी लिखा हुआ है। हमारी प्रधान मंत्री का 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश के तमाम गरीबों की काया बदल सकता है बशर्ते कि विरोधी दलों का सहयोग हो। लेकिन अच्छे काम को यह सदा सैबोटेज करते हैं और अड़ंगा लगाते हैं। कहीं असम को अलग करने की बात करते हैं तो कहीं कुलकों के हितों की बात करते हैं। कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा यह नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह ग्रामीण मजदूरों की दशा सुधारने के लिए एक दीर्घकालीन पालिसी निर्धारित करे। हम फख् के साथ कहना चाहते है कि बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक बूढ़े व्यक्ति को प्रति मास तीस रुपये की वृद्धावस्था पेशन देने का निर्णय किया है। इसी तरह हर एक प्रखंड में हरिजन और आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए आवासीय विद्यालय, मिडल स्कूल, की स्थापना की गई है और हर एक जिले नें आवासीय हाई स्कूल की स्थापना की गई है।

हरिजन और आदिवासियों के बच्चे कृषक मजदूरों के बच्चे हैं। कृषक मजदूर के बच्चे का मतलब हरिजन और आदिवासी का बच्चा होता है, हरिजन का मतलब गरीब होता है और गरीब का मतलब इन्दिरा गांधी होता है। हिन्दुस्तान की जनता इस बात को जानती है। (**व्यवधान**) सिर्फ मोहक नारों से आप गरीबों के हमदर्द नहीं हो सकते हैं। आपको व्यवहार में गरीबों के आंसू पोंछने का काम करना चाहिए।

गरीबी मिटाने का काम गरीब ही कर सकता है, यह काम टाटा और बिड़ला नहीं कर सकते हैं। गरीबी मिटाने का काम डेस्ट्रक्शन से नहीं होता है, जैसा कि श्री ए. के. राय करते हैं। गरीबी हटाने का काम हिन्दुस्तान का गरीब कर सकता है, जो खेतों और फैक्टरियों में काम करता है और हर जगह कड़ी मेहनत से देश को आगे बढ़ाता है। (**व्यवधान**) चौबे जी आज तक घड़ियाली आंसू बहाते रहे हैं। अमरीका के एक अर्थ-शास्त्री ने, उनका नाम मुझे याद नहीं है एक पालिसी दी --क्योंकि मैं अर्थ-शास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं—कि दि अगलियर दि वर्क, दि हायर दि वेजिज। समाज में जिसका काम जितना खराब हो, उसकी तन्ख्वाह उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए।

[श्री राम स्वरूप राम]

हिन्दुस्तान में सब से खराब काम करने वाले हरिजन भंगी हैं, हरिजन चमार हैं, हरिजन पासवान हैं, हरिजन मुसहर हैं और दूसरे हरिजन हैं । भंगी पाखाना सर पर उठाता है । चमार जूता बनाता है । जो लोग खेत में हल जोत कर बासमती चावल पैदा करते हैं, उन्हें मिलता क्या है ? दो सेर कच्चा अनाज । उसकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है । हमारे यहां डा. जगन्नाथ मिश्र ने यह बड़ा कदम उठाया है कि जो खेतिहर मजदूर काम करते हुए मर जायेगा, उसके परिवार को कम से कम दो हजार रुपये दिये जायेंगे ।

अब मैं टाटा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । टाटा के यहां दस हजार कंट्रेक्ट लेबरर्ज काम कर रहे हैं । इसी तरह डालमिया और जे. के. ग्रुप आदि में भी कंट्रेक्ट लेबरर्स हैं । बाप भी कांट्रेक्ट लेबरर था और बेटा और पोता भी कंट्रेक्ट लेबरर हैं । लेकिन आज तक उन लोगों को फैक्टरी में एम्पलायमेंट नहीं मिली है । हमारी कोलियरीज और दूसरे प्रतिष्ठानों में कंट्रेक्ट लेबर की व्यवस्था है । मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि वह टाटा और दूसरे फैक्टरियों में काम करने वाले कंट्रेक्ट लेबरज की लिस्ट बनायें और एक कलम से यह फैसला कर दें कि फैक्टरियों में उनका एबजार्प्शन कर दिया जाये ।

आप जानते हैं कि कोयले और आयरन ओर के कंट्रेक्ट लेबरर्ज को साढ़े उन्नीस रुपये मिलते हैं, लेकिन बगल में शिव प्रसाद बाबू के इलाके में बाक्साइट कम्पनी में छः, साढ़े छः रुपये मिलते हैं । कितनी विषमता है, जरा सा सोचने की बात है । हमारे विद्वान मंत्री जी काफी तजुर्बेकार हैं, हम समझते हैं कि काफी सोच समझ कर वह इस के मेंम करेंगे ।

अन्त में मैं अपनी दो तीन मांग पढ़ देना चाहता हूं ।

एक तो ग्रामीण श्रम आयोग का गठन अविलम्ब इसी सत्र में किया जाये ।

दूसरा है—ऐग्रो लेबर जो खेतों में काम करते हैं उन की लाइफ इन्श्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे कि बिहार सरकार ने लाइफ इन्श्योरेंस उन का किया है । दूसरी स्टेट्स में भी यह होना चाहिए ।

तीसरा है लेबर ऐक्ट—उस में क्या है कि जो व्यक्ति 240 दिन तक किसी प्रतिष्ठान में काम कर चुका हो उसे किसी तरह से हटाया नहीं जायेगा । यह लेबर ऐक्ट में हमारा कमिटमेंट है । लेकिन हमारे हजारों व्यक्ति मास्टर रोल में काम कर रहे हैं, 240 दिन उन को हो गए हैं लेकिन उन को आज तक परमानेन्ट नहीं किया गया क्योंकि वहां बैठे हुए कुछ हमारे ब्यूरोक्रेटस जिनको हराम की तनख्वाह दी जाती है बीच बीच में उन को डिस्कनटीन्यू कर देते हैं ।

ये मेरी तीन-चार मांगें हैं । मैं समझता हूं कि तिवारी जी इन को स्वीकार करेंगे ।

आप ने जो मुझे समय दिया उस के लिए आप को धन्यवाद देता हूं ।

श्री चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा) : मैं श्रम मंत्रालय की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज जैसी कि हम देश की स्थिति देख रहे हैं उस में श्रम का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है । अगर श्रमिक-शांति देश में हो तो देश बहुत थोड़े समय में आगे बढ़ सकता है ।

अपने पिछले कार्यकाल को हम देखें तो श्रमिकों को दो भागों में हम विभाजन कर सकते हैं—एक तो रजिस्टर्ड लोग हैं जो यूनियनों में रहते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते

हैं और दूसरे बंधुआ मजदूर जिन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं होती, दूसरी तरफ उन को हम रख सकते हैं । यह दो तरह का विभाजन उस में है । अगर हम दोनों पर थोड़ी रोशनी डालें तो ठीक आकलन हो सकता है । आज चारों तरफ जैसा कि हम सुनते हैं कि वहां पर हड़ताल हो गई, झगड़ा हो गया, अशांति हो गई, तो इस में ये लोग तो सब चीज मनवा लेते हैं क्योंकि उन की कानूनी शक्ति है, संगठन है । उस में सरकार को यह बात देखनी होगी कि आज जो असमानता की स्थिति देश में पैदा हो गई है उस से मजदूर के दिमाग में भी यह बैठता है कि इस देश के मालिक बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, काम हम करते हैं, हाथों की शक्ति हमारी है लेकिन सारा का सारा पैसा ये लेते हैं । इस के लिए यह हमें करना होगा कि सारे प्राइवेट सैक्टर के अन्दर इतनी जो असमानता हो गई है उस को एक समान लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा । दूसरे, उस में कुछ ऐसा सख्त कानून बनाने की बात है जैसे कि दूसरे देशों में है कि अगर मजदूर इतना काम कर के दिखाएंगे तो उन्हें उसी तरह की बढ़ती मिल जाती है, लेकिन यहां इस तरह का कमजोर कानून अपना है कि श्रमिकों पर पूरी तरह से दबाव नहीं दे सकते जिस से कि देश का प्रोडक्शन ठीक हो, फक्ट्री का प्रोडक्शन ठीक हो । उस के लिए सारे लोगों को तैयार होना पड़ेगा, दलविहीन बात करनी होगी, तब देश आगे बढ़ सकता है । नहीं तो दिन रात यही देखने को मिलेगा कि वहां पर हड़ताल, वहां पर तालाबन्दी वहां पर भूख हड़ताल, वहां पर गोली, तरह तरह की चीजें चारों तरफ सुनाई पड़ेंगी । उस के लिए मैं विरोधी दल का होते हुए भी आप से यह प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की चीज सरकार को लानी चाहिए और सब लोगों को उस में शरीक होना चाहिए । लेकिन उस में राजनैतिक बात नहीं आनी चाहिए जैसे कि बंगाल में आज हो रहा है, कांग्रेस वाले कर रहे हैं या और दूसरे लोग कर रहे हैं । इस तरह की बात जो लोग कर रहे हैं वह भी ठीक नहीं है । उस में सभी को सम्मिलित होना चाहिए और हड़ताल के पहले जितनी आम सहमति हो सकती है कि किन किन मामलों में क्या क्या करना जरूरी है वह पहले ही कर देना चाहिए जैसे मकान की बात है, भत्ते की है, बच्चों के तालीम की है, आवास की है, बाद में उन के पेंशन की बात है, इन सारी बातों में जितनी सुविधाएं दे सकते हैं वह देने का हमें टार्गेट बनाना चाहिए और उस के लिए समयबद्ध कार्यक्रम देना चाहिए । यह सब पहले ही दे देना चाहिए । उस के बाद भी अगर हड़ताल होती है तो सख्ती से कानून उस पर लागू होना चाहिए, यह मेरा आग्रह है ।

दूसरी बात रही बंधुआ मजदूरों की । बंधुआ मजदूरों का जैसा कि शोषण हो रहा है, उस के बारे में चारो तरफ शोर यही है कि कुलक किसान यह कर रहे हैं या वैसे किसान कर रहे हैं । मगर वह मेरे भाई जो अभी बोल रहे थे वह खेतों में जाकर देखें तो मालूम होगा कि उन में किस तरह से आपस में सम्बन्ध अच्छा है और किस तरह से वे लोग रहते हैं, तभी वे तरक्की कर पाते हैं । देहात के किसानों की जहां तक बात है और जो बंधुआ मजदूर हैं वे मिलजुल कर एक परिवार की तरह से रहते हैं । उनके यहां शादियों में, बीमारी में और तालीम के लिए पैसे दिए जाते हैं तभी वे अच्छी पैदावार करते हैं । जोर जबर्दस्ती से कभी भी अच्छी पैदावार नहीं हो सकती है ।

16 hrs.

दूसरी तरफ दिल्ली जैसे शहरों में 15, 17 या 18 वर्ष के जवान लड़के कोठियों में रहकर बर्तन मांजते हैं, होटलों पर रहते हैं, स्टेशन्स पर पड़े

[श्री चन्द्रपाल सिंह]

रहते हैं उनके लिए जरूर कुछ न कुछ करने की जरूरत है । उनका बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है । उन बच्चों की शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए । यह किस प्रकार से हो यह सरकार के विचार करने की बात है । आज देश में बेरोजगारी फैली हुई है, अगर कहीं पर एक आदमी हटने की बात करता है तो सौ वहां आने के लिए तैयार होते हैं । ऐसी हालत में यह लड़के जो कोठियों, बंगलों पर बर्तन मांजने का काम करते हैं जिसके लिए उनको 50 रुपया महीना मिल जाता है, वहां पर उनका जीवन नष्ट हो रहा है । सरकार को चाहिए कि इस सम्बन्ध में कोई कानूनी पाबन्दी लगाए ताकि उनका उद्धार किया जा सके । आप खेती में काम करने वालों के लिए दिनरात कहते रहते हैं कि कुलक किसान शोषण करते हैं लेकिन यहां पर कोई देखने वाला नहीं है । आपको देखना चाहिए कि वास्तव में कहां पर शोषण हो रहा है—शहरों में शोषण हो रहा है या देहात में जो मजदूर हैं उनका शोषण हो रहा है ?

आज सारे देश में जो श्रमिक अशांति फैली हुई है उस पर भी आपको पाबन्दी लगानी चाहिए । जैसा कि मैंने सुझाव दिया है, आप मिलजुल कर कुछ ऐसे नियम और परम्परायें बनायें जिससे कि कुछ समय तक अशांति न रहे ताकि देश में जो बेरोजगारी की समस्या फैली हुई है उसको दूर किया जा सके । यही चन्द बातें मैं कहना चाहता था ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, श्रम मंत्रालय की जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जबसे हमारी कांग्रेस (आई) की सरकार आई है, लेबर डिपार्टमेंट ने ठीक काम किया है । जनता पार्टी के राज में जितने श्रम दिवसों का नुकसान हुआ था और जिस प्रकार से शासन के काम काज में बिगाड़ आया था उसको दुरुस्त करने के लिए श्रम विभाग ने प्रशंसनीय काम किया है । इसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वे इसको और भी आगे सुधारने में अग्रसर हो सकेंगे ।

आज सबसे ज्यादा खराब हालत बंगाल की है । वेस्ट बंगाल में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, वहां पर जानबूझ कर सरकार की तरफ से हड़तालें कराई जाती हैं । सरकार की ओर से मजदूरों से कहा जाता है कि अगर हड़ताल करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जायेगा । इस प्रकार से बंगाल की सरकार देश के उत्पादन को गिराने में बहुत बड़ा योगदान कर रही है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सीटू की यूनियन है यह सबसे अधिक घातक है । यह यूनियन देश के मजदूरों को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रही है । मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये लोग लाठी के जोर से यूनियनों पर कब्जा करते हैं । एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम पूंजीपतियों के दुश्मन हैं और दूसरी ओर ये पूंजीपतियों के दलाल बनकर उनसे पैसा प्राप्त करते हैं और हर इण्डस्ट्री में 10–15 गुण्डे पालते हैं और फिर लाठी, तलवार, बन्दूक और पिस्तौल से फैक्टरीज पर कब्जा करते हैं, वहां अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं । इस प्रकार की हालत है । इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि आपको इस प्रकार की

व्यवस्था को रोकना चाहिए । आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे सभी लोगों को ठीक प्रकार से साधन मिलें और वह अपने आपको साबित कर सके कि वह कौन सी यूनियन में ज्यादा विश्वास करते हैं । मैं जयपुर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोटा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरीके से जब-जब मौका आया, तब-तब कितने आदमियों की जानें गई, कितनी हत्यायें की गई । इसलिए श्रम विभाग को इस संबंध में निश्चित तरीके से ध्यान देना चाहिए । वे जब शिकायत करते हैं कि आपके पब्लिक सैक्टर में आपके अधिकारी लोग किस प्रकार से डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती । इस वजह से दूसरे लोग मजदूर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पनपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है । पब्लिक सैक्टर में जितने आपके अधिकारी हैं, वे सब इन शहर के लोगों से मिले हुए हैं और वे जितने कानून बने हुए हैं, वे उन कानूनों के खिलाफ काम करते हैं । आई०एन०टी०यू० सी० को रिकांगनाइज करने में ज्यादा गड़बड़ करते हैं और उनको मान्यता प्राप्त नहीं होती है । खेतड़ी में कापर प्रोजेक्ट है, वहां पर पहले आई०एन०टी०यू०सी० यूनियन रिकांगनाइज थी, इनटक के नाम से, लेकिन उसके बाद सब अधिकारियों ने मिलजुल कर एटेक को रिकांगनाइज कर दिया है । उनके पास कोई बहुमत नहीं है । उसके बाद मैनेजमेंट के लोग इन लोगों से डरते हैं, लाठी, तलवार और बन्दूक के बल पर, इनको प्रोत्साहन देते हैं । उसकी वजह से दूसरे लोग, जिनका बहुमत होते हुए भी, जिनमें ज्यादा विश्वास होता है मजदूरों को, उसके होते हुए भी ऐसे लोगों को सहायता नहीं मिलती । इसलिए मैं माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं वे इस ओर ध्यान दें ।

आप जहां कहते हैं, इस देश में कि हम गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं, वहां पर तलवार और बन्दूक वाले कब्जा करना चाहते हैं, उनके संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, श्रम विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है, आपके अधिकारी क्या कार्यवाही कर रहे हैं? मैं जानता हूं आपके अधिकारी क्या करते हैं—वे बैठे रहेते हैं, कमिश्नर बैठा रहता है, एसिस्टेंट कमिश्मर बैठा रहता है, लेकिन जब शिकायत की जाती है, तो कोई सुनवाई नहीं होती है । मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है और वहां पर सेठों से मिल जाते हैं । मैं इस बारे में आपको एक नजीर देना चाहता हूं । मैनेजमेंट और मजदूर लोगों ने आपस में समझौता करके सात रु० मिनिमम वेज तय किया वहां के गेनरिया (भीलवाड़ा) सोप-स्टोन के बारे में । उसके बाद वहां झगड़ा बढ़ा और हमने यह मांग की हमको सात रुपए से ज्यादा मिलना चाहिए । मामला आर्बिट्रेशन में गया तो वहां के आफिसर एल०वी०आर० ने उसको घटाकर 6 रु० 65 पैसे कर दिया । जब इस प्रकार के अधिकारी श्रम विभाग में हैं तो कैसे मजदूरों को राहत मिलेगी । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से खास तौर से आग्रह करूंगा कि वे उस ओर भी देखें । लेबर डिपार्टमेंट में हुकूमत करने के लिए अधिकारी नहीं बनाए गए हैं, ये मजदूरों का सहयोग करने के लिए बनाए गए हैं । ये बड़े-बड़े अफसर मोटरों में घूमने और अन्य प्रकार के साधन जुटाने के लिए नहीं बनाये गए हैं, बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिलकर आर्थिक तौर पर अपने आपको सम्पन्न करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि वे इसलिए बनाए गए हैं कि मजदूरों के शोषण को समाप्त करें, मजदूरों पर जो अन्याय होता है, उसको दूर करें । जब इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तब जाकर मजदूरों का हित होगा ।

मैं एक बात अब प्रोवीडेंट फंड के बारे में कहना चाहता हूं । प्रोवीडेंट फंड का महकमा बहुत गड़बड़ हो गया है । इसमें मैंने आपको पहले भी सुझाव दिया था कि जिस तरीके से आपने एल०आई०सी० के पांच जोन बनाए हैं, उसी तरीके से आप इसके भी बना दीजिए ताकि जो उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह समाप्त हो । दस-दस वर्षों से मजदूरों को रसीद

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

नहीं मिलती है । रसीद न मिलने की वजह से उनको लोन नहीं मिलता है । जब वे नौकरी से भी निकल जाते हैं, तब भी उनको प्रोवीडेंट फंड का पैसा नहीं मिलता है । मर जाने के बाद भी उनका पैसा नहीं मिलता है । इस प्रकार का हाल हो रहा है । आपके प्रोवीडेंट फंड के जो अधिकारी लोग हैं जब से हम अपने मिल-मालिकों को कहते हैं कि हमारे प्रोवीडेंट फंड की रसीद दिलाओ, और वे अपने अधिकारी को भेजते हैं, अपने कर्मचारियों को भेजते हैं, तो बावजूद दो-तीन महीने बीत जाने के बाद भी उस की कोई व्यवस्था नहीं होती है । इस प्रकार की हालत आप के विभाग की है और मैं चाहता हूं कि इस को दुरुस्त किया जाना चाहिए । इस से हमारे जो मजदूर हैं उन के दिल व दिमाग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है । हम चाहते हैं कि प्रोवीडेंट फंड के संबंध में जो कानून हम ने बनाए हैं उन का ठीक तरह से पालन हो लेकिन उन का पालन ठीक तरह से नहीं हो रहा है । प्रोवीडेंट फंड का जो रुपया वसूल किया जाता है, वह सेठ खा जाते हैं और अपनी तरफ से वह पैसा नहीं देता है । मैं आप को बताऊं कि हमारे यहां मेवाड़ टेक्सटाइल मिल ने एक पैसा जमा नहीं किया और उस के ऊपर आप की तरफ से 20 लाख रुपये का जुर्माना हुआ मगर आप के जो अधिकारी हैं, वे उस से मिले हुए हैं और एक पैसा भी उस से वसूल नहीं हुआ है और आज भी उस पर 20 लाख रुपया बकाया है । मजदूरों का कितना पैसा बाकी है, इस का आप अन्दाजा लगा सकते हैं । मेरा कहना यह है कि जिस मालिक ने मजदूरों का शेयर खा लिया है, उस के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, मगर आप के अधिकारी उस से मिले हैं और उस का प्रोसीक्यूशन नहीं करते हैं बल्कि उस को बचाने की कोशिश करते हैं । इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अधिकारी पूंजीपतियों से मिले हुए हैं, उन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो । उन को सर्विस से निकाला जाए और उन के खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन होना चाहिए । तब जा कर सारी व्यवस्था ठीक बैठ जाएगी । इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि मजदूरों के प्रति वे सहानुभूति रखते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था आप के विभाग में है, उस से हमारा सिर शर्म से झुक जाता है । हम चाहते है कि इस विभाग में जो वह गन्दगी फैली हुई है और निश्चित रूप से गन्दगी फैली हुई, वह ठीक हो और मजदूरों को राहत मिले । इस प्रकार की व्यवस्था आप के विभाग में होनी चाहिए ।

दूसरा निवेदन मैं ई० एस० आई० डिस्पेंसरीज के बारे में करना चाहता हूं । ये जो सेठ हैं, ये जो पूंजीपति हैं, कितना पैसा मजदूरों का काट लेते हैं लेकिन आप की जो ये ई० एस० आई० डिस्पेंसरीज हैं, इन से उन को अच्छी दवाईं नहीं मिलती है । बढ़िया बढ़िया दवाइयें तो आप के जो अधिकारी हैं, वे ले जाते हैं लेकिन जो गरीब मजदूर है, जो टी० बी० पेशन्ट है और दूसरी भयानक बीमारियों से ग्रसित है, उस को कितनी दवा यहां से मिलती है और किस प्रकार की उस की हालत है । कीमती दवाएं जो हैं व मजदूरों के लिए नहीं हैं, वे तो बड़े बड़े अधिकारियों के लिए हैं, और कुछ अन्य लोगों के लिए हैं । गरीब मजदूर तो मरना चाहता है और उसको मरने का राइट है । इसलिए उस के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है । इस प्रकार की व्यवस्था आपकी ई० एस० आई० डिस्पेंसरीज की कब तक चलती रहेगी । अगर इसी तरह की व्यवस्था चलती रही, तो जो मजदूर टी० बी० का पेशेंट या दूसरी ऐसी बीमारी से ग्रसित है, वह ठीक नहीं हो सकता और अपना इलाज माकूल तरीके से नहीं करवा सकता मेरा कहना तो यह है कि इस तरह की बीमारियों के लिए मजदूर को कीमती से

कीमती दवा मिलनी चाहिए । इस प्रकार की व्यवस्था जब तक आप की नहीं होगी, ई० एस० आई० के मामले में आप ऐसी कोई व्यवस्था जब तक नहीं कर पाएंगे और वहां जो अव्यवस्था है, उस को दूर नहीं करेंगे, तब तक मजदूरों का भला नहीं होने वाला है । सेठों से, मैनेजमैंट पर जो पैसा बाकी है, वह वसूल नहीं किया जा रहा है । उन से पैसा वसूल कर के मजदूरों को राहत दी जाए और इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से करना चाहिए । तब जा कर ठीक प्रकार की व्यवस्था बैठ पाएगी ।

एक बात मैं वर्कर्स एजूकेशन सेन्टर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । पहले भीलवाड़ा में, मेरी कांस्टीटुयेन्सी में वह सेन्टर था, जिस को हटा कर जयपुर कर दिया गया है ।

श्री गवल किशोर शर्मा (दौसा) : उस को वहीं रहने दो ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं जयपुर से हटाने की बात नहीं कह रहा हूं, जयपुर में वह रहे लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर पहले वर्कर्स एजूकेशन सेन्टर था, वहां पर एक वर्कर्स एजूकेशन सेन्टर आप दे दो । मेरी मांग यह है कि वहां पर आप एक वर्कर्स एजूकेशन सेन्टर दीजिए ताकि वहां के लोगों के लिए ठीक प्रकार से व्यवस्था हो सके ।

इसी प्रकार से सोप-स्टोन के मजदूरों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आप ने जो 6 रुपये 65 पैसे न्यूनतम मजदूरी दी है, जो मिनीमम मजदूरी दी है, उस से कैसे एक आदमी का पेट भर सकता है । जो आदमी सैकड़ों फीट खान के अन्दर जा कर खोदता है, उस को आप ने 6 रुपये 65 पैसे मिनीमम मजदूरी दी है, इस को आपको रिवाइज करना चाहिए और दूसरी खदानों में जितना पैसा और मजदूरों को मिलता है चाहे वह कोयले की खदान हो या अन्य खदान हो, उस के मुकाबले में ही उस को पैसा मिलना चाहिए, तब जा कर उस की स्थिति ठीक होगी ।

लाइमस्टोन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं ।..(**व्यवधान**)..माननीय सभापति महोदय, आप तो एक एक मिनट में घंटी बजा देते हैं । यह तो मजदूरों का मामला है, मुझे थोड़ा समय और दीजिए ताकि मैं मजदूरों के फायदे की बात कह सकूं, तो अच्छा होगा । आप इसमें भी मदद कीजिए और सोप स्टोन और लाइम स्टोन की खदानों के मिनिमम वेजिज रिवाइज कीजिए । सभापति जी, चूंकि आप घंटी बजा रहे हैं इसलिए मैं प्वाइंट ही बता देता हूं ।

सोप स्टोन और लाइम स्टोन की खदानों में वे सारी वेलफेअर एक्टीविटीज लागू नहीं हैं जो कि दूसरी खदानों में हैं । जैसे कि मकान के बारे में, बच्चों के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में एक्टीविटीज हैं । आप इन खदानों में भी ये एक्टीविटीज लागू करेंगे तो आपकी दुआ से वे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे ।

मेरा यह भी निवेदन है कि जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है जिसके बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था कि उसके मालिकान मजदूरों को प्रोविडेंट फण्ड का पैसा खा गये हैं, ई० एस० आई० का पैसा खा गये हैं, हर प्रकार का पैसा उन्होंने खाया है । इसको ठीक किया जाना चाहिए । इस मिल का तुरन्त नेशनेलाइजेशन होना चाहिए । चार सौ मजदूरों ने इसके सम्बन्ध में आपको मि० रेड्डी (डिप्टी मिनिस्टर लेबर) को

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

मेमोरेण्डम भी दिया है और निवेदन किया है कि इसको जल्दी से जल्दी नेशनेलाइज किया जाए । अगर आपने यह नहीं किया तो यह बन्द हो जाएगी और तीन हजार मजदूर बेकार हो जाएंगे । मंत्री महोदय, मजदूरों पर कृपा कर के इसको नेशनेलाइज कीजिए अन्यथा उनकी रोजी-रोटी की दुरशीष हमको मिलेगी ।

पहले इंडस्ट्रियल कालोनीज बनाने के लिए 50 परसेंट सहायता भारत सरकार देती थी और 50 परसेंट सहायता राज्य सरकार देती थी । तब स्टेट की तरफ से इंडस्ट्रियल कालोनीज बनती थीं लेकिन वह पालिसी अब नहीं रही है । मजदूरों के पास न कोई मकान होते हैं और न कोई प्लाट होते हैं । दूसरी ओर कोई व्यवस्था भी मजदूरों के रहने के लिए निश्चित नहीं है । इसलिए इस पालिसी को रिन्यू कीजिए ताकि तमाम मजदूर लोगों को देश में रहने के लिए मकान की व्यवस्था हो सके और वे लाभान्वित हो सकें ।

दूसरे जो मजदूरों के लिए कालोनीज बनी हुई हैं जिनमें कि 15–15 और 20–20 सालों से मजदूर रहते हैं उनमें मजदूरों को हायर परचेज के बेसिस पर मकान दीजिए ताकि उन लोगों के लिए स्थायी तौर पर रहने के लिए छत की व्यवस्था हो सके ।

एम्प्लाएमेंट एक्सचेंजिज की व्यवस्था बड़ी खराब है । इनके द्वारा खास तौर पर शेडयुल्ड कास्टस और शेडयुल्ड ट्राइबस, अल्प संख्यक के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है । मैंने देखा है कि बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के कारखानों में पैसा दे कर के लोग बाहर से लग जाते हैं और एम्प्लाएमेंट एक्सचेंज में भी नाम लिखा लेते हैं इन छोटी जाति के लोगों को इनएम्प्लाएमेंट एक्सचेंजों के द्वारा कोई नौकरी नहीं मिल पाती है । इन सारी व्यवस्थाओं को आपको ठीक करना चाहिए । अगर यह ठीक नहीं करेंगे तो नौकरियों में गड़बड़ी रहेगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इनमें व्यवस्था को ठीक करें ।

यूनियंस की रिकगनीशन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उनका रिकगनीशन वेरीफिकेशन के आधार पर होना चाहिए ।

ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पहले साल में 13 दिन की ग्रेच्युटी देने का कानून था लेकिन बाद में इसको 15 दिन का किया गया । लेकिन एक्ट में यह प्रावधान स्पष्ट नहीं है । एक्ट में यह प्रावधान स्पष्ट कीजिए ।

आखिर में मैं पालेकर अवार्ड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े बड़े अखबार जैसे टाइम्स आफ इंडिया और स्टेटसमेन हैं वे इन्हें लागू नहीं कर रहे हैं । उनका प्राफिट पहले से बढ़ा है उसके बावजूद वे इसको लागू नहीं कर रहे हैं । मैं आपको टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप के मुनाफे के बारे में बताना चाहता हूं । इस ग्रुप का 1970 में 1137 लाख का रेवेन्यु था जो जो कि 1980 में बढ़ कर 3291 लाख हो गया । टेक्स काटने के बाद 1970 में जहां इसका प्रोफिट 32 लाख था वहां 1980 में वह 81 लाख हो गया । इस हालत में भी पालेकर अवार्ड को लागू न किया जाए तो यह गरीब जर्नलिस्टों के साथ अन्याय है । बड़े बड़े अखबार बड़े बड़े पूंजीपतियों के अखबार हैं और उन्हीं के लिए ये मुनाफा कमाने की व्यवस्था करते हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि इस अवार्ड को उनसे लागू करवाया जाए । अगर वे इसे लागू नहीं करते तो गवर्नमेन्ट

की तरफ से इसको लागू कराने की समुचित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि गरीब जर्नलिस्टों को पूरा वेतन मिल सके और वे इस देश की अच्छी तरह से सेवा कर सकें।

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore): Mr. Chairman, Sir, we are watching with wonder and awe that the Government of India's policy is gradually becoming the policy of confronting the labour, the Government of India's policy is gradually becoming the policy of wage-freeze, the Government of India's policy is becoming a policy to take away from the workers whatever trade union rights exist instead of expanding and broadening the trade union rights. I will cite some examples.

How have you dealt with the recent strike by the public sector workers of Bangalore? You were standing helplessly. We did not find you amongst the workers to settle the dispute. We found Mr. Stephen going about there and brandishing *danda* over the workers—over the head of the Labour Minister. The Government of India could afford to lose production worth Rs. 126 crores, but the Government of India, the Ministry of Labour, could not give Rs. 6 crores to the workers. This is the direction in which their policy is moving.

The LIC employees are on strike. What for? You speak of democracy. You speak of the rule of law. But what is happening? You are not abiding even by the decision of the Supreme Court. You want to violate the decision of the Supreme Court. Then what can the workers and employees do except go on strike? Kindly tell me. You violate the terms of agreement you entered into; they go to court; the Court gives the decision in their favour, but you do not accept. Then what else can they do? I would request the Government of India, the Labour Ministry to see that this is settled. Don't think that every time you will simply take the sword and smash it. The Finance Department, I am told, has given notice to smash the strike. This is not the way, at least not the Gandhian method of which you are speaking.

You have advocated against full neutralisation of the cost of living index in the matter of D.A. and salary. You even refuse to correct the wrong, anti-labour price index of 1960, although the Committee set up by the Government advocated correction. Why? Is it not an anti-labour policy? I hope that you will see that the recommendations made by the Committee set up by the Government of India in the matter of correcting the wrong cost of living index of 1960, are accepted.

My friend opposite has talked about the Palekar award. You have accepted the Palekar award.—I thank you for that—but not those recommendations concerning the D.A. Why? You have accepted everything, but you have not accepted the recommendation concerning D.A. That is because you are for wage-freeze. You do not want the wages of the workers to rise. You want the profits to rise, but you do not want the wages to rise, you want the wages to be frozen. Even whatever recommendations in the Award you have accepted, you do not see that they are implemented. The *Times of India*, I am told, are not accepting the Award; even whatever you have accepted, they are not implementing. The *Statesman* is also not implementing the Award. And you are sitting like a doll. You are not doing anything. You do not give any protection to the people who are for implementing the Award....

MR. CHAIRMAN: Your Party's time is only five minutes.

SHRI NARAYAN CHOUBEY: I can have it extended, Sir, by your grace.

There is a difference between the Janata and the Congress (I); my friends on the other side every time rise and say that it was in the Janata rule that

[Shri Narayan Choubey]

this thing happened or that thing happened. I am neither for Janata nor for Congress-I. But there is unity between you and Janata in one respect, that is, in bringing the workers down. The Industrial Relations Bill which the Janata Party brought and against which lakhs and lakhs of workers demonstrated and the streets of Delhi were flooded with the workers—that Bill you have again been bringing forward—without changing anything. You speak fighting against the Janata. Then why do you follow the footsteps of the Janata in the matter of Industrial Relations Bill? What are there in this Bill? The workers cannot go on a strike. You have brought so many paraphernolia. If that be followed, you will be binding the hands and feet of the workers and throwing them at the mercy of the employers. I warn you. If you do not desist from brining forward this Bill, the workers will again revolt. You may think of weakening the workers buf the working class, united, will give you a good rebuff in this matter.

Then, Sir, you do not even implement your own rules which are formulated. They are not Janata rules. They are brought by you—by the previous Indira Government. Then the Contract Labour Abolition and Regulation Act. What are you doing? You are not implementing that. I can give you an exeample. In the steel city of Jamshedpur have they implemented it? There 10,000 workers have been thrown out of empolyment and you and we all and particularly you, shed tears and crocodile tears for the Adivasis, Scheduled Castes and the Scheduled Tribes but the poor workers have been thrown out of employment in the TISCO. They are mostly our tribal belt workers. They have been thrown out. Do you want to do something for them?

At Dallirajhara what have you done? Their leader was arrested under the National Security Act, our friend, Shri Shankar Niyogi. He has been released perhaps by the court. Now 9000 workers of that jungle belt, miners, 9000 miners have not been allowed to join duty. And remember it is not a State affair, not that, it is not under the State of Bihar or UP. Central Ministry is very much involved in it and still you are not prepared to do anything. I hope you will do something in the matter.

Much has been said about the functioning of the office of the Provident Fund Commissioner and I do not want to repeat it. Actually it is in total jeopardy. There is no proper keeping of accounts. They do not give you receipts. Workers retire and they do not get their Provident Fund dues and a large number of officers are in close link and league with the management of the big houses. I can give you one example. There is one factory by name Laxmi Chemicals Industries (P) Ltd., Kharagpur. The Government of India here in the Labour Ministry said that the Provident Fund Act will be implemented there and they did so in the month of October. Even till this month of April the management has not done anything and the Provident Fund Act is not implemented and the management is saying that they will go to the court and the Regional Provident Fund Commissioner at Calcutta does nothing except taking money and collecting money from owners...

MR. CHAIRMAN: Kindly conclude.

SHRI NARAYAN CHOUBEY: I am concluding, Sir.

I want to draw the attention of the hon. Minister to one matter. He is a very good friend of ours and I want to ask him—will you kindly hear it and do something? Gradually the Ministry is becoming a doll Ministry. I do not say—impotent. I say a doll Ministry. There are 24 million organised labour in this country. 24 million organised labour and in this 17 million are in the public sector and the most cruel part of the

entire thing is this that you you have no say over them. There your Energy Department comes, your Mines Department comes, your Steel Department comes, this department or that department comes. Then what is the use of keeping this Labour Department you even cannot implement the Industrial Disputes Act there. There is a proverb in Sanskrit which says:

किमतसा क्रियते धिन्ना, सा न सुता न दुग्धदा ।

What is the use of keeping such a cow which does not give milk or which does not give a calf? I suggest that something should be done by your department so that the authority of your department can be imposed in all these things.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Don't kill the cow.

SHRI NARAYAN CHOUBEY: Don't kill the cow. I say you do not kill the cow. What is the use of keeping the cow which does not give milk or calf? I suggest that your department should have authority over these things. Otherwise there is no use in having the ministry. The railways do not abide by the rules. All jobs which are of perennial nature should be departmentalised. Throughout the entire India in all the loco sheds, thousands and thousands are working. You go to Agra or Kharagpur or Bilaspur or Sealdah or to Howrah. Thousands and thousands of workers are working for years together as contract labour even though the work is of perennial nature. So long as there is steam engine, there will be coal or cinders. The railways do not abide by the rules. In the year 1976 they have recommended for making contract labours permanent. They do not abide by the rules. I hope you will go through the problems of these workers also. There should be one national minimum wage for the agricultural labour. I was hearing from the friends opposite, from the Congress Party, that the workers working in the copper mines are getting Rs. 6.50. They were getting Rs. 7.00 through the intervention of INTUC. Your department brought it down to Rs. 6.65. Such is the activity of your department.

You come and see West Bengal. There the agricultural labourer is getting a wage of Rs. 8.90 or Rs. 10. You will see one wage in Bihar and another wage in Bengal or in Orissa. There should be a national wage policy. Kindly see that Government protects the workers. Government can break the strikes but cannot protect the workers. This was what you did in Emergency. You behaved like Mother Kali when there was a strike. But you behaved like Lord Krishna when there was a lock-out. That is what you did in the case of loco workers recently. You break strike, you protect lockouts.

MR. CHAIRMAN: You leave Kali and everything to Shri Vajpayee Ji.

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE (New Delhi): He comes from West Bengal and so he must talk about Kali.

SHRI NARAYAN CHOUBEY: You know that in 24 Parganas in Mohini Mills there was a lockout for more than a year. In Dalmia Dadri Cement Factory in Haryana there was a lockout from 19-3-1980. Will you do something for them? If you cannot do it then it will be

या ना सुता न दुग्धदा

In the end, I would like to sound a note of warning.

PROF. MADHU DANDAVATE: If he talks in Sanskrit, then he will have to explain in the Polit Bureau;

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. Don't go into details.

SHRI NARARAN CHOUBEY: So, I would urge upon you to rise to the occasion. If the Government of India's policy becomes a policy to beat the workers or to belabour them, then, I will say with all humility that you may succeed to-day or

[Shri Narayan Choubey]

you may succeed tomorrow but the day after tomorrow you will never succeed because workers will unite and give you a proper rebuff.

With these words, I oppose the Demands for Grants.

MR. CHAIRMAN: Shri Sunder Singh. You are allowed three minutes only.

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेयरमैन साहब, मैं स्टेट में दस साल तक लेबर मिनिस्टर रहा हूं। मुझे पता है कि हम यूनियन वालों को किस तरह टरका देते थे। हमारे पास तीन लफ्ज थे। जब हम लेबर मिनिस्टर्ज कांफरेंस में जाया करते थे, तो हम आखिर में तीन लफ्ज इस्तेमाल करते थे: यह मसला हल होगा वाई डिसकशन, पर्सवेशन एंड कनसिडरेशन। इस तरह हम सारे मसले को हल कर देते थे।

जब तक देश का हर एक आदमी अपने आप को लेबरर नहीं समझेगा, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। श्री व्यास ने बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कहीं। उनकी स्पीच खत्म ही नहीं हो रही थी। हर एक मेम्बर को पांच मिनट में अपने ख्यालात रख देने चाहिए। मसोलिनी ने कहा था कि आई एम ए. लेबरर फर्स्ट एंड दैन ऐनीथिंग एल्स। जैसा कि मैंने कहा है, जब तक हिन्दुस्तान का हर एक इन्सान अपने आप को लेबरर नहीं समझेगा तब तक सिर्फ कानून बना देने से कोई मसला हल नहीं होगा।

आज सब लोग अपने अपने इन्ट्रेस्ट्स के लिए काम करते हैं। सब पैसा जमा करना चाहते हैं। लेबर के लिए कौन सोचता है? मैं श्री वाजपेयी को भी कहना चाहता हूं कि जब तक सब लोग लेबरर नहीं बनेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। जब मैं श्री वाजपेयी को देखता हूं तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि वह लेबर से बड़ी मुहब्बत करते हैं।

"As long as millions live in hunger and ignorance I hold every man a traitor who has been enducated at their expense and pays not the least heed to them.

लोग लेबर की कास्ट पर आगे बढ़ते हैं और फिर शहरों में आ कर मजे से रहते हैं। जब तक इन्सान अपने आप को ठीक नहीं करेगा, तब तक कोई भी काम ठीक नहीं होगा। मैं सोशलिज्म की बात बताना चाहता हूं। हम लोगों को महात्मा गांधी की शिक्षा को याद रखना चाहिए, स्वामी विवेकानन्द की बातों को अपने सामने रखना चाहिए।

"Even a morsel of food we eat is taken away from another's mouth."

इस उसूल पर चल कर लेबर का भला हो सकता है। कई लोग दस खाने खाते हैं और लेबर की हिमायत का दावा करते हैं। यह ठीक नहीं है।

"Where should you seek for God? Are not the poor, the miserable and the down-trodden Gods? Worship them first. I do not believe in God and religion who cannot wipe out tears from the widow's mouth and cannot bring a morsel of food to the orphan's mouth."

सिर्फ कानून बनाने से ही हमारे मसले हल नहीं हो सकते हैं। मैं किसी खास आदमी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आज तो बाबा आदम ही निराला हो गया है। हर एक आदमी को अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए।

"Be of good cheer and believe that we are selected by the Lord to do great things and we will do them. Hold yourself in readiness. That is

be pure and holy and love for love sake. Love the poor, the miserable, the downtrodden and God will bless you."

जब तक हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं चलेगा। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि लेबर को कारखाने में हिस्सेदार बनाना है। कहां बनाया है ? हम लोग गरीब और लेबर का नाम लेते हैं, लेकिन सही काम नहीं करते हैं। इसी वजह से लोग हैरान और परेशान हैं।

अब मैं जरा गुजरात की बात कहूं। वहां हमारे हरिजन भाइयों को बहुत दिनों से मार मार कर हलाल कर रहे हैं। आप देखें 1947 में जब इनको जरुरत थी तो हमारे हरिजन भाई इन के साथ थे। महात्मा गांधी की बात मान कर हम इन के साथ रहे। जब इनका काम निकल गया तो अब क्या कर रहे हैं। एक परसेंट भी नौकरी में नहीं आ पाए हैं और मार मार कर ढेर कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि हिन्दुस्तान में सब कुछ हरिजन ले गए जी, हरिजन सब खा गए जी। क्या खा गए जी ? कुछ भी नहीं खा गए। देखिए ये कारपोरेशंस हैं, बड़े बड़े कितने कारखाने हैं, मकान हैं इन सब में कितने हरिजन हैं ? सब जगह भारत माता जिन्दाबाद ही है न हम भारत माता जिन्दाबाद ही कहते रहेंगे लेकिन हमारा कहीं कुछ भी नहीं होगा, न कोई मकान, न कोई दूकान, न कोई सामान, बस भारत माता जिन्दाबाद है।

सभापति महोदय : अब खत्म कीजिए।

श्री सुन्दर सिंह : ये गरीबों का नाम लेते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी आती है कि भाई, ये किस मुंह से गरीबों का नाम लेते हैं। यह जार्ज भी उन का नाम लेते हैं जो गाड़ियों उलटाते रहे हैं। ये बेचारे भी उन का नाम लेते हैं। बड़े पीसफुल आदमी हैं, गाड़ियों उलटाते चलते हैं।

सभापति महोदय : टाइम खत्म हो गया।

श्री सुन्दर सिंह : मैं यह सिर्फ आप से कहूंगा चेयरमैन साहब कि बाद में और भी चेयरमैन बनने वाले हैं उन से कहिए कि पांच मिनट से ज्यादा किसी को टाइम न दें। आप देखिए कि हरएक आदमी चाहता है कि उस का नाम आए, वह अपने ख्यालात यहां बताए। लेकिन यहां लोग जो शुरु करते हैं तो खत्म करने को आते ही नहीं। फिर फायदा क्या हुआ। काम एक का भी नहीं बनता। ये बेचारे अपोजीशन वाले तरस तरस कर मर रहे हैं इन का भी काम नहीं बनता।

मेरा सिर्फ यह कहना है कि अपने आप जब तक उस पर हम अमल नहीं करेंगे अपने आप में जब तक इंडिविजुअलिटी नहीं लाएंगे तब तक काम नहीं बनने का है। सीधी बात है कि सारे आदमियों को अपने आप को लेबर समझना चाहिए तब गरीब का भला हो सकता है, लेबर का भला हो सकता है और सोशलिज्म आ सकता है, डेमोक्रेसी चल सकती है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधुपुरा) : सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि किसी भी मुल्क की बेहतरी उसके मजदूरों की संतुष्टि पर निर्भर करती है। यदि मजदूर संतुष्ट हुआ तो फिर अच्छा उत्पादन होगा और मुल्क आगे जाएगा।

बदकिस्मती से इस मुल्क की श्रम-शक्ति सबसे ज्यादा शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित रही है। मैं मजदूरों को दो वर्ग में बांटता हूं—

[श्री रामेन्द्र प्रसाद यादव]

एक असंगठित मजदूर वर्ग जो कारखानों में काम करते हैं और प्रायः शहरों में रहते हैं और दूसरे असंगठित मजदूर वर्ग जो खेतों में काम करते हैं और प्रायः देहातों में रहते हैं। यदि आप गौर से देखेंगे तो दोनों प्रकार के मजदूर आज परेशान हैं। पहले तो इसलिए कि उनको काम के मुताबिक पैसे नहीं मिलते तथा महंगाई इस प्रकार आसमान को छू रही है कि वह अपना पेट भी नहीं भर पाते, परिवार का पेट भरने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। मैनेजमेंट कोई विहित सुविधा भी उनको देने के लि तैयार नहीं है। इन कारणों से आए दिन हड़ताल और तालाबन्दी हुआ करती है। इस हड़ताल और तालाबन्दी के कारण करोड़ों रुपये की क्षति होती है। मंत्री जी ने 1980 में 12.91 मिलियन मैन डेज लास बताया है जब कि 1979 में 43.87 मिलियन मैन डेज का लास हुआ यह इनका कहना है। पता नहीं क्यों यह सरकार बार बार जब कोई बात करती है तो इससे पहले की सरकार का आंकड़ा लेकर सदन में आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो आंकड़े इनके ही मुताबिक आपके सामने हैं 12.91 मिलियन मैन डेज लास्ट के क्या यह वाजिब है?

बदकिस्मती से यह सरकार हड़ताल और तालाबन्दी में बिना कोई काम कर ही नहीं सकती। मैं अगर यह कहूं कि यह सरकार वास्तव में हड़ताल की ही भाषा समझती है तो कई अत्युक्ति नहीं होगी। मैं आग्रह करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या आप नहीं देख सकते कि वास्तव में जिन कारणों से ये हड़तालें और तालाबन्दी हो रही हैं उसके पहले जो वाजिब उनकी मांग है उसे मान लिया जाय जिसे आप मानते हैं कि माना जाना चाहिए और जो हड़ताल के बाद आप मानते हैं और करोड़ों रुपये की क्षति होने के बाद मानते हैं? क्या वह पहले नहीं किया जा सकता?

क्या सरकार हड़ताल तथा तालाबन्दी से पहले वाजिब मांगों को मान कर उस विशेष प्रतिष्ठान को घाटे के बचा सकती है या नहीं? पर इसके लिए भी सहृदयता चाहिए और मजदूरों की समस्या के प्रति सहानुभूति। बदकिस्मती से सरकार के पास वह भी नहीं है।

देहाती असंगठित खेतिहर मजदूरों की हालत और भी दयनीय है। भूखे भारत को खिलाने वाला धरती का लाल आज भूखा है। सुबह से शाम तक पसीना बहाने के बावजूद भी वह खुद का भी पेट नहीं भर पाता, भूखे परिवार को तो खिलाने का प्रश्न ही नहीं है।

सप्ताह और महीनों भूखे रहने वाले मजदूर के पेट की ज्वाला में सारा देश स्वाहा होने वाला है। चार महीने काम करने के बाद आठ महीने काम नहीं मिलने पर उनकी मुश्किलें और भी जटिल हो जाती हैं। सरकार कहने के लिए तो कागज पर बहुत से काम चलाती है लेकिन हकीकत यह है कि जहां से हम आते हैं वहां गांवों में यदि आप देखें तो बास्तव में 8 महीने उनको कोई काम नहीं मिलता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह कोई ऐसी योजना बना सकती है या नहीं जिसमें, जब मजदूरों के पास कोई काम न हो तब उस समय उनको काम दिया जा सके? इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

यद्यपि सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए बहुत से नियम-कानून बनाए हैं जैसे—वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तथा लेबर कोर्टस् की स्थापना, मिनिमम वेजेज ऐक्ट, एम्प्लाइज प्राविडेंट फंड ऐक्ट, एबालिशन आफ बाण्डेड लेबर ऐक्ट—परन्तु क्या ये सारे ऐक्ट्स जमीन पर उतर पा रहे हैं? आपने वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की व्यवस्था की लेकिन क्या वास्तव में यह हो पाता है?

कतई नहीं। यदि यह हो गया होता तो यह समस्या ही सामने नहीं आती। आपने इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ऐंड लेबर कोर्टस की स्थापना की लेकिन आप देखेंगे कि आज भी हजारों केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसी तरह से आपने मिनिमम वेजेज ऐक्ट बनाया लेकिन क्या वह गांवों के मजदूरों पर लागू हो पाता है? आज भी उन्हें जो कम से कम मजदूरी मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है।

इसी तरह से जहां तक एम्पलाईज प्राविडेंट फंड की बात है, आज भी बहुत से ऐसे प्रतिष्ठानों को जिनको इसके अन्तर्गत लाया जाना चाहिए, खास कारणों से इसके अन्तर्गत नहीं लाया जाता है। मैं सरकार से इस तरफ भी ध्यान देने के लिए आग्रह करूंगा।

जहां तक बेरोजगारी की समस्या का सम्बन्ध है, मंत्री जी के मुताबिक ही आज देश में दो करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिनको कि रोजगार की जरूरत है। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए जगह जगह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के दफ्तर खुले हुए हैं लेकिन वहां पर भी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है—इसकी जानकारी भी सरकार को होनी चाहिए। अगर कहीं से एम्प्लायमेंट की नोटिस आती है तो वहां नाम भिजवाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है तभी नाम भेजा जाता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस ओर भी ध्यान दे।

शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज ऐंड अदर बैकवर्ड क्लासेज में जो लोग आते हैं उनको कहने के लिए तो सांविधानिक संरक्षण प्राप्त है लेकिन हकीकत यह है कि यह कह दिया जाता है कि उनका स्टैण्डर्ड उतना नहीं है। आखिर इसके लिए कौन जवाबदेह है? सदियों से जो लोग पिछड़े रहे हैं उनको आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं कहता हूं इसके लिए सरकार जवाबदेह है। उनको अपटु दि मार्क लाने के लिए अगर विशेष प्रशिक्षण देने की जरूरत हो या कोई अन्य सुविधा देने की बात हो, जैसे भी हो, सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि संविधान के अन्तर्गत जो प्रावधान किया गया है उसकी पूर्ति उनके लिए की जाए। पता नहीं क्यों सरकार उनके द्वारा गठित आयोग और कमेटियों की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं करना चाहती है, जिससे मजदूरों में कुछ शान्ति पैदा हो। उदाहरणस्वरूप मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं। भूतलिंगम कमेटी की रिपोर्ट और रथ कमेटी की रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया। यदि इन समस्याओं का आप समाधान करना चाहते हैं, मजदूरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इन समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए वरना मजदूर मजबूर होकर उठ खड़ा होगा, तो शायद वह सरकार व मुल्क दोनों के लिए ही एक समस्या पैदा कर सकता है। आज सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, वह है नेशनल लेबर तथा वेज पालिसी की जिसके कार्यान्वियन के बाद शायद औद्योगिक शान्ति पैदा हो जाए, जो कि समय का तकाजा है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी और कुछ कारगर कदम उठायेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री हरीकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, आदरणीय श्री नारायण दत्त तिवारी जैसे एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति के श्रम मंत्री होने के बावजूद भी उन्हीं के प्रदेश में श्रमिकों का भयंकर शोषण हो रहा है और उनको यातनायें दी जा रही हैं—यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है।

मान्यवर, अभी मैं गाजियाबाद से चला आ रहा हूं। वहां से डेढ़ बजे गया था और वहां पर मजदूरों की समस्याओं का अध्ययन करके आ रहा हूं, इसलिए मैं चाहता था कि

[श्री हरिकेश बहादुर]

तुरन्त उसके बारे में कुछ बताऊं। मजदूरों के ऊपर वहां बहुत अत्याचार हो रहा है। कल एक संसद सदस्य जिनको पीटा गया था, उनके बारे में यहां सारी चर्चा हुई है, मैं वहां पर थोड़ी जानकारी करने के लिए गया था। मैंने वहां की पुलिस चौकी को देखा और वहां के पुलिस अफसरों से पूछा—तो उन्होंने बताया कि वहां पर जो आठ-नौ कुर्सियां पड़ी हुई थीं, वे सब कम्यूनिस्ट पार्टी के लेबर दफ्तर की कुर्सियां थीं; जिसको वे लोग उठा लाए थे। उनके दफ्तर को तोड़ा है और उनके सामान को लूटा गया। वे कुर्सियां पुलिस के दफ्तर में रखी हुई हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं और उन लोगों ने मजदूरों के ऊपर अत्याचार किया है, गोलियां चलाई हैं, जबकि किसी भी उत्तेजना का कोई कारण नहीं था, फिर भी उत्तेजनात्मक कार्यवाही पुलिस की तरफ से की गई है। लोगों ने शिकायत की है एक पुलिस अधिकारी श्री दिनेश पांडे के बारे में, कि वह सबसे ज्यादा लोगों को टेरराइज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से कह कर के इसको देखे, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिएं।

मान्यवर, बंगलौर में जिस तरीके से स्ट्राइक चली वह सरकार की मौजूदा इस नीति का परिणाम है। अभी हम कटिहार गए हुए थे वहां जूट मिल के वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था, उनके ऊपर भी दमनचक्र चलाया गया, वहां के शासक दल के लोग, पुलिस के अफसर, प्रशासन के अफसर और सभी मिल-मालिक से मिले हुए थे। नतीजा यह हुआ कि मजदूरों की बुरी तरह से पिटाई हुई। श्रीमती राम दुलारी सिन्हा वहीं से आती हैं, उनको तो इस संबंध में पूरी जानकारी होगी कि कटिहार जूट मिल की क्या समस्यायें थी। इसके साथ हमारे एक भूतपूर्व संसद सदस्य वहां पर अनशन कर रहे थे, वे 35 दिन अनशन करते रहे और कांग्रेस के लोग कहते थे कि इसको मर जाने दो और समस्याओं का समाधान करने की कोई जरूरत नहीं है। जनता पार्टी के एक भूतपूर्व संसद सदस्य थे। मान्यवर, इस तरह की ये सारी चीजें हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी फैली हुई है। वहां से लोग दूसरे प्रदेशों में—महाराष्ट्र, पंजाब और कलकत्ता आदि सभी जगहों पर जाते हैं और वहां जाकर रोजगार कमाते हैं। ट्रेनों की छतों पर बैठकर यात्रा करते हैं और वहां पर जाते हैं। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास की तरफ भी देखना चाहिए, नहीं तो बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाली है। इस देश में बेरोजगारी की भीषण समस्या है।

मान्यवर, दिसम्बर, 1979 में जैसी कि लेबर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एक करोड़ 43 लाख लोग 1979, दिसम्बर तक बेरोजगार थे, जबकि दिसम्बर, 1980 तक यह संख्या बढ़कर एक करोड़ 62 लाख हो गई है। इस प्रकार से लगभग 13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। चार लाख 66 हजार लोगों को केवल नौकरी मिल पाई। मान्यवर, इस समय जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जून, 1980 में इनकी संख्या 76.62 लाख थी जबकि 1979 में, एक साल पहले जब जनता पार्टी और लोकदल की सरकारें थीं, यह संख्या केवल 69.37 लाख थी। दस फीसदी की वृद्धि केवल इनके एक साल के शासन में हुई है।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 76.62 लाख लोगों में से 14.58 लाख ऐसे लोग हैं जोकि ग्रेजुएट हैं या पोस्ट-ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं या स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल कर चुके हैं। अनुसूचित जातियों

के लोगों को भी बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

जहां तक महिलाओं का सवाल है, गत वर्ष तक 65831 महिलाएं बेरोजगार थीं और केवल 14 फ़ीसदी को ही इन में से नौकरी मिली है । यह सब सरकारी गाथा है, जो मैं बताता रहा हूं । इस तरह से आप देखें कि देश के सामने एक भयंकर बेरोजगारी की समस्या है और इस को दूर करने के लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने चाहिए, नहीं तो यह सरकार पूरी तरह से असफल रहेगी । हमारा केवल आलोचना करने से ही काम नहीं चलता, हम चाहते हैं कि सरकार ठोस काम करे जिस से यह समस्या दूर हो ।

एक बात मैं बॉंडेड लेबर के बारे में कहना चाहता हूं । आज भी देश में विभिन्न भागों में बहुत बड़ी संख्या में बॉंडेड मजदूर हैं । मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता कि बॉंडेड मजदूर और भी हैं लेकिन सरकार की जानकारी में यह है कि बॉंडेड लेबर अभी भी हैं और हरियाणा के अन्दर इन्डियन एक्सप्रेस में कुछ घटनाएं निकली हैं और पुलिस भी उन को छुड़ा नहीं सकी है । वहां पर कुछ कॉन्ट्रेक्टर्स घूम रहे हैं, जो उन लोगों को भगा ले गये हैं । इस तरह की सारी बातें निकली हुई हैं ।

कृषि मजदूरों के बारे में अभी श्री आर० पी० यादव ने बताया है कि वे किस प्रकार से रह रहे हैं । सरकार ने जो उन के लिए मजदूरी निर्धारित की है, वह भी वे नहीं ले पाते हैं । उन की बहुत दुर्दशा है और उन की समस्याओं के समाधान की तरफ़ सरकार को तुरन्त विशेष ध्यान देना चाहिए ।

एक विशेष समस्या की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से सम्बन्धित है । हमारे पोस्ट आफिसेज में जो काम करने वाले हैं, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जो आकस्मिक मजदूर हैं, ये पिछले 6-7 वर्ष से काम करते चले आ रहे हैं लेकिन इन को सर्विसेज को नियमित नहीं किया जाता है । उसी प्रकार से रेलवे के मजदूरों की बात है । मैं खास तौर से पोस्ट आफीसेज के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर 240 दिन इन का काम हो जाए, तो उन को जरूर स्थायी कर देना चाहिए लेकिन उन को स्थायी नहीं किया जाता है । वहां पर घूसखोरी चलती है । जिससे पैसा लिया जाता है, उस को रख लिया जाता है यहां तक कि लोकल एम्पलायमेंट एक्सचेन्जेज से भी लोग नहीं लिये जाते ।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि टाइम्स आफ़ इन्डिया के एम्पलाइज ने और नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के एम्पलाइज ने अपनी समस्याओं के बारे में सरकार के सामने कुछ आवेदन दिये हैं, कुछ पत्रक दिये हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि उन पर तुरन्त ध्यान दिया जाए और उन की समस्याओं का समाधान किया जाए ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि पालेकर ट्रिब्यूनल का जो एवार्ड है, उस के बारे में सरकार क्यों उदासीन है । जो बड़े बड़े अख़बार चलाते हैं, वे जिले के स्तर पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं उन की सेवाएं समाप्त कर रहे हैं । जो सुविधाएं उन को देनी चाहिएं वे उन को नहीं दी जा रही हैं और उन की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं । इस का नतीजा यह हो रहा है कि बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ाने में ये सहायक हो रहे हैं । इस को रोकने के लिए सरकार को कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इन से जो समस्याएं हैं, उन का कोई समाधान होने वाला है।

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): Mr. Chairman, I come from industrial belt of Bihar—Dhanbad. My constituency has one lakh steel workers, more than two lakhs coalmine workers, some 20,000 fertiliser workers and one lakh more workers working in other industries. I am observing the activities of the Labour Department for the last 15 years. What has struck me is the gradual erosion and devaluation of the prestige of both the labour and also the Labour Ministry in the country. This is the Ministry which is the most idle doing little labour. This is the Ministry which can only bark, but has no biting teeth. I am giving an example. In Dhanbad previously there used to be Coalmines Welfare Organisation running different welfare activities for the coal-miners run by the Labour Ministry. This has now been snatched away from the Labour Ministry, and is going to the Energy Ministry. The Central Hospital that used to be run by the Labour Department, has gone to the Energy Ministry. The Coal Mines Provident Fund, that used to be run by the Labour Department, has also been taken away now. The Safety Organization was somewhere in between. It did not have sufficient number of officers to look after the safety of the workers. In the office of the Labour Commissioner there is so much of work. Until recently, there was no Regional Labour Commissioner separately for Dhanbad and Asansol. One RLC used to look after both the places. This is the respect and importance shown to the labour department in the industrial belt.

17 hrs.

I will give you examples. There are three man of workers here—permanent workers of the organized industry, casual workers and contract workers. Most of the poor people, viz. *dalit* people, Harijans and Adivasis come under contract workers. There are 6 million workers in the organized sector as permanent workers, and there are 20 million under contract labour. They brought out a Bill for the welfare of contract workers. It was called the Contract Labour (Abolition and Regulation) Bill, 1970. In this Act, they have defined the job of a perennial nature. The definition says that if a job had been performed for more than 120 days during the preceding 12 months, it would be deemed to be a job of perennial nature.

Section 10(2) of this Act prohibits contract system. It does not say what will happen to the contract workers. I would like that the Minister, while replying, must specify what the aims and objects of this Act are—are they to benefit the contract workers, or to punish them?

In the name of abolishing the contract system, even the public sector enterprises are retrenching the entire contract labour, while the spirit of this Act should have been to departmentalize contract workers. And the Labour Department is looking at this helplessly.

It is said that TISCO has thrown out 10,000 contract workers. What happened to Dalli Rajhara iron ore mines, and the Madhya Pradesh iron mines? Their leader Mr. Shankar Guha Niyogi was arrested under the National Security Act, and the advisory board of the State Government declared it illegal. There is terrorization by police there. There were 8,500 people working in the Dalli Rajhara iron ore mine, as contract workers under the Labour cooperatives. They were not allowed to resume duty. They are still without work. These iron ore mines come under the Bhilai Steel Plant which is under the Ministry of Steel at the Centre; and the miners are governed by the Labour Department at the Centre. The Central Government cannot take refuge under the plea that these workers come under the State's Labour Department, as it is doing in the case of TISCO.

On 16-5-1980, an agreement was reached in the Shram Shakti Bhavan.

MR. CHAIRMAN: After reference to this agreement, please conclude.

SHRI A. K. ROY: If the agreement is implemented, I will conclude.

In this agreement, the signatories are no less than the Chief Labour Commissioner (Central), the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) and R.L.C. (Central); and on behalf of the workmen, the Chhatisgarh Shramik Sangh's leader Mr. Shanker Guha Niyogi. And this agreement assures that the workmen will be departmentalized by 15-9-1981 and that the departmentalization process will be completed by 15-11-1980. And it assures in Section 10 that the management reiterates their earlier assurance that there shall be no retrenchment. This was written; and after that, now 8500 workers are on the streets. You will be surprised to know that the Labour Department is writing to the Steel Ministry telling them—all their officers are convinced—that horrible things are being done—Nowhere in India 8500 workers are thrown out of employment—and the Steel Ministry is not replying to that. With all these things, I say that either you govern or quit. There is no use of having a Labour Ministry whose letters are not being replied to even by the sister Ministry. I want to know what steps you are taking to make your Department, your Ministry effective, assertive and having a full authority over the other Ministries?

SHRI CHITTA BASU (Barasat): At the outset, I would like to draw the attention of the hon. Minister incharge of the Labour Ministry to the Report which he has presented before the House. It is not only unsatisfactory but piecing together of certain performances by different sections of the Labour Ministry. I am also shocked to know that piecing together does not also betray the same skill of tailoring. It is not properly tailored. The major defect of this Report is that it does not project any labour policy at all.

Does the Government possess a labour policy concerning the industrial relations, concerning the wage, concerning the bonus and concerning all aspects of the labour? If you go through this Report you will find that there is no coherent, cohesive, well-marked and well-defined labour policy. Am I to conclude that the Government has no labour policy? No. I cannot conclude that the Government has got no labour policy. As a matter of fact, the labour policy is to assault the working class of our country, to suppress the democratic and legitimate trade union rights of the entire working class.

Generally, an idea is being created in this country that the working class is being pampered and their earning is going higher and higher and, therefore, there should be a policy of wage freeze.

SHRI ANANDA GOPAL MUKHOPADHYAY (Asansol): I remember that you had uttered the same words in the earlier budget also. *(Interruptions*

SHRI CHITTA BASU: So long as you are there, the same words will be repeated. You pursue the same policy and therefore, you should be always at the receiving end.

PROF. MADHU DANDAVATE: That shows the earlier budget was as bad as.....

17.08 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

SHRI CHITTA BASU: I am happy that you are there because you are also a trade unionist. A mistaken idea has been created in our country that the organised working class of our country is getting a higher wage. This idea is a myth and has to be exploded. I quote from some sources. It says as follows:

> "The wage bill as per centage of the gross output declined from 11.2 per cent to 10.2 per cent during 1975-76, 1976-77."

[Shri Chitta Basu]

Of course, it happened during the emergency. Do not become angry. I know even during the Janata Government this decline was there, that is, the wage bill as percentage of the gross output has been on a decline, and it is continuing to decline. If you take another instance you will find Mr. Ananda Gopal Mukhopadhyay should bear it in mind—that in the public sector the decline is more. It has dropped from 17.7 per cent to 14.7 per cent. There has been a gradual decline of wage.

Therefore, there has been a great deal of decline of wages. The wage bill, as percentage of value added, declined from 51 per cent to 49 per cent in the private sector and from 63 per cent to 49.3 per cent in the public sector. My point is that the wages are being eroded. There has been an erosion in the real income. Of course, they say that the country is passing through a period of inflation. I want to make it clear. Inflation is there. But this inflation is not due to wage increase. It is not the wage increase which has created inflation. It is the cost push which creates inflation. The Labour Ministry has to understand the implications of the economy of our country. On the other hand, on the pre-text that there has been an increase in the wages, as there is inflation, they want that there should be a freeze of wages. That is what is called the wage freeze policy. I would not have objected to this policy of freeze. As a trade unionist you should understand that there is no freeze on the prices, there is no freeze on the profits, there is no freeze on the expenditure, and there is a freeze in the wages! The freeze is not there on income. The freeze is there on the wages. It is not there on the prices. If you allow me I can show you that private sector industries are making enormous profits. I would like to say, that the top 101 Indian industrial giants in the private sector ranked high in terms of assets and the year 1978-79 was an excellent year. The profits were absolutely sensational. The gross profits rose by 15.3 per cent — a five-fold increase over the previous years' rise. I do not want to quote more. This proves that there has been a fabulous increase of profit. There has been conering of profits by taking advantage of inflation. But, on the other hand, it is the workers who are at the receiving end. It is the organised working classes who are at the receiving end. Therefore, the Labour Ministry does not project any policy in the matter of wages, how this wage erosion can be arrested.

I pass on to another point. Another point is, that the Labour Minister is determined to see that the industrial relations edifice which has been built up during these years of working classes is destroyed. This edifice has to be retained. But what I find is this entire industrial relations edifice is being broken, it is being destroyed, destroyed in the sense that collective bargaining which is the derivative right of the Fundamental Right of the Constitution is denied. The Labour Ministry should understand that our Constitution provides the Fundamental Right of organisation. Out of that Fundamental Right to organise flows the principle of collective bargaining. This principle of collective bargaining is the hub of the industrial relations. The right to collective bargaining is the fundamental right and fundamental weapon for the working classes. It is the Labour Ministry which is trying to deny that Fundamental Right. As, for example, take the case of the L.I.C. You know it well. The basic right of collective bargaining has been negated, the Supreme Court judgment has been negated, and the entire working class is relying only on their unity, strength, their solidarity and militance. This leads to loss of production. This leads to industrial disharmony. While the Labour Ministry is the instrument to maintain industrial harmony, the policy they are pursuing is bringing about industrial disharmony. In this connection, I want to mention the existence of BPE—Bureau of Public Enterprises. BPE is functioning over the head of the Labour Ministry. It is functioning at cross purpose with collective

bargaining. No direct dialogue, no negotiation, can be done and no settlement can be arrived at in public sector industries unless the BPE clears it. What is the good of having conciliation machinery? What is the good of having the Industrial Disputes Act, if only on the basis of the conditions laid down by the BPE the industrial negotiations are to be conducted? Therefore, the fundamental right to collective bargaining is being assaulted and destroyed. This is the labour policy of the Government today. Therefore, if they are interested in maintaining the industrial harmony, this policy has to be revised. In order to revise this policy, a new set of principles are to be evolved by mutual consent, by discussion, by dialogue, between the leaders of the organised working class and the Government.

Many members have referred to the Contract Labour (Abolition and Regulation) Act. He has been Minister in charge of Planning and I would like to quote what he has commented as Planning Minister. In the Sixth Plan document which he produced it is said:

> "The working of the Act over the years has indicated a somewhat slow rate of progress in abolishing contract labour."

MR. DEPUTY-SPEAKER: He himself accepts it!

SHRI CHITTA BASU: It is he who has produced it. Would he kindly see that this Act is properly implemented?

Regarding inter-State migrant labour, here also the Sixth Plan document makes this observation:

> "Effective steps would be taken during the Sixth Plan to ensure the implementation of this Act— Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979—by a suitable machinery at the Central and State level."

Would he kindly assure the House that that kind of implementing machinery will be set up, so that the object of this Act can be given effect to?

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सोशलिस्ट पार्टी को जो आपने समय दिया है और विशेष रूप से मुझे, उस के लिये मैं आभारी हूं । मुझे यह कहना है कि श्रम नीति से जो उम्मीद की गई थी और देश के लोगों को उम्मीद थी कि कोई बुनियादी परिवर्तन उसमें किया जायगा क्योंकि हमारे पुराने साथी और आज के मौजूदा श्रम मंत्री जी हमारे समाजवादी साथियों में से हैं जिन्होंने श्रमिकों के लिये पहले बहुत बड़ा संघर्ष किया था । लेकिन जो नीतियां देखी हैं वही जर्जर नीतियां हैं जो घिसी-पिटी हैं जिन्होंने हमेशा पूंजीपतियों का साथ दिया है । सारे विवरण को देखने के बाद मालूम होता है कि यह तो पूंजीपतियों के सहयोग का मंत्रालय बन गया है । वह सरमायादारों और उद्योगपतियों को सहयोग देने वाला मंत्रालय बन गया है । इस सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लिए गए निर्णयों को भी लागू नहीं किया है। उसने बहुत से श्रमिकों को छोड़ दिया है, उनकी उपेक्षा की है, उसने क्या सोचा है छोटे छोटे होटलों में काम करने वाले मासूम बच्चों के बारे में, जिनका भयंकर शोषण होता है ? जो लोग दिल्ली की सड़कों पर ठेला खींचते हैं, उसने उनके बारे में नहीं सोचा है । जो नदी और पानी में काम करते हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, इस सरकार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । उसने केवल संगठित मजदूरों के बारे में इतना ही सोचा है कि किस प्रकार पूंजीपति उनका शोषण कर सकते हैं । इस सरकार ने श्रमिकों के लिए कोई उपयोगी काम नहीं किया है, इस लिए मैं इस मंत्रालय की डिमांड्स का विरोध करता हूं ।

आज मजदूर कीड़े-मकोड़े की जिन्दगी जी रहे हैं । उनकी कालोनी में जा कर देखिए : भिनभिनाते मच्छर और गन्दगी । उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है । उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं किया गया है । उनके बच्चों के पढ़ने-लिखने की कोई

[श्री जगपाल सिंह कश्यप]

व्यवस्था नहीं है। वे लोग करते रहे मेहनत और सारा मुनाफ़ा उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को मिले, सरकार ने उनके शोषण का यह तरीका बना लिया है।

आज भी ठेकेदारी प्रथा इस देश में चल रही है, लेकिन सरकार ने उसको समाप्त नहीं किया है। एक बड़ा मज़ाक आज भी देश में चल रहा है। जो एम्पलाईज़ दसियों सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें आज तक मुस्तकिल नहीं किया गया है। भूतलिंगम कमेटी की रिपोर्ट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पी एंड टी में कई लाख कर्मचारी हैं, जिन्हें कनफ़र्म नहीं किया गया है, वे आज तक एड हाक और टेम्पोरेरी बेसिस पर काम कर रहे हैं। सरकार क्यों नहीं यह व्यवस्था करती कि लोग कनफ़र्म किये जायें और उन्हें पर्मानेंट जाब मिले ? इस मंत्रालय को पूंजीपतियों और बड़े-बड़े लोगों के हाथ में खिलौना बना दिया गया है।

रोज़गार दफ्तरों का तो कुछ कहना ही नहीं है। वे भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। अगर नोट खिसकाइये, तो चिट्ठी खिसकेगी। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि लोगों के नाम पांच-पांच साल से दर्ज हैं, लेकिन उन्हें आज तक चिट्ठी नहीं मिली है। अगर उन्हें चिट्ठी भेजी भी जाती है, तो वह उस समय मिलती है, जबकि डेट एक्सपायर हो जाती है, इन्टरव्यू हो चुकता है। कम से कम एक महीने का नोटिस देना चाहिए। ताकि लोग इन्टरव्यू या कम्पीटीशन में जा सकें। मंत्री महोदय को बड़ी गम्भीरता के साथ इस पर विचार करना चाहिए।

जैसा कि श्री डागा ने कहा है, अगर सरकार बेरोज़गार भत्ता नहीं देती, तो देश के लोग किस तरफ़ बढ़ेंगे, इस देश के संविधान और प्रजातंत्र का क्या होगा, यह सोचा भी नहीं जा सकता है। अगर सरकार बेरोज़गारी का भत्ता न दे सके, श्रमिकों को प्रबन्ध और मुनाफ़े में हिस्सा न दे सके, तो देश में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ? आज वे लोग महंगाई से परेशान हैं। उन्हें जितना वेतन मिलना चाहिए, आज उससे कम वेतन उन्हें मिलते है।

आज श्रमिकों और श्रमिक नेताओं को कोई सुरक्षा नहीं है। पता नहीं, पुलिस कब किसी का हाथ तोड़ देगी। आज इस सदन के माननीय सदस्यों के भी हाथ तोड़े जाते हैं। मज़दूर नेताओं को पीटा जाता है। पिछले साल कितने श्रमिक नेताओं की हत्यायें हुई हैं ? उनके बच्चों और स्त्रियों तक को मारा गया है। यह सरकार और यह मंत्रालय उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। प्राविडेंट फंड में घोटाले का प्रश्न तो सरकारी बैंकों से ही उठाया गया है।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन लोगों को रोज़गार की गारंटी और पर्मानेंट एम्पलायमेंट मिलनी चाहिए। आज सरकार द्वारा जो मशीनीकरण, अभिनवीकरण या रेशनलाइज़ेशन हो रहा है, उससे मज़दूर बेरोज़गार हो रहे हैं और पूंजीपतियों का मुनाफ़ा बढ़ रहा है। मैंने गोआ और बहुत सी दूसरी जगह देखा कि जहां मज़दूर काम कर सकता है, वहां मशीन से काम लिया जा रहा है। आयरन ओर को लादने, तोलने और धोने का काम मशीनें कर रही हैं। इस तरह से यह सरकार इस देश के करोड़ों मज़दूरों को बेरोज़गार कर रही है। अगर ऐसा ही होता रहा, तो देश एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा, जबकि यह सरकार श्रमिकों को पेट की आग को बंदूकों की गोलियों से ठंडा नहीं कर पाएगी, पुलिस के डंडे से उनकी जुबान को बन्द नहीं कर सकेगी। आज देश का मज़दूर और किसान जग चुका है। जितना ही यह सरकार बन्दूक, लाठी और डंडे से उन्हें दबाने का प्रयास करेगी, देश में उतनी ही ज्वाला भड़केगी। हमारे श्रम मंत्री जो जो हमारे पुराने साथी हैं, उन को आज मैं याद दिलाना चाहता हूं डा० लोहिया की, याद दिलाना चाहता हूं जयप्रकाश

नारायण की, याद दिलाता हूं उस समाजवाद की जिस के लिए उन्होंने एक बार संकल्प लिया था, आज उसी को ध्यान में रख कर देश के श्रमिकों को ऐसा कुछ दीजिए जिससे देश का श्रमिक आप को याद कर सके। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : श्रीमन्, मैं किन शब्दों में उन सभी माननीय विद्वान सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करूं जिन्होंने श्रम मंत्रालय के अनुदान के सन्दर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं और अपने सुझावों से हम को गौरवान्वित किया है। मैं नत मस्तक हूं श्रीमन्, आप के सम्मुख कि इस सदन के विनम्र सेवक होने के नाते मुझे प्रथम बार यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं श्रम विभाग जैसे महत्व के विभाग के अनुदानों के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उन के संदर्भ में कुछ निवेदन करने की विनम्र चेष्टा करूं।

यह हमारा सौभाग्य है कि इस सदन में ऐसे विद्वान सदस्य विराजमान हैं जिनका जीवन श्रमिक आन्दोलन के प्रति समर्पित रहा है। चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के, उभय पक्ष के बोलने वाले विद्वान सदस्य जो श्रमिक आन्दोलन के प्रति समर्पित हों यदि वह अपना सुझाव देते हैं तो भले ही उस में आलोचनात्मक पुट हो, भले ही उस में विरोधाभास हो, भले ही उस में विरोधात्मक भावनाओं का समन्वय हो, फिर भी शासन पक्ष को समादर के साथ उन सुझावों को सुनना पड़ता हैं।

यह कहा गया कि आज श्रम सम्बन्धी कोई नीति नहीं है। यह भी कहा गया बलपूर्वक शब्दों में, परिमार्जित, परिष्कृत, संसदीय भाषा में कहा गया कि हमारी नीति श्रम विरोधी, ऐंटी लेबर नीति है। मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करूं कि जो आज श्रम नीति चल रही है क्या वह चन्द महीनों की नीति है? नहीं, हमारी श्रम नीति को हमारे संविधान ने शक्ति प्रदान की। हमारी श्रम नीति को जब से यह संसद स्थापित हुआ है तब से उस समय के विद्वान सदस्यों ने समय समय पर जो वहां विचार व्यक्त किए हैं, जो कानून अधिनियमित किए हैं, जो विधि विधान बनाए हैं उन सबने परिमार्जित, परिष्कृत और संपुष्ट किया है। हमारी श्रम नीति, देश की चलती आ रही लेबर पालिसी का इतिहास है। इस के इतिहास निर्माता हैं वी वी गिरि, एन एन जोशी, खासखदा, गुलजारी लाल नंदा, एच ए डांगे ऐसे लोग व विभिन्न संसदीय समितियां जो समय समय पर गठित होती रहीं। यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं रहा। हम ने जो श्रम कानून बनाए हैं, मैं विनम्रतापूर्वक लेकिन गर्व के साथ कह सकता हूं, अपने लिए नहीं, मैं व्यक्ति के रूप में कुछ नहीं हूं लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस संसद ने जो श्रम सम्बन्धी कानून पारित किए हैं पिछले तीस वर्षों में, संसार में इस की मान्यता है कि ऐसे कम कानून बने हैं अन्य देशों में। संसार के दूसरे देशों की तुलना में आज हमारे भारत की जो श्रम-संहिता है श्रम कानून की उसका एक आदर है, एक स्थान है और यह कहा जाता है अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटर-नेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन में कि भारत ने जो कानून श्रमिक के लिए बनाए हैं वे संसार के अनेक देशों की तुलना में प्रगतिशील हैं, अधिक साध्य हैं और श्रमिकों के हितों का संवर्द्धन करने वाले हैं। यह मान्यता आज अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संसार के दूसरे देशों में है। हमारे श्रम कानूनों की एक और विशेषता यह है कि कोई एक दल नहीं, पहले से ही यह त्रिदलीय रूप से अभिभूत होते रहे है। इनका विकास होता रहा है त्रिदलीय सम्मेलनों में। मेरे एक दो मित्र, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं, उनको यह लगा कि क्यों इतनी कमेटीज बैठती है, क्यों इतना विचार-विमर्श होता है, क्यों लंबा विचार विमर्श होता है लेकिन यह विभाग ही ऐसा है. श्रम कानूनों का मतलब ही यह है इसमें त्रिदलीय सम्मेलनों के माध्यम से संविधान की कानकरेन्ट लिस्ट में जो लिखा हुआ है प्रदेश सरकारों से भी और प्रदेश स्तर

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

के मजदूर संगठनों से भी इस सम्बन्ध में परामर्श करके पग-पग आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा कानून एकदम बनायें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस समय जो हम श्रमिकों को साझेदारी का कानून बनाना चाहते हैं जो विधेयक हम प्रस्तावित कर रहे हैं इससे संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सम्मानित भूतपूर्व श्रम मंत्री रवीन्द्र वर्मा जी। इसके सदस्य कौन थे? सदस्य थे :

श्री कुर्ने, सी पी एम (सीटू) के,
श्री के पी तिवाठो, इन्टक के,
श्री भाई जो शर्मा, ए आई टी यू सी के,
श्रीयुत श्रीकांठन नायर, यू०टी०यू०सी के,
श्री एन सी गांगुली, भारतीय मजदूर संघ के,
श्री आर एन शुक्ल, नेशनल लेबर
आर्गेनाईजेशन के और
श्री राम देसाई, हिन्द मजदूर सभा के।

इस कमेटी ने साझेदारी के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी उसी के आधार पर हम विधेयक प्रस्तावित करने जा रहे हैं। अब इसमें अवश्य समय लगता है। हम मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि समय लगता है लेकिन क्या यह उचित नहीं है कि हम श्रम विभाग के सम्बन्ध में जो भी कानून बनावें उसमें इस बात का प्रयास करें कि जो अखिल भारतीय श्रम संगठन है या अन्य संबंधित मजदूर व उद्योग कर्त्ताओं के सुझाव है उनके विचारों को यथासंभव समन्वित कर सकें? अपने विधान और कानूनों को बनाते समय सदैव हमारी यही चेष्टा रहती है।

यह कहा जाता है और आज भी कहा गया है जिसमें कुछ तथ्य भी है कि हमारी राष्ट्रीय वेतन नीति, नेशनल वेज पालिसी अभी तक नहीं बन पाई है। इस सम्बन्ध में हमारा प्रयास रहा है, पिछले शासन के दो वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हैं, पिछले शासन का भी यह प्रयास रहा है कि राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन बुलाया जाए, नेशनल लेबर कांफ्रेंस बुलाई जाए और उसमें राष्ट्रीय वेतन नीति के बिन्दु बिन्दु पर विचार किया जाए। वह सम्मेलन बुलाया नहीं जा सका। कारण यह रहा कि कौन प्रतिनिधित्व करे—यह प्रश्न उठ गया। कल हमारे विद्वान सदस्य आनन्द भाई ने एक सारगर्भित भाषण दिया और यह उल्लेख किया कि एक सी०टी० यू० सी० (लेनिन सारणी) नामक संगठन है जिसकी सदस्य संख्या 10 लाख हो गई हैं जो सीटू की संख्या से ज्यादा है। अब हमारे सामने कठिनाई यह है कि हम क्या करें? मैंने चाहा कि पता लगे कि आखिर लैनिन सारणी की इतनी दस लाख सदस्य संख्या कैसे हो गई। मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल सूचना के लिए कह रहा हूं—पश्चिम बंगाल से आने वाले सदस्य इसको दूसरे मायनों में न लें—मैंने जब सूचना मांगी तो देखा कि इसकी मेम्बरशिप की जो सूचना आई है उसमें 9 लाख और कुछ हजार सदस्य संख्या पश्चिम बंगाल सरकार ने ही भेजी है लेनिन सारणी की। अब हम क्या करें? जब एक प्रदेश सरकार के रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियन्स हमारे पास कोई सूचना भेजते हैं तो उसको स्वीकार करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है। लेकिन चूंकि कल माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया इसलिए मैं दोबारा जांच करूंगा कि क्या कारण है कि लेनिन सारणी की सदस्य संख्या इतनी बढ़ गई। पग पग पर कठिनाइयां हैं कि कैसे श्रमिक संगठनों को मान्यता दी जाए। थोड़ी देर के लिए हम स्वीकार कर लें कि गुप्त रूप से मतदान प्रणाली के द्वारा हम चुनाव कराते हैं। लेकिन जहां पर ग्यारह मुख्य केन्द्र संगठन हों, जहां पर देश की हजारों यूनिटों में, हजारों कारखानों में, सैंकड़ों प्रतिष्ठानों में एक-एक नहीं 12–12 और 14–14 यूनियनें हैं। श्रीमन्, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ देश के वरिष्ठ श्रमिक नेता हैं, उनसे परामर्श करने का, सबसे बड़ा प्रश्न उनके सामने क्या था? प्रश्न यह था कि क्या मान्यता प्राप्त यूनियन की मान्यता आज उतनी रह गई है जितनी

कि पहले थी। क्यों कि मान्यता प्राप्त यूनियन एक है, जो सिक्रेट बैलेट के आधार पर चुनी गई है, लेकिन आज दूसरी जो आठ-नौ यूनियनें हैं, उनके कुल मिला कर सदस्य ज्यादा हैं। इस संबंध में उनसे अमान्यता प्राप्त यूनियनों में किस प्रकार बातचीत की जाए, आज सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ गया है। आज वे मजदूर यूनियनें, जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, लेकिन कुछ केन्द्रीय मजदूर संगठनों से उनका सम्बन्ध है, वे फिर शिकायत करती हैं कि मान्यता प्राप्त यूनियन से ही क्यों बातचीत हो रही है—यह मिलीभगत है और फिर वे आंदोलन करते हैं, इस वजह से भी आज औद्योगिक अशांति है। कई स्थानों में वह एक पराकाष्टा में पहुंच गई है। उसमें केवल एक मान्यता प्राप्त यूनियन से ही या इस तरह बैलट से ही काम चलने वाला नहीं है। हम अपनी सूचना बताती है कि टिस्को में भी यही हुआ। जिस टिस्को ने कान्ट्रैक्ट लेबर की बात की है, वहां पर मान्यता प्राप्त यूनियन यह कहती है कि टैम्पोरेरी तो लेबर है, जो अस्थायी मजदूर हैं, उनको स्थायी किया जाए, स्थायी जगहों पर रखा जाए और जो दूसरी यूनियनें हैं, वह कह रही हैं कि कान्ट्रक्ट लेबर को पहले जगह दी जाए। अब श्रीमन् क्या किया जाए? मान्यता प्राप्त यूनियन की बात को माना जाए या अमान्यता प्राप्त यूनियन की बात को माना जाए। यह प्रश्न सिर्फ मेरे सामने नहीं है, बल्कि सब के सामने है। मेरे सामने यह प्रश्न मजदूर विभाग के मंत्री होने के नाते नहीं है। अपने हृदय पर हाथ रखकर अन्तरतर की गहराइयों में जाकर, हमारे साथी सोचें कि इसका क्या रास्ता हो सकता है? जब तक इसका रास्ता नहीं निकलेगा, तब तक औद्योगिक शांति नहीं हो सकती है। इसलिए आज यह आवश्यक है कि हम इन प्रश्नों को राजनीति से ऊपर ले जायें, अगर हम वास्तव में औद्योगिक शान्ति चाहते हैं, अगर हम वास्तव में इन सब प्रश्नों का निबटारा करना चाहते हैं, तो मैं श्रीमन् आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इन विद्वान सदस्यों को सहयोग देना चाहिए। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता कि इनकी मंशा बुरी है, जिनका जीवन श्रमिक आंदोलन को समर्पित रहा हो, उनसे मैं कह दूं कि उनकी मंशा बुरी है—यह मुझे शोभा नहीं देता है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर रास्ता क्या है, आखिर उपाय क्या है?

हमारे सम्मानित वरिष्ठ साथी, श्री चित्त बसु ने यहां पर कहा कि शासन तो आज जो संगठित मजदूर पक्ष है, आर्गेनाइजड लेबर है, शासन उनके विरोध में है और उसके प्रति हमला बोला हुआ है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि क्या ये स्वीकार नहीं करते कि आज करोड़ों श्रमिक ऐसे हैं, यह प्रश्न नहीं है कि संगठित मजदूरों को ज्यादा मिलता है लेकिन क्या ये इससे सहमत नहीं हैं कि आज जितने संगठित मजदूर हैं, उससे बहुत बड़ी संख्या में शायद चौगुनी संख्या में आज असंगठित मजदूर हैं। यह ठीक है कि आप अवश्य स्वीकार करते हैं, मुझे भरोसा है और इसे मस्तक हिलाकर स्वीकार करने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज श्रमिक संगठनों की क्या स्थिति है। हमारे वरिष्ठ सदस्य, मेरे पुराने मित्र, प्रो० दंडवते जो बैठे हुए हैं, उन्होंने उनके जनता मंत्री मंडल ने शायद स्वीकार किया था और जनता प्लानिंग कमीशन ने जो एक ड्राफ्ट योजना भी बनाई थी। हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी शायद मंत्री मंडल में स्वीकार किया था, यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है, हम सबको मानना पड़ेगा, चाहे हम हों या कोई और हो, उनके प्लान डाक्युमेंट में था कि

1. The real wages of workers in the (lower income) should not be allowed to fail. For other workers except supervisory and managerial personnel in the (highest income and those whose emoluments are far in excess of the average for similar skills, graded compensation for significant increase of cost should be granted.

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

2. Real wages should also change in some relation to the change in real productivity per worker.

मान्यवर, आज प्रश्न यह है कि क्या हम केवल कुछ पेड़ों को देखें या सारे वन को देखें ? हमारा कहना यह है कि हम सारी वन राशि को देखें, सारे जंगल को भी देखें और पेड़ों को भी देखें । केवल एक वर्ग को देखना या यह कहना कि एल०आई०सी० में ऐसा हो गया या बैंक में ऐसा हो गया—यह काफी नहीं हैं । श्रम नीति की सफलता केवल यूनिट या हड़तालों की संख्या से ही नहीं देखी जा सकती ।

अब आप बंगलौर की कहानी सुनिए । कल मेरे परम मित्र संसद सदस्य ने बंगलौर की कहानी के बारे में कहा कि हम चुपचाप बैठे रहे । हम क्या चुपचाप बैठे रहे ? हमारे आग्रह पर मैनेजमेंट द्वारा 220 रु० से बढ़ाकर 225 रु० किया गया, प्रस्ताव रखा गया और पांच रुपया बढ़ाया गया और 300 रु० से 600 रु० एंडवांस का प्रस्ताव रखा गया । यह भी कहा गया कि अगर मामला सही है, एग्रीमेंट में बल है और यह कहा जाता है कि एग्रीमेंट को मान लिया गया था, समझौता मान लिया गया था, तो सरकार बाध्य है, मजबूर है, उस एग्रीमेंट को मानने के लिए । एग्रीमेंट ठीक है या नहीं, सरकार एग्रीमेंट मानने के लिए बाध्य है । तो सरकार की ओर से कहा गया कि इस सम्पूर्ण प्रश्न को पंचनामे को दे दीजिए, आर्बीट्रेशन में दे दीजिए, एडजूडीकेशन में दे दीजिए, जिस में एक हाई कोर्ट का जज रहे, यह प्रस्ताव मैनेजमेंट की ओर से, प्रबन्धकवर्ग की ओर से रखा गया था । अब यह कहना कि कुछ नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं कहा जा सकती । यह कहा जा सकता है कि हमारी सारी मांगें मंजूर नहीं हुई लेकिन यह कहना कि कोई प्रगति नहीं हुई और कुछ नहीं किया गया, यह सत्य से परे होगा क्योंकि पंचनामे की बात भी कहीं गई थी, आर्बीट्रेशन, एडजूडीकेशन की भी बात कही गई थी लेकिन संघर्ष समिति को स्वीकार नहीं हो सकी । श्रीमन् यह जो स्वीकार नहीं किया गया, तो उस के अपने कारण होंगे, मैं इस में नहीं जाना चाहता । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो यह कहते हैं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में दरवाजे बिल्कुल बन्द कर दिये, यह सत्य से परे है । केवल यह तथ्य सदन के सामने लाना चाहता हूं ।

श्रीमन्, यह जो शासन है और यह जो सरकार है, जिस का इतिहास श्रमिकों ने बनाया है, जिस का इतिहास इस देश के दलित शोषित और पीड़ितों ने बनाया है और 94 सालों का जो इस पार्टी का इतिहास है, वह इन्हीं लोगों ने बनाया है । महात्मा गांधी जो ने टेक्सटाइल लेबर एसोसियेशन अहमदाबाद में बनाई थी । यह वही पार्टी है, जिस का आज शासन है । तो वह कांग्रेस शासन मजदूर विरोधी कैसे हो सकता है । जवाहरलाल नेहरु जी का जिसे आशीर्वाद प्राप्त रहा हो, श्री मौलाना आजाद का जिसे आशीर्वाद प्राप्त रहा हो, श्री वी. वी. गिरी और श्री एन. एम. जोशी का जिसे आशीर्वाद प्राप्त रहा हो, वह पार्टी, वह शासन मजदूर विरोधी कैसे हो सकता है ।

श्री नारायण चौबे : श्री वी. वी. गिरी को रिजाइन करना पड़ा था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : बाद को वही श्री गिरी राष्ट्रपति हुये थे । श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं और हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं । क्या यह सम्भव है कि हर हड़ताल की हर यूनियन की हर बात कोई भी शासन क्या मान सकता है ? हमारा काम तो यह है कि हम दोनों के बीच समझौता

कराएं । क्या यह बात है कि लेबर मिनिस्ट्री खुद यह हुकुम दे दे कि हड़ताल की हर बात को मान लो ? क्या यह सम्भव है और श्रीमन, मैं यह कहना चाहत हूं कि यह सम्भव नहीं है । किसी भी देश में और आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है, जहां हर हड़ताल की हर बात मान ली गई हो । हर हड़ताल में एक समझौता होता है, एक समन्वय होता है और इस समन्वय को लाने की चेष्टा करना लेबर मिनिस्ट्री का यही काम है ।

पब्लिक सेक्टर की बात कही गई, सार्वजनिक क्षेत्र की बात कही जाती है । मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में फर्क है । पब्लिक सेक्टर के लिए इस संसद ने नियम बनाए हैं क्योंकि वह पूंजीपतियों का सेक्टर नहीं है, सरमायदारों का सेक्टर नहीं है । पब्लिक सेक्टर का एक कल्चर होना अभी शेष है और पब्लिक सेक्टर में समन्वय होना भी अभी शेष है । पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइज इतने बुरे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ, श्री चित्त बसु जी की बात सुन कर । वे तो इतने बुजुर्ग हैं ।

श्री चित्त बसु : वह तो देश से बड़ा है, कैबिनेट से भी बड़ है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : कैबिनेट से बड़ा नहीं है । कैबिनेट का बनाया हुआ चालक है । श्रीमन, मैं यह कह रहा था ....

श्री नारायण चौबे : लेकिन वह भस्मासुर है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : वह आप के सिर पर सवार है ।.... **(व्यवधान)**

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज पब्लिक सेक्टर के कई यूनिटों को सुधारने की जरूरत है, यह मैं स्वीकार करता हूं । पब्लिक सेक्टर का एक कल्चर होना चाहिए और हमें उसे और सुदृढ़ करना चाहिए । वह एक संस्कृति है, एक विचार है और सार्वजनिक क्षेत्र के उस विचार को हमें और परिपक्व करना चाहिए, इसे मैं स्वीकार करता हूं लेकिन इस का यह अर्थ नहीं है कि हम पब्लिक सेक्टर को कमजोर कर दें, पब्लिक सेक्टर में विश्वास रखते हुए, जो पब्लिक सेक्टर की मर्यादा है, मान्यताएं हैं और जो उस का उत्पादन है, उस को भी हम कम कर दें या आधा ही समाप्त कर दें । तो मैं यह चाहूंगा कि जो नेशनल लेबर कान्फ्रेंस होने जा रही है, राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को हम निमंत्रित कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस संसद के जो विद्वान सदस्य हैं, जो इन संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उन के या उनके संगठनों के विचारों का पूरा लाभ हमें वहां प्राप्त होगा । इसीलिये मैं इस समय यहां कोई ऐसा वातावरण नहीं पैदा करना चाहता जिस से हमारे जो उद्देश्य हैं, जिन को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस से हम में और आप में किसी प्रकार का भेद बढ़ जाए । हम चाहते हैं कि उस राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में बहुत सी बातें चाहे वे नेशनल वेज पालिसी के बारे में और चाहे श्रम नीति के बारे में हों, चाहे वह किसी प्रकार के मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन के चयन करने के बारे में हो, उन सब प्रश्नों को हम सुलझाना चाहते हैं । **(व्यवधान)**

श्रीमन् यह कहा गया कि हमारा जो श्रम विभाग है उसके कुछ सेक्शंस वगैरहा में ढिलाई आ रही है । अगर आप देखें कि हमारे श्रम विभाग द्वारा 1 लाख 82 हजार इरेंगुलरिटीज पाई गयी थीं जिनमें से लगभग 1 लाख 61 हजार पर कार्यवाही की गयी ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

श्रीमन् चाइल्ड वैल्फेयर के बारे में, बालकों के कल्याण के बारे में राजस्थान के मेरे मित्र को पूरी सूचना नहीं हुई इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं । उन्होंने जो इसका जिक्र किया, मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं और उनको समझ सकता हूं । इन भावनाओं के पीछ उनकी जो पीड़ा है, दर्द है, उसको भी मैं समझ सकता हूं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हर मामला विचाराधीन है ऐसा नहीं है । उसकी रिपोर्ट को अगर आप कृपा करके आप पूरा देखें तो मालूम होगा कि आर्डर्स आर अण्डर इशु । मेरे पास भी लिखा हुआ आर्डर है जिसमें चाइल्ड वैलफेयर, चाइल्ड लेबर के बारे में है कि अभी फरवरी में रिपोर्ट आयी और इस पर 13 मार्च, 1981 को निर्णय लिया गया । इसमें मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चाइल्ड वैल्फेयर एडवाइजरी बोर्ड बन गया है । उसकी पहली बैठक भी हो चुकी है । उसकी एक जो संस्तुति है वह बड़े महत्व की है । कमेटी ने यह कहा है जिसे हमने सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है—

The Commitee recommends that the penalty provided in the existing laws for the violation of provisons relating to child labour should be made rigorous..... and imprisonment which may extend to one year or fine extending to Rs. 2,000 or both. In the case of second or continuing offence, penalty should be only imprisonment and that too for two years.

इस संस्तुति को स्वीकार कर लिया गया है ।

अब श्रीमान् एक बात और है । हमें राज्यों के श्रम मंत्रालयों का भी ध्यान रखना चाहिए । हमें इस बात की जानकारी है कि सारे राज्यों में श्रम मंत्रालय और पूरे श्रम विभाग हैं । कल श्री आनंद जी ने इस बात को कहा कि वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 11 सौ कांट्रैक्ट लेबर को रेगुलराइज कर दिया है । जब यहां पर राज्यों की बात आती है तो उसमें राज्य सरकार की तारीफ होती है । जैसे उन्होंने पश्चिमी बंगाल सरकार की तारीफ की लेकिन हमारी तारीफ नहीं की । अगर वे यह कह देते कि आपने भी इसे कराया तो उचित होता । लेकिन जहां हो गया वहां राज्य की तारीफ हो गयी और जहां नहीं हुआ हमको वहां जिम्मेदार कह दिया गया । (व्यवधान) इसका अर्थ क्या है ? इसी तरह से कहा गया कि वैस्ट बंगाल में कृषि के न्यूनतम वेजिज आठ रुपये सबको मिल रहे हैं—

MR. DEPUTY-SPEAKER: Credit goes to you also because 'Labour' is a Concurrent subject.

SHRI NARAYAN DUTT TIWARI: Sir, I do not want credit. I do not want discredit also.

श्रीमन् मैं यह कह रहा था कि एग्रीकल्चरल मिनिमम वेजिज के बारे में, एग्रीकल्चरल वर्कर्स के बारे में बिल बन गया है । अब जब कोई बिल बनता है तो उसके बारे में राज्य सरकारों से भी पूछना पड़ता है । अगर हम राज्य सरकारों से न पूछें तो क्या उचित होगा ? आप देखें कि कुछ राज्य सरकारों ने हमारी छठी पंचवर्षीय योजना को भी मंजूर नहीं किया, उसके उसूलों का विरोध किया, बाद में उन्होंने मान लिया कि योजना के प्रोग्रामों को, कार्यक्रमों को हम मान लेंगे । अगर किसी बिल के बारे में हम राज्य सरकारों से न पूछें तो हमें जो शक्ति चाहिए, उसे लागू करने के लिए, वह पूरे अर्थ में नहीं मिलती है । अधिकतर कानून या नियम राज्य ही लागू करते हैं ।

श्रीमन्, इस प्रकार के एक नहीं कई कानून ऐसे हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि उनको हम जल्दी से जल्दी यहां लाएं । प्रौविडेंट फण्ड एक्ट के बारे में रामानुजम कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर के, 6 महीने के अन्दर हमने कानून लाने का जो वायदा किया, प्रतिज्ञा की, उसको हम यथासंभव पूरा करेंगे । इसके लिए कांफ्रेंस बुलानी पड़ेगी, राज्य सरकारों से पूछना पड़ेगा । श्रमिक संगठनों से पूछना पड़ेगा । तभी हम 6 महीने के अन्दर प्रोविडेंट फण्ड एक्ट के बारे में कानून ला पायेंगे । उसमें यह भी व्यवस्था है कि दस मजदूरों तक वह प्रोविडेंट फण्ड एक्ट लागू होगा ।

इसी प्रकार से एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन के बारे में शिकायतें आयी हैं । मैं यह कह दूं कि वहां सब कुछ अच्छा चल रहा है तो यह उचित नहीं है । कुछ शिकायतें हैं । यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने प्रोविडेंट फण्ड के बारे में भी कहा । उसके सम्बन्ध में हम जांच करायेंगे । मेरा प्रत्येक माननीय सदस्य से आग्रह है कि कहीं भी प्रोविडेंट फण्ड के लागू करने के बारे में, या इम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस की कोई शिकायत उनके पास आये तो वह कृपा कर के हमें भेजिये ताकि हम उस पर उत्तर दे सकें कि हमने क्या किया है । इसलिए आप से आग्रह है कि आप ऐसी बातें हमारे प्रकाश में लाएं ताकि हमें विवरण प्राप्त हो सके । इसी प्रकार सम्मानित व्यास जी ने भीलवाड़ा के बारे में कहा, अगर ऐसा कोई कारण नहीं है, तो हम इस पर भी उचित निर्णय लेंगे और इसी प्रकार से आपने "मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स" के बारे में कहा, उसकी भी हम पूरी जांच करेंगे । इसी प्रकार से तमिलनाडु के श्री कंदस्वामी ने जो विवरण पेश किया है, उसके बारे में भी संबन्धित राज्य सरकार से बात की जाएगी ।

एक माननीय सदस्य : बंधुआ मजदूरों के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : बंधुआ मजदूर कानून तो 1975 में ही मुक्त हो गए थे, तब मेरे छोटे भाई हमारे साथ थे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : व्यवहार में क्या हो रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : व्यवहार में श्रीमान् 25 करोड़ रुपया छठी पंचवर्षीय योजना में रखा गया है । 25 करोड़ रुपया बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए रखा गया है, इससे बंधुआ मजदूरों का रीहैब्लीटेशन किया जाएगा और बंधुआ मजदूरों को तो इसी साल रीहैब्लीटेट किया जाएगा । एग्रीकल्चर लेबर के संगठन में सहायता के लिए एक करोड़ रुपया रखा गया है ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : 50 करोड़ रखा था अब 25 करोड़ कम कर दिया गया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : इस साल 3 करोड़ 25 लाख रुपया 17264 बंधक मजदूरों को रीहैब्लीटेट करने के लिए रखा गया है ।

इसी प्रकार एप्लाइज़ स्टेट इंशोरेंस एक्ट के बारे में हमारा इरादा यह है कि ढाई लाख और मजदूरों को जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं और जो सीजनल मजदूर हैं, जैसे चीनी के मजदूर, उन पर भी इस एक्ट को लागू किया जाए ।

ग्रेच्युटी एक्ट में भी संशोधन प्रस्तावित है । वर्क मैन्स कंपसेशन एक्ट में भी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मुआवजे की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है । पेमेंट आफ वेजेज एक्ट में कवरेज के विस्तार का प्रस्ताव है । इनके अलावा तीन और एक्ट—इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल एंप्लाएमेंट स्टैंडिंग आर्डर्स एक्ट और ट्रेड यूनियन्स एक्ट, इन तीनों के बारे में हम चाहेंगे कि इसी सत्र में अगर सदन इजाजत दे और इनमें से 2-4 कानून पास कर दिए जाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपकी मजबूरी भी समझता हूं कि 60-70-100 बिल आपके सामने और बिजनिस एडवाइजरी कमेटी के सामने आ जाते हैं और आपके सामने कठिनाई यह होती है कि किसको प्राथमिकता दी जाए । मेरा आपसे आग्रह है कि आप कृपया श्रम-कानूनों को प्राथमिकता दिलायें ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : महिलाओं के बारे में अभी तक आपने कुछ नहीं कहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, इसी प्रकार केरल के नायर जी ने सरकस इंडस्ट्री के बारे में कहा, इसके बारे में भी कानून प्रस्तावित है । प्लांटेशन लेबर एक्ट अभी पास नहीं हुआ है, मुझे दुख है कि इसमें देर हुई है, राज्य सभा में यह बिल प्रस्तावित हुआ था, अब हम राज्य सभा से आग्रह करेंगे, संसदीय भाषा में—हम दूसरे सदन से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस सत्र में इस पर विचार करे ।

पालेकर एवार्ड के बारे में चर्चा की गई । स्टेचुटरी वेज बोर्ड जरनलिस्ट्स के लिए है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही अन्य वेज बोर्डों को स्टेचुटरी बनाया जाए । इसके लिए हम कानून प्रस्तावित कर रहे हैं । पालेकर एवार्ड के बारे में कहा गया कि टाइम्स आफ इण्डिया और स्टेट्स मैन वगैरह पत्र इस पर विचार नहीं कर रहे है । आपको मालूम है कि कुछ समाचार पत्रों के मालिकान कोर्ट में चले गए हैं और उन्होंने वहां से स्टे आर्डर ले लिया है । हमारी कठिनाई यह है कि अदालत के सामने हम मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, हमने प्रत्येक मुख्य मंत्री से इस बारे में बातचीत की है, राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक अनदर भी उनसे अलग से बातचीत की गई । अधिकांश राज्यों में अधिकांश समाचारपत्रों ने पालेकर एवार्ड को मान लिया है । दुख की बात है कि चन्द समाचारपत्र अभी भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अदालतों का सहारा लिया है । यह उनका अधिकार है । लेकिन उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वे पालेकर अवार्ड की जो आत्मा है, जो परिधान है, उसको समझें और उसको स्वीकार करें । उसमें कोई ऐसी बात नहीं है । मुझे दुख है कि टाइम्स आऊ इंडिया और स्टेट्समैन जैसे अखबार भी इतनी देर लगा रहे हैं । इस सब को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि इसको लागू करने के लिए राज्य श्रम मन्त्री के संयोजकत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए जो पालेकर एवार्ड को सही मानों में लागू कराने की पूरी चेष्टा करे ।

पार्ट टाइम संवाददाताओं के निकाले जाने की बात भी बहुत से माननीय सदस्यों ने कही है और इसके बारे में भी बहुत से समाचार आए हैं । वर्किंग जरनलिस्ट्स की परिभाषा में ये भी आते हैं, अंशकालिक संवाददाता भी आते हैं, । इस बात को समाचारपत्र भी जानते हैं । बहुत से मुख्य मंत्रियों ने इस सम्बन्ध में कदम उठाए हैं और उन्होंने यह भी निर्णय लिया है कि वे उनको विज्ञापन देना बन्द

कर देंगे । इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों के मालिकों को भी उनके द्वारा बुलाया गया है । विशेष रूप से जो छोटे समाचारपत्र हैं वे कठिनाई व्यक्त कर रहे हैं । हम समझते हैं कि जल्दी ही हम मालिकों को जब बुलाया जायेगा तो इसका कुछ समाधान निकल आएगा ।

बहुत से विषय हैं जिनका मैं उल्लेख कर सकता था लेकिन सदन के माननीय सदस्य तमाम बातों की जानकारी रखते हैं । जहां तक एम्प्लायमेंट का सम्बन्ध है छठी योजना में 3.4 करोड़ लोगों को नए रोजगार देने की बात कही गई है । सबसे अधिक हमने स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करने पर जोर दिया है । सैल्फ एम्प्लायमेंट के माध्यम से मैं समझता हूं कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है । बहुत सी योजनायें हैं जिनका उल्लेख समय-समय पर किया जा चुका है और बहुत सी जानकारी प्रश्नों के उत्तरों में दी जा चुकी है । लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हू कि बेकारी का प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है, न केवल शासन के समक्ष बल्कि सारे देश के समक्ष भी । बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक मुख्य कारण है । शिक्षा का जो हमारा पुराना ढग है उसको बदलने में भी हम उतने सफल नहीं हुए हैं । ये सब बात हैं जिसकी वजह से यह बेकारी का प्रश्न हमारे सामने हैं । यह ऐसा प्रश्न हैं जिसको हम सब को मिल कर सोचना होगा और हम कैसे इन योजनाओं को सफलीभूत बनाए यह देखना होगा । बेकारी और बेरोजगारी दूर करने की योजनायें तभी सफल हो सकती हैं जब सदन का प्रत्येक सदस्य अपना सहयोग दे और बिना पार्टी का विचार किए, पार्टी के से ऊपर उठ कर हम सब एक राष्ट्रीय वातावरण बनाए ।

इन शब्दों के साथ मैं अति विनम्र शब्दों में इस माननीय सदन के सम्माननीय सदस्यों से आग्रह करूगा कि इन अनुदानों को वे स्वीकार करें । इस देश के निर्माण में श्रमिकों का महान योजदान है । इस देश के भविष्य को बनाने में, देश का निर्माण करने में कोटि-कोटि श्रमिकों का महायोगदान रहा है और रहेगा । श्रमिकों के नाम पर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे कुछ साथियों ने कटौती के प्रस्ताव पेश किए हैं । श्रमिकों के नाम पर कटौती प्रस्ताव ? उनको यह कहना चाहिये था कि श्रमिकों के लिये रुपया और बढ़ाओ । मैं आग्रह करूंगा कि हमारे मित्रों ने जिन्होंने श्रमिकों के लिए अपना जीवन अर्पित किया है वे अपने कटौती प्रस्ताव वापिस ले लें और दिखा दें कि वे श्रमिकों के लिए कोई कटौती नहीं बल्कि और बढ़ोतरी चाहते हैं ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : विमेंज एम्प्लायमेंट के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया है । मिनिस्टर आफ स्टेट महिला हैं । यह देश का बहुत बड़ा सवाल है । क्या उन्होंने कोई टारगेट फिक्स किए हैं ? इक्वल रिम्युनरेशन एक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है, बीड़ी वर्कज के लिए कुछ नहीं कहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महिलाओं के बारे में योजना में 27 वां पूरा चैप्टर है ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : नैशनल कमीशन फौर वीमन के बारे में आपने कुछ नहीं कहा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : आप जब मिलेंगी तो बात करेंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri A. K. Roy. Do not make a speech.

SHRI A. K. ROY: The Contract Labour Abolition Act defines what is the perennial nature of a job. What is the fate of the workers after departmentalisation? The Minister may clarify this firstly. Secondly, 9,000 workers of Dali Raja Hare Ore are on strike. I want an assurance whether you will take some initiative in the matter?

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: I would like to invite you over a cup of tea to discuss this matter with me.

एक माननीय सदस्य : कट मोशन्स जितने दिये गये हैं उनका आप जवाब देंगे ? और 30 लाख बीड़ी मजदूरों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जितने भी माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं और जो भी उल्लेखनीय बात कही हैं मैं उनका उत्तर अलग अलग भिजवा दूंगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: In view of the appeal made by the hon. Minister, the hon. Members would agree to withdraw their cut motions.

SEVERAL HON. MEMBERS: No.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If the House agrees, I shall put all the cut motions moved to these demands together.

All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Labour to the vote of the House.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1982, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 65 and 66 relating to the Ministry of Labour."

The motion was adopted.

Demands for Grants 1981-82 in respect of Ministry of Labour Voted by Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on Account voted by the House on 13-3-1981		Amount of Demand for Grant voted by the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
MINISTRY OF LABOUR					
65.	Ministry of Labour	16,21,000	..	81,06,000	..
66.	Labour and Employment	12,11,60,000	2,12,000	60,58,03,000	10,63,000

18.02 hrs.

ARREST OF MEMBER

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have to inform the House that the Speaker has received the following wireless message from the Commissioner of Police, Calcutta today:—

"I have the honour to inform that Shri Ashok Sen, Member, Lok Sabha courted arrest along with others at 13.20 hours on 7-4-1981 at Alipore Criminal Court Compound, Calcutta".

The House stands adjourned till 11 A.M. on 8th April, 1981.

18.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the April 8, 1981/Chaitra 18, 1903 (Saka)

GMGIPMRND—368 LS—Mono— 2-7-81—800